राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या: 08

गुरुवार,
15 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम राम, साहब। नमस्कार, नमस्कार। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपकी तबीयत कैसी है, अब ठीक है?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जी हां।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा आर्थिक सहायता

123. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी है? यदि हां, तो कितनी-कितनी, कब-कब व नहीं, तो क्यों? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नवस्थापित कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि, कब तक? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी नहीं। कृषि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

(तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री)

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को कोई सहायता राशि नहीं मिली है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष बजट प्रावधान में विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत प्रावधित राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो राजस्थान में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता गत चार वर्षों में कितनी कितनी और कब कब दी गयी? दूसरे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं जैसे जोबनेर, कोटा, उनकी बनिस्पत जोधपुर विश्वविद्यालय में कम क्यों दी गयी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है जोधपुर विश्वविद्यालय 2013 में हमारी सरकार के वक्त स्थापित किया गया है। चूंकि विश्वविद्यालय का एक्रीडिटेशन अभी नहीं हुआ है, जहां तक कोटा और जोधपुर को अनुदान का सवाल है, उन्होंने 2016-17 में अपना एक्रीडिटेशन प्राप्त कर लिया है। विश्वविद्यालय भवन का अभी वहां निर्माणाधीन है। उसमें जिस प्रकार की आवश्यकता, मापदण्ड़ होने चाहिये, उनमें प्रशासनिक भवन की उपलब्धता, कालेज भवन का हास्टल, प्ले ग्राउंड, लाइब्रेरी और फैकल्टी संबंधी जितनी भी आवश्यकताएं थीं, आईसीएआर की एक हाई पावर कमेटी का निरीक्षण दिसम्बर, 2016 में वहां किया गया और मैं समझता हूं कि उसमें जो कमियां रही हैं, उसको पूरी करने के डाइरेक्शन विश्वविद्यालय प्रशासन को दिये गये हैं।

आपने कहा कि जोधपुर में अनुदान नहीं मिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करुंगा कि हमारी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सरकार, हम लोग कोशिश करके तीन प्रकार की सहायता विश्वविद्यालयों को देने का काम करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट जो मिलती है वह तो एजुकेशन के हिसाब से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उन कालेजों को दी जाती है जो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो हमारे पांचों विश्वविद्यालय हैं, उनमें चार का एक्रीडेशन का पूरा हो चुका है, एक का अभी बाकी है। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तीन प्रकार के काम होते हैं। एक्सटेंशन होता है, रिसर्च होता है, एजुकेशन होता है। एजुकेशन में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिये आईसीएआर से जो बजट दिया जाता है वह तब तक नहीं मिलता जब तक उसका एक्रीडिटेशन नहीं हो जाए। इसके अलावा एक्सटेंशन और रिसर्च का जहां तक सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा तीन प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत हम लोग उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं जिसमें उनको आईसीएआर के द्वारा भी पैसा मिलता है, राजस्थान सरकार भी देती है और आरकेवाई योजना भी देती है। उन्होंने पूछा अब तक कितनी राशि जोधपुर को उपलब्ध करायी गयी है? मैं 2014-15 से 2017-18 तक आपके माध्यम से निवेदन करूंगा 7155.58 करोड़ रुपये अब तक जोधपुर विश्वविद्यालय को इन चारों सालों में राशि उपलब्ध कराई गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न मद के अंतर्गत इनको राशि 2.98 लाख रुपये दी गयी है। राज्य मद से वेतन भत्ते और कंटीन्जेंसी क्षेत्र के काम, लैब आदि के जो काम है, उसके अंतर्गत 1018.77 करोड़ रुपये इनको उपलब्ध कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक निर्माण कार्य का सवाल है, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, कृषि महाविद्यालय मंडोर, कृषि महाविद्यालय सुमेरपुर और कृषि महाविद्यालय नागौर, चारों एफिलिएटेड कालेज इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, इन सबको जोड़कर 7188 करोड़ रुपये की सहायता अब तक सरकार के द्वारा दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नंबर दो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर कितने केवीके हैं, उनको कितनी कितनी सहायता दी गयी है तथा इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो बीज उत्पादन

(श्री अर्जुन लाल)

और अनुसंधान किये जा रहे हैं, विश्वविद्यालय को कितनी उन पर लागत आई है और उनसे वापस आय कितनी हुई है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 केवीके अभी संचालित किये जा रहे हैं और 6 केवीके के अंतर्गत अब तक सरकार के द्वारा जो उनको राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसका परिशिष्ट में मैंने आपको जवाब दे दिया है। जहां उन्होंने बीज उत्पादन, माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्रीडर सीड देकर सर्टिफाइड सीड तैयार करने का काम यूनिवर्सिटीज करती हैं, जो रिसर्च का एक पार्ट होता है। जहां तक रिसर्च का सवाल है 2016-17 में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा जो बीज का उत्पादन हुआ है वह 1313.69 क्विंटल बीज का उत्पादन विश्वविद्यालय के द्वारा अब तक किया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में कृषि शिक्षा में विश्वविद्यालय ज्यादा हैं, कालेज कम हैं। पिछली सरकार ने ईर्ष्यावश विश्वविद्यालय तो पांच खोल दिये...

श्री अध्यक्ष: जनरल नहीं, इससे संबंधित सवाल कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसी से संबंधित है। 40 साल पहले चिमनपुरा और सवाईमाधोपुर में दो कालेजों में एग्रीकल्चर की फैकल्टी खोली गयी थी। उनको सैपरेट कालेज का दर्जा नहीं दिया गया जबकि नये विश्वविद्यालय खड़े कर दिये गये, नये कालेज खोल दिये गये। 40 साल से जो फैकल्टी चल रही है, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं क्या उनको सैपरेट कालेज करेंगे? सैपरेट कालेज करने पर ही आईसीएआर की ग्रांट मिलेगी वर्ना नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं सवाईमाधोपुर, उनियारा और चिमनपुरा, इन कालेजों को सैपरेट कालेज बनाने का इरादा है क्या? और अगर है तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, जवाब हो तो दे दीजिए, इससे रेलेवेंट तो नहीं है यह। आप जवाब दे दीजिए, इससे संबंधित नहीं है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कालेज खोलने का सवाल है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करुंगा, प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा अभी हाल ही में बजट में की गयी है। चिमनपुरा, उनियारा और सवाईमाधोपुर कालेजों में जो हमारी शिक्षा चल रही है, वहां पर लैंड की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इतनी जमीन की उपलब्धता पर उसको बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी तीनों जगहों का परीक्षण कराकर निश्चित रूप से जो नियमों में प्रावधान है, उनके अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय को आपने सम्बल दिया। मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कितने वर्ष हो गये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में जमीन अलाटमेंट नहीं हुई। एक्रीडिटेशन जो मिलना चाहिये, वह नहीं मिला। बिल्डिंग का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ। रिसर्च और एजुकेशन के मामले में अभी वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय यह बताये कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के इतने समय बाद भी जमीन अलाटमेंट का विषय, बिल्डिंग निर्माण का विषय, एजुकेशन और रिसर्च का विषय, यह कब तक निपट जाएंगे और विश्वविद्यालय अपना पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व कब तक प्राप्त कर लेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि जोधपुर विश्वविद्यालय की 2013 में स्थापना के बाद जमीन का आवंटन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का जो प्रशासनिक भवन बनना था, वह अभी निर्माणाधीन है। उसमें चार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। दो प्रकार की जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। एक तो मंडोर का जहां बनने की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी 61 हैक्टेयर वहां पर लैंड की अवेलेबिलिटी है। जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वहीं पर बनाने का अभी तक

(श्री प्रभू लाल सैनी)

फैसला हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यह कोशिश की है। ओसियां का भी हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो कि जोधपुर से तीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, लेकिन उसका जो टोपोलॉजिकल एरिया था, वह उबड़-खाबड़ था। वह एग्रीकल्चर के मकसद का नहीं था। दूसरा, नोन रिन्युएबल एनर्जी, वह डिपार्टमेंट की जमीन थी, जिसके बारे में आबंटन की बात कर रहे थे, लेकिन विभाग के द्वारा मना किया कि हम हमारी जमीन नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए फिलहाल अभी यही फैसला हुआ कि मंडोर वाली जो 61 हैक्टेयर जमीन है, उसी में कृषि विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन करके उसकी कार्यवाही हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय खुला है, उसमें अभी कितने प्रोफेसर की जगह खाली है और लैंड का मामला कहां पर अटका हुआ है? क्योंकि लैंड बहुत है। करवड़ में इतनी लैंड पड़ी है, जिसको देने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सवाल यह है कि लैंड का अलाटमेंट कब हो जाएगा?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज की जहां पर वैकेंसी का सवाल है, उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूं कि अगले दो माह में, हमने जो 144 पदों की स्वीकृति जारी की है, उन सबका रिक्रूटमेंट प्रकियाधीन है। निश्चित रूप से शीघ्र ही भरकर विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से चालू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री बनवारीलाल सिंघल।

अलवर में स्वीकृत सड़कें

124. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर में गत 01 वर्ष में सरकार द्वारा कितनी सडकें स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

(2) उक्त सड़कों के निर्माण पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई व कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) अलवर में विगत 1 वर्ष में 854 सड़कें (2205.47 किमी.) स्वीकृत की गयी हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़कों पर विभाग द्वारा अब तक किया गया व्यय एवं जो व्यय किया जाना शेष है, उसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) पूर्ण हुई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न करने से पहले मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं, 1417 करोड़ रुपये की सड़कें अलवर में स्वीकृत हुई हैं। जिनमें बहुत बड़ी राशि की सड़कें अलवर शहर में भी स्वीकृत हुई हैं। अलवर शहर में पिछले एक वर्ष में और पिछले चार वर्ष में, ये दोनों स्टेटिक्स आप मुझे बता दें कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा स्वीकृत हुई हैं? यह पहला प्रश्न है, दूसरा इसके बाद पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में तीन ग्राम पंचायतें ही आती हैं। उन तीन में दो ग्राम पंचायतों में तो हमने ग्रामीण गौरव पथ बना दिये हैं और एक फिजीबल नहीं था, उसमें इन्होंने भी नहीं मांगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अलवर विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, उसमें लगभग 31 कार्य, कुल 61 किलोमीटर के काम, 57.23 करोड़ रुपये के काम हमने दिये हैं। काफी काम पूरे हो गये हैं। 13 काम पूर्ण हो गये और जो एक काम है, वह

(श्री युनुस खान)

प्रगतिरत है। मैं सोचता हूं कि इनका एक कट्टीघाटी से घोड़ापछाड़ चौराहे तक फोरलेन का काम था और वह शहर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, उसमें हमने 7.9 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की है। 33 करोड़ 4 लाख की राशि थी, उसमें से 26 करोड़ रुपये होकर, वह काम भी पूरा हो गया है। एनसीआरपीबी के जो काम हैं, अभी दिये हैं, वे प्रगतिरत हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा सवाल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं माननीय मंत्रीजी से यह और जानकारी चाहता हूं कि अलवर शहर के कालीमोरी फाटक पर जो फाटक रेलवे ने बंद किया है, उसको लेकर बड़ा जन आंदोलन भी हुआ था। निवासियों की बहुत बड़ी संख्या उस क्षेत्र में है, जो कि इस फाटक से प्रभावित हुई है। चूंकि वहां पर एक आर.ओ.बी. बना है, लेकिन जो पैदल लोग हैं या साइकिल रिक्शा वाले हैं या फिर विकलांग लोग हैं, उनके लिये अंडर पास के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने मुझे इस बाबत वादा भी किया था, तो आप इस आर.यू.पी. (रेलवे अंडर पास) की अनुमति देने का विचार रखते हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी इनके पूरक प्रश्न में कहा कि सात सड़कें और हैं जो हमने शहर में 39 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है, उनका काम प्रगतिरत है और जिस आर.यू.पी. की अलवर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है। आपने मांग भी रखी थी और उसकी हमने एस्टीमेट कोस्ट मंगवा ली है। उसको हम विद इन 15 डेज में स्वीकृत कर देंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चंद्रभान जी, यह तो अलवर से संबंधित है। अलवर से संबंधित अगर आपका रिलेवेंट सवाल है तो अलाउ करूंगा।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अलवर से संबंधित ही कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहिबा को भी धन्यवाद दूं, युनुस खान जी को भी धन्यवाद दूं कि हमारे पूरे प्रदेश में काफी सड़कें दीं और अलवर में भी खूब सड़कें दीं, पर 2017-18 में अलवर में कोई घोषणा कर रखी है, उस घोषणा की अभी तक पालना नहीं हुई है, उसका क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष: ठीक है आप बैठिये। अलवर के बारे में है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात अलवर के संबंध में कही है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो मैक्सिमम घोषणाएं की हैं, उन सबके टैण्डर भी हो गये और वर्क आर्डर भी हो गये। चूंकि कुछ कार्य ऐसे हैं, जिनके टैण्डर आचार संहिता की वजह से नहीं कर पाये थे। उनके टैण्डर भी 13.03.2018 को खोल लिये जाएंगे। अलवर में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की हुई घोषणा या मेरे द्वारा हाउस में या हाउस के बाहर की हुई घोषणा, कोई भी ऐसी शेष नहीं है, जिसकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। जहां तक चित्तौड़ की बात है, अगर आप अनुमति दे देंगे तो मैं उस पर भी बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष: चित्तौड़ के बारे में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। नो नो, इर्रलेवेंट है। श्री रामहेत सिंह यादव। अलवर से संबंधित हो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि आपने अलवर जिले में एक साल में 2205.47 किलोमीटर की 854 सड़कें मंजूर की हैं और उस पर काम चल रहा है। बहुत सारे रिनुअल के भी दिये हैं, पेचवर्क के भी दिये और क्वालिटीवाइज अच्छी सड़कें बनें, नयी सड़कें अच्छी हो, रिनुअल हो, अच्छा हो, पेचवर्क का काम भी अच्छा व गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिये आप खुद मानिटरिंग करते हैं। आपके ध्यान में एक गोविंदगढ़ के स्टेट हाइवे का विषय आया था कि उसमें पैचवर्क में कुछ गड़बड़ हुई। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपने जे.ई.एन.,ए.ई.एन. के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की। आपने एक जांच कमेटी बैठायी और जांच कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है। जांच में माना कि तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा मौके पर माप पुस्तिका में दर्ज मापों की टैस्ट चैकिंग भी गयी। अधीक्षण अभियंता को टैस्ट चैकिंग के दौरान इस तथ्य को भी देखना चाहिए था कि जिस प्रकार तीन दिवस में 10 लाख 3 हजार 606 रुपये का कार्य निष्पादित हो गया। चूंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग नियमों के अनुसार अधीक्षण अभियंता भुगतान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और इस संदर्भ में अभी अख़बार में भी छपा। अलवर एस.सी.

(श्री रामहेत सिंह यादव)

का बयान आया 'मेरी नजर के मामले में अधीक्षण अभियंता दोषी नहीं हैं। इसके लिये उनका आरोप-पत्र नहीं भिजवाया जा रहा, जवाब दे दिया जाएगा' उधर एडिशनल चीफ का एक बयान आया कि 'इस प्रकरण में भुगतान के लिये दोषी अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, तीनों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर प्रस्तुत करके भेजें। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने दो नीचे के अधिकारियों के खिलाफ तो कार्यवाही कर दी। जिसने उसको चैक किया, मेजरमेंट किया, दस्तखत किये। आपने माना कि उसमें गड़बड़ हुई है। सड़कों का पैच नहीं हुआ और पैसा उठा लिया तो क्या अधीक्षण अभियंता भी दोषी है? आप दोषी मानते हैं तो कब तक कार्यवाही करेंगे? क्या अधीशासी अभियंता भी दोषी है? आप दोषी मानते हैं तो कब तक कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पहले शिकायत की थी, उसकी हमने जांच करवायी। जांच में जो अधिकारी दोषी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की। चूंकि, अभी आप अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता की चर्चा कर रहे हैं, उस प्रकरण को मंगवाकर, अगर उसमें किसी भी स्तर के अधिकारी का दोष है तो उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगे।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): एक्स.ई.एन. को तो दोषी मान लिया आपने। आपने उसकी रिपोर्ट मंगा ली। उसके खिलाफ कार्यवाही की बात कर रहा हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज शाम से पहले ही रिपोर्ट मंगा लेंगे और कोई भी दोषी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: शंकर सिंह, अलवर से संबंधित है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अलवर की बात ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप अलवर की पूछिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि 31 मार्च, 2017 को माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर सड़कों की घोषणा की थी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर का नहीं है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बिलकुल अलवर से संबंधित बात कर रहा हूं। 832.16 करोड़ की जो सड़कों की आपने घोषणा की है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने सबकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। उसमें से सिर्फ दो सड़कें ..

श्री अध्यक्ष: अलवर की ही बात कीजिए आप।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अलवर की ही बात पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कौनसी दो सड़कें है अलवर की?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उसमें से दो सड़कों की वित्तीय स्वीकृति किसी अधिकारियों की बदमाशी से नहीं की गयी है। बहुत दयालु माननीय मंत्री महोदय हैं। आपसे आग्रह है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति, एक वर्ष हो गया है, जारी नहीं हुई है। कृपाया आज जारी करवाएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला सवाल श्री प्रहलाद गुंजल। स्थगित। सरकार की ओर से जो कारण बताए गए उनके औचित्य को स्वीकार करते हुए मैंने इसको स्थगित किया है।

प्रश्न संख्या 125

(स्थगित)

अगला सवाल श्री खेमाराम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: ये जब सवाल आए। आज पूरा प्रश्न स्थगित किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ये मेरी बिना इजाजत से बोल रहे हैं। एक भी अंकित नहीं हो। आपको सवाल करने का मौका मिलेगा। ये वापस आएगा तब सवाल कर लेना आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये स्थगित है। समाप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैंने स्थगित किया है। इस पर कोई सवाल नहीं होगा। अंकित नहीं हो एक भी शब्द। मैंने स्थगित किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो, सचतेक महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: आप भी बैठिए। शकुंतला जी, आप भी बैठिए। नो, नो इस समय नहीं। सुन ली आपकी बात। मिस्टर डोटासरा, सुन ली आपकी बात। जब ये सवाल आये तब आप सारे सवाल कर लेना। विराजिए। अगला सवाल श्री खेमाराम।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, जिनका प्रश्न है उसको तो तकलीफ ही नहीं है। वो संतुष्ट है। इनको क्या लेना-देना इससे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। सवाल स्थगित कर दिया है। इसमें आरोप का सवाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य आसन पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप आसन को आरोपित कर रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, जिन माननीय सदस्य ने ये प्रश्न रखा, वे प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं। उन्होंने आसन की व्यवस्था मान ली, आपको क्या लेना-देना इससे? आपका प्रश्न तो है नहीं। न ही आपके किसी सदस्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: एक भी शब्द अंकित नहीं हो इधर वाला। स्थगित कर दिया है, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप प्रस्ताव लेकर नियमों में आ जाओ, हम चर्चा करने को तैयार हैं। कितना महत्वपूर्ण सवाल है सुजनागढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है। अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: बिलकुल, ये विषय नहीं उठेगा। मैने स्थगित किया है सवाल। उस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। अंकित नहीं हो एक शब्द भी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष ये आपके किये हुए पाप हैं जिनको हमें ढ़ोना पड़ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: नो नो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बजरी के संबंध में पूर्व सरकार द्वारा किये हुए पाप हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले अपने भाषण में कह चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन ऐसे नहीं चलेगा। सदन परम्पराओं से चलेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कांग्रेस सरकार के किये हुए पाप हैं, जिनको हमें ढ़ोना पड़ रहा है। ..(व्यवधान)..

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000 ..(व्यवधान)..

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्वेश्चन स्थगित है और इसमें सारे राज खुलेंगे, आपके समय के किये हुए। ..(व्यवधान)..

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सारे आपके किये हुए पाप है ..(व्यवधान)..

मामला उलझा हुआ है। ये आपके किये हुए पाप हैं, जो आज जनता भुगत रही है। ..(व्यवधान)..

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: आ जाओ, आ जाओ, यहां आ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के टाइम दी हुई लिस्ट थी। कांग्रेस के हाथ से दी हुई लिस्ट थी। इन्हीं के कारण हुआ है ये सब कूड़ा।

श्री अध्यक्ष: विपरीत एक शब्द नहीं आएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये सदन नियमों से चलेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन आपकी बपौती नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000 ..(व्यवधान)..

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन का अपमान कर रहे हो। सदन का अपमान कर रहे हो। सवाल स्थगित किया है। दोबारा मौका आएगा जब बोल लेना आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। मैं प्रतिपक्ष के व्यवहार की निंदा करता हूं कि मेरे आदेश देने के बाद भी, मेरी व्यवस्था देने के बाद भी सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। इनसे निवेदन करता हूं कि आप शांति से बैठिए। मुझे अफसोस है कि प्रतिपक्ष के नेता का भी शब्द अंकित नहीं करने का आदेश देना पडा। आप बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप नियमों में आ जाओ। हम बहस कर लेंगे। ये पाप आपका किया हुआ है, वह हम ढो रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप किताब के अनुसार आ जाओ। हम बहस कर लेंगे। ये प्रश्न काल है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सवाल निरस्त नहीं हुआ है। स्थगित हुआ है फिर आएगा सदन के अंदर। आपके सारे पाप है उसका पता चल जाएगा कि कांग्रेस राज ने बड़े माफियाओं को पनपाने का काम किया है। ..(व्यवधान)..

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके किये हुए पाप हैं जो हमको ढोने पड़ रहे हैं। थोड़ा विचार करिए। आपको तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रश्नकर्ता ने अभी प्रश्न पुकारा नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप किस प्रकार से हंगामा कर रहे हो। स्थगित प्रश्न है, फिर आएगा सदन में, निरस्त नहीं है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप सदन का समय जाया कर रहे हैं। आप सदन के अंदर प्रश्न काल होने दीजिए। आपको अगर कोई और चर्चा करनी है ..(व्यवधान).. प्रश्न काल तो होने दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अभी सदन के सामने आएंगे। कई माननीय सदस्यों को उनका जवाब मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्‌वारा बहिर्गमन)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये काम किसने किये थे? ..(व्यवधान).. ये बनवाने का काम किसने किया है? कांग्रेस जाओ, राजस्थान से बाहर जाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ये नाटकबाजी है आपकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था। प्रश्न काल बड़ा महत्वपूर्ण काल है। आसन की व्यवस्था के बारे में कई अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, आप कहो तो मैं उद्‌धृत कर दूं। ये 23 मार्च, 1976 की व्यवस्था है जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि अगर प्रश्न काल के स्थगन होने पर भी उनको कोई आपत्ति है तो सदन में चर्चा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय के वेश्म में जाकर अपनी बात कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब यह सवाल आया, आपने मुझे भी बुलाया था। विभाग से चर्चा हुई। इस विस्तृत सवाल पर विभाग ने कहा था कि एक सप्ताह के बाद इस सवाल को आप जब भी खान विभाग का नंबर आये उसी नंबर पर, तीन नंबर पर आप निश्चित कर दें। हम इससे बचना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: ये मैंने नहीं कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: देखेंगे, किस नंबर पर आता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जरूरी नहीं है कि तीन नंबर पर आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय आसन सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष: मैंने ये कहा है कि इस सदन में जवाब दिलवा देंगे। मैंने ये कहा है। जरूरी नहीं है कि तीन पर आये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रतिपक्ष का रवैया रहा, यह इस तरह की बात कहना चाहते है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि हम इस प्रश्न को टालना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि जब कभी भी आसन इसको उचित समझेगा तब इस प्रश्न को वापस लिस्टेड कर दें, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, पर इसमें पूछी गयी जानकारी इतनी विस्तृत है जिनका अब तक संकलन नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपने दरख्वास्त दी थी इसको स्थगित करने की, उन कारणों को उचित मानते हुए मैंने स्थगित किया है। इसलिए इस बारे में आपका निवेदन है वह भी स्वीकार है, यह दिलवा देंगे। किस नम्बर पर दिलवाएं, बाद में देखा जाएगा। अगला प्रश्न, श्री खेमाराम।

सुजानगढ़ में आपणी योजनान्तर्गत पेयजल की आपूर्ति

126. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में आपणी योजना का कितना कार्य पूर्ण हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्राम/शहर में कहां-कहां कितनी-कितनी लाइनें डाली गयी व कितनी लाइनें डाली जाना प्रस्तावित है? ग्रामवार व शहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर घर-घर जलापूर्ति कब तक चालू कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आपणी योजना का कार्य निर्धारित अवधि में नही किया गया है? यदि हां, तो क्यों व विलम्ब के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के 2 कस्बे क्रमश: सुजानगढ़ एवं बीदासर तथा 108 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के 3 कस्बे रतनगढ़, छापर एवं राजलदेसर तथा 128 ग्राम, विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के 20 ग्राम, इस प्रकार कुल 5 कस्बों एवं 256 ग्रामों की पेयजल समस्या के दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रतनगढ़-सुजानगढ़ वृहत् पेयजल परियोजना की राशि रुपये 971.21 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को जारी हुई थी। उक्त परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु 2 कार्यादेश निम्नानुसार जारी किये गये हैं:-

प्रथम पैकेज में सरदारशहर से सुजानगढ़ की मुख्य ट्रंक मेन एवं आपणी योजना के प्रथम चरण के धन्नासर से सरदारशहर सैक्शन का नवीनीकरण एवं तत्पश्चात् 10 वर्ष का संचालन व संधारण कार्य हेतु मैसर्स एन.सी.सी., हैदराबाद को दिनांक 06.07.2012 को राशि रुपये 249.75 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार इस पैकेज का कार्य दिनांक 15.01.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित था तथा इस पैकेज के समस्त कार्य दिनांक 30.09.2016 को पूर्ण किये जा चुके हैं।

द्वितीय पैकेज में ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली के कार्य हेतु मैसर्स एल एण्ड टी, चेन्नई को दिनांक 07.08.2013 को राशि रुपये 591.40 करोड़ का जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार इस पैकेज का कार्य दिनांक 16.08.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था।

उक्त पैकेज का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा इसका 94 प्रतिशत कार्य भौतिक रूप से अब तक पूर्ण हो चुका है। इस पैकेज का कार्य दिनांक 30.06.2018 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

इस परियोजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ का कस्बा सुजानगढ़ तथा 9 ग्रामों को आंशिक रूप से अब तक लाभान्वित किया गया है।

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बे छापर व रतनगढ़ एवं 8 ग्रामों को आंशिक रूप से तथा 41 ग्रामों को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया गया है।

(2) उक्त परियोजना के प्रगतिरत पैकेज-द्वितीय के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कस्बों एवं ग्रामों हेतु अब तक बिछाई व जोड़ी गयी तथा शेष बिछाई एवं जोड़ी जाने वाली पेयजल वितरण पाइप लाइनों संबंधी वांछित ग्राम/शहरवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) सम्पूर्ण परियोजना का कार्य दिनांक 30.06.2018 तक पूर्ण किया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जाना अपेक्षित है। विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के पाइप्ड जल योजना अंतर्गत पूर्व से लाभान्वित 24 ग्रामों में घरेलू जल संबंधों द्वारा तथा शेष 84 ग्रामों में परियोजना के प्रावधान के अनुरूप पी.एस.पी. द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(4) जी हां। उक्त परियोजना के पैकेज प्रथम का कार्य कार्यादेश अनुसार दिनांक 15.01.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित था तथा इस पैकेज का कार्य दिनांक 30.09.2016 को पूर्ण किया जा चुका है।

कार्यादेश अनुसार पैकेज द्वितीय का कार्य दिनांक 16.08.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था। उक्त पैकेज का 94 प्रतिशत कार्य भौतिक रूप से अब तक पूर्ण हो चुका है तथा दिनांक 30.06.2018 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार यह परियोजना दिनांक 16.08.2016 तक पूर्ण करनी निर्धारित थी। परन्तु, पैकेज प्रथम एव द्वितीय के कार्यों को निष्पादन करने वाली अनुबंधक फर्मों द्वारा परियोजना का कार्य धीमी गति से करने, पाइप लाइनों के बिछाने एवं जोड़ने के कार्य हेतु रेलवे लाइन एवं नेशनल हाइ वे क्रोसिंग की अनुमति देरी से प्राप्त होने के कारण परियोजना का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सका।

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वीकृत एवं प्रगतिरत लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर वृहत् पेयजल परियोजना के पैकेज-6 के अंतर्गत रतनगढ़-सुजानगढ़ परियोजना हेतु स्वच्छ पेयजल की शेष मांग की आपूर्ति हेतु ग्राम धन्नासर स्थित हैडवर्क्स पर स्वच्छ जलाशय का निर्माण (75 प्रतिशत कार्य पूर्ण), स्वच्छ जल एवं रॉ-वाटर पम्प हाउस का निर्माण (70 प्रतिशत कार्य पूर्ण), जल शोधन संयंत्र के निर्माण (75 प्रतिशत कार्य पूर्ण) एवं मुख्य ट्रंक पाइप लाइन बिछाने-जोड़ने का कार्य (94.50 प्रतिशत कार्य पूर्ण) संबंधित कार्य कार्यादेश अनुसार दिनांक 24.05.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था। परन्तु, अनुबंधक फर्म मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रॉ लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा धीमी गति से करने के कारण परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में देरी हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपणी योजना में सरकार आते ही सबसे बड़ी राशि इस योजना को देकर आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन कुछ कारणों से, माननीय मंत्रीजी अभी बता रहे थे, बार-बार कम्पनियां एक्स्टेंशन ले रही है, उस कारण से काम धीमी गति से चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके कारण हमारे गांवों में पीने के पानी की भंयकर समस्या आ गयी है। पीएचइडी की नयी योजना हमें मिलनी चाहिए थी वह इस कारण से नहीं मिल पाई कि हमारे यहां आपणी योजना का काम चल रहा है। यह काम बार-बार आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सुजानगढ़ क्षेत्र में 20 टयूबवैल ऐसे हैं जो फेल हो गये हैं, फेल्योर के अगेंस्ट आप 20 टयूबवैल सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र को दें। कुछ गांव-ढाणियां ऐसी है जहां यह स्कीम आने में, बार-बार समय का एक्स्टेंशन ले रहे हैं उसके कारण से डिले होने की संभावना है। तो, इसको ध्यान में रखते हुए सात नये टयूबवैल सुजानगढ़ में स्वीकृत करें ताकि उन ढ़ाणियों-कस्बों को स्वच्छ पानी मिल सके।

दूसरा निवेदन है कि योजना के माध्यम से सड़कें तोड़ रहे हैं, उन सड़कों की सही ढंग से मेंटीनेंस नहीं हो रही है, काफी जगह बहुत समय से खड्डे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन तोड़ी हुई सड़कों को शीघ्र से शीघ्र ठीक कराने की, वापस सही गुणवत्ता की कराने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि काम बहुत देरी से हुआ.....

श्री अध्यक्ष: प्रभू लाल जी सैनी, बात नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं आपणी योजना द्वितीय पैकेज में रतनगढ़ सुजानगढ़ का कार्य पूर्ण करने की तिथि 16.08.2016 रखी गयी थी। यह समयावधि प्रथम बार दिनांक 16.11.2016। दूसरी बार 30.9.2017, तत्पश्चात तीसरी बार 31.3.2018 तक बढ़ायी गयी। यह समय सीमा अनुबंध फर्म के साथ करार को जीवित रखने हेतु अस्थाई रूप से बढ़ायी गयी है। अनुबंध फर्म द्वारा कार्य समय पर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि 13.93 करोड़ की रोकी गयी है। दूसरा बताया, उसमें एन सी सी लिमिटेड हैदराबाद द्वारा कार्य तय समय 15.1.2015 को पूर्ण नहीं करके दिनांक 30.9.2016 को पूर्ण किया गया। अनुबंध फर्म के पैकेज के कारण गति धीमी रखने, निर्धारित समय से पूर्ण नहीं करने के कारण फर्म पर 2.75 करोड़ की राशि रोकी गयी है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने सड़कों के बारे में कहा, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि परियोजना के अनुबंध फर्म द्वारा पांच शहरी क्षेत्रों में 256 गांवों में पाइप लाइन डालते समय कुल 351.49 किलोमीटर सड़कें तोड़ी गयीं। सड़कों के एवज में 345.61 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत करवा दी गयी है। शेष 5.88 किलोमीटर सड़क के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। सुजानगढ़ शहर में वर्तमान में अमृत योजना के अंदर पेयजल व सीवरेज का प्रगति पर है। इस कार्य में मरम्मत की गयी सड़कें पुन: तोड़ी जा रही हैं जिसकी मरम्मत का कार्य स्वायत्त शासन विभाग करवाएगा और मेरे द्वारा जो तोड़ी गयीं थीं वह सिर्फ 5.88 किलोमीटर ही है, वह भी बिटुमिन सड़कें है जो तकनीकी कारणों से अभी नहीं की गयी हैं, उनके ऊपर डब्ल्यू बी एम किया गया है। आप निश्चिंत रहें, सड़कों का काम कर दिया जाएगा।

आपने तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि टयूबवैल सूख चुके हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से अब तक कुल 77 नये नलकूप स्वीकृत हुए जिनमें से 71 नलकूप का कार्य पूर्ण करके चालू कर दिया गया है। चार नलकूप विद्युत संबंधित है, होना शेष है, दो नलकूप और शेष है। वर्तमान में 13 नलकूप सूख चुके हैं। भू जल विभाग से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर उनके ऊपर करेंगे। पांच टयूबवैल आपके अर्जेंट है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पांचों टयूबवैल की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न:

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपणी योजना में घर-घर कनेक्शन देने की, चार हजार से अधिक आबादी वाले गांव में हमारे काफी गांव आ रहे हैं, उनमें अभी घर-घर कनेक्शन योजना के अंतर्गत पाइप

(श्री खेमाराम)

लाइन नहीं ड़ाली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चार हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को घर-घर कनेक्शन देने की योजना आप कब तक पूर्ण करा देंगे? उसके साथ ही हमारे क्षेत्र में इस योजना में, तथा पीएचइडी के अंदर, जेईएन, एईएन की बहुत कमी है उसके कारण से काम धीमी गति से हो रहा है और गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जेईएन, एईएन की पोस्ट शीघ्र भरे ताकि सही ढंग से काम हो सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने 4 हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने बाबत कहा, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि आपणी योजना, प्रथम व द्वितीय चरण में चूरू, तारानगर, रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़, सादुलपुर, पीलीबंगा, मण्डावा, नोहर, इनके अन्दर, कुल 9 विधान सभा क्षेत्रों के 4 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 38 गांवों की योजना के स्वरूप परिवर्तन हेतु विभाग द्वारा राशि 12659.80 लाख के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इनमें पी.पी.सी. की 199वीं बैठक, दिनांक 28.06.2017 में चूरू जिले की 8 योजनाएं और हनुमानगढ़ जिले की दो योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष योजनाओं की स्वीकृति बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से चरणबद्ध तरीके से किया जाना अपेक्षित है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। नहीं, नहीं। द्रोपती, यह सुजानगढ़ से सम्बन्धित है, आपको सुजानगढ़ के बारे में बोलना है?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): नहीं, अध्यक्षजी, यह जो आपणी योजना है, यह मेरे क्षेत्र से शुरू हो रही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, यह सुजानगढ़ से सम्बन्धित है। नो, नो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सुजानगढ़ का जो पानी जा रहा है, वह मेरी कांस्टीट्युएंसी से जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: वह सब ठीक है। सुजानगढ़ के बारे में हो तो सवाल कीजिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): धन्नासर का नाम लिया है, मंत्रीजी ने धन्नासर का नाम लिया है। धन्नासर का है, अध्यक्षजी, छोटी-सी बात है, आप अनुमति दें तो मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: पूछ लो, पूछ लो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्षजी।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन कर रही हूं कि जो यह आपणी योजना का कार्य क्षेत्र है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में धन्नासर से शुरू होता है। यह बहुत बड़ा प्रौजक्ट है। इसका जो पानी है, सुजानगढ़, सरदारशहर, रतनगढ़ होते हुए सीकर तक इसका प्रौजक्ट बनाया जा रहा है। सीकर तक यह योजना बनाई जा रही है। लेकिन हम लोग हैं, हमारी प्रोपर धन्नासर पंचायत है, वह भी इस पानी से लाभ नहीं ले रही, इनके पूर्व जो मंत्री थीं, किरणजी, इनके साथ माननीय अभिषेकजी की, हमारी बैठक हुई थी।

श्री अध्यक्ष: सवाल करो, सवाल करो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सवाल ही बता रही हूं, अध्यक्षजी।

हमने मीटिंग में यह कहा था, जो घर-घर कनेक्शन देने की बात है, माननीय सदस्य ने उठाया है। हमारे क्षेत्र में आबादी, बहुत कम, टुकड़ों में है, तो हमने तीन हजार की शर्त रखी थी कि उनकी आबादी चार हजार से घटा कर तीन हजार कर दी जाए। एक तो मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि उस मांग का क्या हुआ, जो तीन हजार करने के लिये बोला था, और यह घर-घर कनेक्शन योजना है, यह कब तक शुरू हो जाएगी।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगी कि धन्नासर प्रौजक्ट है, मैंने खुद ने चैक किया था। यहां कोई अधिकारी नहीं बैठता है। मैंने तीन घण्टे लगाये, पूरा प्रौजेक्ट देखा, एक डेढ़ घण्टे तक तो मैंने इंतजार किया कि कोई ए.ईएन., एक्स.ईएन. यहां आएगा, लेकिन कोई वहां पर नहीं आया। तो, क्या उनका कार्य क्षेत्र सीमित है? वहां पर कोई परमानैंट अधिकारी बैठाने की योजना बनाई है कि अधिकारी यहां परमानैंट रहेगा। इतना बड़ा प्रौजक्ट होने के बाद वह खाली कैसे रह सकता है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। आपणी योजना के लिये माननीय सदस्य को भी धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने यह मुद्दा उठाया है।

श्री अध्यक्ष: विराजो। बैठिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि घर-घर कनेक्शन वाला है, यह जल्दी से शुरू कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आ गया, आ गया, यह आपने पूछ लिया।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): दूसरा, अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने तीन हजार की आबादी के ऊपर घर-घर कनेक्शन के बारे में जिक्र किया है, मैं निवेदन कर दूं कि तीन हजार से चार हजार की बीच की आबादी के करीब 63 गांव हैं। उन पर नीतिगत निर्णय लेना है। नीतिगत निर्णय लेने के लिये मैंने प्रिंसिपल सैक्रेटरी से कहा है कि वह फाइल पुट अप करें। वित्त विभाग से उस पर वैट करवा करके जो भी हो सकता है, आगे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार। यह सुजानगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सुजानगढ़ से ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: इधर-उधर नहीं जाएंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं जाऊंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा था, वैसे हमारे सदस्य ने पूछ भी लिया। पिछली बार सदन में पूर्व मंत्री किरणजी माहेश्वरी जी ने कहा था, तीन हजार आबादी वाली बात की सदन में घोषणा की थी कि हमने कमेटी बना दी है और इस पर हमने सर्वे कर लिया है। इसके बाद भी एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस आपणी योजना में तीन हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिये लाभ नहीं मिला।

दूसरा क्वश्चन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आपणी योजना का पानी गांव में, चौक में सार्वजनिक रूप से दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इसकी राशि वसूल कर रही है। पी.एच.ई.डी. की जो पहली योजना थी उसमें उपभोक्ता से किसी भी प्रकार का पैसा वसूल नहीं किया जाता था। इसको सरकार नि:शुल्क उपलब्ध कराने की मंशा रखती है कि नहीं रखती? रखती है, तो सरकार इसको कब तक लोगों को नि:शुल्क, क्योंकि यह विवाद का विषय हो गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, आपने पूछ लिया।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): गांव में चंदे की तरह हर महीने पैसा उगाहना पड़ता है। इसको देने के लिये लोग तैयार नहीं हैं। इसलिये मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया, जवाब आ जाएगा। बैठिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:शुल्क देने का कोई विचार नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नहीं है, यह तीन हजार आबादी वाला मामला?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह बता दिया मैंने।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया, इसके पहले ही। श्रीमती राजकुमारी, यह सुजानगढ़ का सवाल है।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): सर, यह मंत्रीजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं आपके माध्यम से हिण्डौन का एक प्रौजक्ट मैडम ने सैंक्शन किया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, यह मंत्री से जुड़ा हुआ नहीं।

प्रश्न संख्या 127

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला सवाल, श्री धीरज कुमार, एब्सेंट।

अगला सवाल, श्री विजय बंसल।

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना पर व्यय राशि

128. श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या व उक्त योजनान्तर्गत नदियों को कब तक जोड दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 2017 तक नदियों को जोड़ने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये व किस-किस मद में कितनी राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल पप्पू बन्डा)

(3) सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने हेतु अब तक कितनी राशि आवंटित की एवं उसमें से कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री) (जल संसाधन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों को जोड़ने हेतु दो योजनाओं हेतु डी.पी.आर. बनाई गई है तथा तीसरी योजना की डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने का कार्य स्वीकृति उपरांत वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2017 तक की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत दिसम्बर तक डी.पी.आर. तैयार किये जाने कार्य हेतु करवाये गये कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने हेतु डी.पी.आर. तैयार किये जाने के कार्य हेतु आबंटित एवं व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गम्भीरी, रूपारेल एवं बाणगंगा नदियों का प्रवाह कंटीन्यू होता था। लेकिन पांचना बांध तथा जयसमंद बांध बनने के बाद ये तीनों नदियां सूख गयी हैं। क्या मंत्री महोदय, यह बताना चाहेंगे कि पांचना बांध में चम्बल नदी से जोड़कर गम्भीरी नदी के द्वारा भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार को बचाने का कोई प्लान रखते हैं और रखते हैं तो कब तक?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा है मोटे तौर पर तीन ऐसी परियोजनाएं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हैं, जिन परियोजनाओं पर वर्तमान में राजस्थान की सरकार काम कर रही है। पहली परियोजना जिसे हम पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना के नाम से जानते हैं, ईस्ट राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं। ईस्ट राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में आपने जो सवाल पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर दो बेसिन हैं। साउथ राजस्थान के बेसिन के अन्दर सरप्लस पानी है। साउथ-ईस्ट राजस्थान के बेसिन के अन्दर डेफिसिएंट बेसिन है। इस डेफिसिएंट बेसिन के अन्दर पानी की उपलब्धता, उस पानी की उपलब्धता जो हमारे साउथ के बेसिन के अन्दर एडिशनल पानी है, जिसका उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, उस पानी को किस प्रकार से हम वाटर डेफिशिएंट बेसिन में ट्रांसफर करें, इसकी चिंता के साथ में हमने ईस्ट कैनाल परियोजना बनाई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य पूछ रहे थे इस परियोजना में मानसून के दौरान जिन नदियों में पानी का सरप्लस रहता है, जिस पानी को हम टैप नहीं कर पा रहे, जिसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, वे नदियां हैं पार्वती, कालीसिंध बेस्ड, इनका जो एक्सेस पानी है, उस एक्सेस पानी को, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बनास, मोरेल, बाणगंगा और गम्भीरी नदियों में पहुंचाना चाहते हैं। इस परियोजना के माध्यम से जो आपने चिंता व्यक्त की है, भरतपुर, घना की चिंता आपने व्यक्त की है, पांचना का पानी नहीं पहुंचने की चिंता व्यक्त की है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर काम लगातार जारी है। इस परियोजना के तीन चरण हैं। इन तीन चरणों के माध्यम से जिन इलाकों को हम कवर करेंगे, उन इलाकों में भरतपुर शामिल है। भरतपुर के अन्दर वह इलाका भी शामिल है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, करेंगे कि हो गया?

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी, आप पूरक प्रश्न कर रही हैं।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): यस, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय

(श्रीमती सोनादेवी)

से जानना चाहूंगी कि हरिके बैराज में सतलज और व्यास नदी का पानी आता है। उसके बाद आई.जी.एन.पी. नहर और हमारी गंगनहर आती है। आई.जी.एन.पी. नहर में, व्यास नदी और सतलज नदी का, बहुत सी फैक्ट्रियों का पानी उसके अन्दर गंदा आता है। उसकी वजह से आई.जी.एन.पी. नहर है, उसमें कैंसर जैसी महा बीमारी आ रही है, मैं जानना चाहूंगी कि फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, इसे नदियों में रोकने का विचार, सरकार या माननीय मंत्रीजी रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, जवाब दे दीजिये आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मोटे तौर पर नदियों को जोड़ने वाले प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां, वह है। लेकिन पहली बार सवाल किया है, इसलिये मैंने अलाउ किया।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्षजी, नदियों में जोड़ रखा है। फैक्ट्रियों के गंदे पानी को नदियों में जोड़ रखा है। ...(व्यवधान)...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): फिर भी सवाल आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैं यह जानना चाह रही हूं। नदियों में जोड़ रखा है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, 1200 क्यूसेक्स से अधिक है, इतना गंदा पानी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरक सवाल इस सवाल से सम्बन्धित नहीं होने के बावजूद आप जानते हैं, सदन के अन्दर इस बात की बहुत चर्चा हुई है। सदन के अन्दर, राजस्थान के अन्दर मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्यों की इस बात की चर्चा रही कि आई.जी.एन.पी. के अन्दर जो पानी कई बार आ रहा है, वह पोल्यूटेड पानी है।

राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है, पंजाब के अंदर और हरियाणा के मुख्य मंत्री से इस बारे में चर्चा की है। इस चिंता को हम लगातार उठा रहे हैं, दिल्ली के स्तर पर भी उठा रहे हैं और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान के स्तर पर भी उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह नदियों के पानी का प्रदूषित होना और प्रदूषित पानी नहरों में छोड़ देना, उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां होने का मामला न केवल आई.जी.एन.पी. का मामला है बल्कि मैं सोचता हूं हिंदुस्तान के स्तर पर नदियों के प्रदूषण और उसके द्वारा नहरों के माध्यम से होने वाली सिंचाई के कुप्रभावों के बारे में यह चिंता है। हम उन चिंताओं का समाधान कई स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान सरकार भी इस मामले में काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा। पूरक प्रश्न नम्बर-दो।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश के साथ-साथ सीकर और झुन्झुनूं जिले की नदियों को भी किन्हीं नदियों से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा जहां तक नदियों के जोड़ने का प्रश्न है, वर्तमान के अंदर तीन ऐसे डिफरेंट प्रौजेक्ट्स हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं। एक प्रौजेक्ट, जिसकी मैंने चर्चा की है। दूसरा प्रौजेक्ट है, जिसके अंदर हम साबरमती बेसिन के पानी को हम जवाई बांध में डालना चाहते हैं और तीसरा प्रौजेक्ट, जिस पर हम काम करना चाहते हैं वह है बीसलपुर के अंदर हम जो ब्राह्मणी नदी है, जवाहर सागर डैम के अप-स्ट्रीम की ऐसी नदी है जिसका पानी चम्बल में चला जाता है अन-टेप होकर के, उस पानी को हम ब्राह्मणी नदी को बनास के अंदर डाइवर्ट करके बीसलपुर का पानी भरना चाहते हैं।

जहां तक सीकर और झुन्झुनूं के लिए नदियों को जोड़ने की, वर्तमान में मैं समझता हूं कि कोई ऐसी परियोजना, डी.पी.आर. जिसकी बनी हो, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट टैस्ट हुई हो, उसकी हाइड्रोलॉजी टैस्ट रिपोर्ट हुई हो, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। नहीं, हो गया जवाब।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

बात का प्रयास कर सकती है कि हर वर्ष हथनी कुंड से बाढ़ के पानी से हरियाणा और दिल्ली प्रभावित होती है, हरियाणा की एक नहर गुड़गांव से लेकर राजस्थान के बोर्डर तक पिछले पचास साल से बेकार पड़ी है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसका उपयोग कर क्या बरसात के मौसम में वह बाढ़ का पानी सीकर और झुन्झुनूं जिले को देने की कोई योजना विचाराधीन कर सकती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। खर्रा साहब, विराजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी नदियों को जोड़ने की परिकल्पना हिंदुस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी की सरकार के सामने की गयी। पूरी परियोजना की फिलोसोफी इसी पर आधारित थी कि हमारा एक्सेस वाटर जिसको हम टेप नहीं कर पा रहे हैं, उस पानी को हम कैसे टेप करें, नम्बर एक।

बरसात के दिनों में जो फ्लड का पानी है, उस फ्लड के पानी को जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं जो डैस्ट्रक्शन में तब्दील हो रहा है, उसका हम प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन किस प्रकार से कर पाएं, इस चिंता के साथ में आपने जो हथिनी कुंड की बात कही है और आपने कहा कि अब तो यमुना का पानी और हथिनी कुंड का पानी, मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के स्तर पर नदियों को जोड़ने की जो कल्पना की गयी है, उस कल्पना का मोटा आधार ही यही है कि जो फ्लड का पानी है उस फ्लड के पानी को किस प्रकार से हम टैप करके यूटिलाइजेशन कर पाएं। जिस पानी की चिंता आपने की है हथिनी कुंड के मामले में, पानी को टेप करने का मामला पूरा का पूरा राजस्थान से बाहर के इलाके का मामला है। पानी के यूटिलाइजेशन का मामला सीकर और झुन्झुनूं डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार इस बारे में चिंता करेगी और विभिन्न स्तरों पर इस बात को उठाएगी कि हथनी कुंड का जो पानी है, जिस पानी के कारण फ्लड पैदा होता है, यमुना के बैल्ट में पानी आता है, यमुना के पानी का हिस्सा आपको मिलना चाहिए। उस सारी चिंता के साथ राजस्थान सरकार इस बात को करने की कोशिश कर रही है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से आपके मार्फत पूछना चाहती हूं कि भरतपुर जिले में रूपारेल नदी और यमुना नदी जो हरियाणा से आती है और गंभीरी नदी, इन पर जैसे रूपारेल में तो इतने सारे बांध बने हैं, उन बांधों की वजह से उसका पानी भरतपुर नहीं आ पा रहा है। यमुना जल का जो पानी हरियाणा से आता है, उसमें इतनी ज्यादा चोरियां हो रही हैं, उन चोरियों को रुकवाने के लिए आप क्या करेंगे?

गंभीरी नदी का जो पानी पांचना बांध के द्वारा आना था, जिसकी वजह से पांचना बांध ऊँचाई करके पानी नहीं आ पा रहा है, इन तीनों नदियों के भरतपुर तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार क्या करेगी?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पांचना डैम की ऊंचाई बढ़ने के कारण पैदा हुए संकट का ताल्लुक़ात है, मैं समझता हूं कि उसका संबंध इस सवाल से नहीं है लेकिन भरतपुर के अंदर पानी की व्यवस्था, पेयजल के पानी की व्यवस्था, कुछ और कमांड एरिया को, पूरे पानी के पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सके उसमें आपने घना की चिंता भी व्यक्त की है। उन सबके अंदर पांचना बांध के प्रभाव से निपटने की कोशिश के अंदर ही मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर नदियों को जोड़ने का काम करके और सरप्लस पानी को उस इलाके में इस्तेमाल करने की कोशिश की गयी है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। अगला प्रश्न म. रणधीर सिंह भीण्डर।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपारेल नदी के बारे में भी था, उसके बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हो गया। म. रणधीर सिंह भीण्डर।

वल्लभनगर में उज्जवला योजना के लाभार्थी

129. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में उज्जवला योजना के तहत कितने परिवारों को किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

(2) क्या सरकार जिन परिवारों में महिला मुखिया नहीं है, उन परिवारों को भी उक्त योजना का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में जारी किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या 10938 (आईओसीएल-3798 एवं बीपीसीएल-7140) है। वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में एचपीसीएल की कोई गैस एजेन्सी स्थित नहीं है। गैस कनेक्शनधारियों के एजेन्सीवार, ग्रामवार/नामवार विवरण वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php

https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx

https://ebharatgas.comàmylpgàUjjwala Beneficiary

(2) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सिर्फ ऐसे परिवार जिनका नाम पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी SECC लिस्ट में है, उस घर की किसी भी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, के नाम से गैस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु महिला सदस्य का मुखिया होना अनिवार्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। एक तो यह है कि जिस घर में महिला सदस्य ही नहीं हो तो क्या उसको उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा?

दूसरा, सदस्य को कितने पैसे जमा करवाने पड़ते हैं उस एजेंसी में? यह जानकारी मुझे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री उज्जवला योजना केन्द्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसको लागू करने के पीछे माननीय प्रधान मंत्रीजी का भी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

उद्देश्य यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से परम्परागत स्रोतों के माध्यम से महिलाएं खाना बनाती थीं और जिस प्रकार की उनकी हैल्थ कंडिशंस पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, उसको देखते हुए माननीय प्रधान मंत्रीजी ने इस योजना को लागू किया और इसके जो लाभार्थी हैं, इसकी जो योग्यता है, योग्यता के लिए महिला का बी.पी.एल. परिवार की महिला होना आवश्यक है। लाभार्थी महिला भारत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए तथा उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी के किसी भी सदस्य के नाम पूर्व में गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लाभार्थी बी.पी.एल. परिवार की मासिक आय राज्य सरकार व संघ शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी का डाटा व आयल कम्पनियों के पास संधारित बी.पी.एल. डाटा, 2011 से मिलान होना आवश्यक है। जो सूची में नाम है उसमें महिला, बी.पी.एल. में महिला होना आवश्यक है। उसमें महिला अगर नहीं है तो उसमें गैस कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात आपने पूछी है पैसे जमा करवाने की बात, इसमें योजना के जो प्रावधान है, उसमें 1600 रुपये, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान के रूप में दिया जाता है और 1600 रुपये में, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 1250 रुपये तो गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी राशि, इसके अलावा रेगुलेटर के लिए 150 रुपये, रबर पाइप के 100 रुपये, डायरी के 25 रुपये और इसके अलावा 75 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, इस तरह करके 1600 रुपये का उसको अनुदान है। उसके अलावा 990 रुपये चूल्हे के लिए और गैस की रीफिलिंग, जो भी लागत है, उसके लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि वह उसको लोन के रूप में उपलब्ध होगा, जिसको कि आगे सब्सिडी के रूप में जब भी उसको सब्सिडी मिलेगी तो उससे वह एडजस्ट होगा, इसमें किसी भी प्रकार का पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी जगह हजार-हजार रुपये वसूल कर रहे हैं तो मैं यह चाहता हूं कि आपके यहां पर कनेक्शन भी ज्यादा नहीं है, दस हजार ही हैं, आप इसकी जांच तो करवाएं और जांच करके जो दोषी हैं उनको इस मामले में सज़ा होनी चाहिए।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलवाता हूं कि माननीय सदस्य इसमें मुझे, जो भी इनके पास जानकारी है, जिस प्रकार भी कोई शिकायत है, मुझे लिखकर दे दें। निश्चित रूप से आपके विधान सभा क्षेत्र में एक जांच दल बनाकर मैं भेजूंगा और उसकी पूरी जानकारी करके जांच करवाऊंगा और दोषी होने पर कार्यवाही करूंगा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): यह समस्या तो पूरे राजस्थान में ही है। पूरे राजस्थान में ही लेते हैं। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। ....(व्यवधान).... हां, आपने कर लिया सवाल? यह तो पूरा ही सवाल वल्लभनगर से संबंधित है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): सवाल तो कर दिया।

श्री अध्यक्ष: नारायण सिंहजी देवल और हमीरसिंहजी भायल ने तो कर ही दिया, जोगारामजी पटेल भी करना चाहते हैं लेकिन यह सवाल वल्लभनगर से संबंधित है। ....(व्यवधान)....

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वल्लभनगर से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 2011 में सर्वे हो गया परंतु कम्प्यूटर पर वह डाटा लोड नहीं होने के कारण कई गांव छूट गये हैं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति। शोकाभिव्यक्ति में पधार जाओ सब।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

जगमाल सिंह यादव, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री जगमाल सिंह यादव के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व मंत्री श्री जगमाल सिंह यादव का जन्म 04 फरवरी, 1947 को

(श्री अध्यक्ष)

अलवर जिले के लुहादेरा ग्राम में हुआ। आपने राजऋषि कालेज अलवर से एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जगमाल सिंह यादव आठवीं, नौवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप आठवीं विधान सभा में लोकदल, नौवीं विधान सभा में जनता दल तथा ग्यारहवीं विधान सभा में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति ‘क', प्राक्कलन समिति 'ख' एवं नियम समिति के सदस्य तथा यातायात, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति रहे। श्री यादव नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1992 तक यातायात विभाग के मंत्री भी रहे।

पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री यादव ने अलवर से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक 'मत्स्य संदेश' का प्रकाशन किया।

श्री जगमाल सिंह यादव का दिनांक 13 फरवरी, 2018 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री जगमाल सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

कुपवाड़ा क्षेत्र में बार्डर पर गश्त के दौरान हुए हिमस्खलन एवं सुंजवां सेना छावनी पर हुए आतंकी हमले में शहीद जवान

दिनांक 02 फरवरी, 2018 को जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा क्षेत्र के बार्डर पर गश्त के दौरान हुए हिमस्खलन में सेना के राजस्थान के 3 जवान शहीद हो गये। जम्मू के शहरी इलाके में स्थित सुंजवां सेना छावनी पर दिनांक 10 फरवरी, 2018 को हुए आतंकी हमले में सेना के 6 जवान शहीद हो गये। आतंकियों की इस कायरतापूर्ण कार्यवाही की यह सदन कड़ी निन्दा करता है। मैं आतंकी हमले और प्राकृतिक आपदा में शहीद हुए सैनिकों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

घनश्याम जी, आप डाक्टर को दिखाइये। डाक्टर है यहां पर।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से 30 सितम्बर, 2017 तक अल्पकालीन फसली ऋण में 50 हजार रुपये तक के कर्जे की एकबारीय माफी की घोषणा से किसानों को पर्याप्त राहत न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से लोकायुक्त के 29वें प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 116 से 144 तक में उल्लेखित दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गाड़ौलिया लौहारों को भूखण्ड आबंटित करने के संबंध में।

(4) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कार्यरत चौकीदारों का वेतन न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी खनन माफिया द्वारा अवैध बजरी सप्लाई से बढ़ रही कीमतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर के गांव रीडिया धारा, हेमागुडा, लालजी डूंगरी,

(श्री अध्यक्ष)

धरणावास एवं मेलावास को नर्मदा नहर के कमांड क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

(7) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से सिद्धमुख नहर वितरिका में वर्तमान में तय रेगुलेशन के हिसाब से अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री विवेक धाकड़, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा के गंगापुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र के आटे का हलवा खाने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से रणजीतपुरा से ओसियां सड़क तक की क्षतिग्रस्त सड़क से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम विश्नोई, श्री मनोज कुमार, श्री विवेक धाकड़ एवं श्री भंवर सिंह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को पुलिस के समान वेतन-भत्ते दिये जाने के संबंध में।

(2) श्री तरुणराय कागा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन के पंचायत समिति मुख्यालय धनाऊ पर पुलिस थाना खोले जाने के संबंध में।

(3) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्री बाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु राजस्थान विधान सभा में प्रस्ताव पारित करने के संबंध में।

(4) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से एस.एम.एस. हास्पिटल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से कुम्हार समाज के लिये मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जमीन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम के अपूर्ण पड़े कार्य को पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दौसा के शहरी क्षेत्र में नव विकसित कालोनियों में सड़क व नालियों का निर्माण एवं सीवरेज के कार्य करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैंपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(9) श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बायतु के तहसील मुख्यालय गिड़ा की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(10) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर का गन्दा पानी समीपवर्ती गांव कुडला में बहकर जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की गुमानपुरा इंदिरा गांधी सर्किल और एरोड्राम चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली के मासलपुर तहसील में गत दिनों विद्युत विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 15 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 48 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

1.	श्री शंकरसिंह राजपुरोहित	जालौर जिले में नर्मदा की पेयजल योजना के E.R. प्रौजेक्ट की मैन लाइन को रामसीन से बाघरा तक लाकर पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में।
2.	श्री सुखाराम	विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु करने के संबंध में।
3.	श्री हीरालाल	विधान सभा क्षेत्र निवाई में सड़कों की दयनीय स्थिति से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।
4.	श्री ज्ञानचंद पारख	पाली जिले की रोहट तहसील में वर्ष 2016 एवं 2017 में नष्ट हुई फसलों का मुआवजा बीमा कम्पनी द्वारा अभी तक भी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय श्री सुखराम विश्नोई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सांचौर के कुछ गांवों का नर्मदा नहर के कमांड क्षेत्र में सम्मिलन

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांचौर में 2009 से नर्मदा से सिंचाई हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दु:ख की बात है कि नहर निकली, दोनों तरफ कमांड नहीं हैं और ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, आपस में बातचीत नहीं करें। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं। आपस में बात नहीं करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जिनके खेत खराब नहीं हुए उन्हें कमाण्ड घोषित कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार को कहना चाहूंगा कि एक तो लालजी डूंगरी राजस्व विलेज है, हेमागुड़ा, धरणावास, हमारे जो संसदीय सचिव हैं लादूराम जी उनका पैतृक गांव है

(श्री सुखराम विश्नोई)

एस.टी. ढाणी, रिड़िया धारा, मेलावास, यह जो गांव हैं, इन गांवों के बीचों बीच से मेन वितरिका जा रही है और न तो उनको पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा, न पानी का कोई अतिरिक्त खर्चा है, केवल मात्र माइनर बना करके, डिग्गी बना करके आराम से सिंचाई की जा सकती है। सरकार का कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं आता है। केवल मात्र यह बहाना बनाते हैं कि हमारा लिमिटेड पानी है, उसमें से 1600 सिंचाई के लिए बाकी 5 पानी के प्रौजेक्ट के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल मात्र मनगढ़ंत बात है।

सांचौर क्षेत्र के अन्दर बहुत सारा गोचर का भू-भाग है, औरण का भू-भाग है, उसके बाद में आबादी जमीन है, अभी जो दो साल लगातार फ्लड आयी थी उससे जो लूणी का बैल्ट है वहां पानी से जमीन खारी हो गयी, अगर सरकार के पास इच्छा-शक्ति हो तो उस जमीन को निकाल कर के कम से कम पांच-छह हैक्टेयर जमीन आराम से बच सकती है और उस जमीन के बदले में, यह मैंने आपके मार्फत जो चार-पांच कहे, इन गांवों को आराम से सिंचित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डूंगरी गांव है, उसके तीनों तरफ नहर है। एक अचम्भे की बात है, तीनों तरफ नहर है और बीच में खाली जमीन पड़ी है, कहां तकलीफ आती है। नहर ऊंचाई पर जा रही है, वो जमीन नीचे की है। इस तरह से सर्वे किया है। कहीं तो धोरे पर पानी चढ़ा दिया और कहीं जहां नीचे जमीन थी कहते हैं कि कमाण्ड नहीं है। केवल मात्र मनमर्जी से सर्वे किया गया था और किस हिसाब से सर्वे किया, उसका पता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो चार-पांच गांव हैं, जब पानी नहीं देते हैं, चोरी करते हैं। चोरी करते हैं तब मुकदमाबाजी करते हैं, तो उस मुकदमेबाजी से बचने के लिए किसानों को फायदा मिले। नहीं तो, कुछ नहीं हो तो नहर के पास ही डिग्गी बना दी जाए, उससे भी पानी पिलाई कर सकते हैं। कुल मिला कर के इन गांवों को सिंचित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। रेस्पोंड करेंगे इधर से? हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है कि नर्मदा से जो पानी मिलता है उस पानी के कमाण्ड एरिया में जो इलाके नहीं आते हैं, उन इलाकों के अतिरिक्त कुछ गांवों को पानी दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नर्मदा परियोजना से हमको केवल 0.5 एमएएफ पानी मिलता है और 1969 के अन्दर नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण ने तय किया था। इस 0.5 एमएएफ पानी का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है, इसका प्लान राजस्थान की सरकार ने बनाया और इस पानी का डिस्ट्रिब्यूशन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जो प्वाइंट फाइव एमएएफ नर्मदा से बांध के स्तर से मिलता है वो राज्य की सीमा पर आते-आते रह जाता है 0.484 एमएएफ, सीपेज, इवोपरेशन**,** और इस पानी का डिस्ट्रिब्यूशन किया है पेयजल के लिए। इसमें 0.1064 एमएएफ पानी तो पीने के लिए है, अब 0.3776 एमएएफ पानी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए है। 0.3776 एमएएफ पानी से सिंचाई जो है, जिसका कमाण्ड हमने डवलप किया है 2.46 लाख हैक्टेयर जमीन का। अब 2.46 लाख हैक्टेयर जमीन को पानी, कमाण्ड एरिया को पानी देने के बाद पानी की उपलब्धता, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं रहती। आपका यह कहना है ...(व्यवधान)... मैं इसी पर आ रहा हूं, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो जमीन गोचर है, औरण है, अब खारी हो गयी है उस जमीन को इकट्ठा करके, उस जमीन के बदले में कमाण्ड की जा सकती है। बिलकुल, पानी का तो मुझे ही ध्यान है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, अब वो जवाब दे रहे हैं। आप पत्र लिख देना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका यह कहना है कमाण्ड के इलाके में जो गोचर आ गया है, कमाण्ड के इलाके में जो औरण आ गया है उस इलाके को कमाण्ड से बाहर निकाल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करके उसकी एवज में कुछ गांव को दे दिया जाए। हम उसको एग्जामिन कर लेंगे और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर यह निवेदन कर सकता हूं कि हमने पेयजल के लिए जो पानी एलोकेट किया है वो है 0.1064 एमएएफ।

पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी यहां विराजे हुए होंगे, पेयजल के लिए लगातार डिमाण्ड बढ़ रही है और पेयजल डिपार्टमेंट वाले लोग अतिरिक्त पानी की मांग कर रहे हैं। हमारे पास केवल 0.5 एमएएफ पानी है और उस पानी का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, उसकी आपको जानकारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन करना है कि कोई सरप्लस पानी निकलने की संभावना बनती है या किसी इलाके को कमाण्ड से निकाल कर के नोन-कमाण्ड एरिया को कमाण्ड एरिया में कन्वर्ट करने की कोई फिजिबिलिटी बनती है, अगर पेयजल की डिमाण्ड है, जो रेज लगातार पी.एच.ई.डी. द्वारा की जा सकती है उसको कैटर करने के बाद इस तरह की कोई पोसिबिलिटी बनती है तो उस पोसिबिलिटी को एग्जामिन करने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं यह केवल पोसिबिलिटी एग्जामिन करने की बात है।

श्री अध्यक्ष: एग्जामिन कर लीजिए। माननीय सदस्य भी आपको मदद करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): जहां तक वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में जो टोटल कमाण्ड एरिया है उस कमाण्ड एरिया को कैटर करने जितना ही पानी हमारे पास है।

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

सिद्धमुख नहर वितरिका में तय रेग्युलेशन से अंतिम छोर तक पानी की व्यवस्था

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उप तहसील सिद्धमुख कस्बे के 14 गांव ऐसे हैं जिनमें सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई का पानी, 111 क्यूसेक पानी

(श्री मनोज कुमार)
भिराणी हैड से मेरे विधान सभा क्षेत्र के 14 गांवों में सिंचाई के पानी की व्यवस्था का मामला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 1989 में माननीय तात्कालिक प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने भिराणी हैड का उद्घाटन किया, आज 29 वर्ष हो गये, 29 वर्ष से लेकर आज दिन तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के 14 गांव पानी की सिंचाई से वंचित हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में किसान बार-बार धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एक-दूसरे किसान का सिर्फ चोरी होने के कारण आपसी टकराव हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सरकार में तीन दिन की भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा कि किसान का सिर्फ पिछला किसान पानी आने से रोकता है और उस चोरी को सरकार रोकने में विफल है। एक महीने में मात्र आठ दिन की सप्लाई का मामला है और उस आठ दिन को सरकार उस चोरी को रोकने में विफल है। पिछली बार जब हमारा रैगुलेशन का पानी आया, मैंने भी स्वंय हैड तक नहर के किनारे-किनारे दौरा किया, अध्यक्ष महोदय, लोग बड़ी तानाशाही के साथ चोरी करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को सिर्फ आठ दिन आपके सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फुल फ्लेज पावर में उन किसानों के पानी की चोरी रोकने से और जो लोग, किसान चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मेरे यह 14 गांव के लोग पिछले 29 साल से इन्तजार कर रहे हैं और सिर्फ पानी की सप्लाई का मामला है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने उद्घाटन करने का तो काम किया है, 1989 में प्रधान मंत्रीजी ने किया, 2002 में इसका फिर उद्घाटन किया गया और 30 जून, 1999 को तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने उद्घाटन किया और उसके बाद 12 जुलाई, 2002 को माननीय कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी ने वहां जाकर उद्घाटन किया। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी अंतिम बात एक ही है कि 111 क्यूसेक पानी हमारा सिद्धमुख नहर वितरिका को जो मिलता है, वो पानी दिलाया जाए, चोरी को

(श्री मनोज कुमार)

रोका जाए और मंत्री महोदय, आठ दिन की श्योरिटी दें कि हमारा विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ और पुलिस का सहयोग लेकर सिद्धमुख नहर वितरिका के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाएगा। जिससे किसान आपस में न लड़ें, हर बार किसान आन्दोलन कर रहे हैं और फिर धरना देने की स्थिति है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता सही है और यह संकट बहुत पुराना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1981 के अन्दर एग्रीमेंट के तहत हमें सिद्धमुख नहर वितरिका प्रणाली के लिए 0.17 एमएएफ यानी 600 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था लेकिन हमें 600 क्यूसेक पानी कभी भी नहीं मिला। हमें मिला 470 क्यूसेक पानी 0.5 पर। बिंदु संख्या पांच जहां से हमारे को पानी रिलीज किया जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां वो पानी मिलता है 0.470, सॉरी, 0.470 नहीं 470 क्यूसेक, 470 क्यूसेक पानी भी मिल जाए, तो यह मेहरबानी है। हमें मिलना चाहिए 600 क्यूसेक पानी और मिलता है 470 क्यूसेक और कभी-कभी तो 470 क्यूसेक पानी से भी घट जाता है और यह फ्लैक्चुएशन 100 से ऊपर पहुंच जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 100 से ऊपर फ्लैक्चुएशन पहुंच जाए तो टेल एण्ड पर पानी पहुंचने का सवाल उठता ही नहीं है।

यह जो लगातार हरियाणा के द्वारा हमको पूरा पानी नहीं देना, हरियाणा के इलाके में पानी की चोरी होना और हमारे इलाके में भी पानी की चोरी होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हम इस पर लगातार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सब सरकारों ने चोरी रोकने की कोशिश की। आपने यह भी सही कहा कि पानी का माफिया काम करता है। पानी की चोरी लगातार हो रही है।

हम 2 स्तर पर इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा 133 क्यूसेक पानी जो कि हरियाणा के द्वारा देना चाहिए और वह हमें नहीं दे रहा है। उसने पहले कहा कि भाखड़ा की मेन कैनाल को रेज करो और हमसे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रेज करने के पैसे ले लिये। वह रेज हो गयी। रेज होने के बावजूद हरियाणा ने हमको पानी नहीं दिया। इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। एक फ्रंट पर 133 क्यूसेक पानी जो कि हमें नहीं मिल रहा है और वह हमें मिलना चाहिए क्योंकि .17 एमएएफ का पानी एग्रीमेंट के तहत हमें मिलना चाहिए था। वह नहीं मिला तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, जो पानी राजस्थान के अंदर आ जाता है, उस इलाके में राजस्थान के लोगों द्वारा चोरी की जाती है जिससे कि टेल के अंदर पानी नहीं मिलता है। इसके लिए पुलिस की लगातार कार्यवाही चल रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी मॉनीटरिंग, विजिलेंस में निश्चित रूप से वृद्धि की जाएगी। पानी की चोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपने सही कहा कि 1989 में राजीव गांधी जी ने हैड का उद्घाटन तो कर दिया। लेकिन हरियाणा से पानी राजस्थान को नहीं दिला पाये। राजस्थान का एग्रीमेंट के तहत जितने पानी का हक बनता है, उतना पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक टेल पर पानी पहुंचने की समस्या हमेशा बरकरार रहेगी। इसी कारण से हमने एसएलपी दायर की है। एसएलपी के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि हमें रिलीफ मिलेगी।

इसके साथ ही सिद्धमुख वितरण प्रणाली के बीच में विजिलेंस और पैट्रोलिंग को बढ़ाएंगे और पानी की चोरी को रोकने की कोशिश करेंगे जिससे कि टेल के इलाके में पानी मिल पाये। हम अभी कोशिश कर रहे हैं। रोटेशन के माध्यम से हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे टेल एंड पर पानी पहुंच जाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि विजिलेंस को और बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री विवेक धाकड़।

भीलवाड़ा के गंगापुर क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र के आटे का हलवा खाने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय को आभार वंदन। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का भी आभार।

अध्यक्ष महोदय, शनिवार को विधान सभा सत्र नहीं होने से आभार यात्रा के तहत भीलवाड़ा गया। सुबह समाचार पत्र में पढ़ा कि गंगापुर क्षेत्र के एक गरीब चारण परिवार के 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। मैं सीधा राजकीय चिकित्सालय में हालचाल जानने गया। वहां पर ज्ञात हुआ कि एक गरीब चारण परिवार का व्यक्ति जो मुम्बई में अपनी रोजी-रोटी कमाता है, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जब वह गांव आया तो उसकी साता पूछने के लिए कुछ लोग वहां गये। वहां जाने के बाद हलवा बनाया। वह हलवा आंगनबाड़ी से आए हुए आटे से बना। उस हलवे को खाने के तुरंत बाद 5 व्यक्तियों की तो मौत हो गयी और 3 अस्पताल में भर्ती थे। वहां पर प्रशासन और चिकित्सा विभाग को धन्यवाद दिया कि उन्होंने तुरंत जो सर्वाइवल थे उनकी सार-संभाल की। वहां पर न्यायिक जांच और उनको मुआवजे की मैंने मांग की थी।

अध्यक्ष महोदय, कल रात को 11 बजे मुझे फोन आया कि उसमें से एक महिला की मौत कल हो गयी। आज सुबह जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि उसकी तबीयत खराब होने के बाद हायर सेंटर पर रैफर किया। हायर सेंटर पर रैफर करने के बाद स्थानीय स्तर से एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं करवाई गयी। प्राइवेट एम्बुलेंस की जैसे-तैसे व्यवस्था करके वह गये। उस दरमियान जो कीमती समय उनका वेस्ट हुआ उसके कारण उदयपुर जाते समय उसकी मौत हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। सबसे पहले तो आंगनबाड़ी का आटा वहां कैसे पहुंचा और उसकी वजह से गैस्ट्रिक लेवेज की, एफएसएल उदयपुर में है, अगर तुरंत प्रभाव से उसकी जानकारी मिल जाती और गेस्ट्रिक लेवेज का कुछ हो जाता तथा इतने दिनों का जो डिले हुआ, तो शायद हम उस महिला को बचा सकते थे। हायर सेंटर पर पहले रैफर नहीं किया गया। बाद में रैफर किया गया। एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गयी जिससे एक महिला की मौत हो गयी।

(श्री विवेक धाकड़)

अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति मुम्बई में रोजगार के लिए गया और उसका वहां एक्सीडेंट हो गया। उसकी आर्थिक, मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान खींच लिया है ठीक ढंग से।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो नया हूं। आप लोगों का आभार, आशीर्वाद कि आपने यह किया है। आज सुबह वैसे तो मुझे पता नहीं था कि यह अलग-अलग मैटर्स में है। जिला प्रशासन भीलवाड़ा से संबंधित एक मैटर और है।

श्री अध्यक्ष: वहीं नहीं ले सकते।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): खटीक समाज की एक महिला का एक्सीडेंट हो गया। उसकी डैथ हो गयी।

श्री अध्यक्ष: वह नहीं, वह नहीं।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): उसको भी दिखवाएं।

श्री अध्यक्ष: इसी से संबंधित। माननीय मंत्री।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के भी ध्यान में लाना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने विषय उठाया है कि 5 सदस्यों की डैथ हुई है। यह बात निश्चित रूप से सही है कि 5 सदस्यों की मृत्यु हुई है। लेकिन किन कारणों से हुई है, वह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को श्री मोहन दास पिता श्री मांगू जी चारण के यहां राजसमंद से कुछ मेहमान आए। जैसा कि आपने भी बताया। मेहमानों के आने पर भोजन बनाया गया। भोजन करने के बाद मेहमान जैसे ही रवाना हुए, अपने गांव जब वापिस जा रहे थे तो सांखलों का चौराहा पहुंचते-पहुंचते मेहमानों में से कुछ लोगों को शिकायत हुई। उनको उलटी होना शुरू हुआ। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वह गंगापुर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता लगा कि किसी प्रकार के जहर का मामला है इसलिए हॉस्पिटल ने सूचना थानाधिकारी को भी दी।

अध्यक्ष महोदय, वहां इलाज शुरू किया तो जैसे ही डॉक्टरों को यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

जानकारी आई कि यह गंभीर मामला है। यह कोई फूड पॉयजनिंग नहीं है। जहर का मामला है तो उन्होंने भीलवाड़ा चिकित्सालय में रैफर किया। भीलवाड़ा चिकित्सालय जाते-जाते 2 छोटे बच्चों की डैथ उसी समय हो गयी। बाकी 3 को इलाज के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उसी रात जो 2 वयस्क थे उनकी भी डैथ हो गयी। एक जो विवेक जी ने कहा कि उसको उदयपुर रैफर किया गया था, उसका इलाज लगातार जारी था। उसकी उदयपुर जाते समय रास्ते में ही डैथ हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, आपने आंगनबाड़ी के पोषाहार का उल्लेख किया है, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी का पोषाहार पूरे गांव में बंटता है। उसको सब लोग खाते हैं। उस गांव में जो आंगनबाड़ी केन्द्र है, वहां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वह पोषाहार बंटा। वह पोषाहार पूरे गांव में बंटा, केवल एक परिवार में नहीं बंटा। यदि एक परिवार की बात करें तो केवल एक ही परिवार में वह पोषाहार नहीं बंटा था। लेकिन जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट कहती है कि इसमें सस्पेक्टेड पॉयजनिंग का कोई मामला है।

जब यह बात 9 तारीख की रात को 11 बजे मुझे भी ध्यान में आई तो मैंने भी डाक्टर्स से बात की, पुलिस में एस.पी. से भी बात की, कलक्टर साहब से भी बात की। जिन डाक्टर्स से मैंने बात की, उनका यह कहना था कि जिस तरह से रिएक्ट हुआ खाने के तत्काल बाद, तो वह रिएक्शन अनेकों बार सेल्फोस की गोली के जहर से होता है। हम असावधानीपूर्वक सेल्फोस की गोलियां अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए रख देते हैं। परिवार से जानकारी हुई कि उसी दिन वह आटा पिसवाया गया था।

पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उनमें भी सस्पैक्टेड पॉयजनिंग है। प्रारंभिक लक्षणों में उन्होंने माना है कि आर्गेनिक फास्फोरस जहर के थे। जो आर्गेनिक फास्फोरस जहर होता है, यह सेल्फोस में ही मिलता है। इस कारण से 99 परसेंट डाक्टर्स यह कह रहे हैं। जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तब जानकारी में आएगा कि वह डैथ किस जहर के खाने से हुई। यह जांच का विषय है। इसमें जांच आनी शेष है। जांच आने से पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे ही अनर्गल आरोप लगाने से नहीं होता है। जो रिपोर्ट नीचे

(श्रीमती अनिता भदेल)

से आई है उसमें भी यह बात साबित हुई है कि पूरे गांव में यह केन्द्र पर बंटा था तो वह एक परिवार को कैसे इफैक्टेड कर सकता था। यह तो पूरे गांव को ही इफैक्ट करना चाहिए था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सस्पैक्टेड पॉयजनिंग की बात आई है, उससे यह साबित होता है कि किसी तरह से यह आर्गेनिक फास्फोरस का मामला है। मुझे भी बेहद खेद है कि किसी अंजान तरीके से उस गरीब परिवार में डैथ हो गयी। मैंने निवेदन किया था तो जितनी सहायता कलक्टर पहुंचा सकते थे, उस समय उनको तत्काल पहुंचाई भी गयी है। लेकिन यह अभी जांच का विषय है। इससे मैं अभी इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि जांच पूरी आने पर ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि किस जहर से इनकी डैथ हुई है।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्री भंवर सिंह।

कोलायत में रणजीतपुरा से ओसियां तक की क्षतिग्रस्त सड़क

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, रणजीतपुरा से ओसियां राज्य राजमार्ग संख्या 87 ए सड़क की स्थिति दयनीय होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए आपका आभार।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और उसके समाधान की अपेक्षा भी चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत की रणजीतपुरा से ओसियां जाने वाली सड़क की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस सड़क का जीरो से 110 तक का हिस्सा जिसमें रणजीतपुरा से गोडू, गोडू से बज्जू, बज्जू से सांखला फांटा, सांखला फांटा से मड, कोटड़ी, कोलायत, कोलायत से झज्जू व झज्जू से मोखा गांव तक कोलायत विधान सभा क्षेत्र में आता है।

आगे 217 किलोमीटर तक नोखा विधान सभा क्षेत्र के तहत आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क 0 से 81 किलोमीटर तक रणजीतपुरा से सांखला फाटा तक 7 मीटर चौड़ी है। 81 से 90 किलोमीटर तक 5.5 मीटर चौड़ी है तथा उससे आगे 3.75 मीटर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि यह सड़क बज्जू राजस्व तहसील

(श्री भंवरसिंह)

की 30 ग्राम पंचायतों व सैंकड़ों गांवों को उप खंड मुख्यालय व जिला मुख्यालय से जोड़ती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय भारत-पाक सीमा को भी जोड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को हमारे पूरे क्षेत्र की लाइफ लाइन कहा जाता है लेकिन इस सड़क की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। पिछले बजट सत्र में 21.03.2017 को मेरे द्वारा प्रश्न भी उठाया गया था और माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में यह जवाब दिया गया था कि स्विस चैलेंज मोड योजना के माध्यम से 209 करोड़ की लागत की डीपीआर तैयार कर ली गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक साल पहले मंत्री महोदय के द्वारा सदन में कहा गया था और उसकी बिडिंग अगले महीने अप्रैल में करवा देंगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साल बीत गया, अब उस सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि स्विस चैलेंज मोड में जितनी भी सड़कें मंत्री महोदय ने, सरकार ने ली हैं, उनमें से अधिकांश क्या पूरी की पूरी सड़कें अभी तक चालू नहीं की गयी हैं। एशियन डवलपमेंट बैंक की सड़कें चालू हुई हैं, वर्ल्ड बैंक की सड़कें चालू हुई हैं और भी जो सीएसआर, सेंट्रल रोड फंड है, उसकी सड़कें भी चालू हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को ठीक करवाने के लिए, जो बहुत जरूरी भी है और पूरे इलाके की मांग भी है, इस सड़क को स्विस चैलेंज मोड में एक साल बीत गया, तत्काल आप या तो चालू करवाएं अन्यथा इस योजना में से निकाल कर किसी अन्य ऐसी योजना में डालें जिससे कि हमारे इलाके की जो पापुलर डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहूंगा और माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस सड़क की मांग का समाधान किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने ओसियां से नोखा सड़क का जिक्र किया है। यह बात सही है कि 21.03.2017 को मैंने यह कहा था कि यह स्विस चैलेंज में मलेशियन कम्पनी के साथ हमारा एमओयू हुआ है, उसमें हमने ले रखा है। किन्हीं कारणों से देरी हो गयी। यह बात भी सही है

(श्री युनुस खान)

माननीय सदस्य की, चूंकि उस सड़क को हमने किसी अन्य योजना में नहीं लिया, तो वह जो टूटी हुयी थी, उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गयी। लोगों के आवागमन में दिक्कत भी हो रही है। इसके दो भाग हैं, ओसियां से नोखा 115 किलोमीटर है, नोखा से बज्जू 145 किलोमीटर है। बज्जू से रणजीतपुरा की जो आपने बताई है 41 किलोमीटर की लम्बाई, यह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। अभी तो हमने यह निर्णय किया है, चूंकि उसमें थोड़ा और समय लग रहा है तो यह जो क्षतिग्रस्त सड़क है, हम 41 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर सड़क को 4 करोड़ 10 लाख से, इसी सप्ताह जो हमारी स्वीकृतियां जारी हो रही हैं, उसमें मेंटीनेंस की स्वीकृति जारी करके उसका काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने पहले भी इस विषय को दो बार हाउस में उठाया और अभी 19.01.2018 को भी आपने तारांकित प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है। अगर इस मार्च तक मलेशियन कम्पनी इस काम को शुरू करती है तो ठीक है अन्यथा यह सड़क जीर्ण-शीर्ण है तो इसको हम किसी अन्य, एसआरएफ में या सीआरएफ में लेकर ठीक करवाने का काम करेंगे। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि अगर डिले होता है तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए हम सड़क को किसी अन्य योजना में ले लेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जो पूरा नोन पेचेबल है, वह तो पूरा ठीक करवा दो।

श्री अध्यक्ष: नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

होमगार्ड्स को नियमित रोजगार

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं होमगार्ड जवानों की समस्याओं के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में होम गार्ड जवानों को 12 माह रोजगार दिया जाए। वर्तमान में होम गार्ड जवानों की कुल नफरी लगभग 31700 है, जिसमें से महज 8000 जवानों को ही रोजगार प्राप्त हो पाता है। चूंकि राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा इनको 12 माह रोजगार देने हेतु पूर्व में आदेश जारी किए जा चुके हैं परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने बजट घोषणा पत्र में भी नियमित रोजगार देने की बात की है परंतु अब तक इनकी अनसुनी ही की जा रही है।

वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की द्वितीय पीठ द्वारा होम गार्ड जवानों को पुलिस के समान वेतन भत्ते दिए जाने के आदेश किए जा चुके हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। चूंकि इसी तरह का समान फैसला पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए दिया जा चुका है और लगभग 17 राज्यों में इसका लाभ भी दिया जा रहा है परंतु राजस्थान में इसे लागू नहीं किया गया है, इसे तत्काल लागू किया जाए।

रोज बोलने का आप कह रहे हैं, माननीय सचेतक महोदय, नियम के तहत बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री तरुण राय कागा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ...(व्यवधान)... सचेतक महोदय को बोल रही हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा सचेतकजी को नहीं, चेयर से बात कीजिए, सचेतक से सीधा नहीं।

धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर पुलिस थाने की मांग

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं पंचायतसमिति मुख्यालय धनाऊ पर पुलिस थाना खुलवाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

(श्री तरुण राय कागा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र चौहटन राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, जिसे कुछ समय पूर्व हुए पंचायती राज संस्था पुनर्गठन एवं सीमांकन के वक्त आबादी में वृद्धि व क्षेत्रफल के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए तीन पंचायत समितियों, क्रमश: चौहटन, धनाऊ व सेड़वा में विभाजित किया गया है। इनमें से चौहटन व सेड़वा पंचायत समिति मुख्यालय पर पहले से ही पुलिस थाने खुले हुए हैं जबकि धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय इस सुविधा से पूर्णतया वंचित है। धनाऊ पंचायत समिति का अधिकांश क्षेत्र पुलिस थाना चौहटन के अधीन है और बढ़ते अपराधों की रोकथाम व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए चौहटन थाने की इस क्षेत्र से दूरी व्यवधान बनती है। वर्तमान में धनाऊ व आसपास के क्षेत्र में अपराध दर में वृद्धि के कारण भी माकूल पुलिस व्यवस्था की जरूरत है। विगत कुछ समय से इस क्षेत्र से सौ से अधिक आपराधिक मामले चौहटन थाने में दर्ज हो चुके हैं, इस वजह से चौहटन पुलिस थानाधिकारी ने भी धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर अस्थाई पुलिस चौकी की वैकल्पिक व्यवस्था निर्मित की है जो कि बढ़ती अपराध संख्या की दृष्टि से अपर्याप्त है। धनाऊ कस्बे की सघन आबादी के अनुरूप यातायात व्यवस्था सुधारने, आम चौराहे पर असामाजिक तत्वों, शराबियों व अपराधियों की ज्यादा आमद-रफत पर अंकुश लगाने व आस-पास के संपूर्ण क्षेत्र में आमजन के जान माल की सुरक्षा व सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू करने के लिए धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर नवीन पुलिस थाना स्थापित करने की महती आवश्यकता है।

अत: राज्य सरकार सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित इस क्षेत्र के धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था को मजबूत करने हेतु नवीन पुलिस थाना स्थापित करवाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभा रानी कुशवाह

महात्मा ज्योति राव फुले तथा सावित्री बाई फुले को 'भारत रत्न' सम्मान का प्रस्ताव

श्रीमती शोभा रानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं 19वीं सदी के महा नायक महात्मा ज्योति राव फुले व महा नायिका सावित्री बाई फुले द्वारा समाजोत्थान हेतु किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योति राव फुले और सावित्री बाई फुले महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास और पाम्रपरिक अनीतिपूर्ण रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया तथा गरीबों, शोषितों के हक में अपनी आवाज बुलंद की। 1848 में ज्योति राव फुले और सावित्री बाई फुले ने देश की पहली पाठशाला स्थापित कर समाज के पिछड़े दलित वर्ग तथा महिलाओं को शिक्षा का मार्ग दिखाया। फुले दम्पत्ति ने ऐसे 18 विभिन्न स्थानों में विद्यालय खोले। यही नहीं, उन्होंने 1855 में खेतिहर मजदूरों के लिए रात्रि पाठशालाएं भी खोलीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जातियों और किसानों को संगठित करने के लिए 24 सितम्बर, 1873 को उन्होंने 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। फुले दम्पत्ति ने विधवा विवाह की परम्परा प्रारम्भ की और 29 जून, 1863 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। फुले दम्पत्ति ने 1840-1890, पचास वर्षों तक आजीवन समाज सुधार के अनेक कार्य किये।

डा. भीमराव अम्बेडकर फुले जी को अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने फुले के बारे में पूना में 1932 में कहा था- लोग मुझे महात्मा कहते हैं, लेकिन असली महात्मा तो ज्योतिराव फुले थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विधान सभा में महात्मा ज्योतिराव फुले व सावित्री बाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने हेतु एक प्रस्ताव विधान सभा से पारित किया गया था। उसी भांति राजस्थान विधान सभा द्वारा भी महात्मा ज्योतिराव

(श्रीमती शोभा रानी कुशवाह)

फुले तथा सावित्री बाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने हेतु एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भिजवाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेंद्र पारीक।

एस.एम.एस. हॉस्पिटल में मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के सबसे बड़े हास्पिटल एसएमएस हास्पिटल व इससे संबंधित हास्पिटलों में इलाज कराना आसान नहीं है। सबसे पहले मरीज को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। उसके पश्चात डाक्टर को दिखाने में लाइन में लगना पड़ता है। यदि डाक्टर कोई टैस्ट/जांच लिखता है तो उसके लिए शुल्क जमा करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। उसके पश्चात जांच रिपोर्ट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मरीज जिसके साथ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उस स्थिति में मरीज की क्या स्थिति होती है, यह सहज ही समझा जा सकता है।

आज के तकनीकी युग में जब रेलवे टिकट आप ऑनलाइन मोबाइल पर बुक करवा सकते हैं, पानी/बिजली/टेलीफोन के बिल ई-मित्र के माध्यम से अथवा मोबाइल पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। यही एसएमएस हास्पिटल तथा राज्य के सभी हास्पिटल तथा डिस्पेंसरियों में मरीज का रजिस्ट्रेशन करते समय जो शुल्क लिया जाता है, वह ई-मित्र के माध्यम से अथवा ऑनलाइन मोबाइल पर करवाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है तथा डाक्टर किसी भी प्रकार की जांच लिखता है तो उस जांच के लिए शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके लिए प्रोग्राम बनाया जाकर आमजन को जानकारी दी जाकर कार्यवाही की जा सकती है।

(12.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के एसएमएस हास्पिटल व प्रत्येक जिले के सभी हास्पिटलों में रजिस्ट्रेशन शुल्क/जांच के लिए शुल्क ई-मित्र अथवा मोबाइल के माध्यम से किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर डवलप कर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो मरीज सीधे डाक्टर को दिखाने जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्टाफ रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया गया है, उसका उपयोग हास्पिटल के अन्य कार्यों में लिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

कुम्हार समाज के लिये मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जमीन की व्यवस्था

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत प्रदेश में कुम्हार समाज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जमीन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रदेश में कुम्हार समाज के लोगों द्वारा अनादिकाल से मिट्टी के बर्तन एवं दैनिक जीवन की आवश्यक उपयोगी चीजें बनाकर अपना जीवन यापन किया जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे आज बढ़ती आबादी के साथ ही जमीनों पर अतिक्रमण होने से कुम्हार समाज के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु मिट्टी नहीं मिल पा रही है और उनके सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे उनके परिवार का पालन-पोषण करने में उनको गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुम्हार समाज पूरे मानव समाज को मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से सदियों से अपनी सेवाएं देता आ रहा है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलने से अकेले कुम्हार समाज पर ही संकट नहीं आया है, अपितु पूरे मानव समाज के लिए समस्या उत्पन्न हो गयी है। ऐसी स्थिति में कुम्हार समाज के लोगों की आजीविका चलाने के लिए पूरे राजस्थान में हर पंचायत पर कुम्हार समाज के लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन आबंटित किये जाने के लिए मैं मांग करना चाहता हूं।

(श्री जगदीश नारायण)

अत: इस अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि कुम्हार समाज के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कुम्हार समाज को मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु जमीन आबंटित की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह जी रावत।

ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम के अपूर्ण कार्य

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में ब्यावर शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम को पूर्ण कराये जाने के संबंध में मेरा आपसे आग्रह था। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ब्यावर शहर एवं आस-पास की खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से सेदरिया (ब्यावर) में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम निर्माणाधीन है। इसके निर्माण पर करीब तीस लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वर्तमान में यह स्टेडियम अपूर्ण अवस्था में है। इस स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु काफी विकास की आवश्यकता हैं। इस स्टेडियम के विकास हेतु विधायक कोष से बीस लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसका जिला परिषद, अजमेर द्वारा योजना में स्वीकृत कर बीस लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संख्या 278287 दिनांक 31.08.2012 को सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के नाम भेजा गया था। इस राशि की 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा 180 लाख रुपये आज दिनांक तक जारी नहीं किये गये हैं। स्वीकृत योजना का पैसा वर्ष 2012 से आज तक 90 प्रतिशत राशि 180 लाख रुपये नहीं पहुंचने का क्या कारण रहा है?

अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सेदरिया (ब्यावर) में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम, जो कि अपूर्ण है, इसे शीघ्र ही पूर्ण कराने के लिए विधायक कोष से स्वीकृत बीस लाख रुपये की 90 प्रतिशत राशि 180 लाख रुपये शीघ्र ही जारी करने की कृपा करावें।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने कहां से पढ़ा? यह 295 जो आपने दिया, जैसा आपने दिया, आपको वैसा पढ़ना था।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 90 प्रतिशत राशि के लिए लिखा हुआ......।

श्री उपाध्यक्ष: आपने जो लिखा है, विधायी कोष से स्वीकृत 20 लाख रुपये की 90 प्रतिशत राशि...इतना, इतना, इतना....यह है इसमें लिखा हुआ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 7.79 लाख रुपये...।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, 295 में सिर्फ जो आपने दिया है, वहीं पढ़ सकते हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं सर...पैसे की मांग थी, उसको पूरा कराने के लिए....।

श्री उपाध्यक्ष: आपके यहां अंकित वही होगा, जो 295 में आपने लिख कर दिया है। जो आपने लिखा है, अगर उसके अलावा आपने बोला है तो वह अंकित नहीं होगा। श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हम तो पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, साहब। बस यही था।

दौसा के शहरी क्षेत्र में नव विकसित कालोनियों में सड़क, नालियों एवं सीवरेज के कार्य

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। निवेदन है कि दौसा 1991 में जिला बना एवं दौसा नगर पालिका को वर्ष 2011 में नगर परिषद बनाया गया है। पहाड़ी तलहटी क्षेत्र में बसावट एवं पथरीली जमीन होने के कारण दौसा शहर में घरों में बने शौचालयों के सेफ्टी टैंक में गंदा पानी जमीन सोख नहीं पाती है, जिसके कारण सेफ्टी टैंक में से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर नालियों में बहता है। जहां हमारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता के लिए दिन-प्रतिदिन अभियान एवं मिशन चलाकर स्वच्छता हेतु कार्य कर रही है, वहीं दौसा नगर परिषद में गंदगी निस्तारण के अभाव में स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। दौसा की जनसंख्या 2011 में 1 लाख से कम होने के कारण इसे अमृत

(श्री शंकर लाल शर्मा)
योजना से नहीं जोड़ा गया, परंतु वर्तमान में जयपुर महानगर के सबसे नजदीकी जिला होने के कारण दौसा का तीव्रता से विस्तार एवं आबादी की बसावट हो रही है। इसके साथ ही शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं कोचिंग संस्थान की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण नजदीकी जिलों एवं गांवों के लगभग 20,000-25,000 छात्र दौसा में रहकर शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस अनुसार वर्तमान में दौसा शहर की जनसंख्या 1,40000 है और ऐसे में दौसा नगर परिषद में सीवरेज लाइन एवं ड्रेनेज सिस्टम की सख्त आवश्यकता है। दौसा नगर परिषद को अमृत योजना अथवा आरयूडीआइपी या अन्य किसी भी शहरी विकास की योजना से जोड़ते हुए नगर परिषद दौसा में सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम की स्वीकृति के साथ-साथ नव विकसित कालोनियों- अयोध्या नगर, मधुवन विहार, प्रेम नगर, गुमानपुरा कालोनी, जनता कालोनी, बजरंग नगर, निरंकारी कालोनी, अमन विहार कालोनी आदि सड़क एवं नालियों का निर्माण करवाकर अनुग्रहित करें ताकि दौसा नगर परिषद दौसा का सौंदर्यीकरण के साथ-साथ दौसा को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने का सपना साकार हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह जी।

सैंपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्रमोन्नति

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से सैंपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से 50 बैड में कराने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सैंपऊ उपखण्ड में करीब 250 ग्राम आते हैं और वहां की ग्रामीण आबादी भी एक लाख के करीब है। वहां सरकार द्वारा मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जो कि 30 बैड का है। जनसंख्या तथा वहां की भौगोलिक परिस्थिति एवं मरीजों की संख्या का देखते हुए सैंपऊ स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की मांग मैं सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। इसके अलावा ग्राम पंचायत कैथरी गांव जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है उसके सब सेंटर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की जनहित की मांग आपके माध्यम से कर रहा हूं। कृपया मंत्री महोदय इन

(श्री गिर्राज सिंह)

दोनों अस्पतालों को जनहित में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। इसी आशा व विश्वास के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

गिड़ा पी.एच.सी. की सी.एच.सी. में क्रमोन्नति

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बाड़मेर के बायतू विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय गिड़ा में स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय गिड़ा पर सीएचसी नहीं है तथा जिला मुख्यालस से दूर तथा दुर्गम और दूरस्थ स्थान पर स्थित है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पंचायत समिति की आबादी एक लाख जरूर है और पंचायत समिति गिड़ा की आबादी 2011 में एक लाख 18 हजार 930 थी परन्तु पंचायत समिति गिड़ा में एक भी सीएचसी नहीं है। यहां सीएचसी भवन विस्तार हेतु 06 बीघा जमीन भी उपलब्ध है जिसकी चारदीवारी भी हो चुकी है।

आदर्श पीएचसी गिड़ा स्वच्छता व अन्य क्षेत्रों में प्रदेश में प्रथम है। आदर्श पीएचसी गिड़ा के 50 किलोमीटर की परिधि में कोई भी सीएचसी नहीं है। यहां पिछले दो वर्ष में औसतन इन्डोर 1100, प्रसव संख्या 650 रही है तथा सर्प दंश के 45 रोगियों का इलाज किया गया है। पीएचसी गिड़ा का पिछले दो वर्ष का औसतन आउट डोर 35150 है।

सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानदण्ड पूरे होने के बावजूद भी पीएचसी, गिड़ा को सीएचसी में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। सीएचसी के अभाव में ग्रामीण जनता का समय पर समुचित चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती जिसके कारण आमजन को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

पीएचसी गिड़ा को क्रमोन्नत करने के लिए पिछले 4 वर्ष से विधान सभा की कार्यवाही के दौरान लगातार मांग की जाती रही है लेकिन पीएचसी, गिड़ा को क्रमोन्नत करने की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है।

अत: आपसे निवेदन है कि ग्रामीण जनता की समस्या को ध्यान में

(श्री कैलाश चौधरी)
रखते हुए जनहित में गिड़ा में सीएचसी की स्वीकृति दिलवाकर अनुगृहीत करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर के समीपवर्ती गांव कुडला में गन्दे पानी से जनता को परेशानी

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से बाड़मेर शहर के गन्दे पानी से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर शहर से निकलने वाले गन्दे पानी से बाड़मेर तहसील के कुडला गांव में भारी परेशानी उत्पन्न हो रही है। शहर का गन्दा पानी एवं बरसाती पानी बहकर कुडला गांव में चला जाता है और उक्त गांव के ग्रामीण आवासों के आस-पास भी उक्त पानी फैला हुआ है। गन्दगी का आलम यह है कि वहां के वाशिंदों का जीना दूभर हो गया है। चारों ओर गन्दगी व मच्छरों की भरमार है। कुडला गांव के वाशिन्दे बाड़मेर शहर के गन्दे पानी के कारण अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। स्थानीय वाशिन्दों एवं जन-प्रतिनिधियों ने इस सम्बन्ध में सरकार व स्थानीय अधिकारियों को अनेक बार ज्ञापन एवं आवेदन किये किन्तु उनकी समस्या यथावत है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बाड़मेर शहर का जो गन्दा पानी कुडला गांव में जा रहा है उसके निस्तारण हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है इसलिए उक्त सीवरेज प्लांट से उक्त पानी को कनेक्ट किया जाए ताकि गन्दा पानी कुडला गांव में नहीं फैले। विकल्प में अनुरोध है कि शिवकर रोड पर 700 मीटर नाला बनाया जाकर उसके माध्यम से उक्त गन्दे पानी का निकास कराते हुए कुडला गांव के वाशिन्दों को उक्त गन्दगी से राहत प्रदान करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। (अनुपस्थित) श्री दर्शन सिंह।

मासलपुर (करौली) में विद्‌युत विभाग की लापरवाही

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान

(श्री दर्शन सिंह)

सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर में गत माह अक्टूबर-नवम्बर, 2017 में कनिष्ठ अभियंता द्वारा घोर लापरवाही के कारण से प्राइवेट व्यक्ति की मौत हो गयी तथा दो अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। परन्तु आज दिन तक कनिष्ठ अभियंता, मासलपुर के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, न ही मृत व्यक्ति के परिवार को कोई मुआवजा उपलब्ध करवाया गया है तथा न ही आश्रित को नौकरी दी गयी है। जबकि उक्त प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता द्वारा ही शट-डाउन दिया गया, उसी के द्वारा मृत व्यक्ति को टूटे हुए तारों को ठीक कराने हेतु बिजली के पोल पर चढ़ाया गया तथा स्वयं कनिष्ठ अभियंता द्वारा बीच में ही लाइन को चालू करवा दिया गया जिससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गयी तथा दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये।

अत: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि दोषी कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसे तुरन्त मासलपुर से हटाया जाए और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी में लिया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जालौर जिले में नर्मदा योजना से पेयजल समस्या का निराकरण

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जालौर जिले के 739 गांवों को 2007 में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी की घोषणा से पूरा जालौर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसके बाद में काम को स्पीड से चलाया गया। फिर सरकार बदली, तत्पश्चात् कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया जिसका खामियाजा जालौर की जनता को झेलना पडा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी माननीय मुख्य मंत्री, हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार आते ही इस योजना को पुन: हाथ में लिया और एक से दूसरे, तीसरे बजट में

घोषणाएं कीं। जिसके कारण से इस नर्मदा के सांचौर में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई और एम.आर., ई.आर. और डी.आर., इन तीन प्रोजेक्ट के माध्यम से जालौर की जनता को पानी देना था। डी.आर. और एफ.आर. दोनों लगभग अपनी पूर्णाहूति पर है। ई.आर. में मेन प्रौजेक्ट जो पानी को सप्लाई देगा....

(13.00 बजे)

और एक आता है क्लस्टर जो आगे वितरण व्यवस्था को देखेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस ईआर से रानीवाड़ा, भीनमाल, जालौर और आहौर, इन चारों विधान सभा क्षेत्रों के लगभग-लगभग आधे-आधे गांवों में पानी जाना था। ये ईआर प्रोजेक्ट भी 2016 में पूरा होना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेन जो ट्रांसमिशन लाइन का काम है, वह रामसीन तक ईआर का पूरा हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं जिस विषय को लेने जा रहा हूं ईआर के अन्दर जो पानी है मेन ट्रांसमिशन लाइन है, पानी तो ले आये लेकिन आगे की वितरण व्यवस्था अगर बराबर नहीं हुई तो लाये हुए पानी की उपयोगिता नहीं होगी। इसमें से जहां-जहां क्लस्टर के प्रोग्राम मान लो, लेट हुए हैं, वहां पर पानी अगर मेन ट्रांसमिशन लाइन से आया है, जैसे एफआर में हमारा पानी आया है, जहां क्लस्टर का लेट हुआ। हमने पीएचईडी के रेगुलर सिस्टम से आगे पानी कम से कम लोगों को देना चालू कर दिया तो हमारी जनता ने धन्यवाद दिया कि नर्मदा का पानी हमारे यहां पहुंच गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को इतना निवेदन करना चाहूंगा कि ईआर में जो 384 करोड़ रुपये की योजना है, उसमें से बड़ी मुश्किल से तीन वर्षों में 170 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, बाकी पैसा पड़ा है और अभी एक साल में यह पैसा खर्च होना नहीं है। ईआर क्लस्टर की वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है। अब उस क्लस्टर की व्यवस्था को भी जीवित रखना है और जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है रामसीन जो भीनमाल तक आयी है, उससे आगे जालौर और आहौर विधान सभा क्षेत्र के लगभग 50 गांवों को पानी देना है। अब आगे पानी रामसीन तक तो आपका आ जाएगा, उस उसको आगे पानी कैसे देंगे, इसलिए मेरा एक निवेदन है कि

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

ईआर के लगभग 171 करोड़ रुपये आज बैलेंस है, उसमें से कुछ पैसा इस मेन ट्रांसमिशन लाइन को या तो आगे करने के लिए दे दीजिये या क्लस्टर योजना में कुछ भी पैसे की घोषणा आप करा देंगे तो यह योजना भी जीवित रहेगी जिससे हम एक से डेढ़ साल के अंदर कुछ न कुछ विभागों के पीछे पड़कर काम करवा लेंगे। नहीं, तो यह योजना ठप्प हो गयी तो आने वाले समय में जिन 50 गांवों को जो पानी देना है, उनके सामने प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। बाकी गांवों में पानी चला जाएगा। अब 50 गांव वाले यह कहेंगे कि बाकी में पानी आ गया और जो बाकी 50 गांव रहेंगे, उनमें जमीन का वाटर लेवल खारा है। पानी कम है, मतलब गर्मी के तीन-चार महीनों में तो हमको ट्रांसपोर्ट से पानी भेजना पड़ता है। ऐसे विलेजेज हैं। बहुत संकटमय स्थिति के विलेज हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा आपको पोजिटिव होकर इन 50 गांवों के पानी की व्यवस्था करनी है और ईआर क्लस्टर को जीवित रखने के लिए उसमें कुछ फंडिंग की व्यवस्था करनी है। पैसा खर्च इतना होगा नहीं समय पर, लेकिन वह योजना जीवित रहनी चाहिए जिससे काम आगे चलता रहे। मेन ट्रांसमिशन लाइन जो रामसीन है, उससे बाघरा की लम्बाई है मुश्किल से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर अगर आप लाइन दे दोगे, बाघरा से हमारे 50 गांवों के पीएचईडी सिस्टम से लाइन जुड़ी हुई है तो हम 50 गांवों में उसको भेज देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात के लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि इस बार जैसे सांचौर में फ्लड आया और सांचौर में जो गुजरात से नहर के माध्यम से पानी आता था, उस पानी को आगे हमको सप्लाई देना है। फ्लड में नहरें टूट गयीं, 250 करोड़ रुपये देकर एकदम युद्ध स्तर पर काम करवाया। मैं विभाग के मंत्री और सिंचाई मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका विभाग दो महीने में टूटी हुई नहरों को भी ठीक कर देगा और बजट की एकदम आकस्मिक व्यवस्था करके आपने किया है। नर्मदा के पेयजल से सारा जालौर जिला जुड़ा हुआ है इसीलिए पूरे जालौर जिले की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि एकदम आकस्मिक घोषणा जो हमारे लिए की, यह बहुत बड़ा वरदान साबित

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
हुई है। अब मंत्री महोदय, यह पानी आगे पहुंचाने के लिए आपकी थोड़ी सी हमारे ऊपर नजर चाहिए कि इन 50 गांवों का सवाल है और इन 50 गांवों में पानी पहुंचाने की आप व्यवस्था कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपने ट्रांसमिशन लाइन को, रामसीन तक तो पानी आ जाएगा, लेकिन उसमें पानी 50 गांवों के हिस्से का है, अब आगे पानी नहीं दोगे तो पानी कैसे पहुंचाओगे, यह भी आप जरा बतायें और इसकी व्यवस्था कैसे करोगे, मतलब कहीं न कहीं दिमाग दौड़ा कर व्यवस्था करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापस इन पूरे 50 गांवों की जनता की ओर से आपको हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जालौर जिले के ईआर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि जालौर जिले के भीनमाल शहर एवं 256 गांव नर्मदा नहर से जलापूर्ति के आधारभूत ढांचा निर्माण हेतु नर्मदा ईआर परियोजना का कार्य मैसर्स एसपीएमएल, नई दिल्ली को रुपये 372.70 करोड़ की लागत का आवंटित किया गया था जिसके अन्तर्गत डेडवा गांव पर पम्प हाउस तथा पालड़ी सोलंकियान पर 100 एमएलडी क्षमता का फिल्टर प्लांट बनाकर रामसीन तक 144 किलोमीटर राइजिंग मेन मय पांच पंपिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। जिसमें से लगभग 48 परसेंट काम तो पूरा हो चुका है और शेष कार्य इसी अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। उक्त आधारभूत ढांचे से प्राप्त जल को वितरण करने हेतु उच्च जलाशय एवं वितरण प्रणाली विकसित करने हेतु रुपये 449.82 करोड़ की लागत की क्लस्टर योजना तैयार की गयी है, जिसे वित्त पोषण के पश्चात् क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आपने जैसा कहा, इससे 50 गांवों को लाभ होगा। इसमें 22 गांव हैं जो रामसीन से लेकर बाघरा तक, उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् आहौर विधान सभा क्षेत्र के रामसीन से बाघरा तक 22 गांवों को लाभान्वित किया जाना संभव हो पायेगा।

जैसाकि आप कह रहे हो, उनमें से जो ईआर प्रोजेक्ट है, उनमें जो पैसा बचा हुआ है, वह पैसा इधर खर्च कर दो। वह स्कीम अलग है, यह स्कीम

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

अलग है। उसका पैसा इसमें खर्च नहीं हो सकता और इसका पैसा उसमें खर्च नहीं हो सकता। आप निश्चिंत रहें। यह जो आपने ध्यान दिलाया है, इसके ऊपर अग्रिम क्या कार्यवाही हो सकती है, करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखाराम जी।

मेड़ता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि चिकिसला, मेड़ता और रियां बड़ी जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, एक उपखण्ड मेड़ता का है और दूसरा उपखण्ड रियां का है। हमारे रियां बड़ी में 30 बैड का अस्पताल है। उसके लिए मैं आपकी मार्फत से मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको 50 बैड का किया जाए। हमारे वहां सोनोग्राफी मशीन, ब्लड बैंक उपलब्ध है। इनको चलाने के लिए स्टाफ भेजा जाए ताकि गांव वालों को सुविधा हो सके। महिला विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और जनरल मेडिसिन भी भेजा जाए और हमारे रियां बड़ी में पादू कलां में दो पद सृजित हैं। उनमें डाक्टर डेपुटेशन पर लगे हुए हैं और रियां बड़ी में आठ पद सृजित हैं। वहां मौजूदा दो पदों पर ही डाक्टर लगे हुए हैं तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वहां पर भी डाक्टर्स की सुविधा आप करवायें।

हमारे ग्रामीण एरिया में बहुत बड़े कस्बे हैं, पादूकलां और जसनगर, उसमें पी.एच.सी. से सी.एच.सी. करवाया जाएं और हमारे उप स्वास्थ्य केन्द्र, अब तक हमारे रियांबड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में धोलेराव, रासलियावास, माणक्यावास, समधोळा, पादूकलां, जसनगर, यहां काफी गांव हैं वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाए और हमारे मेड़ता शहर में जो पुराना अस्पताल था, वह नया अस्पताल नागौर रोड पर खुल गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में बोलने के लिए माननीय सदस्यों के पास कुछ नहीं है, इसलिए डिमाण्ड कर रहे हैं। डिमाण्ड पर बोल रहे है, इससे ज्यादा क्या....

श्री सुखाराम (मेड़ता): आपको क्या तकलीफ है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या कुछ तो बोलना ही है आपको खड़े होकर के, कोई न कोई बोलने का विषय नहीं हो तो भी बोलना है।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): आपके स्प्रिंग लगी हुई है क्या?

श्री सुखाराम (मेड़ता): आप कैसे बोलेंगे, बताओं मेरे को? मैं ऐसे बोलूं, तो मैं भी आपके पीछे, मैं भी बोल जाऊं। मेड़ता शहर में हमारे 40 बैड का सफाखाना है। भामाशाहाओं ने और हम सबने मिलकर एक ट्रोमा सेन्टर की बिल्डिंग बनवाई है। अभी घोषणा नहीं हुई, बिल्डिंग का उद्‌घाटन, आज से साल, डेढ़ साल पहले, राजेन्द्र जी राठौड़ मौके पर थे, वहां बिल्डिंग का उद्‌घाटन किया। मेड़ता शहर में, सौ डेढ़ सौ, गांव आस-पास के आते हैं, 80-85 किलोमीटर अजमेर पड़ता है, 80-85 किलोमीटर नागौर पड़ता है, 140 जोधपुर पड़ता है, यह बीच में आता है, इसलिए मैं आपके मार्फत से मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सौ बैड का सफाखाना, आज ही खोला जाएं और रेण में पी.एच.सी. को सी.एच.सी., मौकाला में पी.एच.सी. को सी.एच.सी., कोटण को भी पी.एच.सी. से सी.एच.सी. और वाकई जो ग्रामीण एरिये हैं, उसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र कहीं नहीं है, उसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उस पर जरूर मुख्य मंत्रीजी से और आपसे निवेदन मेरा यही है कि सबसे बड़ा हमारा मेड़ता शहर है, उसमें पुरानी बिल्डिंग शहर के अन्दर है और जो नया सफाखाना बना है, उसमें एक रेलवे लाइन जाती है, रेल निकलती है तो फाटक कई बार बन्द होता है। शहर की 50-60-70 हजार जनसंख्या है, वो फाटक की वजह से टाइम पर नहीं पहुंच सकती है। बिल्डिंग बनी हुई है और आप उस बिल्डिंग को महिला डिस्पेंसरी घोषित कर दें। बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो महिलाओं, ग्रामीणों और शहर वालों को बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मंत्रीजी, यहां बैठे हैं तो मेड़ता का तो 100 बैड का अस्पताल घोषित करने की कृपा करावें। धन्यवाद सा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 126 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति मेड़ता एवं रियांबड़ी का क्षेत्र आता है, पंचायत समिति मेड़ता में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है और रियांबड़ी में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरुद्ध एक सामुदायिक

(श्री कालीचरण सराफ)

स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। रियांबाडी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में मेड़ता सिटी 50 शय्याओं युक्त सी.एच.सी. है, जिसकी वर्ष 2016 में 91.29 प्रतिशत शय्याओं की उपयोगिता डी.ओ.आर. रही है, इसलिए आगामी वित्तीय वर्ष में मेड़ता सी.एच.सी. में 50 से 75 शय्याओं में वृद्धि पर विचार किया जाएगा। विधान सभा क्षेत्र मेड़ता पंचायत समिति में 126 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार किया जायेगा। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़ता सिटी में ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है। इन चिकित्सा संस्थाओं पर चिकित्सकों के 44 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 34 चिकित्सक कार्यरत हैं, सीधी भर्ती से रिक्त पदों की आगामी भर्ती से उपलब्ध होने वाले कार्मिकों एवं पदोन्नति के रिक्त पदों को भविष्य में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे। विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे आउटडोर, इनडोर, संस्थागत प्रसव, नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, 108 और 104 एम्बुलेंस सर्विस आदि का लाभ आमजन को उपलब्ध करवाया जा रहा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल।

निवाई की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हीरालाल जी, एक मिनट मेरी तरफ देखिये। आज ही घोषणा करो इनके पैसे, जो इनके पैसे खा गये आप लोग इनको दिलाओ। ये आरोप लगा रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप प्यार करते हो न?

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हीरालाल जी, मैं कह रहा हूं वेलेन्टाइन

(श्री हनुमान बेनीवाल)
डे तो कल था, आज क्यों लव कर रहे हो आप इनसे? वेलेन्टाइन डे कल था, कल कहते आप ये बात।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो दलितों का अपमान है साहब, राजस्थान के अन्दर आप दलितों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब आपविराजो।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अशोक (हिण्डौली): अभी की अभी घोषणा कर दो।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अशोक (हिण्डौली): मैं मंत्रीजी से बात कर रहा हूं आप कौन हैं जो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट अब आप दोनों विराज जाएं। आप आसन से क्यों संरक्षण चाहे रहे हैं? आप बगैर आसन की तरफ अपना मुख किये आपस में ही बात कर रहे हैं फिर आप आसन से क्या संरक्षण चाहते हैं? आपने 14 मिनट के वक्तव्य में आसन की तरफ तो एक बार भी नहीं देखा। या तो आप शेर शायरी सुना रहे हैं या कभी आप मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, कभी अपने कलीग्स का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान बटोर रहे हैं फिर आप आसन से क्या चाहते हैं? अब आसन आपको यह निवेदन कर रहा है कि अपनी बात को आप...

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री उपाध्यक्ष: आसन खड़ा है, पांवों पर है, आप विराज जाओ। अब आप फर्माओ।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

आज खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य पहली बार सिफारिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... आपकी सिफारिश मानेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने निवाई की विभिन्न सड़कों का जिक्र आज पर्ची के माध्यम से किया। यह बात सही है कि इनके क्षेत्र में अभी एक बहुत बडी सड़क, जिसका आपने मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को भी धन्यवाद दिया और आपकी मांग पर हमने इनके लिये 102 करोड़ रुपये इसी हाउस में बोले, उस पर हमने 102 करोड़ 84 लाख रुपये दिये हैं, उस सड़कका काम चल रहा है। उसके बाद आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने गौरव पथ दिये, नोन पेचेबल रोड दीं, मिसिंग लिंक के लिये दिया, वह सब हमने स्वीकृत कर दी ...(व्यवधान)... आप विराजो, आप विराजो।

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विराजो, आपको दिलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय, आप विराजे। मैं सम्माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी बाध्य नहीं है कि आपके इस सवाल का जवाब दें। अगर आप जवाब चाहते हैं तो आप भी शांति से, धैर्य से इस बात को सुने।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन्होंने विशेष रूप से एक सड़क झिराणा से नानेर को क्षतिग्रस्त बताया है। दूसरी बोंली से निवाई, उसका कुछ हिस्सा आपने क्षतिग्रस्त बताया है। तीसरा, तीन रपटे जो पिछले वर्ष 2016 में बीसलपुर के ओवर फ्लो से टूट गये थे, उनको ठीक करने का निवेदन किया है। उसके साथ साथ आपके क्षेत्र में जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनके लिये भी आपने बात कही है। जिन सड़कों का जिक्र किया, उन सबका तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन माननीय सदस्य की मांग पर आज इनके निवाई विधान सभा क्षेत्र में जो नोन पेचेबल रोड्स हैं लगभग 106 किलोमीटर, उन सड़कों की स्वीकृति हम इसी सप्ताह जारी कर देंगे ...(व्यवधान)... मेरे को बोलने तो दो। 106 किलोमीटर सड़कों पर 21 करोड़ 25 लाख रुपये हम इसी महीने में स्वीकृत कर देंगे। यह तीन जो आपने विशेष मांग की है उसमें

(श्री युनुस खान)
नानेर से झिराना, उसके लिये 14 करोड़ 80 लाख रुपये और बोली से निवाई के लिये 15 करोड़ 90 लाख रुपये और गहलोड से टोंक के लिये 24 करोड़ 91 लाख रुपये, तीनों की स्वीकृति हम एसआरएफ बोर्ड से दे देंगे। इस तरीके से इनके क्षेत्र में जितनी नोन पेचेबल रोड्स हैं, उन सबकी स्वीकृतियां हम जारी कर देंगे। जहां तक टोंक और निवाई के बीच एक सड़क है, जो माइनिंग रोड थी, उसकी स्वीकृति जारी हुई, उसका कार्य प्रारंभ हुआ क्योंकि जो चैनेज प्रारंभ में स्वीकृत हुआ था, वह टोंक क्षेत्र से हुआ था। चूंकि वह माइनिंग रोड थी, माइनिंग वालों ने ही उसकी स्वीकृति जारी की। पीडब्ल्यूडी उसकी वर्किंग एजेंसी थी, हमने उस सड़क को अभी टोंक साइड से शुरू किया है और जो शेष भाग है, उसकी भी स्वीकृति कर देंगे। इस तरीके से जो आज माननीय सदस्य ने जितने इश्यू उठाये हैं, क्योंकि इन सारी सड़कों की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 22 दिसम्बर, 2017 को धोलपुर में घोषणा की थी कि लगभग 14100 किलोमीटर राजस्थान की जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनको हम ठीक करेंगे। माननीय सदस्य की भावना का ख्याल रखते हुए उनकी स्वीकृति भी जारी ...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरी भी आपने सदन में घोषणा की थी, ना तो आपने बाडी वाली का रेवेन्यू बोर्ड का अभी तक कुछ किया, ना आपने बाडी से सबुबाडी रोड का अभी तक कुछ किया। मेरा भी तो कुछ बोलो, एक शब्द तो बोलो, कुछ तो कहो।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप सब विराज जाएं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री महोदय और सचेतक दोनों नहीं हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी आप सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। पर्ची के माध्यम से मंत्री मण्डल के सदस्य, मंत्री बाध्य नहीं है कि पर्ची के द्वारा उठाये गये सवाल का जवाब दें। लेकिन सवाल का जवाब देने के समय सवाल करने वाला सम्माननीय सदस्य इस सदन से बाहर चला जाए, सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह संपूर्ण सदन और आसन, दोनों की अवमानना नहीं है? मंत्री के संपूर्ण जवाब को सुनने के उपरांत अगर उनके मन में फिर भी कोई शंका हो तो मंत्री से संपर्क करके उस शंका का समाधान सुन सकते हैं। आसन ने अगर आपको बोलने की अनुमति दी है तो आसन आपसे यह भी अपेक्षा करता है कि जब

(श्री उपाध्यक्ष)

आपके प्रश्न का या आपके वक्तव्य पर मंत्री वापस प्रतिक्रिया दे रहे हों, तो कम से कम स-सम्मान आपको मंत्री की बात को सुनना चाहिये और जब मंत्री बोलते हैं तो संपूर्ण सरकार की तरफ से बोलते हैं और पूरा सदन इसको सुनता है। क्योंकि सम्माननीय सदस्य मंत्री का संपूर्ण जवाब सुनने के पहले ही बहिर्गमन कर गये और सत्ता पक्ष का सदस्य होने के उपरांत इन्होंने ऐसा किया है, आसन इसको बहुत सख्ती से लेता है और अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो पर्ची सिस्टम को खतम करने के लिये बाध्य होगा। यह सदन अनुशासित तरीके से चलता है, मर्यादित तरीके से चलता है। इस सदन की एक मर्यादा है और यहां बैठने वाले प्रत्येक सदस्य को बाध्य करता है कि उस मर्यादा का अनुसरण करे। अगर उस मर्यादा में नहीं रहेगा तो आसन सख्त होकर मर्यादित आचरण का अनुसरण कराने के लिये सदस्य को बाध्य कर देगा। इस पूरे कथन का कहीं भी अंकन नहीं होगा और आज इस सदस्य को मैं नाम से पुकार कर यह चेतावनी दे रहा हूं इस प्रकार का वक्तव्य और व्यवहार आसन कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञानचन्द पारख।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तबीयत खराब थी, जुकाम लग रहा था, मैं पानी पीने गया था। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मैं उठ कर नहीं गया। मेरा गला खराब है, मैं पानी पीने गया था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में आपकी जो भावना आहत हुई है, मैं इस दल के जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपनी तरफ से क्षमा याचना करता हूं और उन कारणों को भी ढूंढने का प्रयत्न करुंगा कि वह सदन किस कारण से छोड कर गये। अगर वास्तव में बिना किसी कारण से सदन को छोड कर गये हैं तो निश्चित रूप से पार्टी स्तर पर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह करेंगे। भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार कोई सदस्य नहीं करेगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली की तहसील रोहट में फसलों का मुआवजा

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा दैवीय संयोग है कि जब जब भी हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी का

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
राजस्थान में शासन होता है तो प्रकृति की हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी होती है। ...(व्यवधान)... मेरी चिंता मत करो आप, पर कई बार प्रकृति की मेहरबानी अति हो जाती है और पिछले दो सालों से मेरे क्षेत्र में यही हुआ, अतिवृष्टि हुई और जैसे अतिवृष्टि में होता है फसलों का नुकसान, फसलों का भी भारी नुकसान हुआ। एक संयोग और कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री इस आपदा को देख कर नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू करते हैं।

उसमें ऐसे कई प्रावधान थे, जो पहले योजना में कवर नहीं थे, उनको जोड़कर यदि किसान को किसी प्रकार का नुकसान हो तो उसकी भरपाई निश्चित रूप से हो जाए, वे सारे बंदोबस्त इस प्रावधान में किए हैं। मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार जो खरीफ संवत् 2017 की फसल नष्ट हुई तो पहली बार 52 करोड़ रुपये का मुआवजा मेरे क्षेत्र की रोहट तहसील के काश्तकारों को बीमा कंपनी के माध्यम से मिला और इतना ही नहीं, 24 करोड़ 59 लाख रुपये का मुआवजा प्रधान मंत्री आपदा कोष से मेरे क्षेत्र के काश्तकारों को मिला है। कुछ बीमा कंपनी और बैंक की लापरवाही से हमारे कुछ बीमित काश्तकार इस क्लेम से वंचित रह गये। मरूधरा ग्रामीण बैंक की पांच शाखाएं हैं, जिसमें पाली की एक मुख्य शाखा है। दो हमारे उप सचेतक जी के क्षेत्र की हैं। एक रायपुर की भी है। काश्तकारों ने मरूधरा ग्रामीण बैंक की इन शाखाओं में अपना प्रीमियम जमा करवाया था। इनकी फसलें भी पूरी नष्ट हुई। गिरदावरी रिपोर्ट, क्रोप कटिंग रिपोर्ट, केंद्रीय अध्ययन दल की रिपोर्ट, सारी की एक ही बात कि ये फसलें पूरी तरह से नष्ट हुई हैं।

अब झगड़ा कंपनी और बैंक के बीच में पड़ता है। बीमा कंपनी कहती है कि बैंक ने हमको समय पर सूची नहीं भेजी, प्रीमियम नहीं भेजा। बैंक के अधिकारी कहते हैं हमने समय पर कंपनी को सूची भी भेज दी और प्रीमियम भी भिजवा दिया। यह मामला लंबे समय से चल रहा है। बीमा कंपनी बैंक के पास पाली भी आयी और वहां भी इस बात की तसल्ली करती है कि यह प्रीमियम कब कटा? इन्श्योरेंस कब हुआ? वापस जाकर यह आश्वस्त करते हैं कि जो काश्तकार वंचित रह गये हैं, उनको क्लेम मिल जाएगा। एक बार नहीं, कई बार आश्वासन देने के बाद में अंत में यह कहकर टाल देते हैं कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमको सूचियां देरी से मिली हैं और जो प्रीमियम की राशि थी, वह हमने बैंकों को वापिस भिजवा दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें काश्तकार की कोई गलती नहीं है। काश्तकार ने समय पर प्रीमियम जमा करवाया। अगर बैंक ने लेट भेजा तो बैंक उस क्लेम की राशि की भरपाई करे और बीमा कंपनी के पास समय पर पहुंच गयी तो बीमा कंपनी को बाध्य करें कि वह उन वंचित काश्तकारों को, उनका जो मुआवजे का हक बनता है, वह हक उनको दिलवाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि बीमा कंपनी क्लेम का अससेमेंट करने में भी अपनी ओर से कहीं न कहीं जान बूझकर कमी रखती है। ऐसे कुछ प्रकरण हुए हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी ने टेबल को देखकर जो क्लेम बनाया कि इस काश्तकार ने फसल के नाते इतनी प्रीमियम भरा है, इतना क्लेम बनना चाहिए और कंपनी ने जो क्लेम निर्धारित किया, उसमें काफी बड़ा अंतर है। लगभग आधा अंतर है। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि जितने भी बीमित काश्तकार हैं, उन्होंने अपनी कितनी फसल का बीमा कराया? कितना प्रीमियम भरा? उसके अनुसार उसका कितना क्लेम बनना चाहिये और बीमा कंपनी ने कितना दिया, तब शायद हम प्रत्येक काश्तकार के साथ न्याय कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संवत् 2017 में भी अतिवृष्टि हुई। इस बार भी फसलें चौपट हुई। इस बार भी काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ। गिरदावरी रिपोर्ट भी मान रही है कि फसलें पूरी की पूरी चौपट। क्रोप कटिंग की रिपोर्ट मान रही कि फसलें पूरी की पूरी चौपट। केंद्रीय अध्ययन दल भी आता है, वह भी मौका देखता है, खेत-खेत घूमता है। वह भी मानता है कि किसान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी है और आश्वासन देकर जाता है कि जो भी आपका नुकसान हुआ, उसकी हम भरपाई कराएंगे। लेकिन आज आठ महीने बीतने के बाद भी कुछ गांव के काश्तकारों को अंतिम रूप से 25 परसेंट क्लेम की सहायता राशि दे दी। कुछ को, सबको नहीं मिली है। खराबा सबमें है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि आप बीमा कंपनी वालों को थोड़ा टाइट करो। ये जो मनमानी करते हैं। सरकार प्रीमियम देती है, बड़ा प्रीमियम देती है और पहली बात ऐसी नौबत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आयी है कि इनको बड़ी भारी राशि का क्लेम देना पड़ रहा है, इसलिये ये कदम पीछे हटा रहे हैं, तो आप बीमा कंपनी को टाइट करो। जो वाकई में किसान का हक बनता है, वह हक उस किसान को दिलवाओ। मुझे पता है प्रधान मंत्री ने नयी फसल बीमा योजना लागू की थी तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया था आपके लिये ऊपर से निर्देश हैं कि आप गांव-गांव में जाकर इस नयी फसल बीमा योजना के बारे में काश्तकारों को जानकारी दें। अधिकारियों के कहने और हमारी सरकार के निर्देश से हम गांव-गांव जाकर बड़े-बड़े भाषण तो ठोक आये कि ये-ये प्रावधान कर रही है, इतने तक पैसा मिलेगा। पैसा मिला भी है, लेकिन जितना मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। मंत्री महोदय, आपसे आग्रह है कि आप बीमा कंपनी को बुलाओ, बैंक को बुलाओ और सारे दस्तावेज व पेपर मंगवाओ। वाकई में हकदार काश्तकार जो कि अभी तक वंचित हैं, उनको उनका हक दिलाओ।

इसके साथ ही मेरा आपदा मंत्रीजी से भी आग्रह है कि सन 2016 में खराबा हुआ। अनुदान की राशि आपने जिले में आठ महीने पहले भिजवा दी। मेरे क्षेत्र में भी 24.69 लाख रुपये की है, पर अभी तक 75 परसेंट काश्तकारों को पैसा मिला, 25 परसेंट काश्तकारों को पैसा नहीं मिला। आप थोड़ा वहां अधिकारियों को टाइट करो। यह पैसा आ ही गया है। पाली के खाते में पड़ा है। आपके यहां से बिलकुल देरी नहीं है, पर वहां अभी तक लेटलतीफी है, लापरवाही है। वह पैसा बंट जाए और उसके बाद 2017 का तो पूरा का पूरा बंटना बाकी है। यह मैं आपको 2016 की बात कर रहा हूं। यह 2017 वाला पैसा भी आप समय पर बंटवा दें।

इसके अलावा 2017 में शहरी क्षेत्र में जो सम्पत्तियों का नुकसान हुआ है। आपकी सर्वे सूची भी आ गयी कि ये मकान नष्ट हुए हैं, उसमें आधों को पैसा मिला, आधों का पैसा जयपुर से आना बाकी है। जो शहरी क्षेत्र में सड़कें नष्ट हुई हैं। एक बार नहीं, तीन बार आपने जैसे प्रपत्र चाहे, वे सारे के सारे प्रपत्र भरकर नगर परिषद, पाली ने जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवा दिये हैं। तो, वह राशि भी आप जारी करवा दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से संरक्षण चाहता हूं कि मैंने पिछली बार भी पाली शहर में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आपदा से जो मकानों व सरकारी सम्पत्तियों का नुकसान हुआ था, उसके बारे में पर्ची के माध्यम से मुद्दा उठाया था और उसमें माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि पाली से जो रिकॉर्ड आना था, वह देरी से आया है, जबकि नगर परिषद, पाली ने जिला कलक्टर को समय पर वह रिकॉर्ड भिजवा दिया था। इसलिये यह मुआवजा अब दिया जाना संभव नहीं है। आपने ही आसन से व्यवस्था दी थी, निर्देश दिया था। आपको याद होगा। सरकार को आपने निर्देश दिया था कि 'इस प्रकरण को वापस दिखवाकर यदि इनकी राशि बनती है तो इनको दिलवाओ'। मैं उस राशि के लिये भी आपसे वापस संरक्षण चाहूंगा कि आपके निर्देश की पालना हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो ध्यान आकर्षित किया है, उसके संदर्भ में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा निश्चित रूप से यह सही है कि पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर के क्षेत्र में खरीफ में काफी जलप्लावन हुआ, अधिक बारिश हुई, फसलें नष्ट हुईं। जिस रोहट तहसील का जिक्र किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने बीमा कराया, उनमें लगभग 29 लाख किसान थे। कृषक प्रीमियम जो आया, वह 80 लाख रुपया आया। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिलाकर 10 करोड़ रुपये का प्रीमियम हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बीमा क्लेम का सवाल है, 35.29 करोड़ का भुगतान भी हुआ। लगभग 29 हजार किसान इसमें लाभान्वित हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के कुछ किसानों का, जिन्होंने शाखा के माध्यम से 54 लाख 68 हजार 920 रुपये का अपना प्रीमियम अगस्त, 2016 में जमा कराया था। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसमें किसान का कोई दोष नहीं था। चूंकि जब प्रीमियम लिया था, तब किसानों का पैसा स्वयं कटकर बैंक के खाते में चला गया और बैंक के द्वारा वह राशि मार्च, 2017 तक फसल और रकबा की सूचना कंपनी को भेजनी थी।

आल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो भारत सरकार की कंपनी है, इसके द्वारा यहां पर बीमा किया गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 43 लाख

(श्री प्रभू लाल सैनी)

28 हजार 238 में से 11 लाख 40 हजार 681 रुपये का जो प्रीमियम आया, उसको बीमा कंपनी ने वापस बैंक को इसलिए लौटा दिया कि उन्होंने कृषकों की सूची, रकबा आदि की सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराई। जिन किसानों की सूची प्राप्त हुई, उनमें से 43.28 लाख फार्मर्स का भुगतान तो कर दिया, 6816 किसानों का भुगतान तो हुआ, लेकिन यह भुगतान रह गया था। मैं आज आपके माध्यम से सदन में माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें जहां भी कमी-खामी बीमा कंपनी की रही है या बैंक की रही है, बीमा कंपनी यह कहती है कि हमारे पास सूची प्राप्त नहीं हुई और बैंक यह कहती है कि हमने तो लोगों को राशि ट्रांसफर सही समय पर मार्च तक कर दी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोष किसी का भी रहा होगा, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मैंने भी व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको गंभीरता से लिया है।

मैं आज सदन में आपसे निवेदन करके एक घोषणा करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर कमिश्नर के स्तर पर एक कमेटी बनाएंगे। एक महीने के अंदर जो भी दोषी होगा, चाहे बैंक हो या बीमा कंपनी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी करेंगे और भारत सरकार की कंपनी के लिए भारत सरकार को भी लिखेंगे। किसानों को इसका मुआवजा मिले, इसकी प्रक्रिया का मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं।

दूसरा आपने प्रश्न उठाया मिड टर्म। पहली बार जब प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान किया हुआ था कि यदि फसल बुवाई के वक्त भी फसल स्विंग फेल हो जाती है यानी फसल नहीं उगती या फसल के उग जाने के बाद भी 15 दिन में बारिश के कारण से फसल नष्ट हो जाती है या फिर उसके मिड सेशन में भी अधिक बरसात होने से फसल नष्ट हो जाती है या फसल कट जाने के बाद भी 14 दिन में खेत में पड़ी हुई फसल भी यदि नुकसान होती है तो वह इस प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों में कवर होता है। अभी हाल ही में चार जिलों में जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर, जहां पर बारिश के कारण से जो प्रभावित हुए, 105 करोड़ रुपये हम लोगों ने कोशिश करके व्यवस्था की कि उन किसानों को इसका मिड टर्म बीमा, पहली बार 25

(श्री प्रभू लाल सैनी)
प्रतिशत बीमा क्लेम डिसाइड होगा तब हो जाएगा, अभी किसान के नुकसान की तत्काल भरपाई करें। मैं इनकी तहसील के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने 19 हजार फार्मर्स में 2 करोड़ 33 लाख का मुआवजा, जो मिड टर्म था और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने कर दिया है। मिड टर्म में फिर भी कुछ किसान रह गये हैं, उनका भी हम लोगों ने क्रॉप कटिंग के परिणाम हमारे पास में मुश्किल से 15 दिन के अंदर सब मिल जाएंगे और आने के पश्चात निश्चित रूप से सभी किसानों की भरपाई हम करेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य ने आपदा राहत से संबंधित बात भी उठाई थी। मैं कह सकता हूं कि पाली जिले में सम्वत् सम्वत् 2072 अर्थात् वर्ष 2016-17 का हमने 41 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है और अकेले आपकी विधान सभा क्षेत्र का जो हिसाब है, रोहट में हमने 5 करोड़ के लगभग किया है और पाली में 19 करोड़ समथिंग किया है। ये तो हैं सम्वत् 72 का और उसमें भी ये पहली बार है। मैं आज बहुत ही संतोष के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसने 33 से लेकर 50 परसेंट के बीच में जो खराबा हुआ है, वह हमने सम्वत् 2072 का सेंट-परसेंट राजस्थान में पेमेंट कर दिया है, लघु का भी, सीमांत का भी और बड़े का भी। रहा सवाल, इस समय जो 17-18 के बारे में है, सम्वत् 2072-73 के बारे में है, वैसे हम लोगों ने पैसा तो भेज दिया, लेकिन हमारा जो पुराना अनुभव है वह यह है कि हम पैसा यहां से भेज देते हैं और पैसा को-ऑपरेटिव में ट्रांसफर हो जाता है, साल-साल, दो-दो साल तक वह पैसा वहां पड़ा रहता है और किसान को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इस कारण से हमने अबकी बार कहा कि हम सारा पेमेंट उसके खाते में ही करेंगे। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं करेंगे, इस कारण से ये जो सम्वत् 2073 वाला है, वह आपका रोहट तहसील का ही, काश्तकारों की संख्या है 27400, बजट जो हमने दिया वह 24 करोड़ 59 लाख, काश्तकार संख्या जिनका भुगतान हमने कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने खाते में ट्रांसफर किया, वह 16437 को कर दिया है। राशि 16 करोड़ 40 लाख रुपया हमने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही उनके खाते की सूचना मिलेगी, सौ परसेंट पैसा तो हमने अलॉट कर दिया लेकिन पैसा तभी जाएगा जब उनके खाते में जाएगा, नहीं तो ये पैसा हम तो ट्रांसफर करते हैं और वहां जाकर को-ऑपरेटिव के खाते में साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक उस पैसे का उपयोग करते हैं और पडा रहता है। इसलिए किसान को जो लाभ मिलना चाहिए, जो शिकायत आप कर रहे हो, वह शिकायत हमने जांच ली है। अब हम सौ परसेंट राजस्थान में इस साल से उसके ही खाते में ट्रांसफर करेंगे और किसी एजेंसी को बीच में नहीं डालेंगे जिससे सारा का सारा पैसा किसान को पहुंच सके।

पिछली बार का जो सवाल आपने किया, कारण यह है कि आपदा राहत तो उस डिपार्टमेंट का नाम है, जब खराबा होता है और उसको राहत मिल जाए। ये जो आपदा का, फसल का मिलता है, इसमें जरूर समय लगता है। लेकिन अगर सड़क टूट गई, खड्ड़ा हो गया उसमें आप आठ-आठ महीने तक अगर हमको एस्टीमेट ही बनाकर नहीं दो, हमारा तो यह है कि आपका अक्टूबर में खराबा हुआ तो नवम्बर में समय बना दो। हम तो केवल रिपेयरिंग का पैसा देते हैं, हम कोई पूरा पैसा तो देते नहीं है। लेकिन आप 6 महीने बाद अपना एस्टीमेट बनाकर एक लंबा-चौड़ा खाता बना देते हो, तब तक हमारे पास पैसा रहता नहीं है। फिर भी आपको अगर लगता है तो आप अपना रिकॉर्ड ले आओ, मेरे विभाग का रिकॉर्ड मैं ले आता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में ही आ जाते हैं कि हमने कहां गलती की है? जो समय पर सूचना आती है, उसका पेमेंट कर देते हैं। बाद में बढ़ा-चढ़ा कर के जो भी वो जोड़-जुड़ा कर लाते हैं तो उसके लिए तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, न ही वह कर सकता है, न उसकी क्षमता है और न उसके पास इतना पैसा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साथ में इस वर्ष की भी बात की है। इस वर्ष का भी पैसा नहीं मिला है। समय पर हमने सारी सूचियां भिजवा दी थी। एक बार नहीं, तीन-तीन बार जो प्रपत्र आपने अलग-अलग परिवर्तन करके मांगे, वह सारे के सारे भिजवा दिये। आप स्वयं पाली पधारे थे, आपने कुछ स्थानों का जायजा भी लिया और लगा कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
वाकई में सड़कें बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हुई है। मकान भी बहुत बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनका पैसा भी इस बार का बाकी है। इस बार हमारी ओर से कोई पेपर लेट नहीं है। उसका भी मैं आपसे कोई न कोई आश्वासन चाहूंगा कि यह पैसा कब तक आ जाएगा?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका यह जो पैसा इस साल का अगर है हमारे पास और समय पर सूचना है तो निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी यह पैसा आपको मिल जाएगा, आपके व्यक्ति को, किसान को पहुंच जाएगा जिसका नुकसान हुआ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, नहीं। मैं सड़क की बात कर रहा हूं, सड़क व मकानों की।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, सड़क का जो हमारा नार्म्स है, उसके आधार पर जो पैसा बनता है देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा मैं लगातार उनसे सम्पर्क में हूं। आपके वहां यह कह रहे हैं कि राशि हमारे पास कम बची है। हम नियमों में तो आ रहे हैं कि हमारा हक बनता है, परंतु आपके यहां राशि की कमी होगी। उसकी वजह से वो कटौती करके फिफ्टी परसेंट देने के लिए नये प्रस्ताव मंगवा रहे हैं कि आपने जो पहले प्रस्ताव भिजवाए, उसको आप कम करो। पहली बार प्रस्ताव भिजवाएं उस समय भी कम करवाए, दोबारा और कम करवा रहे हैं। वह कम करवाने वाले प्रस्ताव भी यहां भिजवा चुके हैं हम। वह राशि तो आप भिजवा दो, जो आपके पास पड़ी है। उसके अलावा जो मकानों को क्षति हुई है, उसका भी पैसा बाकी है। वह भी आप मेहरबानी करके, वह सूची तो स्वीकृत होकर आ गयी। आधों को मिल गये और आधों का बाकी है, वह पैसा दिया जाए। वह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वापस कृषि मंत्री जी से आग्रह रहेगा। माननीय कृषि मंत्रीजी, मैंने एक विषय और उठाया था कि किसान ने कौनसी फसल की बुवाई की है? कितने हैक्टेयर में की है? और उसने कितनी राशि का बीमा कराया उसमें प्रीमियम कितनी भरी है? उसके अनुसार उसका क्लेम कितना बनता है? उसमें भी ये बीमा कंपनी कही न कही गड़बड़ कर रही है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कुछ केस के बारे में जब हमने पाली के कृषि अधिकारी से बात की और उनके माध्यम से उनकी क्लेम राशि निकलवाई तो आधा-आधा फर्क है। बनती है क्लेम राशि 55 हजार, भुगतान किया है 27 हजार का और कृषि विभाग के अधिकारियों ने पत्र बनाकर भी उन अधिकारियों को, बीमा कंपनी को भेजा है कि आपने कम राशि का भुगतान क्यों किया?

(14.00 बजे)

तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, बीमा कम्पनियां दूध से धुली हुई नहीं है। इनका बस चले तो, ज्यादा क्लेम नहीं देना पड़े और किसान बापड़ा कुछ समझता नहीं है कि उसका कितना क्लेम बनता है। एक बार जितना भी अकाउण्ट है, आडिट करवा दीजिए कि वास्तविक क्लेम कितना बनता है और बीमा कम्पनी ने कितना दिया? उसमें आपको अंतर नजर आता है कि नहीं, अगर वाकई में बीमा कम्पनी ने कम दिया है तो किसान का हक बनता है उसके प्रीमियम के अनुसार वह राशि दिलाने के लिए भी आप कुछ व्यवस्था करोगे कि नहीं, इसका भी आप मुझे जवाब दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, इस विषय पर You are more or less completing half an hour. अगर मैं एक-एक पर्ची पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा कराने लगूंगा तो यह प्रश्न काल का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और जिन माननीय सदस्यों की पर्चियां खुलती हैं, आप अपना मूल प्रश्न जिस विषय पर है, दो-चार मिनट में आप अपना वक्तव्य दे दें या सप्लीमेंट्री इज एनकाउंटर, सप्लीमेंट्री इज ए सब-सप्लीमेंट्री के लिए नहीं है This is not a river which will be filled by tributaries.

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह किसानों से जुड़ा अहम मुद्दा था इसलिए मैं चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: I am sure now that has been (..Interruption..) एक मिनट आप विराज जाए। now it is in the knowledge of the Minister concerned. मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनकी जो भी कोई क्वेरीज है वह पर्सनली बैठकर इनकी क्वेरीज यथा उचित है उनका समाधान कर लें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैंने जो पूछा उसका जवाब तो दिलवा दो। मैंने जो अभी पूछा उसका एक तो जवाब दिलवा दो। करोड़ों रुपये का... ...(व्यवधान)...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आश्वासन दे दिया ...(व्यवधान)...

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आश्वासन दे देंगे, जांच करवा देंगे, करना ही क्या है उसमें? सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बीमा कम्पनी से किसान का हक दिलवाएं। सरकार के हित की बात है इसमें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आप विराजेंगे तो आगे बढ़ेगा मामला।

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यकता ही कहां महसूस करते हैं। ...(व्यवधान)... मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे अनुमति दी। चूंकि राजस्थान प्रदेश से जुड़ा विषय था इसलिए संक्षिप्त में, वैसे तो आपने जैसा आदेश दिया, इसके बारे में हम लोग अलग से बैठकर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि अधिसूचित हमारी जिंस है वह पाली में बाजरा, मूंग, तिल, ज्वार, ग्वार की फसलें थीं। आपने कहा कि हमारा एस्टीमेट ज्यादा और बीमा कम्पनी ने एस्टीमेट कम किया, मैं इस बारे में संक्षिप्त निवेदन करना चाहूंगा कि बीमा निर्धारण करने का, उसकी इनडैम्निटी तय करने के पश्चात बीमा किया जाता है। उसी के आधार पर बैंक उसका प्रीमियम लेती है। प्रीमियम लेने के पश्चात तहसील लेवल पर 16 क्रोप कटिंग होती है। पटवार स्तर पर 4 क्रोप कटिंग होती है, राजस्व मण्डल, सांख्यिकी विभाग के द्वारा उसको किया जाता है। क्राप कटिंग में जितना भी असेसमेंट आता है, जितना प्रोडक्शन आता है, जितना परसेंट कम प्रोडक्शन हुआ, उतना ही कम्पनी के माध्यम से किसान को मुआवजा देने का प्रावधान है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शंका निराधार है। हमारा बेस क्रोप कटिंग है। क्रोप कटिंग का राजस्व मण्डल के माध्यम से जो भी हमें मिलता है उसी के आधार पर गणना करके किसान को बीमा का पैसा दिया जाता है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो..

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक मिनट, आपकी इजाजत हो तो ।

श्री उपाध्यक्ष: इस विषय पर मैं किसी भी प्रकार का वाद-विवाद का अवसर पैदा नहीं करने दूंगा। मैं आप लोगों से बार-बार निवेदन करता हूं, तकरीबन रोज निवेदन कर रहा हूं। पर्ची के माध्यम से एक बहुत सीमित दायरा है। आप अपनी बात को अभिव्यक्त करके मंत्री के ध्यान में लाएं। मंत्री की बाध्यता ही नहीं है जवाब देने की। संवेदनशील सरकार की तरफ से, संवेदना से परिपूर्ण मंत्री आपको अपनी अभिव्यक्ति द्वारा समझाने की चेष्टा करते हैं उसके उपरांत भी अगर आपके मन में कोई शंका, संशय है तो इनसे व्यक्तिगत सम्पर्क करके आप दूर कर लें। संवेदना सम्पूर्ण वेदना में परिवर्तित नहीं हो सकती।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है आदरणीय?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न

किसी विषय पर मंत्री के उत्तर के साथ सदस्य को भी प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: हां तो, आप फर्माइये कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा निवेदन यह है कि पर्ची के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र की या राजस्थान के गंभीर मसलों को सरकार के सामने रखते हैं। आपने फर्माया पर्ची के माध्यम से मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते कि वह उसका जवाब दे। बात सही है, पर अगर मंत्री जवाब देता है तो फिर विधायक को भी हक होना चाहिए कि वह क्वेश्चन कर सके और उसका जवाब भी मंत्री दे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): बीमा कम्पनी गड़बड़ कर रही है, अगर गड़बड़ कर रही है तो जांच करवा ले, सीधी सी बात यह है। कोई लंबी बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक बार विराजिए। एक मिनट विराज जाओ। मुझे सम्पूर्ण सदन से एक बात निवेदन करनी है। ...(व्यवधान)... अब आप एक बार विराज जाइये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, या तो पर्ची सिस्टम ही खतम करवा दीजिए। मंत्री अगर रेस्पोंड करता है तो विधायक को भी हक होना चाहिए कि वह प्रश्न पूछ सके।

व्यवस्था

पर्ची द्वारा उठाये गये मुद्दे पर सदस्य का एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आप इतना तो ध्यान रखे कि जब आसन पांव पर हो तो कम से कम आसन की बात तो आप निवेदनपूर्वक सुन लें।

आसन इस बात को अनेक बार स्पष्ट कर चुका है, पर्ची के नियम नहीं बने हुए हैं। अगर आपका यही आचरण रहा तो नियम बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब आसन स्पष्ट निर्देश देता है पर्ची द्वारा उठाये गये विषय पर, पर्ची द्वारा उठाये गये सदस्य को, एक सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार होगा, वाद-विवाद नहीं होगा।

सदन में चर्चा हेतु विषय के सूचीबद्ध होने के पश्चात् सदस्य का अनुपस्थित रहना सदन की अवमानना

उप सचेतक महोदय, आज के 295 में 12 सदस्यों की सूची थी। एक सम्माननीय सदस्य अनुपस्थित थे। आसन इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि वह सम्माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित थे, लेकिन विधान सभा में उपस्थित थे। 295 के अंदर लिखित होने के बाद उनकी अनुपस्थिति आसन और सदन की अवमानना की श्रेणी में आती है। मैं आखिरी बार आपको चेतावनी दे रहा हूं वर्ना ऐसे सदस्यों को आसन सस्पैंड कर देगा।

राजपाल सिंह जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 26 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-178 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-269 दिनांक 30.3.2016 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-179 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2018-180 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-181 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-182 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-183 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-184 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद-10 में विनिर्दिष्ट किसी कम्पनी के संगम अनुच्छेद के लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

8. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-185 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के संबंध में बैंक और वणिक के मध्य निष्पादित करार पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-186 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा सेबी में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री के लिये अधिकृत करने हेतु निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-187 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद-14 और 37 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-188 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अधीन राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम-157 व 158, राजस्थान सरकारी अनुदान 1961 एवं स्लम रिडवलपमेंट पॉलिसी, 2012 के अन्तर्गत जारी पट्टों पर देय मुद्रांक शुल्क का निर्धारण किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-189 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-156 दिनांक 1.1.2018 में संशोधन किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-190 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-191 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों की वर्तमान डीएलसी दरों में दिनांक 13.2.2018 से 10 प्रतिशत की कमी की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

15. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-192 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों की दरों को डीएलसी द्वारा वर्ष 2018-2019 में पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-193 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(10)वित्त/ग्रुप-4/92-1 दिनांक 10.5.1994 को अतिष्ठित किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-194 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-195 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-196 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आवासीय इकाइयों के संबंध में विकासकर्ता और आवंटिती के मध्य निष्पादित विक्रय करार पर देय पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-197 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-124 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-198 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति के विभाजन की लिखत पर देय पंजीयन शुल्क का निर्धारण किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/27बी-1 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/27बी दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/1 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा नष्ट हो चुके मोटरयान, नष्ट हो चुके मोटरयानों से

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भिन्न यान एवं अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत एवं राज्य में 30 दिन से अधिक के उपयोग के लिये लाये गये मोटरयानों पर देय कर पर ब्याज एवं शास्ति पर छूट प्रदान की गई है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/2 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा मूल रूप से वाहन निर्माताओं द्वारा विनिर्मित एवं एलपीजी, सीएनजी या सौर ऊर्जा से संचालित लोक सेवा यानों पर देय एकमुश्त कर में छूट प्रदान की गई है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/22एफ दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179) परि/कर/ एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

26. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/21ए दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(261)परि/कर/ एचक्यू/2004-21 दिनांक 22.9.2004 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.10(7)यूडीएच/3/2009पार्ट-III दिनांक 8.8.2017 जिसके द्वारा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वास्तुविदों का पैनल तैयार करने एवं एम्पेनल्ड वास्तुविदों द्वारा विकासकर्ताओं को सीधे ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(52)यूडीएच/II/2016 दिनांक 5.9.2017 जिसके द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

3. अधिसूचना संख्या: एफ.18(31)नविवि/एचएफए-2022/2015 दिनांक 4.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषिक आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा/आवंटन की आवश्यकता में संशोधन करते हुए ऐसे प्रकरणों में 90-ए के तहत आदेश जारी किये जाने तथा संबंधित निकाय के नाम भूमि आने के पश्चात् एकल पट्टा/ले आउट प्लान की अनुमति प्रदान की गई है;

4. अधिसूचना संख्या: एफ.1(5)आरजे/रेरा/2017 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी रेग्युलेशन, 2017 विरचित किये गये हैं;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.18(13)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा एकीकृत भवन विनियम, 2017 विरचित किये गये हैं;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 30.11.2017 जिसके द्वारा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों हेतु आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन करने के लिये दरें निर्धारित की गई हैं;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)आरजे/रेरा/२017/450 दिनांक 21.12.2017 जिसके द्वारा रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी द्वारा नगरीय क्षेत्र के बाहर भी विकसित की जा रही आवासीय एवं व्यवसायिक परियोजनाओं का विनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य किया गया है; एवं

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(231)यूडीएच/2014 दिनांक 16.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में संशोधन किया गया हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह जी

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं:-

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

(I) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17, 2017-18

(II) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38(4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018. को मेज़ पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय एक विश्वविद्यालय के तो 2016-2017, 2017-2018 के प्रतिवेदन रख रहे हैं और सुखाड़िया विश्वविद्यालय जिसका 2015-16 का ही रख रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, जल्दी से जल्दी इसका भी आगे रखवाएंगे 2016-17 और 2017-18.

व्यवस्था

वार्षिक प्रतिवेदन रखने में विलम्ब के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही हो

श्री उपाध्यक्ष: आसन से मार्च 2017 में स्पष्ट निर्देश हो गये थे, स्पष्ट निर्देशों के बाद यह बात स्पष्ट कर दी थी कि तकरीबन सात दिन पहले यह प्रतिवेदन सदस्यों के पास आ जाने चाहिए। आसन आपसे निवेदन करता है और आसन आपको निर्देश भी देता है......

यह वार्षिक प्रतिवेदन जो अब तक नहीं आये, जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसके दोषी हैं, उन पर कार्यवाही करके अगले सप्ताह आप आसन को अवगत कराएंगे।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री गोपाल कृष्ण।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' (क्रम संख्या 8)

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह (पुलिस) विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-18 के अष्टम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत, आपकी एक अधिसूचना रह गयी है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.15(5)डीएमआईसी/मिस./2016/एसआईआर एक्ट/16 दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2. अधिसूचना संख्या: एफ.15(5)डीएमआईसी/मिस./2016/एसआईआर एक्ट/16 दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अपील प्राधिकरण नियम, 2017 विरचित किये गये हैं; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.15(5)डीएमआईसी/मिस./2016/एसआईआर एक्ट/16 दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन (लेखा, संपरीक्षा और संपरीक्षा फीस) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य, अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष, 2017-18 (द्वितीय संकलन) एवं अतिरेक मांगें, वर्ष 2014-15 का उपस्थापन, श्री राजपाल सिंह।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगों वर्ष 2017-18 (द्वितीय संकलन) एवं अतिरेक मांगों वर्ष 2014-15 का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें, वर्ष 2017-18 (द्वितीय संकलन) एवं वर्ष 2014-15 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019, प्रथम अवस्था, अग्रेत्तर वाद-विवाद। श्री प्रहलाद गुंजल।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 फरवरी को राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने 2018-19 का बजट सदन में पेश किया है। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। अभी थोड़े देर पहले आसन के सख्त रुख ने, माननीय सदस्यों को पूरी तरह से, मैं झकझोरना तो नहीं कहूंगा, पर अनुशासन में लाने की दिशा में चेतावनी दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस चेतावनी से ही आगे बढ़ना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है एक संकल्प के साथ सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय, और एक लक्ष्य भी है, राजस्थान में इंवेस्टमेंट बढ़ाना,

(श्री प्रहलाद गुंजल)
बेरोजगारी कम करना, अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा में सुधार व कौशल विकास, एक दूरगामी लक्ष्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उन्होंने बजट पत्र के प्रथम पेज पर बाड़मेर रिफाइनरी का जिक्र भी किया और उसमें यह भी कहा है कि हमने रिफाइनरी प्रोजेक्ट को री-नेगोशिएट करके 40 हजार करोड़ रुपये राजस्थान के बचाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के इस कदम से आने वाले समय में एक लाख रोजगार सृजित होंगे। बजट में उज्ज्वल डिस्कॉम योजना का भी जिक्र किया और राज्य में सेंवथ पे-कमीशन प्रभावी हो गया। इसीलिये प्रदेश के सामने गम्भीर आर्थिक चुनौतियां पड़ी हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच में राज्य के वित्तीय प्रबंधन को ठीक करके कैसे हम राज्य की जनता की अपेक्षा पर खरा उतरें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट से बढ़कर इस सदन में कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं बहुत तकलीफ के साथ आज अपनी बात कह रहा हूं। अभी मैंने आपके सख्त रुख को देखकर, आसन के सख्त रुख को देख कर अनुशासन की बात कही। लेकिन कल की तस्वीर मेरे जेहन में से नहीं उतर रही। राजस्थान का 2018-19 का बजट पेश हुआ, यह बजट दूर तक राजस्थान के भविष्य में सुधार लायेगा। बजट है, जो राजस्थान की अपेक्षाओं को पूरा करता है। बजट में क्या संशोधन किये जाने चाहिए, बजट में क्या सप्लीमेंट्स जोड़े जाने चाहिए, बजट में क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, सदन उस पर चर्चा का व्यापक प्लेटफार्म है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं, यहां कई वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। सांगानेर से आने वाले माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, और भी सदस्य बैठे हैं। कल की जो तस्वीर थी, वह कई लोगों के जेहन में बैठ गयी होगी, जब चर्चा प्रारम्भ हुई तो सदन में केवल 28 सदस्य मौजूद थे। मैं प्रतिपक्ष की तरफ झांक रहा था। प्रतिपक्ष की सामने की दीर्घा में केवल प्रतिपक्ष के उप नेता बैठे थे, जिन्हें बजट पर अपनी बात शुभारम्भ करनी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सदन संचालित हो रहा है, इस सदन में मंत्री से लेकर सदस्यों तक सदन संचालित करने के लिये प्रति दिन का दैनिक भत्ता मिल रहा है, इस सदन की कार्यवाही को सुचारु करने के लिये बिजली का एक बल्ब भी जल रहा है तो इस राजस्थान के गरीब करदाता का, जो टैक्स देता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है, राज के खजाने को भरता है, उसका पैसा है। उस करदाता के प्रति हम सबकी सामुहिक जिम्मेदारी है। इसलिये जो आज का आपका, आसन का सख्त अनुशासन का रुख देखा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस मंजर ने अंदर तक हिला दिया। 28 सदस्यों की उपस्थिति में सदन में बात करने में जो अरुचि नजर आ रही थी सदस्यों में, यह मंजर आम-अवाम के प्रति हमारी जवाबदेही से हमको भगा रहा है। एक महत्वपूर्ण काम साल में एक बार बजट का, और उस पर भी ऐसा कमजोर, पूअर दृश्य देखने को मिले, इसलिये विधायकों की अरुचि मायूस करने वाली है। मान लो सत्ता पक्ष 27 की संख्या में बैठा था तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास विपक्ष, जो हमारा निगहबान है, वह निगहबान गायब है। लोकतंत्र की परम्पराओं को कैसे सुदृढ़ बनायेंगे। निगहबान गायब है, सत्ता पक्ष बजट पर चर्चा में मायूसी दिखा रहा है। ऐसी व्यवस्था के चलते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरुर उन आत्माओं को तकलीफ पहुंचेगी, जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित करके इस सदन में महान परम्पराएं स्थापित की हैं। मैं इस पर तो बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन जीवन खपा कर संसदीय परम्पराओं का निर्माण किया और सदन की सार्वभौमिकता को, सदन सर्वोच्च है, इसको प्राथमिकता के साथ राजस्थान में स्थापित करके रखा। ऐसा मंजर राजस्थान के मतदाता को उदास नहीं कर दे। ऐसा मंजर लोकतंत्र की परम्पराओं और प्रक्रियाओं में सदस्यों की उदासीनता के कारण राजस्थान के आम मतदाता में विश्वास पैदा नहीं करता। इसलिये आसन का सख्त रुख इस दिशा में भी होना चाहिये।

चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, आसन की मर्यादा से सब लोग बंधे हुए हैं। कोई आसन की मर्यादा से ऊपर नहीं है और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बात शुरू करने से पहले मैंने अपनी बात कही है। बजट मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है और उन्होंने बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे प्रावधानों के बाद जो मूल बात कही है 2018-19 के बजट अनुमानों में राजकीय घाटा, जी.एस.डी.पी. का 2.95, 2.98 प्रतिशत है जो कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट की निर्धारित सीमा के अंदर आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में एफ.आर.बी.एम. एक्ट पारित

(श्री प्रहलाद गुंजल)
किया गया। 2016 में फिर नये सिरे से उस पर विचार हुआ। उन प्रावधानों के अंतर्गत जिस प्रकार से बजट का घाटा है, उसकी सीमा में रहना चाहिए, यह सरकार का सराहनीय कदम है और 2016 के बाद आज तक हम मूल्यांकन करते हैं तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जी.डी.पी. बढ़ी है। यह सब होने के बाद इस बजट के अंदर एक दूरगामी विकास का दर्शन है जिसमें मैं अकेले अगर सिंचाई की बात करूंगा तो हजारों-करोड़ रुपये की योजनाएं हैं।

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कल प्रतिपक्ष के उप नेता ने अपनी बात यहीं से शुरू की कि क्या गारंटी है कि यह आठ महीने में पूरा हो जाएगा? और उन्होंने अपनी बात कही कि अब तक राज्य का सर्वाधिक कर्जा इस बार लिया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज और सरकार जिसके पास दूरगामी लक्ष्य नहीं है, वह सर्वाइव नहीं कर सकती। बजट आज का एजेंडा नहीं है, यह बजट आठ महीने का एजेंडा नहीं है, यह 2018 के चुनाव का एजेंडा नहीं है, यह एजेंडा है राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक ढांचे में कैसे बदलाव लाया जाए और 70 सालों के इस कुशासन में जिसमें लगातार, वह दिन गिना रहे थे माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता कि बी.जे.पी. और उससे संबंधित पार्टियों ने 6 हजार दिन राज किया, कांग्रेस पार्टी ने 17455 दिन राज किया। दिनों में बांट कर भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें यह कहने में लज्जा आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने 48-50 साल राज किया और उस 48-50 साल में राजस्थान के लिए कोई दूर-दृष्टि नहीं रखी और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम आज सारा राजस्थान भुगत रहा है। इस सरकार के बजट में दूरगामी दृष्टि रखी। एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं बल्कि लंबी मियाद की योजनाएं हैं और मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह योजनाएं, सरकार की दूरंदेशी दूर-दृष्टिता का संकेत है और विकास की एक टिकाऊ, दीर्घायु योजना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में चर्चा की अन्नपूर्णा योजना और उस पर एक बड़ा बजट रखा है। मैं कहना चाहता हूं दो समानांतर मोर्चों पर राजस्थान के बारे में चिंता कि हम अब विकास

(श्री प्रहलाद गुंजल)
की दूरगामी योजना बनाएंगे, ऐसा सामाजिक और आर्थिक बदलाव राजस्थान में लाने के लिए, आम आदमी के जीवन में मौलिक बदलाव लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, एक तरफ तो बजट में उस बात का संकेत है। दूसरी तरफ बजट में कि जिस राजस्थान को 48-50 साल के कुशासन ने आर्थिक बदहाली के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, इन्हीं की पिछली सरकार में जो देश का एक नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन का नमूना आया, उसको लेकर पार्लियामैंट में एक मजाक हुई, मैं कई बार सदन में उसको लेकर चर्चा कर चुका हूं इसलिए नहीं कहना चाहता कि इस हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पांच रुपये और दस रुपये में खाना खिलाने के लिए बम्बई और दिल्ली तक तलब किया। अपने भाषणों में पार्लियामैंट में मजाक किया लेकिन राजस्थान की सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने न केवल उसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक विकास का ढांचा और कार्यक्रम बनाया है बल्कि उसके मुंह में अगर दो वक्त का निवाला नहीं है तो उसकी भी चिंता की है।

यह दूरगामी विकास और गरीब की रोज की जरूरत, उसकी पेट की जरूरत, वक्त के बीच में एक सेतु का काम अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से कि गरीब आदमी को मुंह का निवाला मिलना चाहिए। गरीब आदमी सरकार की योजनाओं से कैसे आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़े, किस प्रकार से यह बजट उसके जीवन में मौलिक चिंतन, मौलिक बदलाव लाने वाला बजट बने, इस पर निश्चित रूप से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और सरकार ने काम किया है। सरकार दोनों सिरों से समानांतर काम कर रही है।

राजस्थान में कोई गरीब व्यक्ति जो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, कभी सुबह का रोजगार नहीं, भूखा सो जाता है, उस व्यक्ति को पांच रुपये, सात-आठ रुपये में कैसे रोज भोजन मिले और कैसे उसको रोज काम मिले, दोनों सिरों पर समानांतर काम करते हुए राजस्थान के सामाजिक जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की ओर सरकार बढ़ रही है इसलिए मैं इस सरकार को साधुवाद व्यक्त कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अकेले ही नहीं, इस पर लगातार भारत सरकार काम कर रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं,

(श्री प्रहलाद गुंजल)
भारत सरकार का बजट मेरे पास है। मैं इसके एक-एक पहलू को पढ़कर तो नहीं बताऊंगा लेकिन जो भारत सरकार को किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हैं, जो योजनाएं बनायी हैं, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कमोबेश जिस केन्द्र में 56-57 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा, कभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की।

कल यहां पर प्रतिपक्ष के सचेतक स्वच्छ भारत योजना फ्लॉप हो गयी, यह कहकर मजाक उड़ा रहे थे। मैं आज यह सवाल करना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान कोई झाड़ू लगाकर लोगों को तमाशा दिखाने का अभियान नहीं। भारत की सरकार के पास वह आंकड़े हैं कि 60 सालों में जो दुर्दशा इस हिंदुस्तान की गंदगी के लेवल पर कांग्रेस सरकारों ने कर दी, इस मुल्क का पैदा होता जीरो से पांच साल तक का दस लाख बच्चा गंदगी-जनित बीमारियों के कारण काल के मुंह में चला जा रहा था। भारत के प्रधान मंत्री ने लोकतंत्र के माथे पर उसको कलंक के रूप में स्वीकार किया और तय किया कि अब हम गंदगी से कोई बीमारी नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान में एक आंदोलन चला दिया। एक आंदोलन, सामाजिक बदलाव का आंदोलन, आज एक-एक आदमी सरकार का, एक-एक एस.पी., कलक्टर से लेकर निगमों के, यू.आई.टीज. के अधिकारी लगातार भाग रहे हैं उस आंदोलन में कि मुझे शौचालय बनाने हैं और 16 करोड़ शौचालय इस हिंदुस्तान की धरती पर बना दिये।

हम राजस्थान की परम्पराओं की बात करते हैं। महाराणा मेवाड़ की धरती के लोग हैं, पद्मिनी के जौहर को लेकर हमने सारे राजस्थान में ही नहीं, हिंदुस्तान में एक तहलका मचा दिया लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी यह विचार नहीं किया कि भारत के प्रधान मंत्री ने दूरस्थ गांव की उस महिला की चिंता की है जो सवेरे चार बजे और सूर्यास्त के बाद शौच के लिए जाती है और सड़क के किनारे कोई आदमी आ जाता है तो या तो बेशर्मी से बैठती है या खड़ी हो जाती है, उस मां, बहन की इज्जत आबरू की चिंता इस मुल्क में निचले लेवल तक अगर किसी ने की है तो वह भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की है। आंदोलन चला दिया, अभियान चला दिया कि अब लोकतंत्र के माथे पर दस लाख बच्चे गंदगी-जनित बीमारी से

(श्री प्रहलाद गुंजल)
मरते हैं, हम इस कलंक को धोएंगे और इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के बंधुओं से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी-कभी अपने शब्दों में संवेदनाएं लाओ, अपने व्यवहार में संवेदनाएं लाओ। इस सदन को मजाक का और राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। यह सदन केवल आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी हम यह तजवीज भी पैदा कर पाएंगे कि सदन में प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर राष्ट्रीय महत्व, सामाजिक हितों, आर्थिक हितों के मुद्दों पर सामाजिक और समानांतर चिंतन करके हम राजस्थान को यह संदेश देने का प्रयास करें कि आपने किसी को पक्ष में भेजा है, किसी को विपक्ष में भेजा है लेकिन दोनों लोगों की चिंता समान है, वह राजस्थान के हित में चिंता करना चाहते हैं। वह गांव और गरीब के हित में चिंता करना चाहते हैं। केवल हम विरोध के आचरण में खामी निकालें, हम केवल सत्ता-पक्ष पर विरोध में बैठे हैं इसलिए टिप्पणी करेंगे, यह नजरिया हमारा बन जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के इस आचरण को लेकर यह कहना चाहता हूं और अगर इसमें सत्ता पक्ष भी कहीं गड़बड़ी और खामी करता है, किसी न किसी लेवल पर हल्ला करने का प्रयास करता है तो सदन की इन परम्पराओं को, लोगों के विश्वास को जीवित रखने के लिए आसन को बाध्यकारी तरीके से रखना पड़ेगा ताकि यह सदन एक विश्वास का प्रतिबिंब बना रहे। यह सदन सर्वोच्च है, सरकार से भी ऊपर है। यह विश्वास का प्रतिबिंब अगर टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा।

मैं तो दूसरी बार एम.एल.ए. हूं और यह दसवां साल चल रहा है, जिस तरीके का अखाड़ा, विरोध के विरोध करना, कठघरे में खड़ा करना, व्यक्ति के शब्दों को मुद्दा बना लेना, व्यक्ति की बात को, व्यक्ति के स्लिप आफ टंग को भी इस सदन में अवसरों की तलाश करके कैसे हम उस पर अटैक करेंगे, कैसे इश्यूज को गेन करके हम काउंटर अटैक करेंगे?

यह गेन करने की, लीड करने की परम्परा और अटैकिंग परम्परा केवल राजनीतिक मत-भिन्नता के आधार पर मैंने इस सदन में देखी है, यह लोगों के विश्वास का अनादर है, अपमान है। हम सब लोग, सामुहिक रूप से, चाहे कोई व्यक्ति वहां बैठा है, चाहे व्यक्ति यहां बैठा है, चाहे कोई व्यक्ति बीच

(श्री प्रहलाद गुंजल)
में बैठा है, जिसको चुनकर भेजा है इस सदन में, उन सबकी सामुहिक जिम्मेवारी है और इसीलिये आज मैं कहना चाहता हूं स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने वाले लोगों से, और अधिक ऋण हो गया, उनका मजाक उड़ाने वाले लोगों से, भारत के प्रधान मंत्रीजी ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस लाख बच्चे मरते थे, कांग्रेस की सरकारों ने इंसान के स्वास्थ्य परीक्षण की चिन्ता नहीं की। आखिर हम बजट किसलिये लाते हैं? क्या हम कर्मचारियों की तनख्वाह देंगे, एक ऐसे आभा-मण्डल में सरकार पैसा खर्च करेगी जिसकी चकाचौंध में एम.एल.ए. बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सरकार बैठी है, प्रतिपक्ष बैठा है, इसके लिये बजट नहीं लाते। बजट लाते हैं राजस्थान के सामाजिक जीवन में बदलाव लाने के लिये, राजस्थान का ढांचागत विकास करने के लिये और इसलिये प्रधान मंत्रीजी ने 2022 तक राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान के किसान की आमदनी को दुगुना करने का जो संकल्प लिया है, वह तारीफे-काबिल है। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पायी कांग्रेस और इस मुल्क में भारत के प्रधान मंत्रीजी ने लोगों के जीवन में स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता लाने के लिये एक लाख मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं। हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य जांच कर इस बात के लिये जरूरी लवणीय किट का वितरण विभागीय आधार पर कराया है कि धरती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये किन-किन चीजों की आवश्यकता है, यह चिन्तन बीजेपी की सरकार ने किया है। यह चिन्तन हमारा था। कांग्रेस ने कभी विचार नहीं किया।

इसीलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि अगर कर्ज भी लेने की बात करते, तो फिर कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। मैं तो इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, न ही फाइनेंस को जानता हूं, लेकिन इस सदन में आने वाला कोई मुख्य मंत्री मुझे यह बता दे या वित्त मंत्री यह बता दे कि अब मौजूदा हालातों में कर्ज लिये बगैर कोई राज्य की व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित कर सकता है? कर्ज आज की जरूरत बन गया, लेकिन कर्ज से परिसम्पत्तियों का निर्माण करना, कर्ज से लोगों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक स्तर में बदलाव लाना, एक दूरदृष्टि के साथ काम करना, यह नजरिया जब तक नहीं होगा, इसका एक उदाहरण है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)
माननीय भैरोंसिंह शेखावत जी ने सबसे पहले प्लान बजट को बहुत बड़ा किया और 17 हजार करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का निर्माण किया। कांग्रेस ने भी कर्ज लिया। जब 2013 में सरकार संभाली तो मैंने राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का पहला बजट भाषण पढ़ा है जिसमें उन्होंने बहुत पीड़ा के साथ कहा और मैं कहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को पीड़ा व्यक्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अशोक गहलोत जाते समय 2013 के आम चुनावों में राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत-पत्र जारी करते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो यह 20 लोग गलती से भेजे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति चुनकर नहीं आता, राजस्थान में प्रतिपक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती। किन हालातों में ले गये।

आखिर हम राजस्थान के बारे में विचार नहीं करेंगे और इसीलिये मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बजट में कर्जा नहीं देखा जाना चाहिये, आर्थिक संतुलन बनाये रखने के लिये इस बात पर गौर जरूरी है कि जी.डी.पी. के अनुसार सरकार कितना खर्च कर रही है। धीमे पड़ने वाले स्थानों का पता लगाया जाए और देखा जाए कि खर्च उत्पादक निवेश के रूप में हो रहा है या लड्डू बंटाई हो रही है। वोटों की खरीद के लिये हो रहा है और मैं जब यह बात कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। राजस्थान की जनता के बजट को 2013-14 में उत्पादक निवेश के रूप में नहीं, खैरात बांटने के रूप में इस्तेमाल किया और यह अधिकार किसी सरकार को नहीं है। सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिये कि कोई सरकार केवल लास्ट के बजट में वोट पाने के लिये बजट को खैरात के रूप में बांट दें। क्या नहीं बंटा? साड़ियां बांटी गयीं। हम साड़ियां नहीं बांट रहे, घी के डिब्बे नहीं बांट रहे।...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आप बैठ जाइये। आपकी समझ के बाहर का विषय है यह।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसका भी जवाब दे देंगे, बैठ जाइये आप। इसीलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं किया, सत्ता पाने के लिये रेवड़ियां बांटी गयीं, धन लुटाया गया, जनता के पैसे को बहाया गया। और इसलिये बहाया गया...(व्यवधान)..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपसे तो मैं यह उम्मीद नहीं करता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपसे उम्मीद नहीं करता, आप मेरे मित्र हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि जिनके पास अपना कोई दूरगामी लक्ष्य नहीं होता, और राजस्थान के इंटरेस्ट में...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति से जो भी बोलें, वह अंकित नहीं होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): जिनके पास अपना दूरगामी लक्ष्य नहीं होता, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका एजेण्डा केवल वोट है, जिनका एजेण्डा पांच साल है, जिनका एजेण्डा एक दिन, एक महीना, एक साल है बजट में, पचास साल का दूरदृष्टि लक्ष्य नहीं है। आज हजारों साल का राजस्थान है। हम आज हैं, कल नहीं हैं। जिनका लक्ष्य हम आज हैं, कल भी हम आयें, यह लक्ष्य है और इस आधार पर जो रेवड़ियां बांटी गयीं, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान की जनता ने स्वयं उनको नकार दिया। साड़ी नहीं चाहिये, लड्डू नहीं चाहिये, घी नहीं चाहिये, रेवड़ी नहीं चाहिये, आत्म-सम्मान चाहिये और ढांचागत विकास की क्या कहानी कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 2008 से 2013 के बीच में, इसके पहले मैं रामगंजमण्डी का एम.एल.ए. हुआ करता था, इस बीच में मैं सदन का मैम्बर नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी। माननीय गहलोत जी मुख्य मंत्री के नाते हाड़ौती के दौरे पर

(श्री प्रहलाद गुंजल)
गये। आज भी रिकोर्डेड बात है, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्री, जिनको जाना था रामगंजमण्डी, जिनको जाना था सांगोद, सड़क मार्ग से रामगंजमण्डी नहीं जा सके, रामगंजमण्डी ट्रेन से गये कोटा, ट्रेन में आये और ट्रेन के बाद फिर बारां सड़क मार्ग से, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्ण चतुर्भुज योजना की सड़क बनायी, उस सड़क से जाना पड़ा वर्ना राज्य के मुख्य मंत्री अपने ढांचागत विकास का चेहरा, जो राजस्थान के सामने रख दिया था, नहीं जा पाये। वह ट्रेन से जा पाये। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सरकार का काम ढांचागत विकास और मैंने उसका एक आईना दिखाया है राजस्थान के मुख्य मंत्री सड़क मार्ग से अपने गन्तव्य स्थल तक नहीं जा सके, वैकल्पिक मार्ग ढूंढ़ने पड़े और वह वैकल्पिक मार्ग अटल बिहारी जी वाजपेयी ने इस मुल्क की सबसे बड़ी सड़क परियोजना, स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना के रूप में स्थापित की। मैं जब स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना की बात कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आप तो जानते हैं कि स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना इस मुल्क के आजादी के बाद की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। इस संसार की पांचवें नम्बर की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। कानपुर जैसे शहर में 14 किलोमीटर का एलीवेटेड रोड निकाल दिया। 2008 में वह पुल टूट गया और 2008 में यहां पर सरकार आपकी आ गयी, दिल्ली में मनमोहन सिंहजी की सरकार थी। 300 करोड़ का हैंगिग ब्रिज, जो टूट गया, बन नहीं पाया, 66,520 करोड़ रुपया जिस परियोजना पर अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार ने खर्च कर दिये, उस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित होने 8 साल का विलम्ब कर दिया। अभी प्रधान मंत्रीजी ने इस मुल्क को उदयपुर में आकर इस संसार की पांचवीं बड़ी योजना, भारत की आजादी के बाद की सबसे बड़ी परियोजना 77 हजार करोड़ की, जिस पर 66,520 करोड़ रुपये का व्यय हो गया, समर्पित किया। हैंगिग ब्रिज टूट गया। न परवाह मुख्य मंत्रीजी को थी, न परवाह वहां के स्वायत्त शासन मंत्री को थी, न प्रधान मंत्री को थी कि भारत की इतनी

(श्री प्रहलाद गुंजल)
बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना जनता को समर्पित की जानी चाहिये।

अटल जी को समर्पित की जानी चाहिए। यहां की सरकार तो उलझी रही, काहे में?

एक माननीय सदस्य: 000

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ठेकेदारों को बचाने में, मंत्रियों को बचाने में, मंत्रियों को उलझाने में, आज भी जेल में है, सरकार मदान्त थी। मैंने कई बार कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता लेकिन प्रतिपक्ष हवा में बात करता है तो मुझे पीड़ा होती है। मैंने राजस्थान के इतिहास में इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा, मैं इस सदन का मैम्बर नहीं था लेकिन मैंने अख़बार में पढ़ा कि काम के बदले अस्मत तक मांगी गयी, अस्मत तक मांगी गयी और हत्याओं के जुर्म में मंत्री ...(व्यवधान)... इसमें व्यस्त है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ईमानदारी से मैं सदन में कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का ढांचागत विकास नहीं किया, राजस्थान की उपेक्षा की। और इसलिए आज एक अपराधी के नाते अपराध बोध मन में स्वीकार कर के कांग्रेस को कठधरे में खड़ा महसूस करना चाहिए, हम राजस्थान के गुनाहगार हैं, अपराधी हैं। मैं कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

प्लीज, आप बोलते हैं जब मैं नहीं बोलता हूं, आप सुनिये। ...(व्यवधान)... कालू लाल जी बोलें जब आप बोलना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में लोकतंत्र आने के बाद केवल एक मात्र निवेशक और उत्पादक था जिसका नाम सरकार था। सरकार को निवेश करना, सरकार को प्रोडैक्टिविटी बढ़ाना। आज तो पीपीपी मोड चल पड़ा है और न जाने कितने असंख्य लोग हर क्षेत्र में आ गये हैं लेकिन जब एक मात्र निवेशक और उत्पादक सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस सरकार का चेहरा-मोहरा क्या बना रहा सार्वजनिक क्षेत्र में, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, जो पांच-सात चीज हमको राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता को समयबद्ध तरीके से दी जानी चाहिए थीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको गहन जानकारी है। अगर आज हम ईमानदारी से चर्चा करेंगे सड़क परिवहन,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चिकित्सा, शिक्षा पर, इतने लम्बे समय तक हुकूमत करने के बाद इसमें निजी क्षेत्र का दबदबा बन गया। आज आप जाइये, जयपुर में सेंट जेवियर के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी स्कूल का है? आप जाइये कोटा में, सेंट पॉल, सोफिया और मॉडर्न जैसे स्कूलों के बराबर का इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी स्कूल का है? निजी क्षेत्र के परिवहन में निजी क्षेत्र का दबदबा हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जयपुर में महावीर मिशन से लेकर अब जो नये-नये अस्पताल खुल रहे हैं, एक एस.एम.एस. को छोड़ दो, क्या किया आपने?

तमाम क्षेत्रों में आपकी बुनियादी सोच राजस्थान के लिए नहीं है और इसीलिए जब हमारा राज आया तो दोहरे स्तर पर, कि शिक्षा में नये मापदण्ड स्थापित करने के लिए एक स्वामी विवेकानन्द आदर्श विद्यालय खोला जाएगा, जिसका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूलों से ठीक होगा, सरकार ने कदम उठाये। कदम उठाये सरकार ने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना चाहिए। मुझे पीड़ा है सदन में दो साल पहले आजादी के 68-70 साल बाद कहा गया कि हम एस.एम.एस. में किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू कर रहे हैं। यह काम 48 साल, 50 साल लगातार राज करने वाली कांग्रेस के गैर-जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार के कारण नहीं हो सका। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आयी तो जोधपुर में एम्स खोला गया। आज जयपुर में 200 करोड़ की मल्टी सुपर स्पेशलिटी, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और कोटा में 600 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी सुपर स्पेशलिटी, देर आये दुरुस्त आये। यह हमारी स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है कि अब डिवीजन के मुख्यालयों पर राजस्थान के गरीब व्यक्ति को, गरीब मरीज को मल्टी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार इस सदन में कहा था, वो आंकड़ा मेरे पास से मिस कर गया है कि हिन्दुस्तान की आबादी का एक निश्चित हिस्सा इलाज कराते-कराते बी.पी.एल. हो जाता है, उसका घर बिक जाता है। उसकी किसने चिंता की? गहलोत जी ने मुफ्त दवा वितरण के नाम पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, मैं किसी एक आई.ए.एस. अफसर का नाम नहीं लेना चाहता, उस पूरी योजना का मालिक बना कर राजस्थान के गरीब, महरूम, बीमार व्यक्ति को किस तरीके से लावारिस हालत में छोड़ दिया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पहली बार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और अब इस बजट में 5 लाख रुपये तक, हम 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को दायरे में लाने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना आरम्भ करेंगे जिसके तहत द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख, अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये प्रति वर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जा सकता है, दिल्ली में बैठ कर नीचे की सोच।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज जरूरत किस बात की है। हमारे सामने मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है। मैं बजट के कुछ अंशों पर जाना चाहता हूं। राज्य में पिछले चार वर्षों में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र के नवीन सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। लम्बे समय से जनता की मांग को देखते हुए 52 हजार करोड़ लागत की निम्न परियोजना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 37 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली ई.आर.सी.पी. परियोजना, 6 हजार करोड़ की लागत वाली ब्राह्मणी-बनास योजना, 2 हजार करोड़ रुपये लागत की माही बांध से अपर योजना, 6 हजार करोड़ लागत की साबरमती बेसिन की योजना, हजारों करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि आखिर इस समस्या से हम निपटेंगे कैसे अगर हमारे पास कोई दूरगामी एजेंडा नहीं होगा, खेत पर हम रोजगार सृजित नहीं करेंगे। लगातार इस मुल्क में प्रति साल दो करोड़ व्यक्ति 18 साल की उम्र पार कर रहे हैं और राजस्थान का हिसाब लगाएंगे तो 9 लाख बच्चे प्रति वर्ष 18 साल की उम्र पार कर रहे हैं। हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे लगातार खेती पर कन्जूम हो जाते हैं, खप जाते हैं और हम 15-20 प्रतिशत को परम्परागत व्यवसायों में खपा हुआ मान लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि आखिर खेत पर रोजगार कैसे जनरेट किया जाए। यह सोच वाजपेयी जी के समय आयी, यह सोच इस बजट में नजर आ रही है। हिन्दुस्तान में किसान की ऐसी माली हालत हो गयी कि कभी हम भाषण किया करते थे ये देश किसानों का देश है, भारत की 80-82 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है, इस देश की आत्मा किसान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन जिम्मेदार है, समय इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बात का सवाल पूछ रहा है इस मुल्क की सारी व्यवस्था से। वो अपने आप किसी को कठघरे में खड़ा कर रहा है कि जिस मुल्क में कभी 80-82 प्रतिशत किसान हुआ करते थे आज उसकी संख्या घट कर 67 प्रतिशत रह गयी। अच्छा होता कि इस हिन्दुस्तान के किसान की संख्या 15 प्रतिशत घटती और आंकड़ा बढ़ता। भारत का किसान समृद्ध व्यापारी बन गया है, भारत का किसान समृद्ध, सम्पन्न अधिकारी बन गया है, उसका हर दृष्टि से आर्थिक उन्नयन हुआ है। जितनी आबादी किसानों की इस मुल्क में घटी है उतनी ही आबादी शहरों में मजदूरों की बढ़ी है। किसान ने खेती-किसानी को मजदूरी से भी खराब धंधा मान लिया।

अगर देश के यही हालात बने रहे तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कहां ले जाएंगे? कहीं न कहीं इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक सन्तुलन को मजबूत बनाने के लिए जरूरत के हिसाब से जगह पर रोजगार जनरेट करने के लिए अगर हमारे पास कोई दूरगामी लक्ष्य नहीं है, एजेंडा नहीं है, आखिर वाजपेयी जी ने यह कल्पनाएं यों ही कीं, दिल्ली में बैठ कर गांवों में सड़क दी, दिल्ली में बैठ कर गांवों में चिकित्सा सुविधाएं दीं, दिल्ली में बैठ कर वाजपेयी जी ने किसान के बारे में सोचा और इतनी बड़ी-बड़ी स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजनाएं, भारत के बारे में यह कल्पना, और उन्होंने सोचा नदियां जोड़ूंगा। नदियां जोड़ने की योजना के पीछे जो इस बजट में वसुन्धरा जी ने प्रदर्शित किया है, वाजपेयी जी की भावना में, वाजपेयी जी की भावना के केन्द्र में किसान था।

किसान की माली हालत का दृश्य हिन्दुस्तान पिछले 70 सालों से देख रहा है। आज भी बिहार में बाढ़ आती है तो लोग मर जाते हैं। आज भी असम में बाढ़ आती है तो लोग मर जाते हैं। राजस्थान में कई दिनों तक तो यह भी कहने लगे थे, मैं बहुत जूनियर सदस्य हूं इसलिए बहुत जोर से नहीं कहना चाहता, एक मुख्य मंत्रीजी का और अकाल का नाम जोड़ दिया। राजस्थान में अकाल से लोग मरते हैं। बिहार में बाढ़ से लोग मरते हैं। कभी किसी ने अकाल को, बाढ़ को, दोनों आपदाओं को अवसर में बदलने की कल्पना नहीं की। आपदा इस मुल्क में अवसर में कैसे बदले?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार जीतकर आया था तो मैंने इस सदन में कहा था कि राजस्थान में लगातार 80 के दशक से पहले अकाल पड़ा करते थे। यहां के सारे के सारे आईएएस आफिसर, ब्यूरोक्रेट्स अकाल के देवता की पूजा करते थे कि हम फेमिन का बजट बनाएंगे। फेमिन का बजट आएगा तो मालामाल हो जाएंगे। अगर 50 से लेकर 85 तक के फेमिन के बजट का हिसाब कांग्रेस पार्टी और यहां की सरकारों से मांग लो तो ढांचागत तरीके से एक नया राजस्थान बन जाए। इतने धन की तबाही, भ्रष्टाचार और बेइमानी इस राजस्थान में फेमिन के नाम पर हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, उस अकाल जैसी आपदा को जो कि अवसर बन जानी चाहिए थी। उसको अवसर में बदलने का काम वाजपेयी जी ने किया। बाढ़ का पानी अकाल में लाकर के छोडेंगे। बाढ़ और अकाल दोनों आपदाएं अवसर में बदलेंगी। इसी परिकल्पना के आधार पर नदियां जोड़ने की परियोजना प्रारंभ हुई। नदियां जोड़ने का ख्याल मन में आया। दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि यह मुल्क यूपीए 2004 के झांसे में आ गया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले सदस्य के डर के मारे विपक्ष तो सारा ही गायब हो गया यहां से।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): प्लीज, मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं खतम कर दूंगा 2 मिनट में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सोच वहां से प्रारंभ हुई कि हम अकाल और बाढ़ दोनों आपदाओं को अवसर में कैसे बदलें। इससे पहले 50 साल में इस प्रकार का चिंतन कभी प्रारंभ नहीं हुआ। वाजपेयी जी का चिंतन और उसकी झलक इस बजट में दिख रही है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि 10 लाख का मकान, 2 करोड़ का मकान या दुकान 2 महीनों में बनाकर के बता दो। अगर मुख्य मंत्रीजी ने कहा है तो हम 8 महीने में, यह 50 हजार, 1 लाख करोड़ की योजना है, इस राजस्थान के भविष्य को तय करने वाली योजना है, 2 साल, 5 साल लगेंगे तब धरातल पर उतरेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हिन्दुस्तान में प्रति वर्ष 2 करोड़ 18 साल से ज्यादा उम्र का नौजवान जनरेट हो रहा है, भारत के प्रधान मंत्रीजी ने यूं ही

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्किल डवलपमेंट नहीं चलाया। मैंने पिछली बार इस सदन में कहा है कि यूपीए के प्रधान मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री का देश की बढ़ती हुई नौजवान आबादी के बारे में नजरिया क्या है। मैंने कई बार मनमोहन सिंह जी का भाषण सुना है। इस मुल्क के नौजवानों को प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत के नौजवान को राष्ट्रीय समस्या बताने वाली यूपीए सरकार की तो विदाई कर दी। लेकिन एक सोच में बदलाव आया। नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि जवान को राष्ट्रीय समस्या नहीं एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में सृजित करेंगे। जिसकी मुट्ठी में रोजगार होगा उसमें एक आत्म विश्वास होगा। रोजगार वाला आत्म विश्वास होगा।

इस मुल्क का एक-एक व्यक्ति स्किल्ड बने। इस मुल्क का एक-एक व्यक्ति डवलप हो। इसके लिए स्किल डवलपमेंट की योजना बनाई। जो इंसान के हाथ में कौशल देगी और कौशल के हाथ में दौलत। जब स्किल्ड आदमी बाजार में निकलेगा तो रोजगार के अवसर स्वयं उसके पास चलकर के आएंगे। एक वृहत योजना बनायी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और स्टेट सरकार मिलकर के काम कर रही हैं। ऐसी योजनाएं बना रही हैं कि जो पचासों सालों से खेत और खलिहान उदास था, अब उसकी उदासी दूर होनी चाहिए। वह बेरोजगार जिसके चेहरे पर राष्ट्रीय समस्या का तमगा था, वह तमगा अब हटना चाहिए। इसके लिए प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एकाएक बिना प्रयासों के एक फल आकर के गिर गया। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ यह बिना प्रयास का फल झोली में गिरने से अभिमान के घुंघरू बंध गये कि हम तो सरकार में आ जाएंगे। अभिमान के घुंघरू बांधने वाले लोगों, अभी 8 महीने का समय है। सूत ना कपास और जुलाहे से लट्ठम-लट्ठा। समन्वय समिति बन रही है। रात को मिलने की बातें हो रही हैं। दिन में लड़ते हैं और रात में मिल लेंगे। यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपरा को हमने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया है। इस बैकअप अलार्म कॉल को

(श्री प्रहलाद गुंजल)
विनम्रता से स्वीकार किया है। काम करेंगे। जिम्मेदारी से काम करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। राजस्थान को आगे ले जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, स्किल डवलपमेंट के माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से कोई न कोई दूरगामी परिणाम राजस्थान के इंट्रेस्ट में आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि बेहतर बजट है, यह एक दिन, एक महीने, एक साल का बजट नहीं है। भविष्य का राजस्थान कैसा होना चाहिए, भविष्य के राजस्थान की चुनौतियों से लड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। प्रधान मंत्रीजी की दूर दृष्टि, वाजपेयी जी की दूर दृष्टि की झलक भी इसमें दिखाई दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक लंबी भर्तियों का आहवान, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। यह बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का बेरोजगार जो सरकारी भर्तियों के इंतजार में बैठा था, उसको एक उम्मीद जगी है। आपने खूब घोषणाएं की हैं। लेकिन एक तबका है, जिसके इतिहास की चर्चा मैं कभी एजुकेशन की डिमांड पर आऊंगा तब करूंगा, जो केवल दुनिया का मैला ढोने और सड़क की सफाई की नौकरी मांगता है उसकी भर्तियों का ऐलान नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि जब बजट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान भी निश्चित रूप से इस बजट में करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कई बार कहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में महाराव भीमसिंह चिकित्सालय है, जिसका इतिहास हाड़ौती का है। जिसके लिए लोग मन्नते मांगते हैं। जिसकी समृद्धि की दुआएं करते हैं। मैं हर बार कहता रहा हूं 474 स्वीकृत बैडों के अगेंस्ट में 670 बैड लगे हुए हैं। यह अस्पताल 1 हजार बैड की क्षमता का बनना चाहिए। इसमें 70 करोड़ का ओपीडी ब्लॉक बनना चाहिए। 30 करोड़ यहां बैड क्षमता बढ़ाने के लिए दिए जाने चाहिए। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि राज्य की मुख्य मंत्री जब बजट पर जवाब देंगी तो इसको समाहित करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि कालेजों में सैल्फ फाइनेन्स में से कई सब्जैक्टों को उन्होंने गवर्नमेंट फाइनेन्स में तब्दील कर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिया। लेकिन संस्कृत कालेजों के विषयों को इसमें नहीं जोड़ा है। बजट पर जवाब आए तो मैं उम्मीद करूंगा कि राज्य की मुख्य मंत्रीजी संस्कृत कालेजों के विषयों को भी सैल्फ फाइनेन्स स्कीम से मुक्त करके स्टेट फाइनेन्स के अधीन लेने की घोषणा करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर कालोनियों की भरमार है। मैंने कई दिनों से पीडब्लयूडी मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्रीजी को 164 करोड़ रुपये का नाली और सड़क का एस्टिमेट बनाकर के दिया हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि पीडब्लयूडी मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, दोनों भी मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करेंगे और बजट के जवाब में मेरे विधान सभा क्षेत्र की नालियां और सड़कों के लिए मुझे 164 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में एक महत्वपूर्ण बिन्दु आया है, उस पर मुझे अपनी बात कहने की आज्ञा प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन क्या है?

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 12 तारीख को मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए एक बड़े बांध की घोषणा की थी, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप पैरा बताओ। पैरा बताओ।

(15.00 बजे)

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा, उसके लिए पेयजल, सिंचाई व्यवस्था का ध्यान रखा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि बिखरी आबादी, बसावट को ध्यान में रखते हुए बड़े बांध की जगह दूसरे विकल्प...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो मजाक बन गया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पाइंट आफ इंफोर्मेशन की परिभाषा, परिधि और प्रकलन में नहीं आता। ...(व्यवधान)... आप अगर इसमें कोई विशेष पैरा में कोई बात ऐसी हो गयी है जिसको उल्लेखित करना चाहते हैं तो वह आप पाइंट आफ इंफोर्मेशन से बता दें। ...(व्यवधान)...

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): अनास बांध के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: कौनसा पैरा है, पैरा नम्बर बताइए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पैरा नम्बर 28.

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): मंत्री महोदय उसके बारे में बताएंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहे हैं?

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: सिंचाई मंत्रीजी या सिंचाई मंत्रीजी की जगह अगर कोई मंत्री इस पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहे तो?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना निवेदन किया उसके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुझसे बांसवाड़ा के, कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के अलावा, धन सिंहजी रावत मिले, पार्लियामेंट्री सचिव, भीमा भाई मिले, प्रभारी मंत्री, कटाराजी मिले, गोपीचन्दजी मीणा, इन लोगों ने हमें कहा कि पूरे बांसवाड़ा के इलाके में लोगों ने इस बात के लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया है कि बांसवाड़ा की जनता की पेयजल समस्या और सिंचाई के लिए उन्होंने चिंता के साथ में अनास बांध की घोषणा की है। परन्तु साथ में उन्होंने यह भी निवेदन किया कि बांसवाड़ा जिले की अलग ट्रोपोग्राफी है, ट्रोपोग्राफी अलग होने के साथ-साथ वहां पर ह्यूमन सैटलमेंट का पैटर्न भी डिफरेंट है। उन्होंन निवेदन किया कि इस ह्यूमन सैटलमेंट के अलग प्रकार का होने के कारण, वहां की ट्रोपोग्राफी अलग होने के कारण, एक स्ट्रक्चर की बजाय मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के द्वारा वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के माध्यम से पानी का कंजर्वेशन हो, सिंचाई के लिए पानी मिले और पीने के लिए पानी की

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

व्यवस्था की जाए। मैंने भी सोचा, मैंने भी जाकर मुख्य मंत्रीजी से बात की और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बांसवाड़ा में अनास बांध बनाने की बजाय 35 हजार हैक्टेयर जमीन को किस प्रकार से सिंचित किया जाए और बांसवाड़ा के लोगों को किस प्रकार से पेयजल दिया जाए, इन सारों की व्यवस्था करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड इर्रिगेशन टू द एरिया, बनाए जाएंगे और अनास बांध बनाने की जो योजना है, अनास बांध बनाने की योजना के बजाय वैकल्पिक रास्ते अख्तियार किए जाएंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री भीमा भाई (संसदीय सचिव): माननीय मंत्रीजी, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: उप सचेतक महोदय, यह पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन की कौनसी परिभाषा में आता है, जरा यह तो बताएं आप? आसन को इस बात को समझने में बड़ी मुश्किल आ रही है, हालांकि आपका कोई एक विशेष उल्लेख था, आपका एक विशेष उल्लेख है, एक विशेष उल्लेख, एक विशेष परिस्थिति और विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए आसन ने अनुमति प्रदान कर दी। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन का बहुत-बहुत आभारी हूं, हमारे सचेतकजी का भी कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस भावना के उद्वेग में आकर अपनी बात कही, बहुत सी बातें सारे सदन के सुनने लायक थी और अच्छी भी थीं। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे मन में कुछ दिन से यह बात आ रही है कि जिस प्रकार से पिछली बार मैंने गहलोत साहब का आखिरी बजट भाषण सुना था और हम प्रतिपक्ष में थे और हमने पूरे पांच साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, इसको सिद्ध करने में अपना समय लगाया। आज कांग्रेस पार्टी, बहुत कम लोग है लेकिन जितने भी लोग बोले हैं उन लोगों ने अपना सारा समय इस बात को सिद्ध

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करने में लगाया कि चार साल हमने बेकार कर दिये। मैं समझता हूं इन सब बातों को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि हमने एक राह पकड़ ली कि सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन सरकारों में बात करने का, विचार करने का तरीका वही रहता है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है, हमको समझना पड़ेगा आज हम किस स्थान पर खड़े हैं और राजस्थान को किस चीज की आवश्यकता है क्योंकि यह आय व्ययक की प्रथम स्टेज है, इस पर न तो पक्ष है न विपक्ष है, न तो समर्थन है न मतदान है, केवल अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा। मैं शेर से शुरू करना चाहता हूं कि अगर हम इसी प्रकार की बातें करते रहेंगे तो जनता क्या समझेगी। पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है, (सरकार जो बदली है),

पंछी यह समझते हैं कि चमन बदला है,
हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है,
श्मशान की खामोशी मगर कहती है,
है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है।

अगर अपन इसी प्रकार की बात करेंगे तो उसका इसी प्रकार का अर्थ निकलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं जब मैं यहां पर आज खड़ा हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि मैं उस राष्ट्र के उस राज्य में खड़ा हूं जिसको आज भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। हमारे प्रधान मंत्रीजी जब दावोस में गये थे तो ऑक्सफाम, जो संस्था है, उसकी रिपोर्ट में पहले भारत छठे नम्बर पर था, अब भारत आर्थिक रूप से विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम विश्व में पांचवें नम्बर पर है लेकिन इसके साथ-साथ कुछ प्रश्न भी हमारे सामने हैं। उन प्रश्नों को विचार करने का आज का समय है, वह प्रश्न जितनी मेरी समझ है उस समझ से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह भी स्पष्ट कर दूं क्योंकि कई बार यहां पर यह विषय चला कि वह लोक सभा है, यह विधान सभा है, आप लोक सभा की बात कर रहे हो, विधान सभा की बात करो। मैं निवेदन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
करना चाहूंगा कि लोक सभा और विधान सभा आर्थिक परिस्थिति भारत संघ की जो है, वह एक साथ जुड़ी हुयी है और जीएसटी के बाद तो और भी अधिक जुड़ गई है। जो भारत सरकार की आर्थिक स्थिति होती है उसका राज्य सरकार पर भी असर है और जो राज्य की स्थिति है उसका देश पर भी असर है। इसलिए कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वच्छता अभियान की और स्किल डवलपमेंट की जो चर्चा की है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिनका राज्य पर भी असर होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? अमेरिका की 32.33 करोड़ जनसंख्या है और 20252 बिलियन की उनकी इकोनोमी है और प्रति व्यक्ति जीडीपी में लगभग 40 लाख, चीन की 137.9 करोड़ जनसंख्या है, 13093 जीडीपी बिलियन्स में है और प्रति व्यक्ति जीडीपी में लगभग 6 लाख रुपये है। जापान का 12.7 करोड़ है, तीसरे नम्बर पर, 4999 बिलियन की उनकी इकोनोमी है और प्रति व्यक्ति लगभग 22 लाख रुपये उनकी स्थिति है। जर्मनी जो चौथे नम्बर पर है, 8.267 करोड़ उनकी जनसंख्या है, 3990 बिलियन उनकी इकोनोमी है और लगभग 30 लाख रुपये प्रति व्यक्ति का जीडीपी में उनका योगदान है। भारत 132.4 करोड़ है हमारी जनसंख्या, सिर्फ 5 करोड़ ही कम है चीन से, थोड़े दिनों बाद आगे निकल जाएंगे अपन, 2876 बिलियन की हमारी इकोनोमी है और लगभग 1 लाख 40 हजार प्रति व्यक्ति जीडीपी में हमारा योगदान है। यद्‌यपि हम पांचवें नम्बर पर हैं, लेकिन जो पहले नम्बर की, दूसरे नम्बर की, तीसरे नम्बर और चौथे नम्बर की जो इकोनोमी है, उनसे अभी हम बहुत पीछे हैं। इसलिए हमको प्रसन्नता इस बात की है कि हम विश्व के पांचवें नम्बर पर आ गये लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि जब तक प्रति व्यक्ति यह नहीं बढ़ेगा तब तक हम सही विकास की गति को प्राप्त नहीं कर सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की अगर आर्थिक स्थिति को देखें तो यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। पिछले साल की जो ऑक्सफाम ने रिपोर्ट दी, अति धनिक व्यक्ति 1 प्रतिशत, उनके पास में पिछली साल की कमाई का 73 प्रतिशत पैसा चला गया जीडीपी से और उनका 2099.84

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बिलियन उनकी कमाई हुई और प्रति व्यक्ति जीडीपी में 1.11 करोड़ उनका हिस्सा रहा। शेष जो 99 प्रतिशत व्यक्ति रहे उनके पास 27 परसेंट जीडीपी में उनका हिस्सा रहा 267.65 बिलियन रहा, 41468 रुपये प्रति व्यक्ति पिछले वर्ष उनको मिले। जो 50 प्रतिशत अति गरीब लोग हैं, 1 प्रतिशत उनका हिस्सा रहा,

और 3 हजार 41 रुपये प्रति वर्ष जीडीपी में हिस्सा रहा। हम सोने की चिड़िया तो वापस हो रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सोना कारपोरेट जगत के हाथ में आ गया और चिड़िया खेतों में उड़ाने के लिए हमारे पास रह गयी। यह हमारी आज आर्थिक स्थिति है और उस आर्थिक स्थिति में से हम राजस्थान और हिंदुस्तान के लोगों को लेकर आते हैं। एक बात इसमें यह भी समझने की है कि यह आर्थिक स्थिति चार साल में पैदा नहीं हुई। यह आर्थिक स्थिति जब से भारत आजाद हुआ है, तब से लेकर अब तक जो हमारी आर्थिक नीतियां रही हैं, उनका परिणाम हैं कि देश ने तरक्की तो की है, विकास तो किया है, देश पांचवे नंबर की अर्थ व्यवस्था तो बन गया है, लेकिन वह आम आदमी जो किसान, मजदूर और काम करने वाला आदमी है, उसको इसका पूरा हिस्सा नहीं मिला। उसको हिस्सा जब तक नहीं मिले, तब तक हम इसे लोकतंत्र में न्याय नहीं कह सकते, इसलिए आज हम सबको आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक छोटी-सी बात और कहता हूं। 2017 में भारत में 17 नये अरबपति हुए और खुशी है कि भारत में अरब और खरबपतियों की संख्या 101 हो गयी, गुलाबजी। इन 101 अरबपतियों की कुल संपत्ति में पिछले वर्ष 4 हजार 891 अरब रुपये की वृद्धि हुई, जो हमारे भारत के केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट की चिकित्सा और शिक्षा दोनों का 85 परसेंट के बराबर है। पिछले वर्ष भारत में जितनी भी संपत्ति पैदा हुई, उसका 73 प्रतिशत अति-धनिक 1 परसेंट के पास चला गया, जबकि 67 परसेंट के पास केवल 1 परसेंट आया। यह हमारी स्थिति है। पिछले 12 महीनों में 1 परसेंट अधिक जो लोग हैं, उनमें 20 हजार 993 अरब रुपये की संपत्ति बढ़ गयी, जो कि भारत सरकार के बजट के बराबर है। साल 2000 में 9 अरबपति थे, अब 2017 में 101 हो गए हैं। कपड़ा व्यवसाय में 50

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रतिशत लगे हुए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है और वर्ष 2014 में अति-धनिक की कुल संपदा 49 परसेंट थी, जो 2016 में बढ़कर 58 परसेंट हो गयी। इस आर्थिक असमानता का मुख्य कारण लोग मानते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म को। भारत को इस समय क्रोनी कैपिटलिज्म से निकालने की आवश्यकता है। मित्रतापूर्ण पूंजीवाद। यह चला कांग्रेस के टाइम से। जब उन्होंने कोटा, परमिट और लाइसेंस का काम किया, कि इनको कोटा देना है, इनको परमिट देना है, इनको लाइसेंस देना है और बाकी लोग इसका उत्पादन नहीं कर सकते। तो उस समय से कारपोरेट जगत का बढ़ना शुरू हुआ और आज भारत की अधिकांश संपदा कारपोरेट जगत के हाथ में चली गयी। मूल रूप से जो हमको लड़ाई लड़नी है, वह इस बात की लड़नी है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया, क्या वे स्वतंत्रता सेनानी इस बात के लिए लड़े, इस बात के लिए मरे, क्या आजादी इस बात के लिए प्राप्त हुई कि सारी संपदा जो इकट्ठा हो, वह कारपोरेट जगत के हाथ में चली जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो 68 परसेंट किसान है, उसके पास भारत की संपदा का टोटल 8.68 परसेंट है और इसलिए जब किसान की कर्ज माफी की मांग करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि किसान के लिए कर्ज माफी की अभी मांग करोगे तो बाद में क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो विद्वान हैं। आप जानते भी हैं कि हमारे यहां पर एक सम्वत् चलता है। विक्रम सम्वत् 2000 चलता है। वैसे यह कलयुग के तो 5000 साल के बाद का सम्वत् है। सृष्टि का भी सम्वत् है, लेकिन हमारे यहां सम्वत् की एक परंपरा रही है कि जो राजा तीन काम करे-

तेषाम एशाम सर्वत्रम घोषयत प्रचारयत....

वह यह घोषणा करे कि उसके राज में कोई ऋणी नहीं है और वह ऋणी को स्वयं राजकोष से पैसा देकर ऋण से मुक्त करे, वह भारत की सीमा को आगे बढ़ाये और जिसके राज में कोई अपराध नहीं हो।

(15.14 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस प्रकार के राजा को सम्वत् चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। 2,074 वर्ष पहले उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य सिंह हुए। उन्होंने शकों को मारकर हिंदुस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बाहर तक भगाया। तब उनको शकारी विक्रमादित्य कहा गया। उन्होंने सारे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटा कि कोई भी आदमी जो कर्जदार है, किसान है, वह राज में आए और राज उसका कर्जा चुकाएगा। उन्होंने सारे भारत को कर्ज मुक्त किया और उनके राज में पांच साल तक कोई अपराध की घटना घटित नहीं हुई, इसलिए उनका विक्रम संवत नाम से अभिषेक किया गया और विक्रम संवत चला।

अब 2,074 साल हो गये। 2,074 साल से भारतवर्ष के किसान और गरीब आदमी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई ऐसा व्यक्ति आए, कोई नेता आए, कोई मुख्य मंत्री आए, कोई प्रधान मंत्री आए, जो भारत के किसान को कर्ज मुक्त कर सके। इसकी वो बाट जोह रहा है। अगर इस कर्ज मुक्ति को देखें तो हमको राजस्थान के बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब राजस्थान के बजट में जाते हैं तो इसका आत्म-विश्लेषण करें कि आज हम कहां पर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2012-13 में राज छोड़ा। खूब घोषणाएं कीं। बीमा ले लो, इंश्योरेंस ले लो। यह ले लो, वह ले लो। सब बंट भी गये। लोगों ने ले भी लिए। सही-गलत जो भी हाथ में आए, ले लिए, लेकिन कांग्रेस को हरा दिया चुनाव में। हम जीतकर आ गये। हमने पांच साल में जो काम किया, उस काम को मैं स्पष्ट रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला काम था कि जब कांग्रेस छोड़कर गयी थी तो रिजर्व बैंक में हमारे 13 हजार करोड़ रुपये छोड़कर गयी थी खाते में। मुझे पूछा....हमारे मित्र भी थे.... कई लोग कहते हैं गहलोत साहब आपके मित्र हैं...मैंने कहा, हैं। तो पूछा मैं क्यों हारा, हमने कहा कि 13 हजार करोड़ छोड़कर क्यों गये, इसलिए हार गये। फिर भी नहीं बांट सके वो। योजना पूरी दिमाग में नहीं थी और अब हमारी क्या स्थिति है। अब हमारे पास रिजर्व बैंक में सिर्फ 24.50 करोड़ रुपये कल बैलेंस था। साढ़े 24 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार का रिजर्व बैंक में आज बैलेंस है। यह हमारी आर्थिक स्थिति है, इसलिए हम बड़ी-बड़ी बातें तो करें, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति का चिंतन भी करें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अब दूसरी आर्थिक स्थिति बताता हूं। हमने 2014-15 में संभाला। 3 हजार 215 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था। 2015-16 में आए तो 5 हजार 994 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। 2016-17 में आए तो 18 हजार 114 करोड़ का विद उदय हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था और विदाउट उदय 9 हजार 114 करोड़ था। 2017-18 में 20 हजार 165 करोड़ विद उदय था और 8 हजार 166 करोड़ विदाउट उदय था। 2018-19 का जो हमने आय-व्ययक अनुमान लगाया है, उसमें 17 हजार 554 करोड़ रुपया विद उदय और 5 हजार 454 करोड़ रुपया विदाउट उदय हमारा रहेगा....तो हम लगातार पांच साल तक रेवेन्यू डेफिसिट में रहे हैं और लगातार पांच साल तक कैपिटल अकाउंट में हमारी बचत हुई, जिससे हमने उसको पूरा करने की कोशिश की।

सभापति महोदय, यह तो अर्थशास्त्र का बहुत सीधा नियम है कि जब तक हम वित्तीय व्यवस्था को संतुलित नहीं कर सकें और उसमें रेवेन्यू का जो डेफिसिट है, उसे कैपिटल की बचत से अगर हम पूरा करते हैं तो वह अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं मानी जाती।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि the growth of state's own tax. हमारी जो टैक्स रेवेन्यू थी 2016-17 की, वह केवल 3.8 परसेंट as compared to previous year 2015-16. 2015-16 से ज्यादा हमारी केवल 3.8 परसेंट हमारी टैक्स रेवेन्यू बढ़ी, जबकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का एवरेज रेट हमारा कम से कम 18 से 20 का होना चाहिए। वह नहीं हुआ और हम टैक्स को वसूल करने में कम रहे, इसका क्या कारण रहा। मशीनरी में क्या लीकेज रहे या छूट दी गयी या कलेक्शन नहीं कर सके। इस बात पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं वित्त मंत्रीजी, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, उनसे आग्रह भी करूंगा वे सदन के सामने बताने का कष्ट करें कि टैक्स रेवेन्यू हमारी कम क्यों हुई?

दूसरी, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे यह है कि नोन-टैक्स रेवेन्यू स्टेट की कम होना, अपने आपमें बहुत बुरी बात है। नोन-टैक्स रेवेन्यू हमारी 2015 से डिक्लाइन हुई और 17.5 परसेंट कम हुई as compared to 2014-15. माननीय गृह मंत्रीजी, 2014-15 से 2015-16 में 17.5 परसेंट नोन-टैक्स रेवेन्यू का कम होना बहुत बड़ा लीकेज है। आप इतने बरसों से सदन में रहे हो, इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और इसके कारण माननीय मुख्य मंत्रीजी को सदन को अवगत कराना चाहिए कि राजस्थान में नोन टैक्स रेवेन्यू में टैक्स नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप जानते हैं कि यह माइंस का, रॉयल्टी का, सारे जो मामले हैं वो नोन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं और उसका कम होने का क्या कारण रहा, यह मेरे समझ में नहीं आता।

इसी प्रकार जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य प्रहलादजी गुंजल बता रहे थे, उन्होंने खूब स्टडी की है, मैंने भी की है कि बजट में 52 हजार करोड़ रुपये लगाये लेकिन बजट स्टडी का पेज 42 मेरे पास है, मैंने पढ़ा है और मैं आपको उसको पढ़कर सुनाऊं उसके बजाय बताना चाहता हूं कि उसमें हमारा सारा का सारा जो इसका खर्चा है, जो हमने बजट में प्रावधान किया है वो 17 हजार 827 करोड़ रुपये है टोटल ही। वैसे तो 4 हजार करोड़ ही है उसमें 2500 वेतन-भत्ते पर है। लेकिन इसके लिए हमने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसका न वित्त पोषण है, न इसकी वित्त व्यवस्था है। हां, यह भविष्य का बहुत सुन्दर खाका है, इसमें दो बात नहीं है। अगर यह योजना पूरी होती है तो राजस्थान का निश्चित रूप से विकास होगा। अगर ब्राह्मणी आकर बनास में मिलती है, बनास से पूरी पांचना में पानी आ जाता है, पांचना से रामगढ़ बांध में आ जाता है और यह पूरी परिक्रमा लग जाती है तो फिर तो कहना ही क्या है। इतनी बड़ी योजना तो भविष्य का खाका है लेकिन भविष्य के खाके का वित्त पोषण नहीं है, इसमें यह भी नहीं है कि डीपीआर कब बनेगी। यह जरूर ईमानदारी से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि इनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको दूर करने के बाद में इस काम को हम चालू करेंगे। लगता तो ऐसा है जैसे अगस्त में ही पूरा हो जाएगा लेकिन इसकी पर्यावरण की मंजूरी आएगी, इसकी वन विभाग की मंजूरी आएगी, इसकी डीपीआर बनेगी, इसका वित्त पोषण होगा और यह काम 14 से 20 वर्ष का है। 6 साल तो ब्राह्मणी को सुनते-सुनते हो गये, क्योंकि ब्राह्मणी में मेरा इंटरेस्ट है।

श्री सभापति: वो ब्राह्मणी दूसरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मेरा इंटरेस्ट है, घर का ही काम है न। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें यह स्थिति है। दूसरी जो बात मैं सबसे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं, इनके भाषण मैंने बहुत सुने हैं। आप देखिये कि हमारे पास 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया और इतनी परिसम्पत्तियां नहीं बनीं ईमानदारी से और अब हमारी कर्जे की लिमिट हो गयी है। अगले वित्त वर्ष में हम 25 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते तो हम राज्य की जनता को यह भी नहीं कह सकते कि हम कर्जा लेकर यह काम कर लेंगे। यह जो आपका डाकूमेंट है, 31.03.2019 को, एन इंडिकेटेड एज पेज 8, 8वें नम्बर पर जो सारगर्भित डाकूमेंट मेरे पास है उसमें है कि हम 25 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते और 3 लाख 8 हजार 33 करोड़ रुपये का हमारे पास कर्जा हो गया है तो राज्य कर्जे के चरम पर पहुंचा हुआ है। राज्य रेवेन्यू डेफिसिट में है और राज्य का जो रिजर्व बैंक में कोष है वह कम है। इन परिस्थितियों में हमको काम करना है। ये दोनों कागज मेरे पास हैं और उन पर मैं ज्यादा समय अब नहीं लगाना चाहता।

माननीय सभापति महोदय, हमको एक बात यह भी देखनी पड़ेगी कि देश की स्थिति का भी हमारे पर असर पड़ता है, केवल राज्य की स्थिति से काम नहीं चलता। जो सबसे बड़ा काम है कृषि की विकास दर का वो कृषि की विकास दर कम हो रही है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो अभी बजट स्टडी पार्लियामेंट में पेश की गयी है। 1991 से 1996 के बीच में 2.4 परसेंट थी, 1998 से 2004 के बीच में 2.9 परसेंट थी, 2005 से 2014 के बीच में 3.7 परसेंट थी और 2014 से लेकर 2018 के बीच में 1.9 परसेंट आ गई। यह कृषि की जो विकास दर गिरी है इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान है और राष्ट्र को भी बहुत बड़ा नुकसान है।

सभापति महोदय, रजिस्टर्ड बेरोजगार 4.5 करोड़ देश भर में हो गये हैं और 20 लाख राजस्थान में हैं। इधर खेती में बेरोजगारी, उत्पादन कम और इधर बेरोजगारों की बढ़ती संख्या, यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिस चुनौती को स्वीकार करके हमको लड़ाई लड़नी है। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने भूल से एक दिन एक पर्ची लगा दी थी और वो निकल गयी। मैंने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि आज मैं कई दुकानें जो बेरोजगारों के नाम से चलती है वो बन्द कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूंगा। दुकान तो हुजूर बन्द कर दो, पर अपना डिपार्टमेंटल स्टोर तो संभाल कर रखो कि उस डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या हो रहा है। अब मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण बताता हूं और यह भारत सरकार का है, मेरा नहीं है। इसको आप www.aajtak.in में देखें जो भारत सरकार की वेबसाइट से आया है। राजस्थान सरकार ने साढ़े 13 लाख लोगों को स्किल डवलपमेंट में ट्रेंड किया है लेकिन भारत सरकार की वेबसाइट में आया है कि किस-किस राज्य ने कितना-कितना डवलपमेंट किया और उसमें कितने को रोजगार मिला। उसमें तमिलनाडु सबसे आगे रहा, उसने 72186 को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश में 66849 मध्य प्रदेश 44836 और राजस्थान में 43986 को रोजगार दिया। तो ट्रेंनिंग का मतलब रोजगार नहीं है। यह सही है कि हमने कौशल विकास में, स्किल डवलपमेंट में साढ़े 13 लाख लोगों को ट्रेंड कर दिया लेकिन उन ट्रेंड में से सब के सब काम पर लगे ऐसा नहीं है। उन ट्रेंड में जो काम पर लगे हैं वो भारत सरकार की वेबसाइट पर है और राष्ट्र का एवरेज 20 परसेंट का है। खुद के धन्धे में लगे होंगे, प्राइवेट में लगे होंगे लेकिन जो वेबसाइट पर लिखा है वो लिखा है।

सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि देश का हैल्थ बजट, उसमें राज्यों का भी शामिल है, प्रति व्यक्ति 92.33 रुपये खर्च करते हैं और 2018-19 का सारा हैल्थ का बजट भारत का, सारी राज्य सरकारों का 58 हजार करोड़ का था और प्राइवेट हैल्थ केयर का बजट 7 लाख करोड़ का है। टोटल 19 हजार हॉस्पिटल सरकार के हैं और 10 लाख 22 हजार 859 रजिस्टर्ड एलोपैथी डाक्टर हैं उनमें सरकारी अस्पतालों में केवल एक लाख 13 हजार 328 डाक्टर हैं। हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी सारी व्यवस्था आज प्राइवेट सैक्टर के हाथ में चली गयी है। 85 परसेंट हायर एजुकेशन प्राइवेट सैक्टर के हाथ है, 85 परसेंट से अधिक चिकित्सा व्यवस्था प्राइवेट सैक्टर के हाथ में हैं और फिर हम योजनाएं चलाते हैं। अब योजनाओं के कारण से हम देश का, राज्य का भला करना चाहते हैं, लेकिन यह चिंता की बात है कि अगर शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन जैसे सारे के सारे काम प्राइवेट सैक्टर में जा रहे हैं तो लोक कल्याणकारी सरकार की कल्पना क्या है। ये प्राइवेट सैक्टर में जा रहे हैं इसलिए प्राइवेट सैक्टर का जो कार्पोरेट जगत है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
वो आज हमारा सारा का सारा काम कर रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ तब एक शख्स श्री योगीराज अरविंद, जो लोकमान्य तिलक के साथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। उनको जब पूछा कि साहब, डैमोक्रेसी का भारत या विश्व में राज करने का सबसे बड़ा तरीका है तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो वर्तमान में चल रहा है उनमें अच्छा है। तब कहा कि क्या होगा तो उन्होंने कहा कि डैमोक्रेसी में दो चीज खतरनाक है। एक तो प्लूटोक्रेसी और एक पार्बोक्रेसी। फिर उन्होंने उसका अर्थ किया कि प्लूटोक्रेसी का अर्थ है धूर्त और धनवान लोगों का शासन। डैमोक्रेसी में जब धूर्त और धनवान लोग पैसे के बल पर, सम्प्रदाय के बल पर, जाति के बल पर राज में आ जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। आज यह जो कार्पोरेट जगत है वह जिस प्रकार से राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है और जिस प्रकार की पकड़ रख रखा है वो बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दूसरा, उन्होंने कहा पार्बोक्रेसी क्या है तो उन्होंने कहा कि पार्टी बोसेज का राज। जो पार्टी का बोस हो गया वो ही टिकट बांटेगा, वो ही पदाधिकारी बनाएगा, वो ही राज चलाएगा।

तो डैमोक्रेसी के दो सबसे बड़े दुश्मन, प्लूटोक्रेसी और पार्बोक्रेसी, आज हमारे इस लोकतंत्र को ग्रहण लगाने के लिए खड़े हैं। यह भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमको स्वीकार करना पड़ेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक चीज से राजस्थान की जनता को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, वह है कर्ज माफी। किसान का कर्ज माफ करने की घोषणा की, इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन कितना किया? करीब 80,000 करोड़ रुपया राजस्थान के किसान पर टोटल कर्जा है। इस 80,000 करोड़ रुपये में से 8,000 करोड़ हमने माफ करने की घोषणा की और 2,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। अब यह 8,000 करोड़ का किया है तो मतलब 10 परसेंट का किया है और 10 परसेंट का किया है, वह भी को-ऑपरेटिव बैंक्स में। उसमें कामर्शियल और बाकी बैंक्स नहीं हैं तो एक तरह से विवाद होगा। फिर हमने इसमें लगा दिया छोटा, लघु और सीमान्त कृषक। इसको तो ज्योंही पटवारी के पास

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
जाएगा, आपके पास 40 बीघा जमीन है और तीन भाई घर में काम कर रहे हैं तो वह उनको कभी भी लघु और सीमान्त लिखेगा ही नहीं और यह समस्या हमारे सामने और अधिक बड़ी आएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि टोटल जितना, 50,000 रुपये तक का ही करो, लेकिन सारे जो भी किसान हैं, उनका माफ करने की कार्यवाही आप प्रारम्भ तो करो, ताकि किसान को एक राहत की सांस तो मिल सके। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

दूसरा माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो रिफाइनरी का मामला है। (व्यवधान) बीजेपी ने, सबसे पहले भैरोंसिंह जी शेखावत ने किया। उसके बाद में अब हम करने की घोषणा कर रहे हैं। भारत सरकार ने चिदम्बरम के टाइम पर 1,79,000 करोड़ रुपये का किया। यू.पी. की सरकार ने किया। महाराष्ट्र की सरकार ने किया। बीजेपी की सरकारें हैं। उनका अनुसरण करिये और उसके हिसाब से अपन भी कर देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार ने आज तक नहीं किया। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ने किया, कांग्रेस अनुकरण कर रही है, यह गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, नहीं किया। कांग्रेस ने तो नहीं किया...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांग्रेस ने नहीं किया। उसका भोग लिया उन्होंने।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने कहा है ना रिफाइनरी के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कुछ किया क्या आपने? एक पैसा भी माफ किया क्या आपने?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस तो किसान की दुश्मन है। किसानों को बर्बाद ही कांग्रेस ने किया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): राजस्थान में जो भी हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): किसान के प्रति तो कोई सहानुभूति है ही नहीं कांग्रेस की। बर्बाद कर दिया है किसानों को तो।

श्री सभापति: विराजिये। अच्छा, विराजिये। आप बैठें, बैठें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कांग्रेस ने ही 72,000 करोड़ रुपये माफ किये हैं। अब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं किसान की? किस मुंह से बात करने लायक हैं आप किसान की? आप क्या बात कर रहे हैं? 72,000 करोड़ रुपये किसने माफ किये?

श्री सभापति: विराजिये विराजिये विराजिये। विराजें। विराजें। माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने किये?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): राजस्थान ने माफ किया है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मंत्री महोदय, हिन्दुस्तान में किया है। आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आज किसानों को मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे रही है। कांग्रेस ने 70 साल में से 55 साल के राज में एक रुपया नहीं दिया आज तक। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप आंकड़ा ले आओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांग्रेस पार्टी अगर करती तो उनकी यह स्थिति क्यों होती? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, यह बात सही है। जो बात यथार्थ है, कांग्रेस ने तो किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। यह तो शुरूआत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। सबसे पहले हरियाणा में चौधरी देवीलालजी ने शुरूआत की...

श्री सभापति: कृपया शांत रहे। कृपया शांति से सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उसके बाद में स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने राजस्थान में किया और उसके बाद में किसानों के बारे में तो, सही बात है चिंतन की धारा ही वहीं से निकली है। वर्ना न तो अन्त्योदय था, न कोई काम के बदले अनाज था, न गांवों के विकास की बात थी। वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
तो विकास की गति उन्होंने ही दी, इसलिए उनके प्रति तो हम सबको श्रद्धावनत रहना ही चाहिए।

अब मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो यथार्थ है वह यथार्थ है। जो बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि 40,000 करोड़ रुपये का हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है रिफाइनरी का, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें मैं दो बात क्लियर करना चाहता हूं। राज्य की जनता का भ्रम मिटना चाहिए। जब राज जा रहा था गहलोत साहब का, तो पश्चिम में सूर्य उगा दिया। बड़े-बडे पोस्टर, विज्ञापन आये। पश्चिम में सूर्य उगेगा। मैंने कहा, यह पूरब में उगता है, यह पश्चिम में अस्त होता है, उग कहां से आएगा? इन्होंने उगा दिया। फैक्ट्री का शिलान्यास करा दिया। रिफाइनरी बनेगी, एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और चार साल में पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार आई। सरकार आने के बाद में कमेटी बनी माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया की अध्यक्षता में, कि छह महीने में जो भी इन्होंने काम किये गलत-सही, उनको देखकर, उनका गुणावगुण से विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करके उसमें अच्छे काम हैं उनको करेंगे और जो गलत काम है, उनको रोक देंगे। कई रोक दिये, कई चालू हो गये। (व्यवधान) मैं किससे रुकता हूं? मुझे कोई रोकने का गम भी नहीं है और इससे ज्यादा भी रोक दे तो मुझे कोई समस्या नहीं है। इसमें रोकने में गुलाबजी कहां से आ गये? (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनें सुनें, सुनें। कृपया डिस्टर्ब नहीं प्लीज, माननीय सदस्य। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे कहीं नहीं रोका। मैं यहां खड़ा हूं। साहब, इनके ये तकलीफ है। ये देखते हैं कि घनश्याम जो है, इनके और इनके लड़ाई करा दो। मेरी लड़ाई सिर्फ एक स्थान से है, वह भी व्यक्तिगत नहीं है। बाकी किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। भ्रम में मत रहना आप लोग। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, वह एक जगह से है। उसमें भी कोई व्यक्तिगत लड़ाई मेरी है नहीं।

तो मैं बात कह रहा हूं रिफाइनरी के बारे में श्वेतपत्र जारी होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था और हमने क्या किया? उन्होंने गलत किया था तो जनता के सामने आना चाहिए और मुझे दु:ख है, सदन में आकर बोलना

चाहिए। सदन में आकर माननीय पूर्व मुख्य मंत्री हैं, उनको कहना चाहिए कि हमने यह किया था रिफाइनरी में और यह-यह हमारा फायदा था, आपने चार साल इसको क्यों रोका? यथार्थ है तो कहना चाहिए और हमको यथार्थ रूप से एक श्वेतपत्र जारी करना चाहिए कि हमने अगर गलत रोकी है तो हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने गलत किया तो वह जिम्मेदार है लेकिन राजस्थान की जनता को टेकन फार ग्रांटेड नहीं ले सकते आप। 7.5 करोड़ लोगों का इससे इंट्रेस्ट जुड़ा हुआ था। अगर उन्होंने सही किया था तो साढ़े चार साल रोका क्यों? और गलत किया था तो इसका श्वेतपत्र जारी करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी राजस्थान की जनता कर सके। यह किसी को अधिकार नहीं होगा माननीय सभापति महोदय, कि कोई आकर कुछ बात करे और इस प्रकार की बात करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका श्वेतपत्र जारी हो।

अब मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा। तीन कानूनों का मैंने विरोध किया। मैं आज भी उनके विरोध में हूं लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं हूं। मैंने एक मामला उठाया कि काला कानून, अब सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इमरजेंसी में काम करने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी मानने की अपनी अधिसूचना जारी कर दी। पर वह लोकतंत्र सेनानी लड़ेगा किसके खिलाफ? मीसा, डीआईआर के खिलाफ जो इनको जेलों में पकड़-पकड़कर ले गये थे। वे लोकतंत्र सेनानी वाले काला कानून पास करे और फिर जवाब दे कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने तो पास कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने तो आपातकाल भी लगाया था। इसलिए इस काले कानून के लिए जिद नहीं करनी चाहिए और इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। इसको प्रवर समिति में भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। अब जब ये प्रवर समिति में जाएगा, तो छह महीने बाद प्रवर समिति आएगी, फिर चुनाव के तीन महीने बचेंगे। आप इसको कर तो पायेंगे नहीं। कर नहीं पायेंगे, फिर इस इल्जाम को अपने सिर पर लेकर क्यों ढो रहे हो? एक बार मैंने गलती कर ली, तो उसके लिए सौ बार गलती करूं, यह जरूरी नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप तो बहुत विद्वान आदमी हो। यह कानून एग्जिस्ट कर रहा है क्या? आज एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो कानून तो अपने आप ही ले लिया। अब अगर सलैक्ट कमेटी चाहेगी, नये रूप में लेकर आएगी तो आपके सामने आएंगे। अभी तो आज की तारीख में यह काला कानून है ही नहीं लेकिन वह झेंप मिटाने के लिए बार-बार, बार-बार काला कानून, आज कहां एग्जिस्ट कर रहा है? काला कानून तो वैसे ही खतम हो गया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह जो कानून का प्रारूप था, गुलाबजी को तो खड़ा होना ही था। आज राजेन्द्रजी नहीं हैं, वर्ना दो होते। इनकी ड्यूटी है। हम फुटबाल का खेल खेलते हैं ना, तो कोई फारवर्ड खेलता है, कोई सेन्टर फारवर्ड खेलता है, इसको आप चैक करना, इसको आप चैक करना तो, मुझे आप चैक कई वर्षों से करते आ रहे हो। आपने चैक कर ली। क्यारी काट ली आपने। आप तो फारवर्ड हो लेकिन मैं तो फुल बैक हूं। इसलिए पैनल्टी शूट करने का और इनका मुझे अच्छी तरह से आता है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उस कानून को अपने को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह झूठी शान के कारण से अपनी प्रवर समिति को भेजा है, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है।

दूसरी जो बात मैंने की, उसमें भी कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है। मैंने एक बात कही कि यह ईयर मार्क मकान होना चाहिए। आठ नम्बर, सिविल लाइन्स, मुख्य मंत्री निवास है...

या 13 नम्बर सिविल लाइन्स है, आप 13 नम्बर को डिक्लेयर कर दें और मुख्य मंत्री आराम से रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 8 नम्बर भी है और 13 नम्बर भी है, फिर कानून में प्रावधान करें कि एक बार मुख्य मंत्री रहने के बाद में आजन्म उसी मकान में रहेगा। चाहे वो प्रधान मंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, उप राष्ट्रपति बन जाए, राज्यपाल बन जाए, किसी पद पर चला जाए, वह बंगला उसके पास रहेगा सिविल लाइन्स में, उसमें न गहलोत साहब बोल रहे हैं, न कांग्रेस बोल रही है, क्योंकि जब पहाड़िया साहब भी विराजमान, गहलोत साहब भी विराजमान हैं और हम भी विराजमान होने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एतराज कर रहे हैं, बन जाने वाले, वो भी नहीं करते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे बना दीजिए, फिर भी मैं नहीं करूंगा, मैं गारन्टी लिख देता हूं आपको। मेरी गारन्टी है, मुझे बना दो और मैं पहले दिन ही कानून खतम कर दूंगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कभी भी बन जाओ, तो उसके बाद आप ऐसी बहस कर लेना, आज क्या जरूरत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलो साहब, मैं यह कह देता हूं कि जब मैं बनूंगा तो इस कानून को खतम कर दूंगा। 13 नम्बर का जो उठाया, उसी प्रकार मैंने उठाया एस.आई.आर. बिल, स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन बिल और मैं चाहूंगा कि सरकार पुनर्विचार करके किसानों के हित में इस बिल को समाप्त कर दे। इससे अभी तक एक पैसा आपके आया नहीं है, आएगा भी नहीं और 8 महीने में कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बिना मतलब अपने सिर पर बोझ क्यों ले रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस काले कानून को आप समाप्त करें, समय ज्यादा हो गया।

एक बात मैं कहना चाहता हूं पी.पी.पी. मोड पर, फिर वो कटारिया कमेटी। हमारे यहां साहब, कोई काम उलझ जाए न, उसमें कटारिया कमेटी और वह कटारिया कमेटी ऐसी है, वो देखते हैं कि इनके सामने कोई कहेगा भी नहीं, कोई डांटेगा भी नहीं, इन्होंने एक अपनी इमेज बना रखी है। मैं तो वैसा ही करूंगा तो कटारिया कमेटी के पास भेज दिया अब कटारिया कमेटी विधान सभा तक तो फैसला नहीं करेगी। हां, विधान सभा के बाद क्या फैसला करें, वो कटारिया कमेटी को पता ही नहीं रहेगा, वो फैसला हो जाएगा और कटारिया कमेटी को पता ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि पी.पी.पी. मोड कम से कम सरकारी स्कूलों को बिलकुल नहीं और हास्पिटल को भी नहीं दें। चिकित्सा मंत्रीजी, बन्द कर दें उचित नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा में बहुत पीछे हैं वैसे भी, शिक्षा और चिकित्सा सरकार के पास रहनी चाहिए, परिवहन भी सरकार के पास रहना चाहिए। हमारी जिम्मेदारियां, विश्व का कोई भी परिवहन फायदे में नहीं है। सभापति महोदय, दुनियाभर का एक भी परिवहन फायदे में नहीं है, आपने कहा कि जयपुर में सौ इलैक्ट्रिक बसें चला देंगे, जयपुर में जब तक सीतापुरा से लेकर चांदपोल तक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
का सैकिण्ड फेज मैट्रो का नहीं बनेगा, तब तक जयपुर का बोझ कम नहीं होगा, इससे आंख चुराने की कोशिश मत करिये। वो आपको करना पड़ेगा। एक अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है, अन्नपूर्णा पार्वती माता का नाम...

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे।
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वति।।

हम जब खाना खाते हैं तो यह मंत्र बोलते हैं। हे पार्वती माता, हमको भिक्षा दे और वह किस चीज के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए, ज्ञान मिले और वैराग्य मिले, अर्जन नहीं। यह अन्नपूर्णा रसोई, इसमें नाश्ता 21 का, लन्च और डिनर 23 के, इसमें 16 और 15 सरकार की सब्सिडी है, और बढ़ा दी है। 2 संस्थाएं हैं, एक जैन समाज की संस्था है, जो 10 रुपये में बहुत बढ़िया खाना सबको खिलाती है और एक अक्षय पात्र वाले हैं, वे खिलाते हैं। ये अन्नपूर्णा रसोई जो है न, किसी समय जांच होगी न, तो बड़ा लगेगा इसमें, मैं अब सावचेत करना चाहता हूं इसके अन्दर बू आ रही है, इसलिए इस अन्नपूर्णा रसोई के बारे में इशारा करिये, टैण्डर करिये और ये जो प्राइवेट संस्थान है, जो सेवा भाव से काम करने वाले लोग है, इनको भी अलाउ करिये, ये केवल बिजनिस मैन के लिए नहीं है, इसलिए इसमें जो इतना बड़ा घपला है, दो चीजों में एक तो....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): लोग दुआएं दे रहे हैं इस अन्नपूर्णा रसोई को, कितने लोग खा रहे हैं खाना आप पूछो। वसुन्धराजी को दुआएं दे रहे हैं 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में फाइव स्टार होटल जैसा खाना मिल रहा है, कोई शिकायत नहीं इसकी अभी तक।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अन्नपूर्णा योजना से गरीब आदमी को जिस तरह से सस्ता खाना मिल रहा है। मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान में तो इतना सस्ता और है नहीं, आप उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। आपको उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको तो बडाई करनी चाहिए कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना चालू की है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, अभी हरियाणा, गुजरात कई राज्यों की सरकारें, इस योजना को

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

देखने के लिए आ रही है, उन्होंने भी लागू की है, उससे भी अन्दाजा आप लगा सकते हो कि यह योजना हिन्दुस्तान की सबसे सफलतम योजना है। सस्ता भोजन, मैं कहता हूं हिन्दुस्तान में किसी राज्य ने नहीं किया होगा, पहला राजस्थान राज्य है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, सस्ता भोजन मिल रहा है गरीब को और वह दुआ देगा, यह भी ठीक है लेकिन उसके पीछे जो सरकार की सब्सिडी जा रही है वो भी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि 10 रुपये में जब अक्षय पात्र देता है। हस्तीमल जैन स्मृति संस्थान लोगों को दे रहा है, चाहे जितना और वे देने के लिए तैयार भी हैं तो उनको भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। दो चीजों की जांच होगी जरूर, एक तो सैनेटरी नैपकिन का, जिस प्रकार से आपने बजट में अभी घोषणा की है और काम पहले ही कर दिया और किन लोगों को दिया, सब जानते हैं उनके नाम, सबको पता, मेरे से मत कहलाओ इन बातों को, मैं उन मित्रों की बात नहीं खोलना चाहता हूं। इसी प्रकार अन्नपूर्णा पर विचार कर लें, यह बहुत बढ़िया है, गरीब को मिल रहा है, गरीब की दुआएं मिल रही है, गरीब की आपको और दुआएं मिले, भगवान करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके पीछे जो सब्सिडी जा रही है, वो कोई दूसरी संस्था अगर इससे कम रुपये में करती है तो उससे कराने में कोई आपत्ति की बात नहीं, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं अभी खतम करता हूं, साहब। बजरी के बारे में भी बात करना चाहूंगा, बजरी का बहुत बड़ा संकट जयपुर में है। जयपुर में सारे काम ठप्प हो गये हैं। जयपुर में जो सारे विकास और कंस्ट्रक्शन के काम थे और इसकी सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे सुबह-सुबह चौखटी लगती है, साहब। हजार-हजार, पांच-पांच सौ मजदूर जयपुर में कई जगह खड़े रहते हैं। उनको लोग रोज काम कराने के लिए ले जाते थे, अब आजकल उनके काम का करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, वो ठाले बैठे रहते हैं 12 बजे तक, और फिर वो कहते है पचास में ले जाओ, सौ रुपये में ले जाओ, डेढ़ सौ रुपये में ले जाओ, तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
उससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है, इस बजरी का करे...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह भी बता दें कि यह पाप शुरू किसने किया था, कहां से इसकी शुरूआत हुई थी, यह तो कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस पाप का तो लम्बा इतिहास है, इस पाप को मेरे से मत खुलवाओ, अगर यह पाप खुलेगा तो इसमें कई लोग जाएंगे और यह खुल भी जाएगा, खुद ही खुल रहे हैं, इसलिए पाप तो इसमें कई जगह हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बजरी की कमी है। विकास के काम को इफैक्ट कर रही है, गरीबों को इफैक्ट कर रही है, काम धन्धा बन्द हो रहा है, राजस्थान के सारे काम रूक रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके, इस बजरी में जो सारा का सारा है, उसको समाप्त करें। मैं सभापति महोदय, आप मुझे कह रहे हैं, तो मैं खतम कर देता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जैन समाज के बहुत लोग, मुनि तरुण सागर जी महाराज भी आये थे, मैं उनका शिष्य भी हूं वे हमारे घर भी रुके थे, मेरा यह सौभाग्य है। बाड़ा पदमपुरा जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, हमारा सबका भी तीर्थ स्थान है, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट में उसके चारों तरफ का एक्वायर कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट इधर भी हो सकता है, थोड़ा उधर भी हो सकता है। आप इतने बड़े तीर्थ स्थान के लिए, इतनी बड़ी जिद मत करिये। आप बनाये या नहीं बनायें....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): छोड़ दिया न उसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं छोड़ा भाई, बात सुन लो, जो उसका नक्शा बना है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी श्रद्धा है उस स्थान के प्रति....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): वो छूट जाएगा, मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया, प्रोसेस में है और सौ परसेन्ट छूट जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद जो नक्शा बना है, उसमें उसके जाने के रास्ते बन्द हो रहे हैं बरखेड़ा का। इसलिए आप कोई समाज उग्र नहीं हो, शान्तिपूर्ण बात करें, कोई सड़क पर आ जाए तो उसकी आप सुन लोगे, अगर कोई समाज शान्तिपूर्ण तरीके से रहता है तो उसकी बात भी हमको सुननी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि बाड़ा पदमपुरा की प्रतिष्ठा बनी रहे, मान बना रहें, उसके आने-जाने के रास्ते खुले रहे और वहां जाने की व्यवस्था रहे, उसको किस प्रकार अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारे ऊपर चोट है।

अन्त में सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, समाप्त कर रहा हूं कि हम चार साल तक रिव्यू करते रहे, हमने रिंग रोड का रिव्यू किया जयपुर में, हमने इन्वेस्टमेन्ट का रिव्यू किया, साढ़े तीन लाख का हमने एम.ओ.यू. किया था और मेरे चार प्रश्न विधान सभा में लगातार लगे, एक का जवाब नहीं दिया कि रिसर्जेन्ट राजस्थान पर कितना खर्चा आया? आज भी आप छुपा रहे हो इस बात को, उसके केवल 9 एम.ओ.यू. हुए, उसका रिव्यू किया हमने, बेरोजगारी का रिव्यू कर रहे हैं हम, हर चीज का रिव्यू कर रहे हैं।

अब रिव्यू करने का पब्लिक का समय आ गया है। अब रिव्यू न करके काम करिये, और जनता ने रिव्यू करना शुरू कर दिया है और इस बजट को हमको इसी आधार पर देखना चाहिए कि बजट में वित्तीय प्रावधान नहीं हैं जिन योजनाओं को पूरा करना है। लेकिन वो योजनाएं आवश्यक हैं, जरूरी हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है और वित्त व्यवस्था हमको ठीक करनी चाहिए। चुनाव आने वाले हैं। मैं, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती राजे ने संकल्प, निष्ठा, दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ में गत चार वर्षों में प्रदेश को उन्नति की नयी परवाज़ दी है, हालांकि बहुत कड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान राज्य विकास की ऊंचाइयों की बुलंदी छू रहा

(डा. मंजू बाघमार)

है। यह सब राज्य की जनता, प्रशासन और नेतृत्व की इच्छाशक्ति का परिणाम और कर्तव्य परायणता की ही परिणाम है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2008 और 2013 में जब राजस्थान प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, लेकिन आज राजस्थान राज्य विकासशील राज्य की श्रेणी शामिल हो रहा है और अब विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। राज्य की तस्वीर पिछले चार सालों में बिलकुल बदल गयी है। कल तक यह तस्वीर दूर-दूर पानी ढोती महिलाओं की थी तो आज गांवों में जल स्वावलंबन अभियान की बदौलत जल संरचनाएं लबालब भरी हुई हैं। पिछले चार वर्षों में इक्कीस हजार गांवों को जल स्वावलंबन अभियान से जोड़ा जा रहा है। पानी, बिजली और सड़क जैसी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनके अभाव में राजस्थान जी रहा था, आज सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में जगमगा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कल तक महिलाओं के पिछड़ेपन के उदाहरण के तौर पर जाना जाने वाला राजस्थान आज भामाशाह योजना के जरिये आधी आबादी के सशक्तीकरण का गवाह बना है। राज्य के नागरिक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। कुल 1,700 बीमारियों को कवर करते हुए लगभग साठ लाख परिजनों को 933 करोड़ रुपये का बीमा लाभ दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की जो योजना है 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा एक महत्वाकांक्षी, एक अनूठी राष्ट्रीय योजना जारी की गयी, जिसमें बच्ची के जन्म से लेकर बारहवीं कक्षा तक पढ़ने और उसके विवाह तक का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इस राष्ट्रीय योजना में लगभग 7 लाख 92 हजार बेटियों को जून, 2016 से 198 करोड़ 20 लाख रुपये का लाभ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, 'न्याय आपके द्वार' जिसमें वर्षों अदालतों के ग्रामीण और किसान लोग चक्कर काटते रहते थे, श्रम, धन और समय दोनों की बर्बादी होती रहती थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक अनूठी योजना चलाई। एक बुनियादी योजना के आधार पर उन्होंने 'न्याय

(डा. मंजू बाघमार)
आपके द्वार' योजना चलाकर करीब 1 करोड़ प्रकरण इसमें निस्तारित किये गये। इसके अलावा राज्य में बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उससे हर वर्ग की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। चाहे वो राजस्थान सम्पर्क पोर्टल हो, उसमें लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और लाखों लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। ये निरन्तर जो अनवरत फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं वो जनता पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक भार नहीं डाल रही हैं बल्कि जनता के सहयोग से संचालित हो रही हैं और ऐसी अनेक अभिनव योजनाएं जो पहली बार राजस्थान के अन्दर शुरू की गयी हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो इसका अध्ययन कर रहे हैं कि राजस्थान में इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे प्रदेश में भी चालू करें ताकि प्रदेश का विकास भी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं विकास की बात करूं पानी, बिजली और सड़क में राजस्थान प्रदेश आज सड़कों के मामले में पूरे देश का सिरमौर बन गया है। पूरे प्रदेश के अन्दर राजस्थान एक मॉडल के रूप में जाना जाने लगा है। चाहे वो गांव-ढाणी की सड़क हो या शहर की हो, आपस में जोड़ते हुए भारत का हमारा जो सबसे विशाल प्रदेश है राजस्थान राज्य उसमें उच्च गुणवत्ता वाले मार्ग, उपमार्ग सभी आज विकास की इस गाथा को बयान कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ग्रामीण गौरवपथ योजना सड़क तंत्र और आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान कर रही है। राजस्थान के अतीत और वर्तमान को सुधारने का श्रेय भी इन योजनाओं को जाता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में औसतन प्रतिदिन करीब 15 किलोमीटर सड़कों का रोजाना निर्माण किया जा रहा है और अब तक इस तरह करीब 20 हजार 725 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। यदि हम सड़कों के नवीनीकरण उसके सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण की बात करते हैं तो करीब 25 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का राजस्थान में प्रतिदिन सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और अब तक करीब 27 हजार 221 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के कार्य को पूरा किया जा चुका है। तो और सभापति महोदय, राजस्थान में औसतन हर दिन चार गांवों को और बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अब तक करीब 1,662

(डा. मंजू बाघमार)
ग्राम और 3,981 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आधारभूत संरचनाओं के अन्दर जो प्रचुरता हो रही है और जिस तरह से विकास हो रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान में निवेश को यह जरूर आकर्षित करेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी की स्वयं महिला होते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उन्होंने जिस प्रकार से योजनाएं बनाई हैं और महिलाओं को शक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में शक्ति और शिक्षा देकर उनको सशक्त बनाने का जो राजस्थान में प्रयास किया है। हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना के माध्यम से परिवार का मुखिया सिर्फ महिला को बनाकर न केवल महिलाओं को ही लाभान्वित किया जा रहा है बल्कि गरीब और निर्धन तबके के जो व्यक्ति हैं उनको भी आधारभूत सुविधाओं से जोड़े जाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और उनको इस प्रकार का लाभ दिया जा रहा है। करीब पांच करोड़ पचास लाख परिवारों को इसका सीधा लाभ दिया जा चुका है। यदि हम लिंगानुपात की बात करें, भारत देश के लिंगानुपात की बात करते हैं तो उसमें राजस्थान का लिंगानुपात बढ़ रहा है और इसीलिए राजस्थान राज्य को भारत सरकार द्वारा 2017 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि लंबे समय से महिला कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की जो बात चल रही थी, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में उनका प्रावधान करते हुए उनका मानदेय बढ़ाया है। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आशा सहयोगिनी हो और उसमें करीब 1 लाख 84 हजार महिलाकर्मी उससे लाभान्वित हो रही हैं और न सिर्फ उनको इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है बल्कि 2006-07 से सामुहिक बजट आधारित जो बीमा योजना चलाई जा रही थी इसमें वो अपना कुछ अंशदान दे रही थी, बीमा में उस अंशदान को समाप्त करके हण्ड्रेड परसेंट उसका अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मेंसस हाईजीन स्कीम के तहत सेनेटरी

(डा. मंजू बाघमार)
नेपकिंस स्कूलों, कालेजों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में दिये जा रहे हैं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 76 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। एक जो बहुप्रतीक्षित मांग थी एनटीटी नर्सिंग टीचर ट्रैनिंग के लिए उसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा एक हजार नयी भर्ती का प्रावधान भी किया गया है और नयी भर्ती निकालने की घोषणा भी की गयी है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ जो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि महिला कर्मचारियों को अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी की आवश्यकता थी तो चाइल्ड केयर लीव के लिए जो उन्होंने दो साल की व्यवस्था की है निश्चित रूप से जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम है और वो इससे बहुत प्रभावित होंगी। न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी उन्होंने स्पष्ट रूप से एक अपनी आशा प्रकट की है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के बारे में कांग्रेस वाले भी काफी सदस्य बोलते आ रहे हैं और यहां से भी सबकी यह मांग चली आ रही थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों को राहत प्रदान की जाए। माननीय सभापति महोदय, जब 2013 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान की मुख्य मंत्री का पदभार संभाला उसी दिन से किसानों के विकास के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, किस प्रकार से किसानों का उत्थान किया जा रहा है उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील थीं और उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये हैं। सकारात्मक प्रयास करते हुए इस पर ठोस कदम भी उठाये हैं।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, राज्य की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका कृषि पर आधारित है और किसान किसी भी देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। प्रदेश में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो लक्ष्य है, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। क्योंकि अब किसान नवाचारों को अपनाते हुए कृषि क्षेत्र में परम्परागत और आधुनिकता के साथ नये प्रयोग कर रहे हैं जिससे उन्हें निश्चित रूप से आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य की

(डा. मंजू बाघमार)

पूति के लिये ग्लोबल राज्य एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जा रहा है, जो कोटा, जयपुर और उदयपुर में आयोजित की गयी है। किसानों को उससे काफी लाभ हुआ है, किसान नई टैक्नोलोजी से अवगत हुए हैं और नई नई जानकारियां भी किसानों को उपलब्ध हुई हैं। निश्चित रूप से जब किसान खेती करेंगे तो उससे काफी फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पहली बार उन्होंने किसानों के लिये सोचा। लघु और सीमांत कृषकों ने सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा था, 30 सितम्बर, 2017 को समस्त शास्तियां और ब्याज को माफी की घोषणा की। साथ ही 30 सितम्बर, 2017 तक आउटस्टेंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण में भी 50 हजार रुपये के कर्जे माफ किये गये। किसानों को बहुत ही राहत प्रदान की गयी है और निश्चित रूप से किसान वर्ग में एक खुशी की लहर जाग्रत हुई है। पहली बार किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गयी है कि किसान आकर वहां अपनी बात रख सके और वहां पर उन्हें राहत मिल सके। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया गया है ताकि किसान वहां जाकर अपनी समस्याएं रख सकें और उन्हें वहां पर उसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, न सिर्फ इन बातों में बल्कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चाहे वह फार्म पौंड हो, चाहे जलहौज का निर्माण हो, चाहे डिग्गी का निर्माण हो, चाहे ग्रीन हाउस हो, सबमें सब्सिडी प्रदान की है और अनुदानों की राशि को बढ़ाया है। नये नये एग्रीकल्चर कालेज खोले जा रहे हैं। जिन जिलों में एग्रीकल्चर कालेज नहीं हैं, वहां पर एग्रीकल्चर कालेज खोले जा रहे हैं ताकि किसान वहां पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, राजस्थान में सभी जगह से यह बात उठ रही थी कि किस प्रकार से गौशालाओं का विकास किया जाये, किस प्रकार से उनका संवर्धन किया जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान में

(डा. मंजू बाघमार)
गौशालाओं के विकास और संवर्धन के लिये जो उनको चारे के लिये पैसा दिया जा रहा है, उसकी तीन महीने की अवधि को बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है। प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला विकसित की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे नागौर जिले में काफी समय से यह मांग चली आ रही थी कि नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वह विश्व प्रसिद्ध हैं और उनको राजस्थान से बाहर ले जाने की उम्र को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा नंदी गोशाला स्थापित करने का बजट में जो प्रावधान किया गया है और उनमें 50 लाख रुपये तक का अनुदान देने की घोषणा की गयी है, निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार किसानों को 33 परसेंट फसल खराबे पर मुआवजा दिया गया और जो फसल का समर्थन मूल्य है, उसमें लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने का भी प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, और तो और माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पहली बार डीएलसी दरों में कमी की है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है। निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि अभी तक हम यह सुनते आये हैं कि डीएलसी दरें हमेशा बढ़ती रहती हैं। लेकिन पहली बार इस प्रकार का माननीय मुख्य मंत्री ने डीएलसी दरों को कम करने का फैसला किया।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक कौशल विकास और रोजगार की बात है, आज के समय की प्रबल आवश्यकता है कि हम युवाओं की जो असीम ऊर्जा है, उसको रोजगार और शिल्प कौशल से जोड़कर देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। प्रदेश में जो शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं, वह इस प्रकार किये जा रहे हैं कि वह रोजगार उन्मुख हों और बालकों में प्रारंभ से ही रोजगार, उद्यम और कौशल के गुण विकसित हो सके। शिक्षा प्रणाली को सीधे स्किल डवलपमेंट से जोड़कर सुखद परिणाम भविष्य में राज्य की समृद्धि और विकास के रूप में दिखाई देगा। कहा जाता है कि विद्या कर्मस्य कौशलम्, इसी धैर्य के साथ राज्य के भविष्य के कर्म कुशल शिल्पी तैयार किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं माननीय

(डा. मंजू बाघमार)

मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि देश में राजस्थान में पहली बार स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और करीब 13 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं खुद अनुसूचित जाति से आती हूं और यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान की बात की जाए, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में भी यही कहा है कि मैं इस वर्ग के लिये कुछ बेहतर करूं यही मेरे लिये अच्छा होगा और यही मैं करना चाहती हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पहली बार उन्होंने राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी और एसपीजी वर्ग के लोगों को विशेष रियायतें प्रदान की हैं, उनके लिये विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं। कांग्रेस सरकार अब तक दलित वर्ग को अपना वोट बैंक समझती आयी है और हमेशा यही समझती आयी है कि दलित के चाहे हम काम करें या नहीं करें लेकिन वह वोट हमें देंगे, हमारा वोट बैंक पक्का है। उन्होंने आज तक दलित वर्ग के उत्थान के लिये कभी इस प्रकार के कोई ठोस कार्य नहीं किये, कोई ठोस योजनाएं प्रदान नहीं कीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त और विकास सहकारी निगम द्वारा उनमें एससी, एसटी, सफाई कर्मचारीगण, दिव्यांगगण, ओबीसी व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु 1980 और 1981 से जिन्होंने लोन ले रखे थे, जो गरीब लोग गांव में बैठे हैं, जिनके लिये एक लाख रुपये बहुत मायने रखते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दो लाख रुपये तक के बकाया ऋण की माफी की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कार्य किया है और उसके लिये उन्होंने 114 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान भी किया है। और तो और अंबेडकर की बात कांग्रेस सरकार करती आयी है और कांग्रेसी कहते आये हैं कि अंबेडकर साहब हमारे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पहली बार नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी हैड क्वार्टर के ऊपर उन्होंने अंबेडकर भवन बनाने का निश्चय किया है और इसके लिये करीब 80 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा जो छोटे कामगार लोग हैं, उनको भी दो लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय सभापति महोदय, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पट्टा वितरण के जो कार्यक्रम चले थे, उसमें 2017-18 में एससी वर्ग को 1 लाख 76 हजार पट्टे वितरण किये गये। एसटी वर्ग के 600 व्यक्तियों को 83 लाख 600 पट्टे वितरण किये गये और महिलाओं को 1 लाख 25 हजार पट्टे वितरण किये गये, कुल 8 लाख 50 हजार पट्टे वितरित किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट पेश किया है मैं उसकी बहुत भूरि भूरि प्रशंसा करती हूं और मैं यही कहना चाहती हूं कि समृद्ध और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिये यशस्वी मुख्य मंत्री राजे की दूरगामी, प्रगतिशील और स्पष्ट सोच का ही यह परिणाम है कि आज राजस्थान राज्य में हर वर्ग को विकास के अवसर उपलब्ध हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2013 में सत्ता संभालते ही पहला सूत्र वाक्य दिया था, हम राज नहीं सेवा करने के लिये आये हैं, इसी सेवा संकल्प ने महिलाओं, बच्चों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों और वृद्धों के सपनों और सोच को धरातल पर उतारा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि नागौर जिले में मकराना तहसील है उसमें बोरावड़ क्षेत्र में कुमारी खानों के पत्थर की जो खानें हैं, उसमें मार्बल खनन के दौरान जो वेस्ट मैटेरियल निकलता है, उन मार्बल खण्डों के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा रायल्टी समाप्त करने की घोषणा की है, मैं पूरे नागौर जिले की ओर से माननीय मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और यह कहना चाहूंगी कि

"यहां हम आये नहीं हैं सिर्फ बतियाने के लिये,
रोशनी लाये हैं हम पूरे जमाने के लिये।"

सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गिर्राज सिंहजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो 12 फरवरी को बजट पेश किया गया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं

(श्री गिर्राज सिंह)

है जो कि हमारे माननीय सदस्य तारीफ कर रहे हैं। एक भी शब्द इसमें अच्छा होता..

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सदस्य कुछ तो ईमानदारी से बोलो। कुछ तो सत्यता से बोलो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक भी शब्द इसमें अच्छा होता तो, तारीफ मैं भी कर देता। ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, चुनाव के सिर्फ आठ महीने बचे हैं। इन लोगों को अपनी-अपनी टिकट की चिंता लगी है कि हमारा टिकट कैसे पक्का हो? उस वजह से सभी तारीफ कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि इनके क्षेत्र में कितना-कितना विकास हुआ है? यहां तो ये तारीफ करेंगे और अलग से जाकर बात करें तो सब रोते हैं कि मेरे क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ। मेरी थानेदार नहीं सुनता है, मेरी तहसीलदार नहीं सुनता, मेरी सिपाही नहीं सुनता। सभापति महोदय, मंत्री तक यह कहते हैं कि हमारी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी नहीं सुनते हैं।

श्री सभापति: मेरा यह निवेदन है कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत विद्वान भी हैं। बजट पर स्पीच हो रही है। कृपया बजट पर सीमित रहें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आप भी थोड़ा-सा पक्ष ले रहे हैं। सभापति महोदय, पहले वालों ने क्या बोला है? मैंने कौनसा अलग से बोला है? जो पहले वाले बोल गये, उसी लाइन पर मैं चल रहा हूं। मैंने कोई गलत नहीं बोला है। सभापति महोदय, 12 फरवरी को बजट में किसानों के लिये घोषणा की है कि 50 हजार रुपये का ऋण माफ करेंगे। कहां से करेंगे? पहले यह तो बतायें कि इनके पास फाइनेंस की क्या व्यवस्था है? इन्होंने बजट में कितना प्रावधान रखा है? उसके लिये इन्होंने क्या व्यवस्था की है? वैसे ही घोषणा करके चले जाएंगे तो पीछे से वही बात होती रहेगी। सहकारी बैंकों की घोषणा कर दी। लोग तो लोन प्राइवेट बैंकों से ले रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक से ले रहे हैं। किसी दूसरे बैंक से ले रहे हैं। उनके लिये हमने क्या किया है? उनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 50 हजार रुपये तक का लोन आपने माफ किया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई, पर आप सब किसानों का करें। ऐसा नहीं करें कि

(श्री गिर्राज सिंह)
सहकारी बैंकों से लिया है, इसका क्या मतलब है? आपके सहकारी बैंक किसी को लोन नहीं दे रहे हैं। वहां पर दलाल बैठे हैं। वे दलाल दस-दस बीस-बीस हजार रुपये लेकर लोन करते हैं, तब जाकर लोन मंजूर होता है।

सभापति महोदय, इन्होंने बजट में संविदा कर्मियों के लिये कुछ नहीं किया। वे बेचारे रोड़ पर दर-दर ठोकर खा रहे हैं। उनकी कोई नहीं सुन रहा है। उनके बच्चे कहां पर जायेंगे? आपने इतने दिन उनसे काम ले लिया। वे कहां जायेंगे? उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सभापति महोदय, न बेरोजगारों के लिये कुछ सोचा, न कर्मचारियों के लिये। जो बेचारे छोटे कर्मचारी हैं, उनके बारे में इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया। सिर्फ बड़े लोगों की बात हो रही है। अपन आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की बात करें, अपन एम.एल.ए. और एम.पी. की तनख्वाह बढ़ाने की बात करें, अपन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तनख्वाह बढ़ाने के लिये बात करें, उनके बारे में तो अपन चर्चा कर लेते हैं। सभी अपने हाथ है, अपन बिल पास कर लेते हैं। पर जो बेचारा छोटा कर्मचारी है, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा है और न ही इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने भी कहीं नहीं सोचा कि छोटे कर्मचारी का कैसे ध्यान रखा जाए?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): इसमें थोड़ा-सा यह सुधार करो, जितनी तनख्वाह छोटे कर्मचारियों की इस बजट में बढ़ी है। वास्तव में आपके पास जो बजट की प्रति आयी है, ऐसा लगता है कि वह अनप्रिटेंड खाली आ गयी, सच में।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरे पास अलग से आयी है। अलग से भिजवायी है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मलिंगा जी आपको बुकलेट भिजवायें क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें। माननीय सदस्य को अपना वक्तव्य देने दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो सुराज संकल्प यात्रा में वादा किया था। कभी परिवर्तन यात्रा, कभी सुराज संकल्प यात्रा, अब तीसरी बार पता नहीं कौनसी यात्रा का नाम रखा जायेगा, वह तो

(श्री गिर्राज सिंह)
अभी घोषणा नहीं हुई है। विधान सभा के बाद में नयी घोषणा हो जायेगी। पता नहीं, अब की बार मुख्य मंत्रीजी कौनसी की घोषणा करेंगी? मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सभापति महोदय, अभी प्रदेश में तो 15 लाख कर्मचारी है ही नहीं, तो इन्होंने 15 लाख लोगों को नौकरी कहां से दे दी? नौकरी से हटकर ये आये कि हम रोजगार देंगे। सभापति महोदय, इन्होंने किसको रोजगार दे दिया? कितने लोगों को रोजगार दे दिया? सिर्फ असत्य बोलकर यह सरकार अपने सवा चार साल पूरे कर गयी।

श्री सभापति: असत्य कर देना।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, असत्य बोलकर यह सरकार आ गयी और आने के बाद इनकी जाने की तैयारी हो गयी है, यह आपको भी मालूम है कि विदाई की भी तैयारी हो गयी। विदाई की तैयारी हो गयी तो भी इन लोगों में सुधार नहीं हुआ। विधान सभा में कोई भी क्वेश्चन लगाओ तो इनके पास से जवाब आता है कि फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है। जब फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है तो आप घोषणा किस बात की कर रहे हैं? आपने नौजवान लोगों के साथ में धोखा किया है। बेरोज़गारों के साथ में धोखा किया है कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे। 15 लाख नौकरियों की जगह आपने 2 लाख नौकरियां भी नहीं दीं। वह भी आपने गलत किया।

सभापति महोदय, बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया है। बाड़ी, सैपऊ, बसई नवाब। सभापति महोदय, बाजार में अगर कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कोई घटना हो जाती है तो एक-दो घंटे निकल जाते हैं, लेकिन बाजार में से वाहन नहीं निकल पाते हैं। इतनी जाम की स्थिति है। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री हमारे बड़े भाई युनुस खानजी ने घोषणा की थी कि मैं आपके धौलपुर जिले में चलूंगा, मैं तीन दिन बाड़ी में रूकूंगा, आपके यहां कैम्प करूंगा और आपके साथ में बाड़ी की समस्या का समाधान करूंगा। सभापति महोदय, दो साल हो गये, तीसरा साल चालू हो गया। अब मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय ने आज तक कहीं जाने की जरूरत नहीं समझी कि मैंने इस सदन में घोषणा की है। इस सदन को हम पवित्र सदन कहते हैं। सभापति महोदय, इसके बाद भी मंत्री जी ने अभी तक कोई जवाब

(श्री गिर्राज सिंह)

नहीं दिया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं बाड़ी की रिंग रोड़ बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। सभापति महोदय, इन्होंने पहले तो घोषणा की कि मैं बाड़ी मैं रिंग रोड़ बनाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कभी लौटकर जवाब नहीं दिया। मैंने इसमें दो-तीन बार जिक्र किया, उन्होंने जवाब देना भी उचित नहीं समझा कि मुझे जवाब देना है या नहीं देना है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने सैपऊ के लिये कालेज की मांग हमेशा बार-बार इस सदन में उठायी है कि तहसील हैडक्वार्टर पर एक कालेज खोली जाए। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जगह-जगह घोषणा की है। धौलपुर जिले में उन्होंने बसेड़ी में कालेज दे दी, धौलपुर में मेडिकल कालेज दे दी। राजाखेडा़, धौलपुर में पानी के लिये नहर की योजना दी है, पर बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में आज तक मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में, चार बजट हो गये, इनका पांचवाँ भी हो गया, आज तक एक भी घोषणा नहीं की है कि बाड़ी के लिये हम यह करेंगे। सभापति महोदय, 'संभाग आपके द्वार' में मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला। बाड़ी में आयी थीं। चलो मुख्य मंत्रीजी आयी हैं, हमारे बाड़ी का भी कुछ उद्धार होगा, भला होगा। मैं जाकर मिला। नमस्कार हो गयी। उन्होंने कहा लिखकर दे दो। मैं लिखकर नहीं ले गया था। मैंने वह भी दे दी, उन्होंने सोने के गुरजा वाले पुल के लिये तत्काल अधिकारियों को बुलाकर आदेश दे दिये। आदेश देने के बाद पुल को चैक करा लिया। चैक कराने के बाद 'सरकार आपके द्वार' संभाग भरतपुर में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी कि इस पुल को बनाएंगे। उसके बाद विधान सभा का बजट सैंशन चला। मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की कि हम सोने के गुरजा वाले पुल को बनायेंगे। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जब सदन में घोषणा की। इसके बाद मैं मुख्य मंत्रीजी से जवाब चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यह बतायें कि आप इस पुल कब बनायेंगी?

अभी तक तो आपने उस पुल की डीपीआर भी नहीं बनायी। कोई टैंडर प्रक्रिया भी नहीं बनायी। आपकी विदाई का समय हो गया। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में सत्य और असत्य की बात होती है। जब मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी घोषणा की और उस पर गौर नहीं किया, तो इस सदन का क्या

(श्री गिर्राज सिंह)

औचित्य? यहां पर हम अपनी आवाज उठाते हैं। मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद में भी अगर हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है और मंत्रीजी द्वारा आश्वासन दिये जाते हैं। उसके बाद में अब हम किस पर भरोसा करे? किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला तो हो और जो सुनने वाले है वो लोग यहां ही हैं। सत्य और असत्य की बात करते हैं। उन्होंने यहां पर घोषणा की है और घोषणा करने के बाद में भी आज तक उनको लागू नहीं किया गया है।

श्री सभापति: हो गया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी तो बहुत बाकी है।

श्री सभापति: आप बजट पर तो आओ।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ये बजट की ही तो बात है बजट में कोई घोषणा ही नहीं की है। सभापति महोदय, मेरे यहां चार तालाब है। सैपऊ बाड़ी, पार्वती नदी। जब नदी छनती है बरसात में तो रास्ते जाम हो जाते हैं। सभापति महोदय, चार-चार, पांच-पांच दिन तक आने-जाने के लिए सम्पर्क टूट जाता है। उस पुल के बारे में मैंने हर बार विधान सभा में क्वेश्चन लगाये। हर बार मेरे को एक ही जवाब मिलता है कि बजट का प्रावधान नहीं है। हर साल उसमें पांच-दस लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार बार-बार इसको दिखवा लेती है। लेकिन दिखवाने के बाद भी इस पर कोई विचार नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, पार्वती बांध, रामसागर बांध, तालाबशाही बांध, उर्मिला सागर। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इन चारों बांधों के लिए एक सम्मिलित योजना, स्कीम बनाई जाए। चौतरफा धौलपुर क्षेत्र का विकास हो। क्या मालूम कल मुख्य मंत्रीजी मुख्य मंत्री रह पायें या नहीं रह पायें। आगे सरकार किसकी आये। बीजेपी की आये या कांग्रेस की आये। ये किसी को नहीं पता है। मुख्य मंत्रीजी हमारे धौलपुर की हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं अशोक गहलोतजी ने जोधपुर को खूब दिया तो मुख्य मंत्रीजी धौलपुर को क्यों नहीं देती है? मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी मेरी इस मांग पर गौर करें और धौलपुर जिले की जो समस्याएं है उनका समाधान करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने होमगार्ड के जो जवान है, पुलिस के जो जवान है या छोटे-छोटे कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार है, उनके बारे में, होमगार्ड वालों को क्या मिलता है? महीने में दस दिन के लिए उन लोगों को काम मिलता है। उन लोगों को नियमित करना चाहिए। जो पुलिस का जवान है, उनकी तनख्वाह डबल करनी चाहिए। थानेदार तो इधर-उधर से मंथली से अपना काम चला लेते हैं। डीएसपी, एसपी साहब काम चला लेते हैं। परंतु पुलिस के जवान के लिए, सभापति महोदय, वही गोली खाता है, वही गुंडों के पीछे भागता है, हर जगह जहां पर बलि चढ़ती है, पुलिस के जवान की ही बलि चढ़ती है। होमगार्ड के जवानों को नियमित किया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मैंने अपने जिले की और प्रदेश की जो मांग उठाई है, मैं मुख्य मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों पर विशेष ध्यान रखें। मेरे जिले की जो समस्या है, मुख्यमंत्री जी को भी धौलपुर में रहना है, वह भी धौलपुर की हैं, धौलपुर से आती हैं और धौलपुर में उनका ज्यादा आना-जाना रहता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जो हमारी मांगें है, उन पर विचार करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती अनिताजी।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे गिर्राज सिंहजी भाई साहब बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहती हूं कि धौलपुर में इस बार मेडिकल कालेज मिला है, उसके लिए तो आपको मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना ही चाहिए। मगर आपने ध्यान नहीं दिया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे चार साल के अंदर, पूरे जिले में हर विधान सभा क्षेत्र में दिया, मेरे क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिया। भेदभाव किया जा रहा है।

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा कहना है कि क्षेत्र के साथ जिला भी बहुत बड़ी चीज होती है। जिले का विकास होता है तो क्षेत्र का उसके साथ होता है। मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो केवल जिले के ही लोग जाएंगे क्या? आपके शहर, आपके बच्चे भी पढ़ेगे उसमें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सदस्य, घोषणा तो मैंने आपको चार साल पहले ही बताई। मेरे सेवर पाली वाले सोन गुरजा वाले पुल की भी हुई घोषणा तो।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सदस्य, मेरी बात सुनें। धौलपुर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मुख्य मंत्री साहब ने विकास के काम नहीं किये हों और यदि आप हमारी लाइन में आ जाएं तो बाड़ी भी आपकी जुड़ जाएगी और विकास के काम होंगे। थैंक्यू जी।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के लिए दो लाइन कहना चाहती हूं-

'तुम यहां धरती पर लकीरे खींचते हो, हम वहां अपने लिए नए
आसमान ढूंढते हैं' तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा,
हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं।

सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, यह जनता के विश्वास, बुलंद हौसलों, सशक्त और सम्पन्न राजस्थान बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। 'सबका साथ-सबका विकास, सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' से ओतप्रोत ये बजट है। सदन में अपने सभी साथियों से यह कहना चाहती हूं कि सदन की चर्चा को सुनिए, फिर चिंतन करिए, मनन करिए और उसके बाद निर्णय करिए कि इस बजट में किस-किसको क्या-क्या मिला और ये हमारा प्रदेश बढ़कर आगे कहां जाएगा। प्रतिपक्ष बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है। जब इनका समय था, मेरे ख्याल से 70 साल में 56 से 60 वर्ष इन्होंने राज किया है। जिस समय इनको किसान को देखना था, उसकी मजबूरियों को देखना था, मजदूर की चिंता करनी थी। इनको गांव के गरीब के लिए कुछ काम करना था। इनको पिछड़ों के लिए कुछ करना था, इनको दलितों के उत्थान के लिए कुछ करना था, इनको सड़कों को जहां कीचड़ भरा हुआ था, वहां पर इनको कुछ देखना था, इनको पानी की व्यवस्था, कुओं को देखना था, जब तो इन्होंने कुछ देखा नहीं। अगर ये उस समय देख लेते तो आज 70 साल में राजस्थान कहीं का कहीं होता। मैं पूरे सच्चे मन से और आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि राजस्थान में जो विकास हुआ है, वह वसुन्धराजी की वजह से हुआ है, उनकी जिम्मेदारी

(श्रीमती अनीता)
की वजह से हुआ है। वर्ना कांग्रेस का जब राज था, हम उधर बैठते थे। हम हमेशा देखते थे नये-नये घोटाले होते थे। कभी आटा घोटाला हो जाता था, कभी इनके बड़े-बड़े मंत्री, महिलाओं पर अत्याचार करके जेल जाते थे। वह सब समय हमने देखा है। लेकिन अब वह सब चीजें भूल गये। आज दलितों के लिए अगर कोई बात करना चाहे, कांग्रेस ने अपने पूरे समय में दलितों को हमेशा ही बहकाने की कोशिश करी कि वोट बैंक हमारे पास रहे। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने दलितों के लिए कोई योजनाएं बनाई हो, कुछ काम किया हो तो बतायें? लेकिन इन्होंने ऐसी कुछ भी योजनाएं बनायी नहीं। आज इस सदन के माध्यम से मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने दलितों के मान-सम्मान के लिए और जाति प्रथा के बंधन तोड़कर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की है, वह कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। इन्होंने कभी विचार भी नहीं किया कि हमें इनके लिए ऐसा काम करना है।

मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सब नगर पालिकाओं में अम्बेड़कर भवन बनाने का 80 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, जो निर्णय लिया है वह काबिले तारीफ है। पूरे राजस्थान के दलित उनको आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा किया है, हमारे मन से, हमारी इच्छा से, हमारे मान-सम्मान को बढ़ाने के लिए किया। आज एससी/एसटी के जो लोन थे वे भी दो लाख तक माफ किये। ये होता है दलितों के लिए काम, ये होता है दलितों को ऊपर उठाने के लिए काम, जो वह कर रही हैं। अपना काम तो इन्होंने किया नहीं, अब एक-एक पन्ने को संवार रहे हैं और कह रहे हैं इस पन्ने में हमारा विधान सभा क्षेत्र नहीं लिखा।

जब मैंने यह बजट की किताब पढ़ी तो हर पन्ने में कहीं न कहीं किसान था, कहीं न कहीं मजदूर था, गांव में खेत के पानी की, बिजली की, सबकी बातें उसके अंदर थीं। 'आगे दिन पीछे गये गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत।' आज बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। बहुत सारी यह भी करते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह आप पर लागू हो रही है ना। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता (नगर): नहीं-नहीं, मैंने तो आपके लिए कहा है सर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां तो यह बताओ कि हम पर है या आप पर है?

श्रीमती अनीता (नगर): हम तो आगे दुबारा आने वाले हैं। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्योंकि हम तो आपके लिए ही समझ रहे हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता (नगर): यह तो आपके लिए ...(व्यवधान)... मैं आपके लिए कह रही हूं आज बजट पढ़कर आप लोगों को लग रहा है कि इतना बजट क्यों आ गया, अब क्या होगा, हमने ऐसा क्यों नहीं किया इसलिए यह आपके लिए है ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह अच्छा बजट होता तो यह हाल नहीं होता एक भी मेज नहीं थपथपाते ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): डोटासराजी, आप महिला विरोधी हो क्या? ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं ...(व्यवधान)... बहुत सम्मान करता हूं। आपकी तरह नहीं हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): फिर बोलने दो न, उनको क्यों टोक रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत सम्मान करता हूं। आपकी तरह नहीं हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्यों टोक रहे हो, बोलने क्यों नहीं देते। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना

(श्रीमती अनीता)

चाहती हूं कि नीति और नीयत में ...(व्यवधान)... इन्होंने बांटी तो यह ऐसे ही रह गये न, अब भी रह जाएंगे। नीति और नीयत में बहुत फर्क है। जब हमारी सीमाओं पर हमारे फौजी भाई, हमारी फौज के लोग रहते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं और उन पर भीड़ बनाकर पथराव होता है, हमला होता है तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिल में टीस उठती है। टीस इस बात की उठती है कि इस प्रकार की घटना गलत है। हमारे फौजी देश की रक्षा करते हैं, राष्ट्र भक्ति करने से जो इनको रोकते हैं, आतंकवाद से लड़ने से इनको रोकते हैं और हमारे प्रतिपक्ष के नेता है इस बात को कहते हैं कि यह लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, यह नासमझ बच्चे हैं, इनके ऊपर कैसेज नहीं होने चाहिए, इस तरह की भावना हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि देशभक्ति के प्रति हम लोगों को आगे सजग रहना चाहिए, देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत रहना चाहिए। आज जब नहीं रहते हैं तो आपके चरित्र और चलन का पता लगता है।

हमारे सांसद है हुकम देव नारायणजी, उनके भाषण का एक छोटा अंश में यहां पढ़ना चाहती हूं। उन्होंने कहा हिन्दुस्तान के अंदर आज भी कुछ कालनेमिवाद से ग्रसित लोग रहते हैं। कालनेमि कोई व्यक्ति नहीं है। कालनेमि एक विचाराधारा है, कालनेमि एक चरित्र और चिंतन है। आज भी हिन्दुस्तान की राजनीति में कालनेमि रहते हैं। उनसे लड़ने के लिए आज भी देवी देवताओं और हनुमानों की जरूरत है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से लड़ने के लिए सबसे आगे बढ़कर काम करती है।

मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, जब हम बात करते हैं, वैसे भी मैं आपके बीच में कहना चाहती हूं कि नीतियों की और विचारों की लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनमे नीतियां होती है, विचार होते हैं, उनकी लड़ाई होती है। उन्हीं लड़ाइयों पर हम करते हैं। हम समझते हैं कि भारत के संविधान में हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, द्वंध हो सकता है। उसी पर हम सब महत्व देते हैं। हम सबको विचार करना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, बहस भी करनी चाहिए, आपस में समन्वय, सहमति भी बनानी चाहिए, तब जाकर आगे बढ़ना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं अलवर में गौ रक्षा के

(श्रीमती अनीता)
लिए पुलिस जब गौ तस्करों को मार देती है तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बहुत आपत्ति होती है। उनको लगता है कि पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है क्योंकि आपको गौ तस्करी और वहां के लोगों की भावना नहीं दिखती, आपको तो सिर्फ अपना वोट दिखता है। आपके लिए भी कह सकती हूं कि आपकी कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। कहते कुछ है और करते कुछ है। अब बात ही करें तो कर्नाटक और केरल में इनकी क्या नीति है। इनकी पार्टी की नीति है, विचार है, वह सामने आने चाहिए। कर्नाटक में जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग वहां पर साम्प्रदायिक दंगे करते हैं, जिनके ऊपर गंभीर केस बने हुए हैं उनके ऊपर भी यह चाहते हैं कि केस वापस लिये जाएं। साम्प्रदायिक दंगों का यह समर्थन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं।

सभापति महोदय, जब डोकलाम का विवाद हुआ उसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, किसी ने इस प्रकार का विचार नहीं किया कि मुझे क्या? जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। मुझे इस बात का दु:ख है, पूरे देश को भी दु:ख हुआ कि इनके कांग्रेस के अध्यक्ष चीन के राजदूत के साथ मिलकर क्या भला कर रहे थे देश का, उसको पूरे देश ने देखा है। मैं कहना चाहती हूं कि साम्प्रदायिक दंगे, जिस प्रकार से यह बार-बार कर रहे हैं और जिस प्रकार से हो रहा है वह गलत है। हम सब लोगों को, हमारे देश में रहने वाला चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, यह मैं आप सबसे कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, आज जब हम गाय की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह समझते हैं कि हमारे भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा गोकशी की, तस्करी की घटनाएं होती है क्योंकि हम बोर्डर पर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हरियाणा है। जहां से भी गोकशी की बात होती है, वहीं से उसको लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के में भाजपा सरकार आयी है, उन्होंने जिस प्रकार से स्लाटर हाउसेज बंद किये, उसकी वजह से सही मायने में हम कह सकते हैं कि हम गौ माता को, नंदी को बचाने में समर्थ हुए हैं। भरतपुर कृष्ण की धरती है, बृज नगर है, यहां गाय और बछड़े से प्रेम, लगाव और भक्ति तो स्वाभाविक ही है। वसुन्धरा जी ने जिस प्रकार से गौ शालाओं, गायों के लिए

(श्रीमती अनीता)
काम किया है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूं, साधुवाद करना चाहती हूं। गौ शालाओं को मिलने वाले अनुदान को जो तीन महीने मिलता था, उन्होंने उसको छह महीने कर दिया, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद।

राज्य की 25 गौ शालाओं में बायो गैस संयंत्र लगाने के लिए उन्होंने अनुदान देने की घोषणा की है, वह बहुत बधाई के लायक है। राज्य में प्रत्येक जिले में एक नंदीशाला खोलने की घोषणा की है, जिसके लिए पांच करोड़ रुपये देने का भी उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। मैं समझती हूं कि गायों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, गौशालाओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कोई सरकार, कांग्रेस ने तो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि इनका तो ध्यान ही कहीं और है।

मैं बजट के बारे में भी कहना चाहती हूं। हमने अभी बजट देखा, वसुन्धराजी का पहला बजट भी हमको याद है, उस समय भी उन्होंने जो बात कही थी वह भी हमें याद है कि हम इतनी बुरी स्थिति में है। फिर भी बुरी स्थिति होने के बाद भी मैं कभी भी पूरे प्रदेश के किसी व्यक्ति से नहीं कहूंगी कि मेरे पास पैसे की कमी है और उस पैसे की कमी की वजह से मैं कभी भी हाथ आगे बढ़ाकर किसी से मांगू ऐसा नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि पांच वर्षों में राजस्थान को देखे तो जीडीपी रेट प्लस में है। अगर प्लस में है तो इसका मतलब है कि प्रगति कर रहे हैं। प्रति आय भी अगर हम अपने राजस्थान के प्रति व्यक्ति की देखेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यह निश्चित रूप से है कि एग्रीकल्चर से कुछ कम हुआ है। कम होने के पीछे है कि एग्रीकल्चर पूर्णतया ईश्वर पर आधारित है। ईश्वर पर इसलिए आधारित है कि अगर समय से बरसात कर दे, पूरी बरसात कर दे तो किसान की अच्छी फसल आ जाए और अगर पूरी बरसात नहीं करे तो किसान को दिक्कत हो जाए। सभापति महोदय, आप चिंता मत कीजिए, जो समय दिया है उसी समय में मैं अपनी बात खतम करूंगी।

मैं कहना चाहती हूं कि कम्पेरिजन भी अगर हम पूरे देश का करें तो राजस्थान कहीं बेहतर स्थिति में है। जिस जीएसटी की यह इतनी बातें करते रहते हैं, उस जीसटी की वजह से भी राजस्थान में सेंट्रल रेवेन्यू है 28.6 बनकर आया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह बजट हर वर्ग के लिए है।

(श्रीमती अनीता)

सब इस बजट से बहुत खुश हुए हैं। सस्ते घर मिल रहे हैं वह इसलिए कि डीएलसी रेट दस परसेंट घट गयी है। कोई नया सैस नहीं लगाया है। 650 करोड़ की कर राहत हमको इसमें मिली है। स्व रोजगार योजनाएं लांच हुई हैं, सुंदरसिंह भण्डारी और भैरोसिंह शेखावतजी के नाम पर। मैं समझती हूं कि इसके अंदर 4 परसेंट ब्याज तो है लेकिन 50 हजार परिवारों को अगर 50 हजार रुपया मिलता है तो रोजगार की तरफ, स्व रोजगार की तरफ यह बहुत बड़ा कदम है, जो हमारी सरकार ने रखा है।

आरपीएसी, यूजीएससी की परीक्षाओं व इंटरव्यू के लिए जाने हेतु छात्र को बस में मुफ्त जाने के लिए भी हमारी मुख्य मंत्री ने किया है, वह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। उनको बड़ी चिंता रहती थी कि हमें हर रोज कहीं न कहीं परीक्षा के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है। यह कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार की यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने राज्य का बजट दिया, किसानों और बेरोजगारों को समर्पित कर दिया। युवा रोजगार के लिए 54 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां कीं। 9 हजार सैकिण्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्तियां कीं। 2 हजार पटवारियों की भर्ती कर रही है। खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए यूथ आइकन स्कीम बनायी है। स्व रोजगार योजना के तहत 50 हजार परिवारों को 50 हजार रुपये का कर्ज दे रही है। 5 हजार 518 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की है। इतनी सारी भर्तियां निकली हैं।

इससे युवा रोजगार की तरफ, आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा, यह मैं कहना चाहती हूं। क्योंकि हमारी मुख्य मंत्री महिला हैं, और महिला के लिये उन्होंने जो काम किया है वह इस प्रदेश और देश के किसी व्यक्ति से छिपा नहीं है। मैं तो छोटी से छोटी बातें आपके बीच में कहना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये उन्होंने महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं जितनी मानदेय में कर्मियां थीं, उन सबका मानदेय बढ़ा दिया। महिला कर्मचारियों के लिये एक बहुत बड़ा काम किया, जो आज तक पूरे देश में अगर देखें तो यह एक मिसाल होगी कि हमारे महिला कर्मचारियों के लिये दो वर्ष की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। मैं समझती हूं कि महिला कर्मचारियों में एक बहुत अच्छा संदेश, और महिलाएं, जिनको लगता था कि

(श्रीमती अनीता)
हम अगर नौकरियों पर जाएंगी तो हमारे बच्चों की परेशानियां जो महसूस करती थीं, उन्होंने उसकी दूर की हैं। 24 आई.टी.आई. में महिला विंग खोले जाने के लिये उन्होंने कहा। सैनेटरी पैड के वितरण के लिये भी 76 करोड़ रुपये अलग से देंगी, यह भी बहुत अच्छी बात की है।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बिजली-पानी का जितना काम मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने इन 4 वर्षों में किया है, और जो आने वाले समय में करेंगी, वह अपने आपमें बहुत बड़ा काम है। सभापति महोदय, मैं दो लाइन कहना चाहती हूं,

'निगाहों में मंजिल है, गिरे और गिर कर सम्भलते रहे
हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे।'

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि विकास और सुशासन है, यह निरन्तर चलने वाला है। यह लगातार यात्रा है, किसानों की आय बढ़े, कमजोर तबकों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान हो, महिलाएं शिक्षित हों, सुरक्षित हों, नौजवानों को काम मिले, ऐसे खुशहाल राजस्थान का सपना केवल भा.ज.पा. देख सकती है और हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ऐसे सपने को साकार कर सकती हैं।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं। जब पहला बजट हुआ, उस समय हमको हमारे नगर विधान सभा क्षेत्र के लिये 790 करोड़ रुपये की चम्बल लिफ्ट योजना है पानी की, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिली। दूसरे बजट में 200 करोड़ रुपये हमको ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा के लिये वित्तीय स्वीकृति मिली। चम्बल योजना का भी काम चल रहा है और चौरासी कोस परिक्रमा का भी काम चल रहा है। पूरे देश में इस चौरासी कोस परिक्रमा के 20-30 लाख लोग एक साथ इस यात्रा पर आते हैं, उन सब लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैडम ने इतना बड़ा अच्छा काम किया। तीसरा जब बजट हुआ, उसमें 77 करोड़ रुपये, जो हमारे विधान सभा क्षेत्र डीग में आती है, सेऊ-परमंदरा-खोह-निगाही-पानोरी और गिरसे तक, टेल तक उस नहर को खोद कर उसके पुनरुद्धार का काम किया, जिसमें आज गुडगांव कैनाल से लेकर हमारे सैंकड़ों गांवों को सिंचाई के लिये पानी

(श्रीमती अनीता)

मिल रहा है। यह उन्होंने तीसरे बजट में किया। चौथे बजट में उन्होंने 140 करोड़ रुपये, एक मेगा हाइवे, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के बीचों-बीच से निकलता था, इतनी हालत खराब थी, जिसकी कोई हद नहीं, उसके लिये 140 करोड़ रुपये दिये, जिसका भी काम बहुत जोर से चल रहा है। यह उनका पांचवां बजट है। इस पांचवें बजट में उन्होंने हमारे यहां पर कालेज खोला और ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोली। मैं समझती हूं कि मेरे पास वे शब्द नहीं हैं, जिससे मैं मुख्य मंत्री की प्रशंसा करुं। प्रशंसा इस बात की कि हमारे क्षेत्र में हमने जितने काम मांगे, वे काम उन्होंने हमको दिये। आज हमारा पूरा क्षेत्र इस बात को कहता है कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, कांग्रेस की सरकार में वह काम नहीं हो पाता।

सभापति महोदय, इन चार वर्षों के अन्दर 45 किलोमीटर नयी सड़क बनायी। नेशनल हाइवे हमको केन्द्र सरकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी की सिफारिश से हमको मिला, जिसका नम्बर 47-ए है। इसमें भी सीकरी और नगर, जो मेरे मेन कस्बे, शहर, और नगरपालिका है, उसमें बाई-पास की भी व्यवस्था है, जिससे हमारे शहर का एक्सटेंशन भी होगा और एक्सटेंशन के साथ-साथ मैं समझती हूं कि दिल्ली से जो हमारी दूरी है वह दूरी कम होने के साथ, जो रोजगार और इण्डस्ट्रीज दिल्ली से चलकर आ सकती हैं, वे इस रास्ते से जल्दी से हमारे यहां पर आ जाएंगी। हमारे यहां पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो भरतपुर से अलवर का मेगा हाइवे बनाया था, वह नोन एक्सीडेंटल जोन के रूप में, उसमें जब मैंने बात रखी तो उन्होंने नॉन एक्सीडेंटल जोन के लिये भेजा और वहां से वह सैंक्शन होकर आया। उसके साथ हमारे यहां एक ट्रोमा हास्पिटल भी सेंक्शन होकर आया। मैं समझती हूं कि मेरे क्षेत्र के सब लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा।

हमारे यहां पेयजल की भी मैं कहना चाहती हूं। मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में सवा दो सौ गांव हैं, जिसमें 175 गांवों में, हमारी मुख्य मंत्रीजी, हमारे पेयजल मंत्री हैं और हमारी किरणजी जब पेयजल मंत्री थीं, उन्होंने हमको इतने आर.ओ. दिये कि सबने आर.ओ. के किये। गौरव पथ तो आप सब जानते हैं, गौरव पथ की तो पूरे देश में प्रशंसा हो रही है कि हमने

(श्रीमती अनीता)

पंचायत हैड-क्वाटर्स पर कीचड़ मुक्त का जो काम किया है, वह अपने-आपमें एक बहुत बड़ा काम किया है। जनता जल योजना भी आयी, पी. एण्ड टी. योजना भी आयी। बिजली की हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। परेशानी इसलिये थी कि इतना बड़ा विधान सभा क्षेत्र, इतना विस्तृत विधान सभा क्षेत्र, उसके बाद भी हमारे यहां पर 132 का एक, और तीन 33 के.वी. के थे, जिसकी वजह से बिजली का काम सही नहीं था। जो आपूर्ति थी, वह सही नहीं आती थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरे यहां पर सात नये 33 के.वी. इन चार सालों में बनाये हैं, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी हो गयी है। हमारे सब लोग इस बात को कहते हैं कि बिजली बहुत अच्छी हो गयी, काम हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अनीता (नगर): लास्ट, दो लाइनें हैं, सर।

'एक ही चौखट पर सिर झुके तो सुकून मिलता है,
भटक जाते हैं वे लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं।'

एक ही चौखट पर हम रहे, उसकी वजह से भरतपुर में सम्भाग बनाया। यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और आज भी इस बात की खुशी है कि पूरे प्रदेश में 17 कालेज हुए, उन 17 में से तीन कालेज नदबई, कामां और नगर को मिले। ए.डी.जे. कोर्ट हुए, उनमें से दो, एक कामां और एक नगर में मिले। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ऐसा अच्छा बजट कांग्रेस ने कभी सपने में सोचा नहीं था। अब इन्होंने सोचा नहीं, लेकिन बजट बहुत अच्छा आ गया। इनके पेट में जरूर दर्द हो रहा है कि अब ये जनता के बीच में ज्यादा कहेंगे। क्या कहेंगे, मैं इस बजट की बहुत प्रशंसा करना चाहती हूं और समझती हूं कि यह बजट हमारे राजस्थान प्रदेश को अग्रसर करके आगे ले जाएगा और विकास की एक नई मिसाल लिखी जाएगी। राम-राम, साहब।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामलालजी शर्मा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि आज की कार्यवाही के दौरान सदन का समय दो घण्टा और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

आज की कार्यवाही के दौरान सदन का समय दो घण्टा और बढ़ाया गया।

माननीय रामलालजी।

आय व्ययक

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का समय दिया, उसके लिये आपका आभार।

सभापति महोदय, यह चंद कागजों का एक दस्तावेज, इसको कोई दस्तावेज भी कह सकता है, कागज भी कह सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने इस दस्तावेज के माध्यम से अपनी सरकार की अभिव्यक्ति और प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को प्रस्तुत करने का काम किया है। सभापति महोदय, इस दस्तावेज के अन्दर उन सब वर्गों को छूने का काम माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया है, जो वर्ग वर्षों से इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कोई तो ऐसी सरकार आएगी, जो हमारे भविष्य को भी संवारने का काम करेगी, या कोई ऐसी सरकार आएगी, जो हमारे दर्द को भी दूर करने का काम करेगी।

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सत्य है, यह मानव की प्रकृति है कि हर आदमी एक तो सलाह देना चाहता है और हर आदमी एक आलोचना भी करना चाहता है। आलोचना करने में उसको आनन्द की अनुभूति होती है और सलाह देने में उसके अन्दर उत्साह का संचार भी होता है। यह मानव की प्रकृति है। लेकिन, सभापति महोदय, अगर आलोचना और सलाह

(श्री रामलाल शर्मा)

मापदण्डों के आधार पर की जाए, अगर वास्तविकता के आधार पर की जाए, अगर पैमाने के आधार पर की जाए तो उसका वास्तविक परिणाम भी निकल कर आता है। सभापति महोदय, सिर्फ आलोचना इस आधार के ऊपर करें कि हमने तो यह किया था, लेकिन आपने क्या किया। अगर वे ही सब काम कर देते तो वर्तमान के अन्दर राजस्थान की यह स्थिति नहीं रहती।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि गौरव-पथ योजना अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है लेकिन एक भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर बन रहे गौरव-पथ को रोकने का काम भी नहीं किया कि साहब, मैं तो अलग विचारधारा का व्यक्ति हूं और गौरव-पथ को तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर मैं तो नहीं बनाने दूंगा। एक भी माननीय सदस्य ने ऐसे विचार नहीं रखे। इसका मतलब यह है कि आलोचना सिर्फ आलोचना करनी है, इस आधार के ऊपर कर रहे हैं। वास्तविकता के अंदर तो वह भी राजस्थान का जो विकास हो रहा है, उसको स्वीकार भी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा। मारवाड़ी के अंदर एक कहावत है कि- 'गांव की स्थिति उसके बाड़े ही बता देते हैं।'

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, आपने यह सही कहा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): और यह बात मैं इस आधार के ऊपर कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल सही कहा, अभी उप चुनाव ने आपकी स्थिति जो आगे आने वाली है, वह बता दी। यह सही है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): डोटासराजी, हर चुनाव की स्थिति एक नहीं होती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह हम चार साल पहले कहते थे तो माननीय सदस्य, आप मानते नहीं थे। आप तो मोदीजी के और वसुन्धराजी के सुराज से इतने प्रफुल्लित थे कि हमको कुछ समझते ही नहीं थे। ....(व्यवधान)....

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): डोटासराजी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इतने उत्साह के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। इतने जोश के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। इतने उत्साह और जोश में आने की आवश्यकता नहीं है। आप जमीन पर आ जाओ, धरातल के ऊपर आ जाओ, ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति यदि आता है तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे खाटू-श्यामजी का स्थान ले लो, चाहे सालासर का स्थान ले लो, चाहे सांवरिया सेठ का स्थान ले लो, चाहे श्रीनाथजी का मंदिर ले लो, चाहे आपके मेहँदीपुर बालाजी ले लो या अन्य स्थान ले लो, तो वह उस मंदिर की परिस्थितियों को ही, अपनी यादों को साथ लेकर नहीं जाता है, वह पूरे प्रदेश का एक संदेश लेकर जाता है कि उस प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल के दौरान एक भी रुपया इन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए आपने खर्च किया था क्या? क्या उन धार्मिक स्थानों के ऊपर हमारी विचारधारा के लोग ही जाने का काम करते हैं? साढ़े सात करोड़ जनता उन धार्मिक स्थानों के ऊपर अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए जाने का काम नहीं करती क्या? माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम किया। अगर खाटू-श्यामजी स्थान की अगर मैं बात करूं, हमारे माननीय चिकित्सा राज्य मंत्रीजी उसी जिले से आते हैं, तीस से चालीस लाख लोग एक महीने के अंदर उस मेले के अंदर दर्शन करते हैं। इसी तरह से मेहँदीपुर बालाजी के लाखों लोग दर्शन करते हैं। रामदेवरा एक पवित्र स्थान है, वहां पर 60-70 लाख से अधिक लोग दर्शन करते हैं। इन धार्मिक स्थलों का विकास और इसी आधार के ऊपर यह प्रदेश की छवि बनती है कि प्रदेश के अंदर कैसा विकास हुआ है, प्रदेश कैसा है, प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि इसी क्रम के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र के पड़ौस के अंदर वीर हनुमानजी का मंदिर है, वह लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र है। एक छोटे से आग्रह पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, जो हमें आशा और उम्मीद थी, उससे भी कहीं अधिक बजट देकर उस मंदिर का सर्वांगीण विकास किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर समय रहते नहीं चेते, समय रहते अगर परिस्थितियों को नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी और मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने समय रहते हुए इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी खुशहाल कैसे रहे, इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को पेयजल कैसे मिले, इस आने वाली पीढ़ी को सिंचाई के लिए पानी कैसे मिले, उसकी चिंता भी इस सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, गलती तो सिर्फ एक जो यह बता सकते हैं कि आपने राजनीतिक आधार के ऊपर काम नहीं किया। आपने सबको एक परिवार के रूप में मानकर सबके हित को ध्यान में रखकर काम किया, गलती यह एक मान सकते हैं। इनके कार्यकाल के अंदर जो इनकी कार्य-शैली है, मैं उसको बताने का काम करूंगा कि अगर किसी बोरिंग लगवाने का प्रस्ताव भेजा तो उसकी माला पहले यह पहनेंगे, बोरिंग स्वीकृत हो गया, फिर उसकी भी माला पहनेंगे, फिर बोरिंग लग रहा है, उसकी भी माला पहनेंगे और फिर बोरिंग चालू हो गया उसकी भी यह माला पहनेंगे। यह कांग्रेस कल्चर है कि एक काम को चार बार जताने का काम करो और यह इतना एहसान उन लोगों के ऊपर करते थे कि अगर हम नहीं होते तो यह आपका बोरिंग लगता ही नहीं।

लेकिन, प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश में एक आदेश के आधार पर कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सारी की सारी ग्राम पंचायतों के अंदर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल्स बनेंगी। जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर गौरव-पथ बनेंगे। जितनी भी

(श्री रामलाल शर्मा)
ग्राम पंचायतें हैं उन सब ग्राम पंचायतों के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के तहत कनेक्शन होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा कि आज वर्तमान में दो प्रमुख योजनाओं के शुभारंभ की घोषणा भी की है, उनकी डी.पी.आर. भी तैयार हुई है, उनकी रिपोर्ट भी सम्पूर्ण आयी है। एक योजना, ब्राह्मणी नदी के अधिशेष पानी को बीसलपुर बांध से जोड़ने के लिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल मेरे कांग्रेस के मित्र भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि समय रहते अगर यह योजनाएं नहीं बनतीं तो आज कानून-व्यवस्था बनाये रखना भी मुश्किल होता। लेकिन आज यह स्वीकार नहीं करेंगे, आने वाले भविष्य के अंदर यह स्वीकार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी योजना जिसके अंदर पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना, इन दो परियोजनाओं से मुझे आज भी पता है जब जयपुर के अंदर पानी की समस्या आयी थी तो रामगढ़ के बांध से पानी लाया गया था। जयपुर के बाशिंदे यह कहते थे कि गये सौ साल की, सौ साल के अंदर रामगढ़ का पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई करेगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सबको पता है कि 15-20 साल की आपूर्ति के बाद में रामगढ़ बांध का पानी भी पूर्ण रूप से सूख चुका है।

बीसलपुर बांध के पानी के लिए भी सब लोग यह कहते हैं। आज बीसलपुर का बांध दौसा की पूर्ति भी कर रहा है, जयपुर की पूर्ति भी कर रहा है, अजमेर की पूर्ति भी कर रहा है और अब तो छोटे-छोटे गांवों के अंदर भी यह मांग उठने लगी है कि हमें भी बीसलपुर की योजना से जोड़ा जाए। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उसकी भी एक सीमित क्षमता है जिसके अंदर वह पर्याप्त पानी दे सकता है, उसके बाद तो अन्य सोर्स ही हमें अपनाने पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इसमें एक निवेदन और करूंगा कि इसमें 13 जिले शामिल किये गये हैं और उन 13 जिलों के अंदर झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है, सवाईमाधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, जयपुर है, दौसा है, करौली है, अलवर है, भरतपुर है और

(श्री रामलाल शर्मा)

धौलपुर है। माननीय सभापति महोदय, इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ना चाहूंगा कि यदि यमुना के पानी को जो कई मृत-प्राय नदियां हैं, या कई मृत-प्राय जो प्राकृतिक स्रोत हैं, यदि उनके अंदर भी इस यमुना के, बरसात का बहकर जाने वाला पानी जो नुकसान करता है अगर उसको डालने की योजना भी इसके साथ में बना ली जाए तो मैं मानता हूं कि जयपुर जिला ही नहीं, जयपुर जिले के आस-पास के जो अन्य जिले भी हैं, वह भी इससे लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले के अंदर कई नदियां हैं। बाण-गंगा भी है, त्रिवेणी भी है, मेंढ़ा नदी भी है, अगर इन नदियों को भी पुनर्जीवित करने की कोई योजना बनती है तो मैं यह मानता हूं कि यह सार्थक होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा कि इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के मित्र तो लोगों को उकसाने का काम करेंगे, बहलाने का काम करेंगे, उनको बहकाने का काम करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदमी की नीति और नीयत कैसी है। इस नीति और नीयत के मामले में जो युवा आशा-भरी निगाह से देख रहे थे इनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान, यह तो काम करके नहीं गये और आज जब वर्तमान के अंदर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक लाख से अधिक रोजगार के, सरकारी नौकरी देने की जो घोषणाएं बजट के अंदर की है और 31 दिसम्बर के बाद में 75 हजार नौकरियों की और विज्ञप्ति निकालने की जो बात कही है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के युवा इन सरकारी नौकरियों का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना निवेदन जरूर है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से इसको गति मिले।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि किसानों को उकसाने का काम, लेकिन किसानों के हित में कोई काम हम नहीं करेंगे कांग्रेस के कार्यकाल में। माननीय सभापति महोदय, आप इनसे डिबेट के माध्यम से कहीं पर भी पूछ लें, प्रदेश के अंदर ओलावृष्टि हुई, इन्होंने एक रुपये का मुआवजा किसान को

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं दिया। प्रदेश के अंदर शीतलहर चली तो कांग्रेस शासन के दौरान एक रुपया मुआवजे का नहीं दिया। 50 परसेंट खराबा, उसको 33 परसेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, बिजली के बिलों के अंदर रियायत देने का काम भी, जब शीतलहर या ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इन्होंने कभी भी किसान के हित में एक परसेंट भी काम नहीं किया। पर, इसके बावजूद भी किसानों को उकसाने का काम यह जरूर कर रहे हैं। लेकिन, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज का किसान भी सभी परिस्थितियों को समझता है, सब बातों को जानता है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि इस बजट के अंदर, जो 50 हजार रुपये के ऋण माफी की घोषणा की है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस शासन के दौरान किसी की सुनवाई नहीं होती थी। कोई गरीब सैंकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई गरीब है, कोई असहाय है, चलकर नहीं आ सकता, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर गलती से दु:ख-सुख पाकर इनके शासन तक पहुंच भी गया तो भी वह मुखिया से नहीं मिल सकता था। लेकिन, सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिलों के अंदर जाकर, ग्राम पंचायतों के अंदर जाकर जनता के दर्द को हरण करने का काम, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। इससे पहले किसी भी माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसा काम नहीं किया।

सभापति महोदय, आप भी अधिवक्ता हैं, कई माननीय सदस्य भी अधिवक्ता हैं, सब लोग परिस्थितियों से वाकिफ है कि न्यायालयों के अंदर आखिरकार मिलता क्या है? तारीख के अलावा और कुछ मिलना बहुत मुश्किल है। तारीख भी मिल जाए तो ठीक है, बहस के दौरान एविडेंस, एविडेंस के दौरान फिर जो भी है, और रेवेन्यू के अंदर तो स्थिति यह थी, अगर तहसीलदार से कोई चीज खारिज होती है, तो तहसीलदार से अपील के माध्यम से तीन-चार पीढ़ियां गुजार दे, लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिलता था।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पूछना चाहूंगा कि यदि लाखों लोगों को 'न्याय आपके द्वार' के माध्यम से रिलीफ मिली है तो आपको क्या पीड़ा है? कई लोगों का पैसा बचा है। कई लोग, जो अपना न्याय प्राप्त करने के लिये जमीन गिरवी रखते थे, जेवर गिरवी रखते थे, अगर उन लोगों को सुकून से न्याय मिल गया तो मेरे खयाल से आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिये।

सभापति महोदय, एक ही बात नहीं, पट्टे अभियान के माध्यम से भी बहुत-से लोगों को रिलीफ मिली है। वह आज अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। बिजनस भी कर रहे हैं, लोन भी वह ले रहे हैं।

अन्नपूर्णा रसोई की चर्चा भी इस सदन के अंदर हुई। सभापति महोदय, जिसके पास है, उसको चिन्ता नहीं कि मेरे कल का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन जिसके पास सुबह की व्यवस्था है, शाम को नहीं है, उसकी चिन्ता कौन करेगा? सभापति महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बिलकुल सत्य है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर भी दो अन्नपूर्णा रसोई वैन लगी हुई हैं। 300 प्लेट सुबह नाश्ते की, 300 प्लेट दोपहर के भोजन की और 300 प्लेट शाम के भोजन की। एक वैन से 900 की सप्लाई होती है, दो वैनों में 1800 लोगों के लिये सप्लाई होती है। सभापति महोदय, ईमानदारी की बात है 1800 में एक भी कम नहीं है। लोगों की आवश्यकता और है। वह दिल से आशीष देकर जाते हैं कि इस सरकार ने यह एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया है, जो लोगों को भरपेट भोजन रियायती दरों पर मिलने के काम का शुभारम्भ हुआ है।

सभापति महोदय, इस बजट के अंदर अन्य बातें भी कही गयी हैं, मैं उन बातों का जिक्र करते हुए एक ही निवेदन करूंगा कि यह बजट किसान के हित में है, यह बजट व्यापारी के हित में है, यह बजट युवा के हित में है और यह बजट उस गरीब आदमी के हित में है, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देखता है कि कोई योजना मेरे तक आकर पहुंचेगी और मुझे मदद पहुंचाएगी।

सभापति महोदय, एक अंतिम योजना का जिक्र करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। पैसे के अभाव में दम तोड़ते हुए लोगों को हम सबने देखा

(श्री रामलाल शर्मा)
है। पैसे के अभाव के अंदर कई बार हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती थी कि हम उस व्यक्ति की आर्थिक मदद भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमें पता था कि इसके इलाज के अंदर हजारों रुपये खर्च होंगे। हम भी बगलें झांकने का काम करते थे। लेकिन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आज भी गांवों में जाते हैं तो लोग डिमांड यही करते हैं कि मेरा नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़वा दो, मैं मेरे बच्चे का इलाज करवा लूं, मेरा इलाज करवा लूं। सभापति महोदय, यह योजना माननीय मुख्य मंत्री महोदया को इतना आशीर्वाद देने वाली योजना है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। मैं इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री महोदया को तहेदिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने सभी वर्गों का ध्यान रखा, सभी क्षेत्रों का आपने ध्यान रखा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि यह जो दस्तावेज है, इसको जनता स्वीकार करेगी और आने वाले समय के अंदर राजस्थान को मरू प्रदेश से निकालकर विकसित प्रदेश में ले जाने में कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, 12 फरवरी को जो बजट के रूप में यह 78 पेज का और 269 बिन्दुओं के साथ एक विकास का पुलिन्दा इस सदन में रखा और यह बजट अगर ओवरऑल देखें...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय शंकर सिंहजी, यह पुलिन्दा नहीं है, पुस्तिका है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या कहा? ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: शंकरसिंहजी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैंने पुस्तक बोला है, क्या बोला है?

श्री सभापति: कोई बात नहीं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): नहीं, मैंने पुस्तक बोला है। आपने सुना होगा ऐसा, मैंने पुस्तक बोला है। सभापति महोदय, मैंने पुस्तक बोला है।

श्री सभापति: कोई बात नहीं, मैंने पुस्तिका लिखा है।...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैंने पुस्तक बोला है। ठीक है, मारवाड़ी में कभी-कभी कुछ ऐसा कहें और आप...(व्यवधान)..

श्री सभापति: एहसास हो जाता है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ऐसा है, बानसूर से आने वाली विधायिका को मैं थोड़ा बता देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहने जा रहा था कि यह बजट किसान के हित में, मजदूर के हित में, युवा के हित में, व्यापारी के हित में और गांव में बैठे हुए एक अंतिम व्यक्ति के हित में है जहां अंत्योदय के नाम से भी हमने कोई न कोई योजना इस बजट के माध्यम से लागू की है। मुख्य मंत्री महोदया को जितना धन्यवाद देना चाहिये, उतना कम है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में ही माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र हो या राज्य हो, जनता के हित में कहीं न कहीं बजट इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जनता का हित रहता है, देश का हित रहता है और राष्ट्रीय राजनीति से लगाकर, राज्य की राजनीति में अगर किसी को यह सर्टिफिकेट देना पड़े कि वो तो यहां के लोग हैं, जैसा पूर्व में बानसूर से आने वाली विधायक को कहना पड़ा कि हमारी कांग्रेस की नेता, वह यहां की बहू है और वह विदेशी नहीं है, वह इटली की नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, क्या कह रहे हैं कि वह बहू है। वह बहू तो हैं ही, इसमें आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़े ही है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने इस बात की शुरूआत क्योंकी? मन में कहीं न कहीं कुंठा थी। हम यह कभी नहीं कहेंगे ...(व्यवधान)..

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक मिनट, सर्टिफिकेट तो पुरोहित ही देगा। यह कह रहे हैं न सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या?

श्रीमती अनीता (नगर): नागरिकता की जरूर बता देना कि कहां की नागरिकता है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मन में कहीं न कहीं कुंठा थी इसलिये इनको यह कहना पड़ा कि इस देश में ..(व्यवधान)..

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको भ्रमजाल था, वह निकालना था मुझे। इनकी जो मन की भाषा थी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें, व्यवधान नहीं करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो भ्रमजाल था मन का, वह निकालना पड़ा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं, आप व्यवधान नहीं करें। ...(व्यवधान)...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हम आज भी इस परम्परा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह हमारे पूर्व प्रधान मंत्री की धर्मपत्नी हैं। इसलिये ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि वह विदेशी है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि वह इटली की है। ऐसा भी नहीं कहेंगे कि उनका एक कथित ब्रदर इटली का सुरक्षा सलाहकार इस देश में आया था और उन्होंने उनके घर पर भोजन लिया था। माननीय सभापति महोदय, ऐसा हम नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसलिये आप सर्टिफिकेट मत लीजिये।

माननीय सभापति महोदय, देखिये वास्तव में ऐसा है। आज पिछले 50 वर्षों में आपने गरीब को और गरीब बना दिया, अमीर को बहुत ज्यादा अमीर बना दिया। इतनी बड़ी खाई रख दी। ...(व्यवधान)..

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, नहीं। जो माननीय सदस्य बिना अनुमति बोलते हैं वो अंकित नहीं होगा।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ऐसा है हमने क्या किया, आपने क्या किया, यह देश की जनता जानती है। आपने आज दिन तक बजट के माध्यम से काला बाजारियों का अड्डा बनाया हुआ था। आपके पूर्व वित्त मंत्रियों के पास में सारे काला बाजारी करने वाले व्यापारियों का चक्का जामा था। ऐसा है, इसलिए इस बात को मत कहो।

श्री सभापति: शंकरसिंह जी, आप बजट पर आसन को सम्बोधित करें प्लीज।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बजट है न, बजट ही है न।

माननीय सभापति महोदय, अब बात छेड़ी है इसलिए इस बात को

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

इनको सुनना तो पड़ेगा इनको। देखिये पूरी दुनिया के मानचित्र पर तीन, एक तो पूंजीवाद चला है, एक कामरेड चला है और एक जिसको कहना चाहिए एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद, हम तो जियेंगे, दूसरे का भला भी हम तो करेंगे, हम गरीब का उत्थान भी करेंगे, उस विचार को लेकर हम बजट बनाते हैं इसलिए हमारे बजट की सराहना होती है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम कृषि से चालू करें। लघु सीमांत का कर्जा माफ किया। देखिये 50 हजार तक का कर्जा माफ किया है, कुछ नहीं किया? लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को इस बात का भी निवेदन करना चाहूंगा कि लघु सीमांत के साथ सारे किसानों पर लागू करें जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर सारे किसान उसके अन्दर आ जाएंगे। ऐसा भी करना चाहिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सारा हिसाब बता दूंगा।

श्री सभापति: आप बैठे-बैठे नहीं बोलें। आप सबसे वरिष्ठ सदस्य बैठे-बैठे बोलते हैं, शोभा थोड़े ही देता है आपको, आपकी हल्की लगती है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, किसान की आय दोगुनी कैसे हो, इसकी चिंता आज तक किसी ने नहीं की। किसान को कमजोर करते गये। आज हमने यह कहा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसान जो भी वस्तु उत्पादन करता है, उसका उचित दाम कैसे मिले, राजफैड को 500 करोड़ रुपये बिना ब्याज के दिये कि किसान का आने वाले समय में, अभी जैसे मूंग खरीदी हुई, वैसे आने वाले समय में किसान मजबूत हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है और सदन में, पक्ष-प्रतिपक्ष सबको इस बात को सोचना चाहिए कि आज नरेगा के कारण से हमारे देश के और राज्य के श्रमिक की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो इतनी कमजोर होती जा रही है, मजदूर इतना कमजोर होता जा रहा है, बार-बार कर्जा लेना और कर्जे को माफ करना, यह व्यक्ति को और कमजोर करते हैं। व्यक्ति को मजबूत कैसे करना है, किसान की आय कैसे बढ़े, इस बात की चिंता हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की है। मैं इस बारे में निवेदन

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
करना चाहता हूं कि नरेगा को प्रत्येक किसान परिवार से जोड़ो। अगर किसान परिवार के घर में दस मैम्बर हैं और मस्टररोल 200 रुपये पर व्यक्ति उनका बना तो दस लोगों के दो हजार रुपये हुए, महीने के 60 हजार रुपये हुए तो यह 50 हजार का कभी ऋण माफ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब, नरेगा को आप खेती के कामों से जोड़ने की कहीं न कहीं ऐसी चर्चा बनाओ, ऐसा करना पड़ेगा जिससे आने वाले समय में उसकी आय कैसे बढ़े और किसान का जो खेती पर लगने वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा तो वो खुद भी काम करेगा। माननीय सभापति महोदय, इस बात का भी विचार करना चाहिए।

आज राजस्थान भण्डारण व्यवस्था के लिए 350 करोड़ की व्यवस्था की है। जो भी किसान के उपयोग में आते हैं, जल हौज हो, उनके लिए भी हमने वृद्धि की है, इसमें 75 हजार से 90 हजार की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात है कि पहले खाद के लिए दर- दर भटकना पड़ता था। पूर्ववर्ती सरकार के लोग जानते हैं, उनको लाइन में लगना पड़ता था, ब्लैक मार्केटिंग से आना पड़ता था, आज यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गयी और सरकार ने भी उनके भण्डारण की व्यवस्था की, उनके लिए कोई भी सब्सिडी है वो सरकार देगी। ऐसा करते हुए आज किसान को सही समय पर यूरिया मिलता है तो वो अपनी खेती में काम करता है।

माननीय सभापति महोदय, गायों की बात करते हैं, बहुत चिल्लाते थे, बहुत बातें करते थे लेकिन वास्तव में गायों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो 2003 से 2008 में भी हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने किया था और अभी भी यह घोषणा हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने की है, नंदी शाला, निराश्रित गौवंश और पूरे जिले में 50 लाख रुपये देकर कर गौशाला को नंदी शाला बनायी जाए तो पूरे जिले की समस्या का निवारण होगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक विषय और निवेदन करना चाहूंगा। नगरपालिका मंत्री और पंचायती राज मंत्री दोनों इस बात को लें कि जितना हर गांव में, ग्राम पंचायत में गोचर होता है उस गोचर का पांच परसेंट, दस परसेंट निराश्रित गौवंश के लिए आरक्षित कर दो जिससे सामाजिक संस्थाएं इधर-उधर भटकने वाले गौवंश को इकट्ठा करके उसकी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
सार संभाल करें, नहीं तो अतिक्रमण होते हैं। गोचर में से पांच परसेंट, दस परसेंट निराश्रित गौवंश के लिए एक आदेश करके उसको आरक्षित कर देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गौपालन मंत्री हैं, अब हमने इनका अनुदान भी बढ़ा दिया है। ...(व्यवधान)... गौशालाओं का अनुदान बढ़ा है गौपालन मंत्री के द्वारा। ...(व्यवधान)... चलो, चलो, कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों का जाल बिछाया है। 49,878 किलोमीटर सड़कों का रिन्युअल वगैरह का कार्य करने के बाद आज सभी ने कहा है, कह रहा हूं गौरव पथ है, एक अफसोस यह होता है कि क्या प्रतिपक्ष के व्यक्तियों के यहां गौरव पथ नहीं बना, बना है न? कभी तो बड़ाई कर लो। कभी ऐसी सीमेंटेड रोड आपने पंचायतों पर देखी है क्या? कभी तो बड़ाई करो, कभी तो बड़ाई करो।

आज मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि सारी, 200 की 200 विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर नयी सड़क के लिए फंड की घोषणा की है। यह घोषणा सबके लिए है, यह आपके लिए भी है, तो इसका तो कम से कम धन्यवाद दे देते। ...(व्यवधान)... बिलकुल लेंगे 200 की 200, देखिये, आपके विधान सभा में ही बनेंगी, अब कैसे बनेगी, क्या बनेगी लेकिन बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 3464 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का 1622 करोड़ की लागत से, कहने का मतलब यह है कि हरेक मद में हमने बजट की व्यवस्था की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हरेक व्यवस्था में हमने बजट की व्यवस्था की है और आज की तारीख में ऐसी मेगा हाईवे की सड़कें बनायी हैं, माननीय सभापति महोदय, आप उस पर भले ही हैलिकॉप्टर उतारो। ऐसी गुणवत्ता की सड़कें बनायी हैं और चारों तरफ जाल फैलाया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सभापति महोदय, इसमें इतनी गुणवत्ता है। पहले क्या था, आप लोग, यह कांग्रेस के लोग उद्घाटन करके जाते थे सातवें दिन सड़क से पत्थर निकलते थे, यह होता था। गुणवत्ता, गुणवत्ता, आज सड़कों पर हैलिकॉप्टर उतारो।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, रोड़वेज में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है 80 वर्ष से ऊपर के बुजुगों के लिए। देखिये क्या होता है, एक गांव का गरीब व्यक्ति जब रोड़वेज में जाए, बड़े मान और सम्मान के साथ यात्रा करेगा न तो उसकी बहुत बड़ी दुआ लगेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि आपने रोड़वेज पर तो कर दी अब जो लोक परिवहन चालू की है, उन पर नहीं है तो रोड़वेज और घाटे में जाएगा, उन पर भी अपन करें। जिनको भी राजस्थान सरकार की तरफ से हम संरक्षण देते हैं उन पर भी यह योजनाएं लागू होनी चाहिए। रोड़वेज को और बढ़ाने के लिए क्योंकि देखो, यह कोई व्यापार नहीं है यह जनता की सेवा के लिए निगम बनाया हुआ है, इसको और मजबूत करने के लिए इस पर करना चाहिए। बाकी यह जो योजना लायी गयी है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज जनता की मांग को देखते हुए 52 हजार करोड़ की लागत की परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं।

सिंचाई में मूलभूत ढांचा कैसे बढ़े। नदियों से नदियों को जोड़ने वाला विषय है। यह सारी योजनाएं सबने गिनाई हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं।

सभापति महोदय, मैं विस्तार से एक-एक योजना नहीं ले रहा हूं। बस दो मिनट। मैं खाली सारांश ले रहा हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके यहां कितना पानी है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मेरे यहां इतना पानी है कि आप चाहे 4 बार नहाओ दिन में।

श्री सभापति: आप एक दूसरे का पानी नहीं नापें। आप अपना-अपना वक्तव्य दें बस।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, साबरमती बेसिन से जवाई की योजना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और 70 साल तक किसी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पहली बार साबरमती बेसिन से जवाई बांध पुनर्भरण की

योजना शुरू की है। इससे पाली, जालौर और सिरोही, तीनों जिलों की जनता आपकी बहुत-बहुत प्रशंसा करेगी। यह पेयजल के लिए काम आएगा। पेयजल की योजना इससे बनेगी। मेरा जालौर और आहौर 110 मीटर के ढलान में हैं जवाई से। आप उससे पेयजल की योजना भी कर सकते हैं। सिंचाई की योजना भी कर सकते हैं।

सभापति महोदय, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: बहुत टाइम हो गया।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पाइंट तो लेने दो मुझे।

सभापति महोदय, एक सबसे मुख्य बात है कि नदी के प्रवाह पर नैचुरल बांध बनाया जाता है। अब वह नदी डार्क जोन में आ जाती है। नदी के डार्क जोन को भी सही करने के लिए पूरे राजस्थान के लिए यह होना चाहिए कि उस बांध में जो पानी रोका है उसका कुछ प्रतिशत बरसात के समय नदी में छोड़ देने से नदी जीवित रहेगी। पुराने जमाने में गांव वहां बसते थे जहां नदियां होती थी। यह नदियों से नदियां जोड़ने वाली बात है। यह विषय भी होना चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी वहां आकर के देखें, 17 गांवों का भैंसवाड़ा डाइवर्जन, इसको कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। सूकड़ी नदी जो जवाई में गिरती है और भैंसवाड़ा से डाइवर्ट होकर 17 गांवों को छूती हुई वापस जवाई में गिरती है, पूर्व की सरकार ने बंद कर दिया। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी जालौर पधारीं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हमने वहां 50 लाख से बहुत अच्छे गेट बनाए। उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने 1 करोड़ 65 लाख की घोषणा जालौर में की, जिससे उस पर एक बड़ी कैनाल बन रही है, 16-17 गांव आनंदित हो गए। इस बार सारे गांवों को छूती हुई यह नदी वापस जवाई में गिरी। यह मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का भी एक पार्ट हो गया। ऐसा एक कार्यक्रम हमने किया है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, पेयजल में भी 36 परियोजनाओं को पूरा करके 16,439 गांव, ढाणियों में गुणवत्तायुक्त पानी पहुंचाया है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, मुझे 5 तो मिनट हुए हैं। आपने मुझे 10 मिनट बोला था। ऐसा क्या करते हो।

श्री सभापति: 25 मिनट से ऊपर हो गये हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अच्छा, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं। बड़ी-बड़ी योजनाएं चाहे बीसलपुर, डूंगरपुर वाली योजना हो, बूंदी जिले की हो, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर की योजना, जयसमंद झील में डालने की हो, इसमें हर जिले का विचार किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि 2003 से 2008 के अंदर नर्मदा का पानी गुजरात से जालौर जिले में लाकर सांचौर जहां बिलकुल रेगिस्तान था, वहां अनार के बगीचे हो गये है। पूरे जालौर जिले को उससे पेयजल पिलाने की योजना है। एक हमारा ईआर प्रोजेक्ट जो है, वह अधूरा है, उसको भी हम कैसे पूरा करें, इस बात की भी हमें चिंता करनी होगी।

सभापति महोदय, गांव, ढाणी का व्यक्ति जो सुदूर रहता है, उसने कभी सोचा था कि मेरे वहां भी लाइट आएगी? दीनदयाल योजना लाकर वास्तव में ऊर्जा मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे सुदूर गावों, ढाणियों में लाइट जा रही है। इसके लिए उनका बहुत-बहुत अभिवादन करना चाहूंगा। बाकी 33 केवीए के जो हमें दिये हैं, वह तो दिये ही हैं। वह सब जगह किये हैं। सबसे बड़ी बात 2012 तक 2 लाख कृषि कनेक्शन लंबित थे। 2003 में भी हमने बहुत बड़ा गैप पूरा किया था। अभी भी हम ही कर रहे हैं। बोलो किसानों की हितैषी कौन सरकार हुई? हमारी सरकार हुई। आपने हमेशा किसानों के साथ धोखा किया है।

सभापति महोदय, एक-दो मिनट में पूरा करुंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद। हो गया है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बस हो गया, हो गया। एक मिनट। आज शिक्षा में 77 हजार अध्यापकों की और उसके साथ टोटल मिलाकर 1

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लाख 8 हजार सरकारी नौकरियों में भर्ती करके यह अपने आपमें एक रिकार्ड कायम करेंगे। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, कौशल विकास में 13 लाख भर्तियां, यह भी अपने आपमें एक इतिहास है। मैंने आहौर की आई.टी.आई. की मांग की है। मेरे आहौर में कालेज दिया। साढ़े 6 करोड़ की लागत से कालेज बन रहा है। हरियाली देवासी हॉस्टल, मतलब आवासीय विद्यालय, यह रेबारी जाति जो मालवा और मेवात में चराने जाती थी, उनके बच्चे कहां पढ़ें, उनकी भी चिंता मुख्य मंत्रीजी ने की। बच्चे छोड़कर के जाओ, हम पढ़ाई, लिखाई, खाने, पीने, पहनने की सारी व्यवस्था करेंगे। उस समय 2004 में हमने 4 करोड़ रुपये लगाकर के आवासीय विद्यालय बनाया। आज वहां 480 बच्चे पढ़ रहे हैं। देवासी समाज का पहला बैच इंजीनियर बनकर के निकल गया है। अभी साढ़े 7 करोड़ रुपये लगाकर के साइंस लैब, और उसमें कमरों की वृद्धि कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, एक सैकिण्ड और, बस हो गया। आहौर कॉलेज में कॉमर्स चाहिए, वह तो है ही।

महिला बाल विकास विभाग में सबसे मजबूत काम इन्होंने 1 लाख 84 हजार महिला कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर के किया है। इसका मतलब सीधे 1 लाख 84 हजार परिवारों को फायदा दिया है। यह बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता वगैरह के लिए वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है। शुभ लक्ष्मी योजना, मैरिट वाले में सारा ही काम किया है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, एक सैकिण्ड, हो गया, हो गया। चिकित्सा वाले मामले में भी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आपमें बहुत बड़िया योजना है। नर्स ग्रेड की भर्ती और फिर 28 पीएचसी, इसमें से एकाध पीएचसी हमको भी मिलेगी।

श्री सभापति: सभी भर्तियों का विवरण आ चुका है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, आज दिन तक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
पत्रकारों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पत्रकार भी सत्य लिखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। हमने उस पत्रकार के बारे में भी सोचा। 25 लाख तक के लोन का भी सोचा है। हर वर्ग को छुआ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी हमने छुआ है।

सभापति महोदय, मेरे चार-पांच पाइंट हैं। एक जनजाति विकास के लिए, जालौर जिले में 19 प्रतिशत जनजाति का बंधु रहता है। हमने पाली, जालौर, सिरोही में एक एकलव्य मॉडल स्कूल मांगा है। जनजाति विभाग वह हमको दे देगा। जनजातियों के लिए आज सुंदर सिंह भंडारी और भैरोंसिंह जी शेखावत के नाम पर जो योजना चलाई है, वह भी अपने आपमें बहुत ही बढ़िया है।

सभापति महोदय, अन्नपूर्णा, राशन डीलर, गेहूं वितरण वाले राशन डीलर्स का भी हमने कमीशन बढ़ाया है।

श्री सभापति: वह सब आ चुका है। माननीय सदस्य सोनादेवी जी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, एक सैकिण्ड, हो गया, हो गया। अभी मंत्री महोदय यहां बैठे थे। मेरे आहौर में एक इंडोर स्टेडियम दें। आईटीआई मांगी है। कौशल विकास, यह भी अपने आपमें एक बहुत बड़ा काम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तीसरी बार हैं इधर से।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट। आज रिफाइनरी वाली बात चली थी। सभापति महोदय, विद्वान सदस्यों ने भी कहा। लेकिन वास्तव में रिफाइनरी में 40 हजार करोड़ की जो बचत राजस्थान की जनता के लिए की है, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदया को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, बजरी खनन, यह विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने पट्टे देकर के करोड़ों रुपयों का घपला किया था, उसके बंद कर दें। नदी के ऊपर बजरी बहती है। उस पर खनन में मत लो आप। बजरी की एक रायल्टी बनाकर जिस तरह से पहले चलता था, लेबर ओरिएन्टेड कर लो, उसमें मशीनीकरण खतम कर दो। इससे बजरी का बहुत बढ़िया काम हो जाएगा।

श्री सभापति: बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। सोनादेवी जी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, एक सैकिण्ड। गृह विभाग में आज पुलिस को चुस्त करने की जरूरत है।

श्री सभापति: हो गया। हो गया शंकरसिंह जी। आहौर से आने वाले माननीय सदस्य आपने सभी विषयों पर बहुत गंभीरता से वक्तव्य दिया है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पुलिस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से अपराध रुक पाएंगे। पुलिस को मजबूत करने के लिए आधुनिक गाड़ियों की जो व्यवस्था की है, उसके लिए भी मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, लॉ मिनिस्टर यहां पर विराजे हैं। मुंसिफ कोर्ट, एसीजेएम फर्स्ट के अंदर सारे आहौर के केस जालौर में चलते हैं। 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एसीजेएम फर्स्ट जो हमारे आहौर के केस लेता है, उसको जालौर की जगह आहौर में ट्रांसफर कर लें तो बहुत बड़ा काम होगा।

सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत प्रशंसा के साथ जो हमें बजट दिया है, यह चहुंमुखी विकास करने वाला और इससे राजस्थान एक विकसित राज्य बनेगा। राजस्थान हर ओर मजबूती से बढ़ेगा। हर वर्ग की तरफ से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य सोनादेवी जी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

भारतीय किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। किसान की बहू-बेटी हूं इसलिए, किसानों की पार्टी से सम्बन्धित हूं इसलिए, किसान का दर्द और उनकी भावनाओं को व्यक्त करती हूं,

(श्रीमती सोनादेवी)

किसानों से अब कहां मुलाकात करते हैं
बस रोज नये ख्वाबों की बात करते हैं,
कोई परेशान है सास-बहू के रिश्तों में
किसान परेशान है कर्ज की किश्तों में।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की, उनके लिए आभार परन्तु आप थोड़ा सा पिटारा और खोलें, अन्नदाता के लिए थोड़ी सी दात और बिखेरें, जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से विभिन्न बैंकों से ऋण ले रखा है, उसको भी ब्याज और कर्ज से मुक्त करने के लिए घोषणा करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करती हूं।

माननीय सभापति महोदय,

किसान की समस्या खतम नहीं होती,
बाकी के पास पैकेज अस्सी हैं,
अंत में समस्या खतम करने के लिए
किसान चुनता तो रस्सी है।

माननीय सभापति महोदय,

उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है किसान
घायल भी उम्मीदों से और जिंदा भी उम्मीदों से है किसान।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। पक्के खाळे बनाने के लिए या नहरों की जो पुलियाएं नीची हो चुकी हैं, उनके लिए भी कोई प्रावधान सरकार की तरफ से बजट में नहीं आया है। करणीजी माइनर, खाटा माइनर और निजामुद्दीन, सरदारपुरा, बीका माइनर और गोमावाली माइनर का पुनर्निर्माण करने के लिए मैंने बार-बार सरकार से आग्रह किया लेकिन बजट में मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया। समझ में नहीं आता कि कृपा कहां रुकी हुई है। वर्षा के मौसम में गंग नहर में हमेशा ही केळी की समस्या रहती है जिसका बजट में समस्या समाधान के लिए कोई प्रावधान नहीं दिखाई दिया।

(श्रीमती सोनादेवी)

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में किसानों को अगर हक देना चाहते हैं तो एटा सिंगरासर माइनर के निर्माण की मंजूरी दें। इससे 54 गांवों के किसान आपके इस बजट को ऐतिहासिक बना देंगे। एटा सिंगरासर माइनर के लिए 5 फरवरी को जब बजट भाषण हो रहा था उस दिन भी सैंकड़ों औरतों और हजारों किसानों ने सूरतगढ़ में धरना दिया था। उन पर लाठी चार्ज किया गया, सरकार ने किसानों को पीटने का काम किया है। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, गंगानगर के किसानों को बचाने के लिए फिरोजपुर फिल्टर का तुरंत निर्माण करवाया जाना चाहिए, जो बजट में कहीं नहीं दिखा। पंजाब के हिस्से की 168.5 बुर्जी का निर्माण 1958 में हुआ था जिसकी अवधि 50 साल की थी, जो 2008 में पूर्ण हो चुकी है। फिर भी 10 वर्ष बाद इसके निर्माण की किसान बाट जोह रहा है। मैं पूछती हूं कि

सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा?
सिंहासन अपनी चालों से
कब तक किसान को छलता रहेगा?
वह क्या जाने पीर पराई
जीदे अंदर दर्द न राई

माननीय सभापति महोदय, आईजीएनपी और गंग नहर के किसानों की लगातार बारियां पिट रही है। मैंने पहले भी बात रखी थी कि हनुमानगढ़ में जब रेगुलेशन की बैठक होती है, हमारी डिमांड हमेशा से रहती है कि चार में से दो समूह चलाये जाने चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात का प्रस्ताव हमारा कभी मान्य नहीं होता है तो मैं आसन से और सरकार से गुजारिश करूंगी कि मेरा प्रस्ताव जो मीटिंग में रखा गया है उसको या तो खारिज कर दें या मेरी बात को मान लिया जाए कि चार में से दो समूह चलाए जाने चाहिए। क्योंकि सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के किसानों को आईजीएनपी नहर का रेगुलेशन बना हुआ है। रबी की फसल जो अभी तैयार हो रही है, उसमें एक महीने बाद पानी की बारी आ रही है, गिनी-चुनी बारियां दी गयी हैं इस बार। पोंग

(श्रीमती सोनादेवी)

डैम का पहले भी 1270 फीट था, उसको डाउन करके, 1270 फीट डाउन करके, किसानों को चार में से दो समूह पारियां पहले भी दी गयी थीं तो इस बार क्यों नहीं?

माननीय सभापति महोदय, जानना चाहती हूं सरकार से, आप बेहतर करें, आपने कहा कि

आप बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है,
किसी के लिए बेहतर करें तो फर्क पड़ता है।
किसानों को झूठी कर्ज मुक्ति और
हाथ में झुनझुना दें तो फर्क पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, बात करें सीमावर्ती किसानों की तो वह पाकिस्तान जैसे हालातों से जूझ रहा है। वहां पर गांव 24 घंटों में से केवल मात्र 2 घंटे ही बिजली की सुविधा ले पा रहे हैं, इससे क्या तो वह किसान सिंचाई कर लेगा और क्या वह छात्र पढ़ाई कर लेगा? यह ऊर्जा की पॉलिसी है? आखिर लोचा कहां है? यह लाइट आखिर जाती कहां है? आपके बिजली सुधार कार्यक्रम कहां चल रहे हैं? मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नया जीएसएस नहीं है। बस स्टैंड, बांडा में हमेशा से मांग रही है कि बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई काम नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार बीएडीपी में बजट में 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में 20 वर्षों से करोड़ों रुपयों का बजट ले रही है लेकिन आज भी सीमावर्ती एरिया पेयजल, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि बजट संशोधन में 10 से 20 किलोमीटर का दायरा बढ़ाकर, बजट को भी और बढ़ाया जाकर, वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर, करणपुर, गंगानगर, सूरतगढ़ क्षेत्र के सैंकड़ों किसानों की हजारों बीघा भूमि खसरा में पड़ी है। मैं सरकार से आशा करती हूं, राजस्व मिनिस्टर साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि खसरा भूमि वाले किसानों को किला बंदी करके इस समस्या से निजात दिलायी जानी चाहिए।

(श्रीमती सोनादेवी)

माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट विलेज राजस्थान में सरकार ने बहुत से घोषित किये हैं। 3000 की पापूलेशन की पाबंदी लगाकर स्मार्ट विलेज रायसिंहनगर को दिये ही नहीं। मैं बजट में संशोधन की डिमांड करना चाहूंगी कि 2000 की पापूलेशन वाले विलेज को स्मार्ट विलेज में लिया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में चिकित्सा सेवा का लगातार अकाल पड़ा हुआ है। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, यूं लगता है कि

जिनको पंछी की नहीं रही पहचान,

कह दूं कैसे कि उन्होंने सुनी कोयल की तान

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी विजयनगर, रायसिंहनगर, समेजा कोठी, महिला चिकित्सालय, सभी जगह पद खाली हैं। मैं सदन के माध्यम से श्रीगंगानगर क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग मेडिकल कालेज की जो थी, कल पुन: शुरू करवाने पर मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, सरकार और साथ ही कैबिनेट मंत्रीगणों का। मैं उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि मेडिकल कालेज बनाने का बिंदु प्रस्ताव में लिया है।

माननीय सभापति महोदय, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या है। मैं पिछले चार साल से लगातार मांग करती आ रही हूं कि हमारे यहां की पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए। प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली, प्रत्येक मौहल्ले में, पंचायत स्तर पर प्रमाण पत्र लेकर पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि बजट में गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान में 100 हैंडपम्प देने की घोषणा की है। मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो 100 हैंडपम्प हैं वह गंगानगर जिले के लिए तो नाकारा है क्योंकि वहां पर फ्लोराइड युक्त पानी है। इन हैंडपम्पों का हम क्या करें? माननीय सभापति महोदय, बजट में संशोधन करके 100 हैंडपम्प की जगह हमारे क्षेत्र के प्रत्येक विधायक को जो हमारा चैनल नहर से लेकर

(श्रीमती सोनादेवी)

वाटर वर्क्स तक खुले में चल रहा है उसके लिए पाइप लाइन दिए जाने का मैं निवेदन करना चाहूंगी, इस ओर भी सरकार ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र बोर्डर एरिया में है शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने कई विद्यालयों को मर्ज कर दिया है और बोर्डर एरिया के दूरदराज गांवों में पहले तो पूर्व सरकार ने आठवीं तक फेल नहीं करके शिक्षा का भट्टा गोल करके बैठा दिया, अब वर्तमान सरकार ने पांचवीं तक के स्कूलों को मर्ज कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो स्कूल मर्ज किये है जिनमें पर्याप्त मात्रा में बच्चे हैं, उन स्कूलों को पुन: संचालित किया जाए और जहां-जहां वास्तव में डिमांड है, क्रमोन्नत करें। दसवीं से बारहवीं तक क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की है कि इतने क्रमोन्नत किए जाएंगे, रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों को भी उसमें लिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करती हूं कि शिक्षा को ट्रिपल-पी मोड में ठेके पर देने या शिक्षा को बेचने का काम किया है इसको भी आप वापस लें ताकि शिक्षा में सुधार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करती हूं कि आबकारी में मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में अनेक अवैध ब्रांचें चल रही हैं।

नशामुक्ति, मैं चाहती हूं कि इस ओर भी सरकार ध्यान दे कि अवैध ब्रांचों को बंद किया जाए और गांव के अंदर सार्वजनिक स्थान पर या किसी स्थान पर अवैध ब्रांचें या शराब के ठेके हैं, उनको गांव से कम से कम एक किलोमीटर तक बाहर किया जाना चाहिए, यह मैं सरकार से आशा रखती हूं।

इसके साथ ही सरकार ने सिंचाई वाले एरिया के लिए घोषणा की है कि आगामी जो फसल आएगी....रबी की फसल का मामला तो कर के रूप में ले लिया है सरकार ने और आगामी जो खरीफ की फसल आएगी, उसका मामला हम माफ करेंगे। मामला माफ करने से किसान कर्ज मुक्त नहीं होगा, मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि इस ओर कभी किसी भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया था कि किसान पर कर लगा हुआ है। मामला तो कुछ भी नहीं है। मेरे खयाल से प्रति बीघा 25 रुपये 6 महीने में सिंचाई वाले काश्तकार से लिए जाते हैं। 6 महीने में प्रति बीघा 25 माफ किये हैं आपने। मैं मांग करती हूं कि क्रेडिट कार्ड्स से

(श्रीमती सोनादेवी)
विभिन्न बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा उठा रखा है, उनका भी अगर आप शत प्रतिशत कर्जा माफ न कर सकें तो कम से कम 25 परसेंट को...

श्री सभापति: रिपीट नहीं करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): कम से कम 25 परसेंट कर्जे को मुक्त करें ताकि किसानों के अंदर पचाने की बजाय भरने की या लौटाने की बात आए। इसके साथ ही मैं गंगानगर के किसानों की बात भी कहना चाहूंगी। शुगर मिल द्वारा हर वर्ष गन्ने का खरीद मूल्य पंजाब एवं हरियाणा द्वारा निर्धारित मूल्य का औसतन भाव तय किया जाता है। वर्ष 2018-19 का भी पंजाब एवं हरियाणा द्वारा घोषित कर दिया गया, परंतु गंगानगर शुगर मिल ने अभी भी मूल्य तय नहीं किया है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैं मांग करती हूं कि हरियाणा में जो खरीद है 320 रुपये और पंजाब में 310 रुपये, गंगानगर के किसानों को भी प्रति क्विंटल के हिसाब से औसतन 320 रुपये होने चाहिए, जो कि आज तक किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से मात्र 275 रुपये आप दे रहे हैं। प्रति क्विंटल के हिसाब से जो 55 रुपये का घाटा आप दे रहे हैं, अगर आप इसमें संशोधन कर देंगे, प्रति बीघा के हिसाब से किसान को 11 हजार रुपये की आमदनी होगी और उसको राहत मिलेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): लास्ट एक मिनट के लिए। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि 200 क्विंटल गन्ना उत्पादन होता है किसानों का और किसान के साथ घोर अन्याय हो रहा है। किसान हित की बात सरकार करती है। क्या यह किसान हित की बात है कि गन्ना उत्पादक किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं, क्योंकि इतना बड़ा भाव में अंतर है। किसान कैसे सहेगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): लास्ट एण्ड फाइनल। शुगर मिल से संबंधित किसान जब अपना गन्ना लेकर जाते हैं तब गैट पर एरिया लगता

(श्रीमती सोनादेवी)

है। पूरे देश में गैट पर एरिया नहीं लगता तो गंगानगर किसान पर गैट एरिया क्यों? मैं यह भी मांग करना चाहूंगी।

श्री सभापति: हो गया, बस हो गया। धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धर्मपाल जी चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 12 तारीख को राजस्थान का 2018-19 का जो ऐतिहासिक बजट पेश किया, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा। चाहे बेरोजगार हों, चाहे किसान हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे कर्मचारी हों, हर वर्ग का ध्यान रखकर इस बजट को पेश किया है। सन् 2014-15 का बजट पेश करते समय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो सुराज संकल्प यात्रा में वादे किये थे, उनको पूरा करने के लिए पहले साल से ही काम चालू कर दिया था। कांग्रेस की तरह नहीं कि चार साल का इंतजार करें और पांचवें साल में रेवड़ियां बांट दें। इनका जनता ने जो इलाज किया, उसी की मेहरबानी है कि आप 21 सीट पर आये।

विपक्षी भाई कहते हैं कि यह बजट चुनावी बजट है। मैंने 2013-14 का भी बजट पढ़ा था, जो माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा पेश किया गया था। उसमें आपने जो-जो वादे किये, जो घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं के बाद भी साड़ी बांटने का काम, फ्री में गेहूं देने का काम, यह जो आपने आखिरी में किया, उसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान की जनता ने आपको 110 से 21 पर पहुंचाया। हमारी भी सरकार रही थी। पहले आपकी सरकार रही थी 1998 से लेकर 2003 तक, जब आप 156 सीटें जीतकर आये थे। उसके बाद में जब चुनाव हुआ तो आपकी दुर्दशा हुई और आप 56 सीटों पर आ गये। हमारा राज भी था, हम 120 सीटों पर जीतकर आये थे हम 78 सीट पर रहे और आप भी पूर्ण बहुमत से नहीं आये थे उस समय। आपको भी 94 सीटें ही मिली थीं। जोड़-तोड़ से बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्यों को तोड़कर और अन्य सदस्यों को मिलाकर आपकी संख्या पूरी हुई थी। इतना बड़ा कोई बहादुरी का काम आपने नहीं

(श्री धर्मपाल चौधरी)
किया था। अब 3 उप-चुनाव हुए हैं। मैं भी सन् 1999 में जब उप-चुनाव हुए थे, उस उप-चुनाव में ही जीतकर आया था, जब 156 सीट आपकी थी। 6 सीटों पर उस समय राजस्थान की विधान सभा के चुनाव थे। 6 मैम्बर हमारे विधान सभा के लोक सभा में चुने गये थे, उसमें मात्र 2 सीटों पर आप जीते, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 सीटों पर निर्दलीय जीते और एक निम्बाहेड़ा की सीट तो आप सिर्फ 11 वोटों से जीते थे। इस तरह से आप जो बहुत खुश हो रहे हो कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया और तीन सीटें जीतने के बाद में, अब आज आप कितने जने बैठे हैं यहां पर? राजस्थान का बजट पेश हो रहा है, राजस्थान की जनता सुन रही है, राजस्थान के किसान की चिंता की बात करते हो, राजस्थान के बेरोजगार की बात करते हो और बैठे कितने जने हो? आपको है क्या किसी की चिंता? चिंता की तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने।

राजस्थान के अंदर जिन बातों को लेकर हम आये हैं, उनको हम पूरा करेंगे। आपने अपने समय में हर जगह शहर में बोर्ड हो, हाइवे पर बोर्ड हो, एक मैट्रो ट्रेन और एक रिफाइनरी, ये हमने इतने बड़े दो तीर मार दिये कि पूरे राजस्थान की जनता आपको वोट दे देगी। मिल गये आपको वोट? मैट्रो ट्रेन का कोई बजट रखा नहीं, रिफाइनरी का कोई बजट रखा नहीं। अब हमारी मुख्य मंत्रीजी ने चिंता करके कि कहां पर रिफाइनरी बनेगी, कहां नहीं बनेगी।

कहां नहीं बनेगी और उसका उद्घाटन, शिलान्यास आपने सोनिया गांधी से करवाया। अब राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार करोड़ रुपया इस रिफाइनरी को शुरू करने में बचाया है। हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी से शिलान्यास कराना और उसका काम भी शुरू कर दिया। इससे वहां के एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और बाड़मेर जिले के तस्वीर ही बदल जाएगी। ये काम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किये हैं।

देश की आजादी के बाद में किसान की बात करने वाली पार्टी, 'गरीब का साथ कांग्रेस का हाथ' कहकर किसान को हाथ का निशान दिखाया, पर आपने गरीब और किसान के लिए क्या किया? देश की आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 साल राज किया हो और वो पार्टी आज भी किसानों का भला

(श्री धर्मपाल चौधरी)

करने की बात करे तो आपने क्या इस राजस्थान की विधान सभा में एक बार भी किसान का कर्जा माफ किया है पहली बार कर्जा माफ किया था भैरोंसिह जी शेखावत ने और दूसरी बार अब कर्जा माफ किया है, किसान का ध्यान रखा तो यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने कि आज किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ किया है। इसके लिए अब आयोग भी बना दिया। आयोग का गठन कर अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो उस आयोग के माध्यम से उन लोगों को भी मुआवजा मिलेगा जो उसके अन्दर अपनी शिकायत लेकर जाएंगे, जांच करने के बाद सही होगा तो उनको भी मुआवजा देने का काम यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया और किसानों के लिए अनेक योजनाएं घोषित कीं।

शिक्षा के अन्दर सबसे बड़ा काम कि हर पंचायत में एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जिससे हमारे गांव में रहने वाले गरीब के बेटा-बेटी उसमें पढ़ें, सबको अच्छी शिक्षा मिले तो एक ही बार में 9871 पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की। घोषणा ही नहीं, आज पूरे राजस्थान के अन्दर.....

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अभी तो बाकी है। मैंने तो यही कहा है कि अभी तक बाकी है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप इतने सीनियर आदमी हो और बैठे-बैठे बोल रहे हो। आपने तो कुछ किया नहीं, शिक्षकों की भर्ती की नहीं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि अभी तक बाकी है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आपने कुछ किया नहीं और आप करते तो 21 नहीं आते। आगे आएगा वो तो देखेंगे। इस तरह से 9871 पंचायतों में हर पंचायत में स्कूल क्रमोन्नत कर दिये और कोई पैण्डिंग नहीं है। 77 हजार शिक्षकों की भर्ती, आज जो टीचर्स की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए 77 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और यह भर्ती दिसम्बर से पहले-पहले हम करेंगे, यह मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। आपकी तरह नहीं है कि शिलान्यास करके चले गये और हमारी सरकार ने आने के बाद उन कामों को किया। आप बड़ाई लेते हुए कि यह तो हमारी घोषणा थी, तो

(श्री धर्मपाल चौधरी)
घोषणा तो कुछ भी कर देंगे लेकिन काम क्या किया?

आज राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रत्येक पंचायत में गौरव पथ हो, गांव में चलने के लिए गांव के लोगों को सड़क भी अच्छी मिले, मय नाली सीमेंटेड रोड बने, इसका काम भी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जीने किया। इसके साथ-साथ सड़कों का सुदृढ़ीकरण, लिंक रोड, स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे। आज सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। यह नहीं है कि आपकी तरह, जब हम सुराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ गये थे तब सड़कों की हालत राजस्थान में देखी थी। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे थे और आज सड़कों की हालत यह है कि अच्छी सड़के बनने में राजस्थान का देश में पहला नम्बर है। एक लाख 84 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ देते हुए सबका मानदेय बढ़ाया। यह भी हमारी मुख्य मंत्री जी ने किया। अलवर जिले में एनसीआरपीबी के अन्दर 963 करोड़ की सड़कों का निर्माण, जिसमें 86 करोड़ की सड़कें मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में बनाने का काम किया। आरआईडीएफ-24 में 800 करोड़ का काम होगा। पेयजल हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100 हैण्डपम्प देने का काम किया, 500 नये आर.ओ. प्लांट लगेंगे। इसके पहले पानी की व्यवस्था का सुचारू रूप से हमारी सरकार ने समयबद्ध तरीके से काम किया। जहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी था वहां आर.ओ. लगाये हैं। उसकी सफलता के कारण 500 आर.ओ. नये लगाने की भी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हमारी सरकार ने ऊर्जा के अन्दर, बिजली आपके समय में कितनी आती थी और आज बिजली की हालत क्या है? हमने 6700 मेगावाट बिजली की वृद्धि की। इसके साथ-साथ अक्षय योजना के अन्दर भी हमने 3 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता विकसित करने का काम किया। 2 लाख किसान भाई जो अपने कृषि कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे थे, 1 जनवरी, 2012 तक के जो 2 लाख कृषि कनेक्शन पैण्डिंग हैं उनको भी कनेक्शन देने की हमारी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और 7 लाख घरेलू कनेक्शन पैण्डिंग हैं उनको भी सरकार कनेक्शन देगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पांच मिनट बोले नहीं और धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत ज्यादा हो गया।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): पहली बार तो मौका दिया है माननीय उप मुख्य सचेतक जी ने और यह भी यहां तक नम्बर दे दिया, यह इनकी बड़ी मेहरबानी है।

श्री सभापति: आज लम्बी लिस्ट है, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इसी तरह सरकार ने आरक्षित वर्ग के लोगों का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ किया और मिड-डे मील में हमारे बच्चों की सेहत ठीक रहे, उसके लिए सप्ताह में दो दिन दूध मिले और महिला दुग्ध समिति बनाकर उसके माध्यम से दूध की सप्लाई होगी जिससे उन महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। समिति के माध्यम से वो गांव में बच्चों को दूध देंगी और उनकी सेहत का ख्याल रखेंगी। आदर्श स्कूलों में 3389 क्लास रूम नये बनाने की भी घोषणा की।

अब मैं आपकी टोका-टाकी के बाद मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस वर्ष नया महाविद्यालय मुण्डावर में दिया, ए.डी.जे. कोर्ट भी खोला और करीबन 250 करोड़ रुपये की सड़कें बन रही हैं। इसके बाद में मैं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मुण्डावर क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें उप तहसील नहीं है,

(18.00 बजे)

इसलिए ततारपुर में उप तहसील खोलने का माननीया मुख्य मंत्रीजी आशीर्वाद देंगी। मैं मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इसकी बहुत सराहना करता हूं और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय की मर्यादा के अंदर रहते हुए, आप सभी विद्वान हैं, बजट में अनेक और पहलू हैं। जो आ चुके हैं, उनको रिपीट नहीं करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। बाकी आपका स्वतंत्र अधिकार है। माननीय शंकर सिंह जी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं भाग्यशाली हूं कि आप आसन पर विराजमान हैं। मुझे मालूम है, आप दयालु हैं समय के लिए।

माननीय सभापति महोदय, जो बजट पेश किया है राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने, वह हमारी सरकार ने "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" से ठोस नीतियां और कार्यक्रम को तैयार कर, राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह बजट पेश किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी के अंदर अधूरे सपने को पूरा करने के लिए योजना बनायी और उसका शिलान्यास किया है, पूर्ववर्ती सरकार से 40,000 करोड़ रुपये की हमारी इस सरकार ने बचत की है। अब 40,000 करोड़ रुपये, इनको तकलीफ होती होगी कि ये कहां ले जाते हैं। आज प्रदेश में भामाशाह योजना में 4.50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा गया है। 1,304 चिकित्सालयों को इस भामाशाह योजना से जोड़ा गया है। इससे इतने गरीबों का बहुत फायदा होने वाला है। हमारी सरकार ने बेटी बचाओ योजना का, माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने राजश्री योजना का शुभारम्भ किया। उसमें 5 लाख बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। विकास और सुशासन की मंजिल निरन्तर चलने वाली यात्रा है। हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में कई अहम पड़ाव हासिल किये हैं। किसानों की आय बढ़े, कमजोर तबके की सामाजिक, आर्थिक उत्थान हो, महिलाएं शिक्षित और सुरक्षित रहे, नौजवानों को काम मिले, ऐसे खुशहाल राजस्थान का सपना हमारी सरकार ने संजोया है। हमारी सरकार ने चार वर्षों में 49,878 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है। साथ में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15-15 किलोमीटर की और भी सड़कों की देने की योजना बनायी है।

सरकार ने जल संसाधन विभाग में भी काफी अहम बजट पेश किया है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उसमें हमारे देवाता फीडर का कार्य है, वह भी चल रहा है। उसमें भी हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट की घोषणा की है और वह कार्य चल रहा है। बहुत ही बढ़िया कार्य है। किसानों की पेयजल समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी।

(श्री शंकर सिंह)

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने 100-100 नये हैण्डपम्प और 500 आर.ओ. प्लांट लगाने की घोषणा की है। वह भी बहुत स्वागत योग्य है।

किसानों के लिए दो लाख कृषि कनेक्शन मिलेंगे। राजस्थान के किसानों की काया कल्प होगी। आज तक किसी भी सरकार ने दो लाख कनेक्शन एक साथ में घोषित करने के लिए हिम्मत नहीं की है। यह हमारे राजस्थान की यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धराजी की हिम्मत है जो दो लाख किसानों को एक साथ में कनेक्शन देकर उनको राहत पहुंचाई है।

50,000 रुपये तक के किसानों के कर्जे माफ, कांग्रेस के भाई कहते हैं कि अभी आपने 50,000 रुपये ही कैसे कर दिये। उसमें संशोधन करवा रहे हैं। मैं भी उसमें निवेदन करना चाहता हूं कि जो को-आपरेटिव का कर्जा माफ किया है, उसमें अन्य बैंकों के भी कर्जे हैं, उनको भी राहत मिले तो 50,000 रुपये का कर्जा कोई कम नहीं होता है। 50,000 रुपये आज तक कांग्रेस के इतिहास में कभी किसी ने कर्जा माफ ही नहीं किया राजस्थान के अन्दर। आप किसानों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं।

गायों के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आज नंदी गौशाला, 50 लाख रुपये तक का अनुदान देने की घोषणा की है और तीन महीने सहायता से बढ़ाकर उनको चारा के लिए छह महीने के लिए, और भी आगे बढ़ाने के लिए घोषणा की है। यह सब स्वागत योग्य हैं। मैं भी पिछली सरकार में था। आप भी कोई हिम्मत कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, लेकिन आपकी गांधीवादी सरकार के दिमाग में ऐसी बातें आ भी नहीं रही थीं।

हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,730 से बढ़ाकर 6,000 रुपये किये हैं। इसी प्रकार मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और साथिनों का, सबका पेमेंट बढ़ाया है। वह बहुत ही स्वागत योग्य है। समय का अभाव है। मैं पूरी डिटेल नहीं बता पाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भी योजना बनायी है और हमारी सरकार ने सभी जिलों के अंदर 6,165 अन्नपूर्णा

(श्री शंकर सिंह)
भण्डारों की योजना बनायी है, यह भी बहुत स्वागत योग्य है। उससे काफी चोरियां भी बंद हो जाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार के जैसे हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदया के शासन में ऐसा नहीं होता है। आज भी एक रुपये प्रति किलो गेहूं की पिसाई से बढ़कर नहीं है, लेकिन पांच साल पहले आप लोगों ने दो रुपये प्रति किलो गेहूं पिसाकर राजस्थान की जनता को बांटा है। यह बहुत ही निंदनीय है। हमारी सरकार सुशासन से सारे कार्य करा रही है।

हमारी सरकार ने हर उपखण्ड मुख्यालय पर एक-एक कालेज की भी घोषणा की है। उसमें हमारा एक टाटगढ़ उपखण्ड भी बचा हुआ है। मेरा निवेदन है कि वहां पर भी कालेज खोला जाए और हमारे कन्या महाविद्यालय भी, हमारी उच्च शिक्षा मंत्रीजी वहां ब्यावर आये थे तब कहा भी था कि ब्यावर में वास्तव में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। तो, मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि आप भी वहां कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए आशीर्वाद दिलाए।

हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, दो लाख रुपये तक के बकाया ऋण को भी माफ करने का काम किया है, वह भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए बहुत खुशी की खबर है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 50 वर्षों पूर्व एससी के लोगों ने सवर्ण जाति के लोगों को पांच रुपये और दस रुपये के स्टाम्प पर जमीन का बेचाननामा लिखकर उनको जमीन का बेचान कर दिया था...

(18.08 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

...और कब्जा भी दे दिया लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड के अंदर उनका नामान्तरण नहीं हुआ और आज जमीनें महंगी हो गयी है। इसके बाद कोर्ट में हजारों केस चल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कृपया तत्कालीन स्टाम्प के रिकार्ड को नामान्तरण करवाने के आदेश फरमायें ताकि हजारों लोगों को उस केस से मुक्ति मिल सके और न्याय मिले।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे कार्य हमारी सरकार ने किये हैं। मैं

(श्री शंकर सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे भारत में वर्ष 2007-08 के अंदर नरेगा योजना शुरू हुई थी। उस समय में हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धराजी को, पूरे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ कार्य राजस्थान में हुआ था और तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 2009 और 2013 के बीच में सरकार से पंचायत समिति जवाजा की ग्राम पंचायतों की दो-दो, तीन-तीन बार जांचें करवायी गयी थीं और वह जांचें सिर्फ भाजपा वर्सेज कांग्रेस की नीति अपनाकर, उन्होंने भाजपा के लोगों को ज्यादा मानकर, क्योंकि मैं वहां से ज्यादा वोटों से जीता, इस परेशानी से उनकी जांचें करवायी गयी। उनका भुगतान आज तक उन्होंने किया नहीं। पूरे कार्यकाल में उन्होंने उलझा कर रखा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन सरपंचों का कम से कम भुगतान कराने के लिए भी आप आदेश करवायें।

अन्नपूर्णा योजना के अन्दर प्रत्येक गरीब को 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये के अन्दर खाना, ऐसी योजना हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने बनायी है, यह गरीब के प्रति है। पहले ये लोग कहते थे कि साहब, गरीब का भला करने के लिए कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का हाथ, गरीब के गले पर पड़ा है, गरीबी मिटायी नहीं है, गरीबों को आपने मिटाने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीबों के लिए आप सोच सकते थे। राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया ने गरीबों को आज श्रमिक कार्ड के माध्यम से जो योजना बनाई है, उस श्रमिक का कल्याण करने के लिए, श्रमिक के लड़का पैदा होने पर 20 हजार, लड़की पैदा होने पर 21 हजार, लड़की की शादी-पढ़ाई के लिए भी पूरे पैसे। लड़की की शादी होगी तो वसुन्धरा जी की तरफ से 55 हजार रुपये, शादी के लिए दिये जाने की योजना है, यह गरीब के कल्याण के लिए है। श्रमिक की, कहीं एक्सीडेन्ट के अन्दर मौत होने पर 9 लाख 70 हजार रुपये का उसको क्लेम पास होना, यह योजना बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-

(श्री शंकर सिंह)
बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीबों के प्रति आपने हमेशा ऐसी योजना बनाई है, स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय मांग को भी थोड़ा-थोड़ा निवेदन कर दूं। शिक्षा के अन्दर हमारे मिडिल स्कूल्स हैं, वे भी काफी बची हुई हैं, उनको क्रमोन्नत करने के लिए भी इस योजना के अन्दर जोड़ा जाए। अरनाली, कालींजर, शेरों का बाला, फतेहपुर प्रथम, इनको भी जोड़ने के लिए है और हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के टाइम पर जितने भी वायदे किये है, हर वायदे को पूरा करने का काम हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किया है।

निवेदन है कि उस योजना के अन्दर सिर्फ एक घोषणा बाकी रह गयी है ब्यावर जिले की। निश्चित तौर पर मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया जब भी बजट का रिप्लाई देंगी तो ब्यावर की जनता उनकी तरफ टुकुर-टुकुर देख रही है और वे जिला बनाएंगी।

मैं कहना चाहूंगा किसानों के हितैषी भाइयों से अभी जो विपक्ष में बैठे हुए कह रहे हैं कि साहब, हम तीन सीटें क्या जीत गये, हमने आसमान को छू लिया है, ऐसे अपने को आपा नहीं खोना चाहिए। कांग्रेस, काल और कंस, तीनों राशि एक ही होती है। इसलिए आप इतना ज्यादा अभिमान नहीं करें, गर्व नहीं करें, घमण्ड़ नहीं करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर गरीबों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस जीतकर आएगी। आप मुंगेरी लाल के सपने हमेशा-हमेशा के लिए आप छोड़े। एक लाइन मैं बोलूंगा 'केसरिया में हरा-हरा और राजस्थान में सिर्फ वसुन्धरा'। इस प्रकार का आप हमेशा रटते रहे। याद रखे कि वही जीतकर आएगी और मुख्य मंत्री वापस बनेगी। यह मैं आपको बताता हूं। जय-जय राजस्थान, जय-जय भारत। धन्यवाद साहब। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानवेन्द्र सिंह।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मेरा पाइन्ट आफ इंफोरमेशन का था, आप कहें तो, बोल दूं क्या।

श्री उपाध्यक्ष: हां, फर्मायें। जो आपकी बेसिक इंफोर्मेशन है न, उसका आप ध्यान आकर्षित करें।

सूचना

जयपुर में हुए तेजाब हमले के बाद भी तेजाब की खुली बिक्री जारी

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी के अन्दर कल एक घटना घटी थी जिसने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। कमिश्नरेट की सारी पोल खोली दी, ट्राइटन मॉल के अन्दर तेजाब की बोतल लेकर महबूब नाम का युवक, जो वहां के ए.सी.पी. का बहुत करीबी है, झोटवाड़ा एसीपी का व्यवधन एक मिनट रुक जाओ। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद उसको मौके पर पकड़ लिया, मॉल कर्मियों ने मारपीट भी कर दी, लेकिन उसके बाद आज भी झोटवाड़ा, किशनपोल, इन क्षेत्रों में खुले आम तेजाब बिक रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में गृह मंत्रीजी को वक्तव्य देना चाहिए। कमिश्नरेट के अन्दर, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता...

श्री उपाध्यक्ष: चलिये, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। मानवेन्द्र सिंह जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूर्व सरकार के अन्दर सी.एम. का खास हुआ करता था आज भी कमिश्नरेट भू माफियाओं के शिकंजे के अन्दर आ गया है, उपाध्यक्ष महोदय। कमिश्नरेट का जो विश्वास था, लोगों का कमिश्नरेट से विश्वास उठ गया।

श्री उपाध्यक्ष: पाइन्ट आफ इंफोर्मेशन से सिर्फ आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, अब आप विराज जाओ।

आय व्ययक

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण 2018-19 में 70 वर्ष स्वतंत्रता के बाद शिव मुख्यालय पर कालेज की घोषणा करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शिव विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है, एक पंचायत है और एक पंचायत

(श्री मानवेन्द्र सिंह)

मुख्यालय पर, विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर कालेज खोलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसका लाभ शिव विधान सभा क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को भी मिलेगा और उससे अधिक लाभ पड़ौसी फतेहगढ़ तहसील जो जसमेर में है, वहां के भी बालक बालिकाओं को मिलेगा, इसलिए मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है। मुख्य मंत्री ने अपने उद्बोधन में आहवान किया था कि कालेज के निर्माण के लिए एम.एल.ए. लैड, दानदाता सबका सहयोग होना चाहिए, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एम.एल.ए. लैड की जो सीमा है वह पूरी सीमा हम कालेज निर्माण के लिए डालेंगे और दानदाताओं का भी सहयोग लेंगे। उसमें मेरा एक सुझाव है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, यदि प्रयास करें तो नरेगा के माध्यम से कुछ सहयोग मिल सकता है। क्योंकि नरेगा की जो गाइड लाइन है, उसमें संशोधन करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। परन्तु यदि राज्य सरकार ऐसे निर्माण कार्य के लिए गाइड लाइन में संशोधन के लिए भेजे तो मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार इस पर सहयोग देने के लिए पुन:विचार कर सकती है। गाइड लाइन में संशोधन कर सकती है और मैं यही आशा करता हूं, मांग करता हूं कि राशि बढ़ाने के लिए, लेबर बढ़ाने के लिए, नरेगा का भी सहयोग लिया जाए। शिव ग्राम पंचायत है जहां यह कालेज बनेगी, वहां नरेगा कार्य की सीमा है। यदि कालेज को नरेगा से जोड़ा जाए तो मुझे विश्वास है कि जो श्रम सीमा है, जो उसके साथ जो मैटेरियल एड करना है, उसमें हमें लाभ मिलेगा और कालेज निर्माण के लिए भी बहुत सहयोग मिलेगा। मैं एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि हम वहां एक लोकल संस्था बनाएंगे और संस्था के मार्फत हम स्वचालित एक गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। चर्चा में है, अभी दानदाताओं को भी इकट्ठा किया है, हम चाहते हैं कि हमारी जो बालिकाएं है शिव की रहने वाली, जैसलमेर फतेहगढ़ की रहने वाली, उसका लाभ लें। इसलिए गर्ल्स हॉस्टल भी हम वहां बनाएंगे। वहां तहसीलदार से, एस.डी.एम. से बात हुई है, जमीन उपलब्ध है, कॉलेज के लिए भी उपलब्ध है और गर्ल्स हॉस्टल के लिए हम मांग करेंगे हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बालिका शिक्षा के लिए हम बिलकुल सक्रिय हैं और कालेज का पूरा लाभ हमें जब बालिका पढ़ेगी तब मिलेगा। बजट उद्बोधन में जो आंकड़े हैं, कई

(श्री मानवेन्द्र सिंह)
लाभदायक योजनाएं हैं, उसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने, मेरे साथियों ने, सभी ने की है, दुबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। न आंकड़े दोहराने की आवश्यकता है, न योजना के बारे में दोहराने की आवश्यकता है। परन्तु, एक योजना है जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की। मेरी समझ में, मेरे ज्ञान में वह सबसे लाभदायक है समाज के लिए और भारत में पहली बार ऐसी घोषणा हुई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि न तो इस पर यहां सदन में चर्चा हुई और विशेषकर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं हुई। मिड-डे मील के साथ तीन दिन दूध देने की जो घोषणा की है मुख्य मंत्रीजी ने, इतनी लाभदायक कोई योजना नहीं हो सकती इस समाज के लिए। बच्चों के भविष्य के लिए जो घोषणा है कि उसका संचालय पंचायत की महिला दुग्ध डेयरी करेगी।

जो सैल्फ हैल्प ग्रुप है महिलाओं का वो उसका संचालन करेगी। इसका लाभ केवल बच्चों के लिए नहीं है, परंतु महिला सशक्तीकरण का एक बहुत-बड़ा उदाहरण है यह और इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सबका सहयोग उसमें रहे और इसी संदर्भ में मैंने आज इसकी एक लेख भी लिखा है ऑनलाइन वैब पोर्टल के लिए कि भारत में पहली बार ऐसी घोषणा हुई है और इसकी किसी ने चर्चा ही नहीं की, न यहां, न बाहर सोशल मीडिया में। केवल ढाई सौ करोड़ रुपये में इतना फायदा होगा अपने बच्चों के लिए। इसमें एक थोड़ा संशोधन चाहता हूं मैं। जो घोषणा है वह तीन दिन के लिए है, मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन जब स्कूल बैठे तो बच्चों के लिए दूध मिले और ग्रामीण क्षेत्र में जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, न्यूट्रिशन पैरामीटर्स हैं, उसके लिए आवश्यकता है कि दूध का फोर्टिफिकेशन किया जाए, क्योंकि जब तक विटामिन 'डी' उसमें एड नहीं करेंगे तो कैल्शियम शरीर में स्वीकार नहीं होगा। पूर्ण रूप से तो मैं चाहता हूं कि इस योजना में मिल्क फोर्टिफिकेशन का भी कुछ प्रावधान किया जाए और ज्यादा राशि बढ़ेगी नहीं। मिल्क फोर्टिफिकेशन का अभियान देश भर में कई वर्षों से एनजीओज चला रहे हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो चला रही हैं, तो उसका भी लाभ राजस्थान ले सकता है। क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिशन पैरामीटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत ही दुखदायक हैं। केवल राजस्थान की ही बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है कि हमारे बोन डेन्सिटी का जो डेटा अवेलेबल है, वो

(श्री मानवेन्द्र सिंह)
बहुत ही पूअर है। उसमें मेरी इच्छा यह है, क्योंकि मैं फुटबाल से जुड़ा हुआ हूं। खिलाड़ी बनाने के लिए शरीर चाहिए। कोचिंग तो हम कराते हैं, ट्रेनिंग हम कराते हैं, सामग्री हम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन खिलाड़ी चाहे बालक हो, या बालिका हो, अगर उसकी हड्डी तैयार नहीं है, बोन तैयार नहीं है, बॉडी तैयार नहीं है, तो हम उनको ऊपर लेवल तक का खिलाड़ी नहीं बना सकते। जिले लेवल तक या स्टेट लेवल तक तो ठीक है, चलता है, लेकिन नेशनल स्तर के लिए जो शरीर चाहिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहां वो शरीर बनता नहीं है क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत पूअर हैं। तो यह मेरा एक सुझाव है कि दूध का फोर्टिफिकेशन भी हो और प्रतिदिन जब स्कूल बैठे तो इसका लाभ मिले, यह बच्चों के लिए हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जैसलमेर जिला, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े हैं और सरकार की परिभाषा में लघु, सीमान्त कृषकों के लिए जो घोषणा की है कर्ज माफ करने की, वो हमें लाभान्वित नहीं करती। हमारे एरिये को लाभान्वित नहीं करती, क्योंकि हमारे यहां चालीस-पैंतालीस बीघा तो सामान्य कृषक के पास है और दो हैक्टेयर को लघु सीमान्त में माना जाता है। उसमें हमारे किसान वंचित रहते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से बाड़मेर और जैसलमेर जिला वंचित रहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि लघु, सीमान्त की जो परिभाषा है, उसमें कुछ चेंज किया जाए। उसमें पुन: विचार किया जाए जिससे हमारे कृषक भी लाभान्वित हो सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विधायक के 15 किलोमीटर सड़क की जो घोषणा की है कि प्रति विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर दिया जाएगा अपने प्रस्तावानुसार। हमारे जैसलमेर, बाड़मेर जिले में 15 किलोमीटर एक ढाणी से दूसरी ढाणी कवर नहीं करता। एरिया हमारा ऐसा है यदि आप शिव विधान सभा देखें तो शिव विधान सभा लगभग नौ हजार वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के कई लोक सभा क्षेत्रों से बड़ा शिव विधान सभा क्षेत्र है। भारत के तो अनेकों लोक सभा क्षेत्रों से बड़ा है तो उसमें 15 किलोमीटर कुछ मायने नहीं रखता है और अंग्रेजी में कहावत है कि 'वन साइज डजन्ट फिट ऑल' तो इसलिए मेरा प्रस्ताव है, सुझाव है, प्रार्थना है कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए इसमें संशोधन किया जाए। वैसे भारत सरकार ने एक समय

(श्री मानवेन्द्र सिंह)

विकास की योजना की घोषणा की थी जिससे बाड़मेर, जैसलमेर जिला लाभान्वित हुआ था। बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड और बीआरजीएफ में पापूलेशन, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों का एक रेश्यो बनाया था। उसके आधार पर बीआरजीएफ फंड बाड़मेर, जैसलमेर को अधिक मिलते थे, क्योंकि उन्होंने एक रेश्यो बनाया था, परंतु वो योजना समाप्त हो गयी तो उस रेश्यो को हम अपने यहां लागू कर सकते हैं। राजस्थान सरकार लागू कर सकती है। मेरी प्रार्थना है कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए यह लागू किया जाए, क्योंकि मापदंड हर क्षेत्र के लिए एक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बहुत भिन्न है। इस पर पुन: विचार हो, यह मेरी प्रार्थना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सौ हैंडपंप की घोषणा बहुत सराहनीय है, क्योंकि हमारे यहां तो पेयजल की समस्या हमेशा रहती है और उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए यह घोषणा हुई है। विधान सभा क्षेत्र को देखते हुए चूंकि कच्छ का जो भूकंप आया था उसके बाद कई स्थान हमारे बाड़मेर जिले में ऐसे हैं जहां पानी ऊपर आया है, भौगोलिक और भूजल का स्तर बढ़ा है तो कई जगह ट्यूबवैल बन गये और ट्यूबवैल लोगों ने स्वयं बनाये हैं। रेगिस्तान में ट्यूबवैल बने हैं। धोरों पर स्प्रिंकलर से सिंचाई हो रही है, परंतु हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र में 132 केवीए का जीएसएस नहीं है विशेषकर जो गिराब क्षेत्र है जहां सबसे अधिक ट्यूबवैल लगे हैं। आज की तारीख में लगभग 2 हजार ट्यूबवैल गिराब क्षेत्र में ही है तो गिराब के लिए यदि एक 132 केवीए का जीएसएस बनाया जाए तो हमारे किसान बहुत लाभान्वित होंगे और पेयजल की समस्या के लिए भी जो दूरदराज ढाणियों को पेयजल योजना से जोड़ते हैं वो भी बहुत लाभान्वित होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिव विधान सभा क्षेत्र नर्मदा नहर परियोजना का अंतिम स्थान है। बाड़मेर और जालौर को कवर करते हुए शिव विधान सभा क्षेत्र में इसकी समाप्ति है। चूंकि अभी जो परिस्थितियां हैं सरदार सरोवर डैम में जो संकट है गुजरात में जो समाचार पत्रों में यहां तो कम ही आया है, लेकिन जो गुजरात से सम्पर्क रखते हैं उनको जानकारी है कि सरदार सरोवर डैम क्रिटीकल लेवल से एक मीटर ऊपर है और अभी

(श्री मानवेन्द्र सिंह)

फरवरी का महीना है। गुजरात के चार जिलों में नर्मदा का पानी उन्होंने बंद कर दिया है। अभी गर्मी का सीजन आने वाला है। जालौर और बाड़मेर जिला विशेषकर बाड़मेर का गुढ़ामालानी, चौहटन, सिणधरी का कुछ भाग और हमारा शिव जो नर्मदा से लाभान्वित होने वाला है, कुछ हुआ है, कुछ और होगा। तो, मैं यही प्रार्थना करता हूं सिंचाई मंत्रीजी हैं नहीं, परंतु सिंचाई मंत्रीजी के समक्ष आपके मार्फत मैं बात रखना चाहता हूं कि गुजरात से कुछ वार्ता करके गर्मियों के समय हमारा पानी नहीं कटे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मुझे सचेतक महोदय ने अवसर दिया था इस बजट के ऊपर बोलने के लिए। मैंने एक मांग, एक सुझाव रखा था उस समय कि राजस्थान की एक विरासत है बीकानेर में जो हमारी स्टेट आर्काइव्ज हैं, वहां मुझे जाने का अवसर भी मिला उस उद्‌बोधन के बाद, मैं बहुत प्रभावित, और प्रसन्न हुआ। जिस प्रकार वहां काम चल रहा है, डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है और हमारे जो पुराने डाक्यूमेंट हैं, कई-कई डाक्यूमेंट तो 6-7 सौ साल पुराने हो सकते हैं, उनके रखरखाव के लिए जो वहां अधिकारी हैं, जो अधीक्षक हैं, जिन्होंने कार्य किया है, वो बहुत सराहनीय है। इस उद्‌बोधन में मुख्य मंत्रीजी ने इस पर घोषणा की, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि स्टेट आर्काइव्ज हम सबके लिए एक विरासत भी है। भविष्य के लिए मैं चाहता हूं कि यदि हम डिजिटाइजेशन और प्रगति पर करें तो राजस्थान का एक रिसर्च सेंटर बना सकते हैं, एजुकेशन हब बना सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने अभी इस लोक सभा सत्र में घोषणा की थी कि भारत को केवल एक 'मेक इन इंडिया' नहीं बनाना है, भारत को एक स्टडी इन इंडिया बनाना है। उस स्टडी इन इंडिया का भाग राजस्थान भी बन सकता है। बीकानेर को लेकर, टोंक में जो आर्काइव्ज हैं, जो डाक्यूमेंट्स हैं, उनको लेकर यह मेरा सुझाव है। बीकानेर के लिए मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2018-19 के बजट पर चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष वाले सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। मैं कहना चाहूंगा कि यह जो अंतिम साल का बजट दिया गया है कि अंतिम साल में ऐसा बजट पेश कर दे ताकि जनता इस बजट के बहाने अजमेर और अलवर में क्या हुआ, वह भूल जाए। अच्छी बात है, जब हमने अशोक जी के समय लास्ट में बजट दिया उस समय यही बात कही गयी थी कि रेवड़ियां बांटी, रेवड़ियां बांटी और उसका हश्र यह हुआ कि हम आज 21 पर बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा आप ऐसा नहीं समझे कि इस बजट की वजह से आप वापस आ जाएंगे, राजस्थान की जनता सब जानती है। बजट आपने दिया, अच्छी बात है, पर समय कम बचा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो, इस पर आप जोर दोगे तो ही जनता को राहत मिल सकेगी। हमारे बाड़मेर में सबसे ज्यादा तेल, गैस, लिग्नाइट है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा माइनिंग राजस्थान को मिल रही है। मैंने बजट में देखा, बाड़मेर के अख़बार भी देखे और हमारे बाड़मेर के सभी एमएलएज के भी देखें, सारे बाड़मेर को करीब करीब शून्य ही मिला, एक दो कालेज को छोड़कर मुझे नहीं लगा कि इस बजट में कोई बडी घोषणा बाडमेर के लिये हुई। रिफाइनरी की भी बात चली, मेरे से पहले खूब चर्चा हुई। सांगानेर से आने वाले माननीय घनश्याम जी ने भी बात कही कि 40 हजार का फायदा हुआ। मैं यह कह रहा हूं और घनश्याम जी ने भी कहा कि आप इस पर श्वेत पत्र जारी कर दें ताकि जनता को पता लग जाए कि इसमें देरी करने से कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, जनता के सामने बात आ जाएगी, इस पर ज्यादा वाद विवाद की भी जरूरत नहीं। किसानों की कर्जा माफी का बहुत श्रेय लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर 50 हजार सबका कर्जा माफ कर लेते तो, परंतु मैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में कहना चाहूंगा कि 10-15 परसेंट लोगों का कर्जा माफ हो जाए तो पता नहीं, बाकी जो आपने दो हैक्टेयर का पैमाना लिया है, इससे तो लघु किसानों को लाभ मिलने वाला नहीं है। यह खाली थोथी घोषणा ही रह जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हर किसान का आप 50 हजार का लोन माफ करो ताकि जनता को

(श्री मेवाराम जैन)
इसका लाभ मिले और आप कुछ वाहवाही की बात कर सकोगे, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, यह खाली एक घोषणा ही रह जाएगी।

जैसलमेर, बाड़मेर कांडला रेल लाइन की बात भी मैंने इस बजट में देखी, मैं भी खुश हुआ कि अच्छी बात है, हम तो बहुत सालों से मांग कर रहे थे कि यह रेल लाइन का काम शुरू हो जाए। इस बजट में लिखा हुआ ही देखा है, इसका प्रावधान तो हमने नहीं देखा और मेरे खयाल से केन्द्र की योजना है। मैं आप सभी से और सदन की नेता से भी कहना चाहूंगा कि इस योजना को आपने इस बजट में लिया तो वास्तव में इसको स्वीकृत कर बाड़मेर और जैसलमेर की जनता को लाभ दिलायें, इससे कई जिले जुडेंगे और यह एक बहुत बडी योजना है। उम्मीद है कि इसको स्वीकृत कराएंगे, यह केवल कागजों में ही नहीं रह जाएं।

पेयजल योजना की बात करें, हर विधायक को 100-100 हैंडपम्प दिये, मैं इसका स्वागत भी करुंगा और कहना भी चाहूंगा कि यह जो 100-100 हैंडपम्प दिये हैं, वह विधान सभा क्षेत्रों में सभी विधायकों की अनुशंसा पर दें, इसमें भेदभाव नहीं करें।

सडकों की बात है, सड़कें भी 15 किलोमीटर दी, हालांकि कम है। उसके बाद जो नॉन-पेचेबल सड़कें हैं, चाहे गौरव पथ हैं, इसमें भेदभाव नहीं करके सभी को हिसाब से दे दें तो मेरे खयाल से अच्छा रहेगा।

चिकित्सा क्षेत्र में भी कहना चाहूंगा, अभी कुछ माननीय सदस्य बोले भी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूं नि:शुल्क दवा जो पहले चालू की थी, अभी भी उस पर ज्यादा जोर दें। भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 48-48 घंटे उनको वहां पर सुविधा नहीं मिल रही है, लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है और मरीज को इतना फायदा नहीं हो रहा है। स्टाफ की भी उसमें कमी है, स्टाफ भरें। पहले जो पीएचसी स्वीकृत हुई है या सब सेंटर है, जहां भवन नहीं बने हैं, वहां भवन बनायें।

नगरपालिका क्षेत्र बाड़मेर की बात करना चाहूंगा, बाड़मेर तीन हिस्सों में बंटा हुआ था। तीन जगहों में से दो जगहों पर तो सीवरेज सैंक्शन हो गया

(श्री मेवाराम जैन)
और काम हो गया, तीसरा मेन शहर का बीच का हिस्सा है, वह स्वीकृत ही नहीं हुआ, करोडों रुपये खर्च हुए हैं। जब तक वह स्वीकृत ही नहीं होगा तो यह सीवरेज कैसे जुडेगा और उसका फायदा कैसे जनता को मिलेगा? सारे पैसों का दुरुपयोग होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको सीवरेज से जोडें। पंचायत में नरेगा में मैटेरियल का भुगतान सरपंचों को नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि नरेगा के मैटेरियल का भुगतान कराये। हमारे यहां तो नरेगा के काम भी स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। आज भी कई सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। नरेगा में तो जो भी काम मांगे वह तत्काल सैंक्शन होना चाहिये, उसको आप स्वीकृत करायें। दीनदयाल विद्युतीकरण का कार्य हमारे यहां शुरू तो किया है, वह बहुत धीमी गति से है। इसी गति से चला तो पूरा करने में तीन चार साल लगेंगे और चार छह महीनों में आचार संहिता लग जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको तत्काल शुरू करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में मैं कहना चाहूंगा कि जो स्कूलें बंद की हैं, आप जिद पर मत अड़ो, उस पर पुनर्विचार करो। जो वाजिब हैं, जहां आवश्यकता है, भवन बना हुआ है, उसको वापस चालू करने का प्रयास करो। यह आपके लिये बहुत घातक निर्णय है। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पर अभी भी पुनर्विचार करो और उन स्कूलों को वापस शुरू करो, गरीबों को उसमें लाभ मिले। पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी की बात करें, अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य कह रहे थे सभी मुख्यालयों पर सीनियर सैकण्डरी स्कूलें खुल गयी, अभी तक कई स्कूलें बाकी हैं, अगर वह नाम भी चाहे तो मेरे पास है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 6-7 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां स्कूलें नहीं खुली हैं। एक पंचायत मुख्यालय जूनापतरासर ऐसा है जहां 8वीं ही है, दसवीं भी नहीं हुई है अभी तक। निवेदन करना चाहूंगा कि सभी पंचायत मुख्यालयों पर स्कूलें खोलें।

एक मेन बात है कि हमारे जोधपुर डिवीजन में एसटी के भील है, जिनको नाम मात्र का आरक्षण का लाभ मिलता है। नौकरी में सबसे पिछड़े और गरीब हमारे भील जाति के हैं, उनको कतई लाभ नहीं मिल रहा है, एक परसेंट भी लाभ नहीं मिल रहा है, बाकी दूसरे ही आरक्षण का लाभ ले रहे

(श्री मेवाराम जैन)
हैं। इसलिए इनको स्पेशल लाभ कैसे मिले, एससी को तो कृषि कनेक्शन का लाभ भी मिलता है, इनको वह लाभ भी नहीं मिलता, मेरे खयाल से इनसे गरीब और कोई नहीं है। टाडा, माडा का भी लाभ इनको नहीं मिल रहा है, वह भी दिलाने का प्रयास करें।

अन्नपूर्णा योजना बहुत स्वागत योग्य है, पर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो भिखारी है, जिनके पास 5-10 रुपये नहीं है, उनको तो कम से कम फ्री खाना खिलायें ताकि वह आपको दुआ दे सकें। वह भूखे मर रहे हैं, 5-10 में तो कोई भी खाकर चला जाएगा, उनको भी साथ में जोडें।

आपने कृषि कनेक्शन 2012 तक दिये। जनवरी, 2012 तक के लिये घोषणा की है, वह बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहां पर मैटेरियल नहीं है। वहां पर मैटेरियल वगैरह की सारी व्यवस्था करके तुरंत करोगे तो इनको लाभ मिलेगा, वर्ना ये खाली घोषणाएं ही रह जाएंगी। मैं राजस्व विभाग से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे मंत्रीजी बैठे हैं और गोचर ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इन पर सख्ती करें। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा बाड़मेर में सार्वजनिक श्मशान घाट है, दान जी की होदी। पांच बीघा जमीन अलॉट हो गयी। एमएलए कोटे से चारदीवारी बन गयी। उसके अंदर एक पर्टिकूलर बोर्ड लगा दिया और तीन केस ऐसे हुए हैं कि चार-चार, पांच-पांच घंटे लाश जलाने नहीं दी। बाहर लेकर बैठे रहे। फिर प्रशासन को ले जाकर, बड़ी मुश्किल से ताला खुलाकर उस लाश को जलाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक श्मशानों में जो इस तरह से कब्जा कर बैठे हैं, उनको हटायें। जो गरीब हैं, पास में रहने वाले हैं, उनको लाश जलाने में तकलीफ नहीं हो, यह भी आप करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करूंगा कि जैन समाज के बरखेड़ा व पदमपुरा जिसकी माननीय घनश्याम जी ने भी पहले बात की, इसको आप अधिग्रहण में नहीं लें। तरूण सागर जी और सदन की माननीय नेता जी की आपस में चर्चा भी हुई थी। उसमें कहा था कि हम इसको छोड़ेंगे, अधिग्रहण नहीं करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा प्राचीन मंदिर है। जन भावना को देखते हुए अवाप्ति से मुक्त रखें और निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मेवाराम जैन)

शराब बंदी में हमारे गुरुचरण जी छाबड़ा, जिन्होंने इस आंदोलन को लेकर मेहनत की और काफी धरने-प्रदर्शन किये, आखिर वो दुनिया से चले गये। उनकी पुत्रवधू पूजा छाबड़ा इस मिशन को लेकर आगे चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अभी तीन-चार रोज पहले की बात है, धरने पर बैठी थी, रात को उठाकर उस अकेली औरत को जंगलों में छोड़ा। उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना मेरे खयाल में अच्छा नहीं है। उनका सहयोग करना चाहिए, बात सुननी चाहिए। शराबबंदी सबके लिये घातक है, इसमें हम किस तरह से सहयोग करें, उनकी बात सुनें। इस तरह करें तो अच्छा रहेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): शराबबंदी सबके लिये घातक है। आपने अभी बोला कि शराबबंदी सबके लिये घातक है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): शराब बंद करो, मैं तो यह कह रहा हूं। आप सहयोग करो, उठाकर बाहर मत फेंको। ..(व्यवधान)..

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): शराब घातक है, सुनने में फर्क है। सो गये थे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका मतलब यह था कि शराबबंदी घातक है। बंद नहीं होनी चाहिए। यही चाहते हो न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं शराब बंद करने के लिये कह रहा हूं। आप उलटा मतलब लगा रहे हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सचेतक महोदय, आपको शायद नींद आ गयी थी। ये कह रहे थे कि शराबबंदी फायदेमंद है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कोई बात नहीं, मुझे तो नींद आ गयी, पर आप क्यों सो रह हो? आपको पता नहीं, आप सो रहे हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप शराब बंदी नहीं कराना चाहते हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सचतेक महोदय अभी जगे हैं और जगते ही इनको याद आ जाता है कि मैं क्या बोलूं? ये याद कर बोले हैं। अब इनकी नींद टूट गयी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्व मंत्रीजी भी बैठे हैं, बाड़मेर में स्वीकृत कुडा लिग्नाइट प्रोजेक्ट में आज से चार साल पहले किसानों की भूमि अवाप्त की गयी। अवार्ड जारी कर दिया। चार साल बाद अब सरकार कह रही है कि हम नहीं लेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। किसानों ने कहा कि या तो आप जमीन ले लो। जमीन नहीं लो तो आप इसको मुक्त करो। दो ही बाते हैं, न तो उनको पैसे दे रहे हैं, न जमीन छोड़ रहे हैं। किसान न तो बेच सकते हैं, न उसमें किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं। कम से कम एक निर्णय तो करो। आप चार साल से इसको लटकाकर बैठे हो। आप किसानों के लिये कम से कम इतना तो करो।

मिड-डे-मील में आप हैल्पर को सिर्फ 1200 रुपये ही दे रहे हो, कम से कम इसे तो बढ़ाओ। आपने जैसे आंगबाड़ी, आशा सहयोगियों के पैसे बढ़ाये हैं, बढ़ाये तो कम हैं, फिर भी इनके बहुत कम हैं। इनके पास पैसे बढ़ाओ। बेरोजगारों की बात, सारे घूम रहे हैं। चाहे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनके लिये अब करने का समय है। इसमें जितनी रिलीफ दे सको। नौकरी एवं भर्तियों में यह आश्वासन ही रहेगा, यदि आप भर्ती नहीं कर पाये। आप चार साल से नहीं कर पाये तो छह महीनों में क्या कर पाओगे? अभी भी आप हो सके इतना करो। पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था की बात है। आज चोरी, डकैती वगैरह जितनी हो रही है, पुलिस में स्टाफ कम है। मैं चाहूंगा कि इनका स्टाफ पूरा हो। इनको हर तरफ से सुविधाएं दें। क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए उनको मजबूत करना भी आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जो भी वाजिब मांगें हैं, उस पर ध्यान दें। हमारे बाड़मेर में ग्रामीण थाना सैंक्शन है, जमीन का अलॉटमेंट हो गया है, उसको भी दो-ढाई साल हो गये। उस थाने की स्वीकृति... माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भवन की स्वीकृति दे दें ताकि वह भवन बन जाए। किराये के भवन में चल रहा है। एक चंवा चौकी हमारे यहां सैंक्शन हुई। छह साल हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आये थे, उस समय भी मैंने निवेदन किया और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हमारे पास सारी रिपोर्ट आ गयी और हम उसकी घोषणा कर देंगे। चौकी का

(श्री मेवाराम जैन)

सिर्फ बायतू की जगह बाड़मेर सदर थाने का संशोधित आदेश निकालना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें ध्यान दें।

आपने गायों के लिये अनुदान तीन की जगह छह महीने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह एक अच्छा निर्णय कम से कम आपने लिया है, साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो ज़िलों में नंदी गोशालाएँ खोलने की घोषणा की है, घोषणा खाली कागजों में नहीं रहे। यह एक बहुत बड़ी बात है और आपके पास बड़ी चुनौती है। ये अगर हर जिले में खुल जाए और जो सारे पशु हैं, वे उस गोशाला में आ जाएं तो शहर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और जनता को इसमें लाभ मिले। बस एक मिनट और।

पी.पी.पी. मोड की बात कर रहा था। हॉस्पिटल है, स्कूल है, चाहे बिजलीघर है, जितनी भी है, आप इनको मुक्त करो। जितनी भी हैं, पीपीपी मोड को छोड़कर, जनता की भावनाओं का सम्मान करो। स्वच्छ भारत की ही बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर, इसमें हम जिस तरह से कह रहे हैं कि शौच मुक्त हो रहा है, कम से कम 20-25 परसेंट हर पंचायत में वैसे ही रह रहे हैं, जिनका इस सर्वे में नाम ही नहीं है, उनको भी जोड़ा जाए, तभी स्वच्छ भारत और स्वच्छ जिले व पंचायत की बात आएगी। उनका जो पेमेंट बकाया है, वह भी दें और इनकी गुणवत्ता भी चैक करें कि ये जो बने हैं, पुराने तो नहीं दिखाये। सही बने, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

मैं अंत में बजरी के लिये कह रहा हूं कि बजरी के लिये जिस तरह से मारा-मारी और जिस तरह से यह खेल खेला जा रहा है, इस पर भी समय रहते विचार करना चाहिए। इसके लिये अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो सारे भू-माफिया जनता को खा जाएंगे और सारे विकास के कार्य रुक जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: कृषि मंत्री महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया गया।

स्पष्टीकरण

प्रभू लाल सैनी, श्री, कृषि मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 206 के अंतर्गत, आज प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न संख्या 1 में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय का यूजीसी सहायता से संबंधित जो प्रश्न था, उस प्रश्न के दौरान मैंने अपने उत्तर में राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाले सहायता का उल्लेख किया था। उस सहायता के अंतर्गत 7155.58 लाख था, उसके स्थान पर करोड़ बोलने में आ गया था। एक तो मैं उसके स्पष्टीकरण और शुद्धि के लिये आग्रह करता हूं। दूसरा, मेरा निवेदन भर्तियों के बारे में था। भर्तियों के बारे में जो संख्या और मुझे प्राप्त हुई है। पहले 141 के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था। अब 178 पदों की शैक्षिक और तकनीकी भर्तियां की जा रही हैं।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। राजस्थान प्रदेश में जो बजट पेश हुआ उस बजट के लिए मैं अकेली नहीं पूरे प्रदेश की जनता माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बार-बार धन्यवाद अर्पित करती है। धन्यवाद इसलिए अर्पित कर रही है क्योंकि ये बजट एक मां

(श्रीमती अनिता कटारा)

बनकर तैयार किया गया है। एक मां को परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रहता है। एक मां को पूरे पड़ौसी, गांव, फला जिला सभी का ध्यान रहता है। उसी का ध्यान रखते हुए हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए हमारी आम जनता उनको बार-बार धन्यवाद देती है।

डूंगरपुर जिले की मैं बात करूं। मैं वांगड़ से आती हूं। मैं वांगड़ की बात करूं तो हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने वांगड़ में कौन संत है? वांगड़ में विकास क्या होता है? ये सब अगर किसी ने दिखाया है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने दिखाया है। गोविन्द गुरु के भक्त हर घर में मिल जाएंगे। परंतु गोविंद गुरु कौन है? गोविंद गुरु की क्या शिक्षाएं थीं? गोविंद गुरु कहां से उत्पन्न हुए? यह सब अगर किसी ने बताया तो वह हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने बताया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हम बचपन से देखते थे कि काली बाई रास्तापाल में एक छोटी सी 13 साल की बालिका थी, जिसने अपने गुरु की रक्षा के लिए अपने आप की बलि दी थी। ऐसा हम पढ़ते आये थे। परंतु वह काली बाई खांट कौन है? यह अगर दिखाने का काम किया है तो वह हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। मावजी महाराज का जो बेणेश्वर धाम पर हमारा बहुत बड़ा झोपड़ा होता है। उस मावजी महाराज की धरती के दर्शन करवाने का अगर किसी ने काम किया है तो वह माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। मैं बजट की बात पर आंकड़ों को न गिनाते हुए वास्तव में हमारे वांगड़ में क्या-क्या चीजें हुई हैं, उस पर अमल करूंगी, उस पर बात करूंगी। बेणेश्वर धाम में हजारों की संख्या में मेला भरता है, अपने देश के ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम का मेला है। उस मेले के उत्थान के लिए अगर बहुत बड़ा बजट किसी ने लगाया है तो वह हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने लगाया है। उसके लिए मैं वांगड़ की पूरी जनता की ओर से धन्यवाद देती हूं।

प्रतिपक्ष के भाई हमेशा बजट अच्छा नहीं है, यह काम हुआ वह अच्छा नहीं है। ऐसी बात आती रहती है। परंतु अगर बजट की बात करें तो हमारी सरकार ने, जब विपक्षियों ने बड़ी-बड़ी योजनाओं के अपने नेताओं के नाम रख कर के अधूरे छोड़ दिए थे, बड़े-बड़े पत्थर लगाने का जो काम किया था। उस

(श्रीमती अनिता कटारा)

काम को पूरा करने का अगर काम किया है तो वह माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। उसका जीता जागता उदाहरण है मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में भीखा भाई नहर। नाम तो भीखा भाई नहर रख दिया परंतु उसका काम नहीं हुआ था। 2008 में जब सरकार हमारी बनी उस समय हमारी सरकार ने इस नहर का काम शुरू किया और जब वापस पांच साल का गेप हों गया, उस समय नहर का काम रुक गया और आज उस नहर का काम चल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। हमारे बांसवाड़ा में कालेज का नाम गुरु गोविन्द कालेज रखा। यह माननीय मुख्य मंत्री महोदया और हमारी सरकार का काम है। सागवाड़ा में देखे जब कालेज खुली थी विपक्षियों के समय में तो उस कालेज का नाम रखा था भीखा भाई कालेज। यह होता है काम करने का अंतर और तरीका। जो वरिष्ठ है, उनको याद करते हुए, किसी योजनाओं को लागू करने का कार्य अगर कोई करता है तो वह हमारी सरकार करती है और यह हम ही नहीं कहते हैं। ये विपक्षी भाइयों के भी मन में है, ध्यान में है कि वास्तव में इनकी सरकार बनेगी तो देश का विकास होगा, इनकी सरकार बनेगी तो गांवों का विकास होगा। ये भाई भी जानते हैं।

आज हम गौरव पथ की बात करें, 9891 ग्राम पंचायतें है, उसमें से 6593 ग्राम पंचायत में गौरव पथ का काम बन गया है। गौरव पथ, यहां सदन में सिटीज के जितने भी माननीय सदस्य आते हैं, वह गौरव पथ का नाम सुनकर विचार करते होंगे कि कौनसा बहुत बड़ा काम हो गया। परंतु हमारे पहाड़ों वाले उस जिले में आकर देखो, जहां पर पानी-कीचड़ भरा हुआ रहता था और उस पानी को मिटाने का अगर काम किया है तो इस ग्रामीण गौरव पथ ने किया है। धन्यवाद तो हमारी जनता दे रही है, जिसने कभी नहीं देखा था ऐसा विकास। वह विकास अपनी सरकार के समय में हुआ।

मेरा छोटा सा जिला और उस जिले में अगर मेडिकल कालेज जैसी बात होती है तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि जब भी हमारे सिर दर्द हुआ, हमारे बुखार हुआ तो हमने गुजरात देखा, हमने उदयपुर देखा, परंतु कभी भी मेडिकल कालेज जितनी बड़ी कल्पना आज तक नहीं की थी। हमारे डूंगरपुर जिले में माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने यह बहुत बड़ा तोहफा आदिवासियों को दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती अनिता कटारा)

बहु उद्देश्यीय छात्रावास योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, 100 छात्राओं के लिए यह बजट घोषणा में किया गया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं। हर नगर पालिका में 2 करोड़ का बजट देकर हमारी सरकार ने जो सड़कें बनाने का कार्य किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं। हर नगरपालिका में भीमराव अम्बेड़कर भवन का निर्माण कार्य करने की जो बजट घोषणा हुई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूं क्योंकि आज तक हम यही बात सुनते हुए आ रहे थे कि एसटी, और एससी के साथ में कांग्रेस रहती है और ये वोट कांग्रेस के हैं। परंतु जब काम करने का अवसर आया और जब-जब हमारी सरकार बनी तब-तब एसटी व एससी के विकास के लिए कार्य शुरू हुए हैं। इसीलिए मैं नहीं मानती कि एससी और एसटी की सरकार कांग्रेस है। मैं तो यही मानती हूं कि एससी एसटी के सेवा करने वाला कोई है तो वह हमारी सरकार है और उसके लिए हमारी सरकार को, सभी माननीय मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मेरे सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ी कोई मांग नहीं है। आज तक जितनी भी मांगें रखी हैं, सभी मांगे मेरी पूरी हो गयी हैं। भीखा भाई नहर का काम शुरू करवाने की मांग रखी, भीखा भाई नहर का काम शुरू हो गया। मैंने 132 केवी जीएसएस की मांग रखी थी, 37 करोड़ का 132 केवी जीएसएस का काम शुरू हो गया है। मैंने नीलकंठ महादेव, सिलोही ग्राम पंचायत में पुल निर्माण की बात रखी थी, 37 लाख का पुल निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मैडम के आशीर्वाद और मंत्री महोदय के प्रयास से 10 करोड़ का मेरे सागवाड़ा में सड़क का कार्य शुरू हो गया है। नगरीय गौरव पथ का काम शुरू हो गया है। वह पूर्ण होने वाला है। एडीजे कोर्ट की घोषणा हो गयी। ब्लड बैंक भी बन गया और हर ग्राम पंचायत पर विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। इसके अलावा मैंने जो-जो भी मांगे रखी हैं, मेरी सभी मांगे पूर्ण हो गयी हैं। इस अवसर पर मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। हर जिले में नंदी गौशाला खोलने की घोषणा हुई है, उसके लिए भी मैं आभारी हूं क्योंकि यह काम कोई सेवा करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। हमारी मैडम और हमारी टीम के हाथों से ही यह शुभ कार्य होना था।

(19.00 बजे)

(श्रीमती अनिता कटारा)

और यह कार्य बहुत जल्दी होगा। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यगण बता रहे थे कि यह घोषणा सिर्फ घोषणा ही नहीं रह जाए। नहीं, घोषणा घोषणा नहीं रहेगी क्योंकि नगर पालिका में भी बहुत बजट रहता है, हम कार्य करने में सक्षम है इसलिए घोषणा की है। मैं उनको आश्वस्त करती हूं कि यह कार्य जरूर पूरा होगा।

मांग के रूप में मैं मेरी बिलूडा ग्राम पंचायत की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का निवेदन करती हूं। कडाना बैंक वाटर से शुद्ध पेयजल हेतु गलियागोठ सीकली सीमलवाड़ा को इस प्रस्ताव में जोड़ा जाए, यह मैं निवेदन करती हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा। श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण 2018-19 माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है। मैं भी तीसरी बार विधान सभा का सदस्य हूं। यह पन्द्रहवां ऐसा बजट, शायद पहली बार पेश हुआ है जो राजस्थान की जनता के हित में है। जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुझे 1993 में माननीय भैरोसिंह जी शेखावत के साथ विधायक रहने का मौका मिला। 1977 में पहली बार माननीय भैरोसिंह जी की सरकार बनी थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार फिर से याद दिलाई क्योंकि पहली राजस्थान की सरकार थी माननीय भैरोसिंह जी की जिन्होंने अंत्योदय योजना चालू की थी। हम छोटे थे, गांव में जाते थे, एस सी, एस टी के लोगो को बकरी पर लोन, वो लोन, छकड़े पर लोन, वह सारा मिलता था। उसकी नकल पूरे भारत में ही नहीं विदशों में भी हुई। दूसरी बार 1989 में सरकार बनी, ढाई साल बाद सरकार गिर गयी, 1993 में फिर सरकार बनी, माननीय भैरोसिंह जी शेखावत उसके मुखिया थे उन्होंने एक योजना बनायी थी कि गांव, गरीब, किसान, व्यापारी का भला कैसे हो। माननीय कटारिया साहब सामने विराजे हैं, शिक्षा मंत्री थे। प्रत्येक हैड क्वार्टर के अंदर 5वीं से 8वीं स्कूल खोली थी। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी दुनिया में नहीं रहे, प्रत्येक हैड क्वार्टर के अंदर सड़क बनाने की योजना अगर किसी ने बनायी थी तो वह माननीय भैरोसिंह जी शेखावत की सरकार में बनी। उसके बाद

(श्री पूराराम चौधरी)

अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बनायी, वह सेंट्रल का मामला है। ...(व्यवधान)... पिछली सरकार में आप भी थे और मैं भी था। पांच वर्ष आपने भी निकाले, मैंने भी देखा, कोई योजना नहीं बनी। क्योंकि नीतिगत योजना यदि कोई बनती है तो वास्तव में वह सरकार नीतिगत काम कर सकती है। इस बार नीतिगत योजना बनायी। प्रत्येक हैडक्वार्टर के अंदर 12वीं के स्कूल खुले ताकि हमारे गांव की लड़कियां पढ़ सकें क्योंकि लड़की बड़ी होने के बाद शहर में नहीं जा सकती। मां-बाप भेज नहीं सकते इसलिए माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 12 वीं स्कूल प्रत्येक हैड क्वार्टर में (व्यवधान)। श्रवण जी, आप भी थे 93 से, पिछली बार भी थे ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं खुली ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): प्रत्येक हैडक्वार्टर में पहले भी खोली थी और अभी भी खोली है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दस पंचायतें हैं, आज तक नहीं खुली। ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): खुल जाएंगी चिंता मत करो ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान की सरकार में ऐसा हुआ है कि प्रत्येक हैडक्वार्टर पर जहां पशु कम्पाउण्डर की पोस्ट नहीं थी, उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं थे, लगभग पूरे राजस्थान के अदंर खोले। इससे ज्यादा सरकार की उपलब्धि क्या होगी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के अंदर जितना माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा जी ने, (व्यवधान) यह कह रहे हैं कि घोषणा की, पिछली सरकार में जरूर घोषणा हुई थी। वह सिर्फ रेवड़ियों की घोषणा थी और जनता ने लास्ट में रेवड़ियां निकाल दीं, वह आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं भी इस सदन में था, आप भी थे, माननीय सदस्य श्रवण जी भी थे। इस बजट भाषण के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 50 हजार कर्ज माफी की है इससे किसान को, आम जनता को, लघु किसानों को काफी फायदा मिलेगा। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलाया था, यह बहुत ही अच्छी योजना थी। इस योजना से समूचे राजस्थान में ही नहीं, मैं मेरे

(श्री पूराराम चौधरी)
विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की बात कर रहा हूं, उसमें छोटे छोटे चैक डैम बनाये, एक करोड़ पचास-साठ लाख के। आज स्थिति ऐसी है जब मैं गांवों में गया कि यहां पानी तो नहीं था, अब पानी कहां से आया तो बोले आपने चैक डैम बनवाए उससे और माननीय मुख्य मंत्रीजी की जल स्वावलम्बन योजना है उसकी वजह से हमारे जीरे की फसल खड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, 2018-19 का बजट है, इसमें सबके हित को ध्यान में रखा गया है। योजना बनायी जो व्यापारियों की है ...(व्यवधान)... भंवरी योजना वह तो मुझे पता है। सदन में हनुमान जी आप भी थे, मैं था और माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी थे, वह तो बन गयी थी। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या बनी थी? ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): फिल्म बनी थी ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे फिल्म बनी थी भंवरी वाली ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): तो मैं क्या करूं उसमें, मैंने थोड़े ही बनायी थी ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में सभी व्यापारियों का भी ध्यान रखा गया है। अब यह कुछ भी कहें ...(व्यवधान)... सही कह रहा हूं, मैं गलत तो कह ही नहीं रहा। पिछली सराकर में पांच साल के अंदर बड़ी मुश्किल से, भरत सिंह जी से मेरा अच्छा व्यक्तिगत संबंध था मैंने गले पड़कर एक-दो छोटी मोटी सड़कें ली थीं। लेकिन इस बार सड़कों के मामले में, चाहे सेंट्रल का मामला हो, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे गौरव पथ हो, कोई कहे कि हमारे तो गौरव पथ बने ही नहीं, तो यह गलत है। प्रत्येक हैडक्वार्टर के अंदर गौरव पथ बनाया, मिसिंग लिंक बनायी गयी, बाकी भी बन जाएंगी। लोगों में इससे बहुत खुशी है। एक बार मैं गांवों के दौरे पर था, 85 वर्ष के जनसंघ के राजपूत थे उन्होंने कहा आपके कुछ काम नहीं हो रहा, मैंने कहा ठाकुर साहब, काम क्यों नहीं हो रहा, आप खड़े हैं, आपके गांव में जब मैने वहां पर सरपंच साहब को बुलाया कि सरपंच साहब, बताइये क्या काम नहीं हुए तो बोले साहब साढ़े आठ करोड़ के काम मेरी एक ही पंचायत में हुए हैं, फिर क्या बात करते हो, तो बोले कि हमको, गांव वालों को बताया नहीं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदस्य महोदय फिर उप चुनावों में यह दुर्गति क्यों हुई ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): कोई दुर्गति नहीं हुई। दुर्गति देखते देखते मैं तो थक गया हूं। माननीय डोटासरा साहब, मेरी बात सुनो कहीं आपकी खुद की दुर्दशा नहीं हो जाए ...(व्यवधान)... कम से कम अपनी सीट संभाल कर रखना। मैं पहली बार 93 में लड़ा था। जबरदस्ती भैरोंसिंह जी बोम्बे से मुझे बुलाकर लाये कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और मैंने लड़ा था। बाकी हम सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो हालात पैदा हो रहे हैं वह ऐसे हो रहे है कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं होगा तो भी आप हारोगें। ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति आने वाली नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूराराम जी का तो ठीक है मामला ...(व्यवधान)... बढ़िया है।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): हनुमान जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर आये हैं, उनको कह कर आएंगे वोट किसको देना है ...(व्यवधान)... ध्यान रखना कि तीन सीट जीत गये और हमारी सरकार आगे-आगे बन गयी, यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। हम अभी से चेत गये और आप निश्चित रह जाओगे कि हमारी सरकार आ गयी, हमारी सरकार बन गयी, इस भरोसे पर कभी रहना भी मत। क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से 2018-19 का बजट पेश किया है, यह पहला बजट है,

इस विधान सभा के अन्दर बैठकर मैं भी 15 वर्ष से देख रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें सबका ध्यान रखा है। चाहे वह किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अन्य वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, सबको ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बजट की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विवेक धाकड़।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय तो बहुत ज्यादा समझते हैं, सारी बातें समझते हैं। सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन आप यह कह रहे थे, 15 किलोमीटर सड़क दी है। 15 किलोमीटर सड़क किसको दी है, बी.जे.पी. वालों को दी है, हमें तो एक टुकड़ा भी दिया नहीं। हमारी सरकार ने जब 15 किलोमीटर सड़क दी थी न, बी.जे.पी. को भी दी थी। बी.जे.पी. के साथ कोई भेदभाव नहीं था। यह भेदभाव आपने किया है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): थोड़ा इंतजार करो, आपको भी दे देंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या भेदभाव, आपने कभी सोचा ही नहीं कि कांग्रेस के 21 आदमी हैं, इनको भी देते। हमने तो आपको बराबर दिया है। जब आपके 70 थे, तब भी बराबर दिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह सूट-बूट और टाई वाले को भी सड़क चाहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय सारी बात समझते हैं। ये तो लैण्ड लोर्ड आदमी हैं, सब समझते हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग ही नहीं है। आप कहें अपने मुख्य मंत्री को कि 20 आदमियों से क्यों भेदभाव कर रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): कोई बात नहीं। हमारी सड़कें हो जाने दो। फिर थोड़ी-बहुत बची-खुची आपको दे देंगे। बची-खुची आपके लिये तैयार हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी सरकार ने बराबर डिवाइडेशन किया था कि कांग्रेस का हो चाहे बी.जे.पी. का हो, सबको 15 किलोमीटर सड़क मिलेगी। लेकिन आपकी सरकार ने हमें नहीं दिया है।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): काम तो हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): काम कहां हो रहा है। ...(व्यवधान)... ये कह रहे हैं, हमारे तो हो रहा है। दशा आपकी खराब होगी, मेरी थोड़ी होगी। फिर भी दशा आपकी खराब होगी।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): परम सम्माननीय आसन एवं सदन, यह एक संयोग ही है कि जस्ट मेरे से पहले अभी हमारे वरिष्ठ साथी पूरारामजी ने ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही विवेकजी बोलने लगे तो चिकित्सा मंत्रीजी हंस रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप नये सदस्य को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं, यह समझ में नहीं आया। आप इनसे भी ईर्ष्या करते हो क्या। ये आप सबको पटखनी देगा, देख लेना, नया सदस्य बहुत तेज है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप इनसे इतने नाराज क्यों हो, जो इनको पहली बार नहीं बोलने दे रहे हो। ...(व्यवधान)... पहली बार हैं, शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): पूरारामजी ने 15 बजट देखे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, विवेकजी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। यह आशीष और विवेक का मतलब क्या है, हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या है?

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): भाई साहब, वह अभी मैं बता रहा हूं। आप, प्लीज।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके पीछे है।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): जी, मैं बता रहा हूं, सर।

इन्होंने बजट का जिक्र किया है। 29 तारीख को वोट पडा। बार-बार माण्डलगढ़ विधान सभा को लेकर चर्चा हो रही है। 29 तारीख को हम देखें तो कहावत है, 'दो' और 'नौ', उसमें शब्द है, उसको थोड़ा सा उलटा कर दें तो नौ दो ग्यारह। एक तारीख को रिजल्ट आया। एक नम्बर का बटन कांग्रेस का बटन था, संयोग यह रहा कि पांच तारीख को बजट सैशन शुरु हुआ और मेरा सौभाग्य है कि पहली ही बार में आप सबके आशीर्वाद से मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

धर्मपालजी यहां गिनती कर रहे थे और वे स्वयं अब वहां नहीं हैं। उन्होंने एक अच्छी चीज बताई कि बाई-इलेक्शन में वे जीते और अपोजिशन की गवर्नमेंट बनी, और वे वापस सैकिण्ड टर्म आये। अगर यह संयोग रहा

(श्री विवेक धाकड़)

तो सैकिण्ड टर्म भी आएगा और कांग्रेस प्रचण्ड बहुमत से आएगी। ...(व्यवधान)...

निवेदन है, सर, जूनियर मोस्ट हूं। अभी आया हूं, पहली बार है। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। एक चीज और कही थी, कांग्रेस और कंस का कहा था। कांग्रेस 'क' से शुरु हो रही है तो काश्तकार भी 'क' से शुरु हो रहा है, और गीता सार, कर्म और काम बताने वाले कन्हैया भी 'क' से शुरु हो रहे हैं। यहां सदन के हमारे सम्माननीय अध्यक्षजी, कैलाशजी मेघवाल साहब भी 'क' से शुरु हो रहे हैं। मेरे आदरणीय तात श्री हैं, ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: काल भी 'क' से शुरु हो रहा है।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): वह तो अपन किसी भी तरीके से, किसी भी तर्क से कर सकते हैं। केसरिया का इन्होंने जिक्र किया था, केसरिया भी 'क' से शुरु हो रहा है। केसरिया, भारत में वन्दे मातरम हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। भारत का फ्लैग है, उसका सबसे ऊपर का जो केसरिया है, वह भी 'क' से शुरु हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

शुरुआत करना चाहूंगा। पक्ष और विपक्ष के बीच में एक जो चीज आ रही है, वह आ रही है काश्तकार और उसकी कर्ज माफी को लेकर। शायद मैं मानता हूं कि दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत हैं कि आज काश्तकार की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर है और उसको तुरन्त प्रभाव से रिलीफ मिलनी चाहिये। इस बजट में एक घोषणा की गयी है कि सीमांत और लघु सीमांत कृषकों की 50 हजार तक की कर्ज माफी की गयी है। यह तुरन्त रिलीफ चाहिये। कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया कि सम्पूर्ण कर्ज माफी हो, उसके पीछे मैं तर्क यह देना चाहता हूं कि एक तरफ बजट भाषण में 173 नम्बर पर सरकार के द्वारा दो हजार पटवारियों की भर्ती की घोषणा की गयी है। उप चुनाव के दौरान पीले बस्ते बांटकर पटवारियों ने एस.डी.ओ. के यहां पर दफ्तर में बस्ते दाखिल किये थे। जो उनका मूल काम है तरमीम और बंटवारा, वह भी वे नहीं कर रहे हैं। चाहे आपने 50 हजार की माफी की है, उसके लिये हृदय से मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूं। काश्तकार के लिये चाहे कोई भी सहयोग कर रहा है, कितना भी सहयोग कर रहा है, वह हम सबके लिये महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमेशा से यह

(श्री विवेक धाकड़)

कहा गया है कि काश्तकार यहां बड़ी संख्या में निवास करता है। उस स्थिति में कौन तो आइडेंटीफाई करेगा और कौन डिस्बर्स करेगा। क्योंकि रेवेन्यु सारा डिपेण्ड करता है पटवारी पर और पटवारी की शोर्टेज आप बता रहे हैं। कौन आइडेंटीफाई करेगा कि 50 हजार तक की लिमिट में कौन आ रहा है, कौनसा सीमांत कृषक है कौनसा लघु सीमांत कृषक है। मेरा निवेदन यह है कि कम से कम, सम्पूर्ण कर्ज माफी को रिवाइज किया जाये। क्योंकि एक तरफ समर्थन मूल्य से उसकी उपज नहीं खरीदी गयी। यहां हम सदन में बैठे हैं। सामाजिक कार्यों में भी मैं काम करता हूं। सामूहिक विवाह सम्मेलन का आर्गनाइजर हूं, मेरी खुद की शादी सामूहिक विवाह में हुई है। चाहे हम कितनी भी चीज कहें, के.सी.सी. का जो उपयोग हो रहा है, वह उपज के लिये नहीं हो रहा है। क्योंकि काश्तकार धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में इस तरीके से बंधा हुआ है कि उसको जो पैसे की जरूरत पड़ती है, वह या तो शादी के लिये जरूरत पड़ती है या मृत्युभोज के लिये जरूरत पड़ती है, वह पैसा उसमें उपयोग करता है। यही समय है, जब उसके यहां पर शादियां होंगी, खेत जब खाली होंगे तब वह वहां शादी करेगा और वहां पैसा उसको तुरन्त चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन, सब्मिशन यह है।

सैकिण्ड, पी.डबल्यू.डी. पर मैं बात करना चाहूंगा कि संयोग ऐसा है कि गत कार्यकाल में भी सेण्टर में गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट, यह पहली बार संयोग रहा था राजस्थान के लिये कि सेण्टर और स्टेट, दोनों गवर्नमेंट सेम थी। अब तक इनमें दोनों में अलग-अलग चीज होती रही थी। पिछली बार, मैं भीलवाड़ा के उदाहरण से निवेदन करना चाहूंगा, एन.एच.ए.आई. की तरफ से हमारे सम्माननीय डा. सी.पी. जोशी साहब वहां पर सांसद थे और केन्द्र में मंत्री थे। अशोकजी गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे। एन.एच.ए.आई. की तरफ से भीलवाड़ा से लाडपुरा और भीलवाड़ा से राजसमन्द की सड़क एम.डी.आर. से सीधी एन.एच. में डिक्लीयर हुई। त्रिवेणी से लेकर देवली की सड़क मेगा स्टेट हाई-वे में है। इस बार भी, मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बड़ी घोषणाएं हुई थीं। आदरणीय नितिनजी गडकरी साहब, एन.एच. मंत्रीजी यहां पधारे थे। एक बहुत बड़ा बजट राजस्थान के लिये अलोकेट किया था। उसके बाद पी.डबल्यू.डी. के लिये जो सड़कें बचती हैं, वे इण्टरनल सड़कें हैं, एप्रोच

(श्री विवेक धाकड़)
सड़कें हैं। उनके लिये बजट अलोकेशन होना चाहिये। अगर चौथे साल में, वैसे इसका ध्यानाकर्षण भी, मैं साहब के आफिस में आया था, 131 में जो प्रस्ताव लिया है, एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगा। गेंदलिया हमारे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में है। उसमें दो साल से एक पुलिया टूटी हुयी है। चुनावी घोषणा के तहत डी.एम.एफ.टी. में घोषणा की गई कि इस पुलिया का निर्माण होगा। अभी दो-तीन दिन पहले अख़बार में आया, पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, नेता के स्टेटमेंट नहीं थे। एक्स.ईएन. ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, फाइनेंशियल नहीं है। कब तो वह फाइनेंशियल सैंक्शन होगी, कब टेंडरिंग होगी और कब वह एप्रोच होगी। यह स्थिति पी.डबल्यू.डी. को सोचनी पड़ेगी। विशेष रूप से मैं गोविन्दपुरा-श्यामगढ़, क्योंकि वहां पर तीन तरीके से अलाटमेंट हुआ है। अभी उप चुनाव को लेकर काफी बड़े अलाटमेंट्स हुए हैं और घोषणाएं हुई हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, बिफोर मानसून ठेकेदारों को पाबंद करके टाइम बाउण्ड और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कराया जाए। चाहे वह कृषि मण्डी के तहत गोविन्दपुरा वाली सड़क हो, चाहे पी.डबल्यू.डी. की सड़क, स्वयं पी.डबल्यू.डी. मंत्री बिजोलिया पधारे थे, चाहे डी.एम.एफ.टी. के थ्रू जो सड़क और पुलियाएं हैं, वे निर्माण होनी चाहिए।

तीसरी जो चीज है, महत्वपूर्ण जो आर्थिक विषय है, जिस वजह से विवेक धाकड़ यहां पर है, वह विषय है माइनिंग खातेदारी में खनन नीति। इंजीनियर कन्हैयालालजी धाकड़, जो मेरे पिताश्री भी हैं, उन्होंने इस मुहिम को लिया कि खातेदारी में काश्तकार को खनन पट्टा आबंटित होना चाहिये।

मुझे यह कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, कहीं गुरेज़ नहीं है, सामने कालू लालजी गुर्जर साहब विराज रहे हैं, यह खनिज मंत्री हुआ करते थे उस समय और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने उस खान की खातेदारी नीति को लागू किया था। इनिशियली दो ब्लॉक्स की उन्होंने सैंक्शन दी थी। कुछ वहां के लोकल कारणों से, माइन्स माफिया के कारण से, 1999 तक वह पैंडिंग रहा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की जो कमेटी थी, उसमें 2 हैक्टेयर में सिर्फ, हैक्टेयर और एकड की जो इसमें आपकी यूनिट है, उस डिफरेंस की वजह से वह चार हैक्टेयर हुआ, मंत्री महोदय उस चीज को जानते हैं। संयोग फिर देखिये कि 1999 में हमारे सम्माननीय विधान सभा अध्यक्षजी- श्री कैलाशजी

(श्री विवेक धाकड़)
मेघवाल माइन्स मिनिस्टर होते थे, फर्स्ट क्वारी लाइसेंस उनके हाथ से बना और मेरा खुद का क्वारी लाइसेंस श्री कैलाशजी मेघवाल के हाथ से बना 1999 में। बिलकुल सर, जो है उसकी बात कर रहा हूं। पर, साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि अभी जो मेरे अधिकार क्षेत्र का था, अभी वहां पर खुली नीलामी हुई है, चाहे किसी भी रूप में हुआ हो, कल उसकी खुली नीलामी होकर जो मेरे अधिकार क्षेत्र का था और मेरा वाजिब हक था, वह हक कल समाप्त कर दिया गया। खुली नीलामी सिर्फ एक जगह पर हुई। दो एग्जॉस्टड ब्लॉक में हुई और एक नया नगर में हुई, कोई बात नहीं, जैसा भी है शिरोधार्य है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा।

इस चीज में मैंने अभिभाषण के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मुलाकात की चूंकि, सम्माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने यह घोषणा की थी, यह खातेदारी पॉलिसी उनकी देन थी, हमारे सबके सम्माननीय हैं। खातेदारी में उन्होंने ओपन ऑक्शन की बात को खतम करते हुए प्रीमियम के आधार पर खातेदार को आवंटन का विषय रखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिप्सम में फर्टिलाइजर का आधार बनाकर खातेदार को खनन पट्टे देने का काम किया गया, अगर भैरोंसिंहजी शेखावत ने खनन नीति बनायी है और वह खनन नीति अब चल रही है तो बिना प्रीमियम के जैसा पहले से चल रहा है, उसी प्रकार से खातेदार को खनन आवंटित किया जाए और जो मार्बल के खंडों को कच्ची दीवार बनाने के आधार पर, मैंने मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया, लिखित में अब उनको दूंगा। मार्बल खंडों पर जो रॉयल्टी माफी की बात की है, सेम चीज सेंड स्टोन पर भी लागू होनी चाहिए, उनकी भी रॉयल्टी माफ होनी चाहिए। कच्ची दीवारे हैं, मैं सदन का बता दूंगा, फोटोज भी ला दूंगा और चूंकि खंडे, वह हैवी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लोकल उसमें डिस्पर्स होता है, एक तरफ जब हम क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, चाहे डी.एम.एफ.टी. के माध्यम से, चाहे रॉयल्टी के माध्यम से, तो वहां के स्थानीय लोगों को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि वहां के हैवी ट्रांसपोर्टेशन को क्योंकि वह खंडे बाहर नहीं जा सकते, बहुत महंगे पड़ते हैं, उनकी रॉयल्टी माफ होनी चाहिए।

पैरा 250, 252 और 253 में स्पेशल परमिट फीस जो समाप्त की गयी है, उसके लिए पुन: आभार। एक चीज जो बार-बार आ रही है, बजरी खनन

(श्री विवेक धाकड़)
को लेकर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेच, बनास की बजरी सबसे फेमस है। बनास का सबसे बड़ा स्ट्रेच भीलवाड़ा जिले में है और उसमें से भी माण्डलगढ़, आमा-गेंदलिया से शुरू होकर राजगढ़ तक पूरी जो लंबाई है वह बनास की लंबाई है। उसमें दो तरीके से वहां पर लोसेज हो रहे हैं। नीति बना दी, लाइसेंस दे दिया, सारी चीज देने के बाद वहां पर एक सेंट्रलाइज्ड स्कीम बना दी गयी, ठेकेदार की मर्सी पर है, वह किसी के, अपने लोगों की रॉयल्टी माफ कर देता है और जो स्थानीय लोग, दूसरे जो आम आदमी हैं उनकी रॉयल्टी लेता है, यह फेयर डील नहीं है। अगर लेनी है तो दोनों की ले लीजिए और नहीं लेनी है तो दोनों की नहीं लीजिए, इस तरीके से स्थानीय आदमी वहां पर पिस रहा है, स्थानीय आदमी उसकी मर्सी पर हो गया, उस ठेकेदार की मर्सी पर। उसको सरकार ने क्वारी लाइसेंस दिया है और व्यक्तिगत रूप से वह इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। जे.सी.बी. से खनन हो रहा है, बनास का सेजा खतम हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है तो इसको भी कहीं न कहीं देखना होगा।

जल संसाधन, इर्रिगेशन संबंधी मैं बात करूंगा। माण्डलगढ़ जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर बीइंग एन इर्रिगेशन इंजीनियर श्री कन्हैयालालजी धाकड़ ने काफी बड़े डैम स्ट्रक्चर्स बनाये। कोठारी, पचानपुरा जिससे इर्रिगेशन, पोर्टेबल वाटर, मोतीपुरा, जुड़ का नाका और हमारे विधान सभा अध्यक्षजी के क्षेत्र शाहपुरा में स्टेट टाइम के इर्रिगेशन स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं। कोठारी का जैसे मैं एग्जाम्प्ल दूं, वह मेरे फादर द्वारा 1986 में बनाया गया और इधर जो स्टेट टाइम के स्ट्रक्चर्स हैं, इतने पुराने स्ट्रक्चर्स में रिपेयर और मैनटिनेंस के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया, सारा बजट एलोकेशन अन्य जगह हुआ। कम से कम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर इतने पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, उनको देखना होगा।

चित्तौड़ और माण्डलगढ़ के बीच में ओराई बहुत बड़ा बांध है जिसकी टेल एंड पर माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विलेजेज आते हैं। हमेशा से यह प्राब्लम रही है कि रिपेयर के अभाव में और टोकन प्रणाली या इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करने से टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है, इसके लिए भी दिखवाने का श्रम कराएं।

(श्री विवेक धाकड़)

पेयजल संबंधी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि नार्थ इंडिया में दो ही एग्जाम्प्ल हैं, एक महाराष्ट्र में वाटर ट्रेन आती थी और एक भीलवाड़ा में वाटर ट्रेन आती थी। बीसलपुर डैम की बात हो रही है, बीसलपुर में सैकिण्ड फेज में एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्राह्मणी बनास परियोजना में 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। इतने बड़े प्रावधान के बाद 90 परसेंट रन-ऑफ भीलवाड़ा का है और सारा पेयजल बाहर जा रहा है।

हमारे आदरणीय सी.पी. जोशी साहब और गहलोत साहब के प्रयासों से फ्लो के अगेंस्ट लिफ्ट करके चम्बल परियोजना को वहां पर लाया गया पूरे जिले में, वहां पर कहीं पक्ष-विपक्ष नहीं किया गया। पूरे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एवरी रेवेन्यू विलेज, पहुंचाने का काम किया गया। हमारी माननीय प्रभारी मंत्री महोदय अनिताजी भदेल द्वारा कई बार घोषणाएं की गयीं कि अब इतनी तारीख तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अब इतनी तारीख को, जब से सरकार बनी है, तब से यही घोषणा होती रही और अब यह चौथा साल आ गया इसमें उसकी सुनिश्चितता करवायी जाए क्योंकि विशेषकर माण्डगढ़ में ऊपरमाल में जो है, होरिजेंटल बैंडेड सेंड स्टोन है, जिसमें वाटर परकोलेशन नहीं होता, इस वजह से उसमें विशेष ध्यान दिया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में मैंने उच्च शिक्षा के बारे में, कालेज के बारे में वैसे ही स्थगन में निवेदन कर दिया था। कांस्टीट्यूशन, उसमें वैलफेयर स्टेट की यहां पर कल्पना की गयी है, स्टेट और सेंटर की लिस्ट अलग बनाई गयी है। स्टेट की लिस्ट में शिक्षा का एजेंडा दिया गया है। स्टेट को व्यवस्था में भी अगर यह पी.पी.पी. मोड पर जाता है तो यहां सदन और निर्वाचन का क्या रहेगा, सरकार का क्या रहेगा? उसके जिम्मे क्या काम रहेगा? पी.पी.पी. मोड और जो स्कूल मर्ज हुए हैं, साथ ही मैं शिक्षा-कर्मियों संबंधी, उस पर भी सरकार को गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

मेडिकल कालेज की बार-बार बात हो रही है। हमारे सभी सम्माननीय सदस्य, अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह निवेदन किया। भीलवाड़ा मेडिकल हब बन चुका है, सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भीलवाड़ा आर्थोपेडिक का एक मेडिकल हब बन चुका है। वहां पर मेडिकल कालेज की घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद पिछले वर्ष बिल्डिंग तैयार

(श्री विवेक धाकड़)

है, एक महीने की डिले से पूरा सैशन खतम हो गया। वहां पर अपाइंटमेंट्स भी हो गये, उनकी सैलेरी भी ड्रॉ हो रही है। स्टूडेंट्स का भविष्य भी खतम हो गया, एक साल डिले हो गया। कम से कम इस वर्ष भीलवाड़ा और उसके साथ के जो मेडिकल कालेजेज हैं, जिनमें बिल्डिंग्स कम्प्लीट्स है इस सैशन में, कहीं बाद में यह नहीं आये, पेपर में यह पढ़ने को नहीं मिले कि इस डिले से क्योंकि एम.सी.आई., सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इस चीज को सुनिश्चित कराएं।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं। प्राइवेट कालेजेज आने के बाद में और उनको अच्छे पैकेजेज मिलने के बाद में निश्चित रूप से जो एक्सपर्ट डाक्टर्स हैं, उनकी स्थिति गंभीर है। सरकार चाहते हुए भी उनको वहां पर नहीं लगा सकती, परंतु कुछ चीजें देखने में आयी है कि जो जहां चिकित्सक चाहता है और वहां पर पोस्ट वेकेंट है तो मेरा निवेदन है। ताकि वह रुचि से भी काम करेगा और वह कहीं इधर-उधर जाने का प्रयास नहीं करेगा, उस पर ध्यान दिलाएं।

एक चीज आई थी कि राजस्थान में कर्मचारियों का, जो नये होते हैं उनका दो वर्ष का प्रोबेशन है। सातवें वेतन आयोग, इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी अदर स्टेट्स और राजस्थान में है। वह प्रोबेशन खतम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के वर्जन भी है और सातवें वेतन आयोग संबंधी किया जाए।

ग्रीन हाउस संबंधी घोषणा हुई है। मैं आकड़ों पर आता हूं, 32 करोड़ रुपये इसके लिए सरकार द्वारा इस बजट में निर्धारित किये गये हैं। मैक्सिमम जो सब्सिडी रखी गयी है वह दस लाख रखी गयी है। गणित के हिसाब से 3200 लाख रुपये, 32 करोड़ के हिसाब से 3200 लाख हुए अगर मैं गलत नहीं हूं तो? दस लाख की सब्सिडी है तो कुल ग्रीन हाउसेज अलॉट होंगे 320 और 33 जिले हैं, एक जिले में दस ग्रीन हाउस भी नहीं आएंगे और वह कहीं न कहीं प्रभावशाली और व्यक्तिगत रूप से उसका बंटवारा हो जाएगा क्योंकि उसमें शायद 70 परसेंट की सब्सिडी है छोटे ग्रीन-हाउसेज में, अभी यह भीलवाड़ा में हुआ है। इसको बढ़ाने का किया जाए और एक्चुअल जहां हम इजराइल पद्धति से कर रहे हैं ड्रिप-इर्रिगेशन, उनसे लाने की बात कर रहे हैं तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

(श्री विवेक धाकड़)

आज ही के अख़बार में ऊंटनी के दूध वाला भी एक समाचार आया था तो आज ही के अख़बार में आर.सी.डी.एफ. ने जिसने प्रपोजल दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जयपुर में वह फिजिबल नहीं है क्योंकि वहां से लाना, जो उसकी लाइफ है वह सैवन टू एट आवर्स है।

पक्ष-विपक्ष सब जगह होता है, करना भी पड़ता है, करना भी चाहिये। उसमें तीन वर्जन इसके अगेंस्ट थे, बाड़मेर और जोधपुर का बताया गया कि उधर होना चाहिये, क्योंकि ऊंटों की वहां पर मैक्सिमम संख्या है। उसमें आया था कि हवाई सेवा जहां पर है, जोधपुर में हवाई सेवा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हवाई सेवा का इतना विस्तार किया है कि किशनगढ़ और वहां तक, तो कम से कम इनिशियल लेवल पर जहां, क्योंकि वह बन भी जाएगा, स्टॉफ भी लग जाएगा, पैसा भी लगेगा, बिल्डिंग भी बनेगी पर अगर उसकी उपयोगिता नहीं है तो पुन: विचार करके उसको गंभीरता से लिया जाए।

पाइंट 90 में स्वाइन फ्लू पर विशेष प्रावधान किया, इसके लिये मैं विशेष रूप से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण, दु:खद घटना के तहत हमारे यहां जो एम.एल.ए. थीं, कीर्ति कुमारी जी का, स्वाइल फ्लू की वजह से जब निधन हुआ तो उसके बाद इतने बड़े व्यक्तित्व का, सदन के इतने बड़े व्यक्ति का निधन होने के बाद आमजन में एक डर और भय का माहौल हो गया कि स्वाइल फ्लू बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं खुद उसका उदाहरण हूं। उसके थोड़े दिन बाद मेरे पिताश्री को जब खांसी-जुकाम हुआ तो सबसे पहले मैंने प्रिकोशनरी टेमी-फ्लू चालू कर दी। आपने स्वाइन फ्लू के लिये इस पर विशेष ध्यान दिया, इसके लिये आभार।

100 नम्बर पर मिड-डे-मील में हमारे साथी शिव विधान सभा क्षेत्र से पधारे मानवेन्द्र जी ने मिड-डे-मील में दूध दिलवाने की जो व्यवस्था की, वास्तव में सराहनीय कदम है। हमारे सरस डेयरी के चेयरमैन हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं रामलाल जी जाट ने, इसको समय-समय पर उठाया है। मेरा निवेदन है कि जहां हमारी को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं, सरस खुद एक बड़ा को-ऑपरेटिव सोसाइटी है। पैकेज्ड और पाश्च्युराइज्ड मिल्क है, तो वह हैल्थ के हिसाब से ठीक और सेफ भी है तो प्रायोरिटी उनको दी जाए सैल्फ हैल्प ग्रुप

(श्री विवेक धाकड़)
की बजाय। ताकि उनको भी संबल मिले और वह हमारी को-ऑपरेटिव है, हमारी आब्जर्वेशन उस पर है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरफियरेंस है, दखल है।

पैरा 106 में कालेज और स्थानीय दानदाताओं का वर्णन किया। बिजौलियां क्षेत्र में कहना चाहूंगा कि जल-स्वावलम्बन में माइनिंग बिजनसमैन से, स्थानीय दानदाताओं से कई स्ट्रक्चर बनवाये, वह फिजिबल नहीं रहे। माइनिंग बिजनस बहुत डाऊन है। माण्डलगढ़ कालेज में भी बिल्डिंग स्थानीय दानदाताओं से बनी। एम.एल.ए. लैड और स्थानीय दानदाताओं की बजाय गवर्नमेंट खुद प्रपोजल बनाये ताकि उसकी फिजिबिलिटी वहां पर हो। एम.एल.ए. लैड का, वैसे तो शायद 01 अप्रैल से एक-दो करोड़ बचेगा, जिसमें लम्बी लाइन लग रही है तो इसमें थोड़ा-सा ध्यान दिलावें।

पैरा 113 में मदरसों के आधुनिकरण के 'ए श्रेणी' के जिन 500 मदरसों का चयन किया गया है, उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डलगढ़ में बिगोद और प्रोपर माण्डलगढ़ में बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई वहां विराजते हैं तो मेरे यहां इसमें क्लियर नहीं हुआ है, उसमें माण्डलगढ़ को भी लिया जाए।

बजट के पैरा 125 में प्रत्येक नगरपालिका में अम्बेड़कर भवन के लिये जो 80 करोड़ दिये गये हैं, तो निवेदन है कि साथ में उसकी डिजाइन, लैण्ड एलोकेशन कहां से होगा। गवर्नमेंट स्टेट लेवल से उसको किसी लैण्ड को सैट-अपार्ट करके देगी, नगरपालिका को देनी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑलरेडी नहीं है। नगरपालिकाओं में आबादी के पट्टे ही नहीं हैं, तो वह लैण्ड कौन देगा? सबसे पहले तो बिल्डिंग की डिजाइन और वर्किंग स्टॉफ की क्या पोजीशन है, उसको भी क्लियर किया जाए।

पैरा 126 में छोटे कामगारों के लिये 10 करोड़ की योजना दी गयी है। उसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छोटे कामगारों में सभी आते हैं जैसे बढ़ई हैं, लुहार हैं, सुनार हैं, सैन आते हैं। ...(व्यवधान)... एक मिनट सर, थोड़ा-सा आपसे निवेदन है।

इसमें 10 करोड़ में दो लाख तक की राशि ब्याजमुक्त की गयी है। उसमें सिर्फ 500 लोग ही आते हैं, अगर इसको डिवाइड करें। अत: इस राशि को बढ़ाया जाए।

(श्री विवेक धाकड़)

पैरा 158 में ओ.डी.एफ. में जो कहा गया है 12 हजार में, जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उसमें साथ में पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही है और वह केवल स्ट्रक्चर नाम के ही हो रहे हैं। उन पर भी ध्यान दिया जाए।

पैरा 179 में जो सबसे बड़ी चीज आयी है वह है मेवाड़-भील कोर, मेवाड़ और भील, इन दोनों नामों को लिया है। यह गौरवान्वित करता है।

विधि और न्याय विभाग से संबंधित एम.ए.सी.टी. और एन.आई. कोर्ट भीलवाड़ा में दी गयी है। एम.ए.सी.टी. के ऑलरेडी दो कोर्ट्स हैं, पर उनका एडिशनल स्टॉफ नहीं दिया गया है। वहां पर एडिशनल स्टॉफ दिया जाए। ऑलरेडी दो कोर्ट्स हैं। साथ ही माण्डलगढ़ में ए.डी.जे. का कैम्प कोर्ट है, उसको स्थायी कराया जाए ताकि उससे ज्यादा उपयोगिता भीलवाड़ा जिले को मिल सकेगी और वहां उसका लाभ मिल सकेगा।

पर्यटन, कला और संस्कृति में माण्डलगढ़ का किला, एक ऐसा किला है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा कि मुगल आक्रमण में भी यह अजेय किला रहा। यह एकमात्र ऐसा किला है, जिसके जो शासक रहे हैं, वह मेहता परिवार रहा है। वैश्य समाज से इसके शासक रहे हैं। ऐसी विशेषता रखता है। आज सुबह ही मीडिया से जब मैं रूबरू हो रहा था तो उप-चुनाव में वहां कवरेज करने के लिये गये। उन्होंने बताया कि ए.एस.आई. में वह आ रहा है और एक गार्ड भी वहां नहीं था, जब वह वहां जाएं तो इस चीज को भी देखें। मंदिर में चमलेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, तिलस्मा और त्रिवेणी संगम, प्रयाग के बाद त्रिवेणी संगम वहां है, बेणेश्वर में भी है। इसके महत्व को देखते हुए वह भी शामिल करें।

वन एवं पर्यावरण संबंधी पैरा में कहना चाहूंगा कि वन का बहुत बड़ा क्षेत्र वहां पर है और स्थानीय स्तर पर पेडोक्स के रूप में एक नई व्यवस्था ग्रामीणों ने अपने स्तर पर की है, उसको सहायता दिलायी जाए। फूला सती का वहां पर एक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम डायवर्ट कर रहे हैं, माइनिंग के लिये फोरेस्ट में डायवर्ट कर रहे हैं तो पर्टीकुलर वहां पर रास्ते के लिये एक बहुत छोटी-सी स्ट्रिप चाहिये, उस पर विचार किया जाए।

पैरा 201 में सी.ई.टी.पी. द्वारा इंडिया के मैनचेस्टर भीलवाड़ा में जो कार्यरत इकाइयां हैं, उनको तुंरत रिसर्जेंट राजस्थान में भी करायें। रीको और

(श्री विवेक धाकड़)
पोल्यूशन बोर्ड इसको तुरंत करें ताकि एक्सपांशन आ सके।

पोल्यूशन बोर्ड और माइनिंग द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जो दिया गया, दोनों विभग राजस्थान के हैं। पोल्यूशन बोर्ड भी राजस्थान के अंडर में आता है और माइनिंग डिपार्टमेंट भी आता है। जब वह क्वेरी लाइसेंस देते हैं तो यह व्यवस्था हो और इनके आपस में टाई-अप होना चाहिये। क्वेरी होल्डर को पोल्यूशन बोर्ड में अलग जाना पड़ता है, वहां इधर रेंट दे रहा है तो यह आपस में समन्वय करके करें।

पत्रकार कल्याण में आपने जो दिया है, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा में आबंटित भूखण्डों की क्रियाशीलता पर सहानुभूति और प्रेक्टिकली विचार करके पत्रकारों के पक्ष में लाभ दिलावें।

कर प्रस्ताव में, व्यापारी कल्याण बोर्ड के लिये 10 करोड़ दिये गये हैं, मारवाड़ी व्यापारियों का नाम भारत में ही नहीं, विश्व में भी है। यह बहुत बढ़िया चीज की है कि व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित हुआ है। परन्तु यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा लायक है। जहां बिड़ला और बड़े-बड़े हमारे ग्रुप्स हैं, 10 करोड़ रुपये व्यापारी कल्याण के लिये दें, तो कम है। इसको थोड़ा-सा बढ़ाने का कष्ट करायें।

पैरा 224 में आपरेशन ग्रीन में जो रीफर वैन (कोल्ड चैन) दिया कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने के लिये, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है, परन्तु इसकी संख्या और किस तरीके से आपरेट होंगे, इसके लिये कितना बजट दिया जाएगा, क्योंकि काश्तकार एक भेड़ चाल की तरह बात करता है, ज्यादा रेट आती है तो उस चीज को वह नैक्स्ट ईयर ज्यादा बोता है तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है और स्टोरेज के अभाव में और समर्थन मूल्य के खरीद के अभाव में कई जगह इतनी दयनीय स्थिति होती है कि जिस फसल को वह 6 महीने सींचता है, पालता है, बड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसको रोड पर फेंकना पड़ता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

पैरा 230 में 10 प्रतिशत डी.एल.सी. रिड्यूज की गयी है। भीलवाड़ा में बजट के एक दिन पहले 15 प्रतिशत डी.एल.सी. बढ़ा दी गयी थी।

परिवहन विभाग में आर.एस.आर.टी.सी का लोगो एक सेफ और पंक्चुअल

(श्री विवेक धाकड़)

सर्विसेज के रूप में जाना जाता है। उसके निजीकरण को लेकर जो चीज हो रही है, उसको भी दिखवाया जाए।

स्थायी लगान में एक चीज कही गयी। 40 से 50 लाख काश्तकार इससे लाभान्वित होंगे, परन्तु उस अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के माध्यम से, कि वह अमाउंट बताया जाए। 10 पैसे बीघा और 20 पैसे बीघा, वह कितना अमाउंट हो रहा है। इसमें संख्या नहीं है तो वह भी बताया जाए।

लास्ट में, मैं कंक्लूड करते हुए ऊर्जा के संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि जब उप-चुनाव हुए तो उस समय दिन में पूरे 6 घंटे लाइट आ रही थी। अब मेरे लिये प्रॉब्लम हो गयी कि आपके वोट देते ही, आपको जिताते ही लाइट कट रही है। पुरानी व्यवस्था को वापस, जो उप-चुनाव से पहले व्यवस्था थी, मांडलगढ़ के लिये विशेष रूप से आभार, कि लाइट दिलाने की कृपा करावें।

एक चीज से मैं कंक्लूड करता हूं कि 13 मई को मेरी मदर की पुण्यतिथि है, उसमें हम ब्लड डोनेशन कैम्प आयोजित करते हैं। रूरल और माइनिंग एरिया में ब्लड डोनेशन कैम्प बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से एनकरेज करते हैं। उसमें हजार यूनिट का ब्लड डोनेशन कैम्प आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहां आर्गनाइज करवाता हूं। ब्लड बहुत मुश्किल से मरीज को मिलता है और जिस स्थिति में मरीज वहां पहुंचता है, दवाई एक ऐसी चीज है कि एक दुकान से नहीं, तो दूसरी दुकान से ले सकता है। एक सब्सिट्यूट नहीं है तो दूसरा सब्सिट्यूट ले सकता है, पर ब्लड हमेशा इमरजेंसी में यूज आता है। उस पर जो जी.एस.टी. लगा है, क्योंकि मैं उस कैम्प का आर्गनाइजर हूं और मदर की पुण्यतिथि पर कैम्प लगाता हूं तो कम से कम उस जी.एस.टी. को हटाने का हम सब प्रयास करें और आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आमंत्रित हैं 13 मई को, मेरे वहां मांडलगढ़ में, बिजोलिया में जो ब्लड डोनेशन कैम्प है, आप सब पधारें, आशीर्वाद दें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल। एक मिनट विराज जाए। मुख्य सचेतक महोदय, हमीर सिंहजी भायल के अलावा चार और एक पांच सदस्य और हैं, जिनका सूची में बोलने के लिये नाम हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है, क्योंकि पांच व्यक्तियों को 10-10 मिनट या 15-15 मिनट भी देंगे तो आसन को एक घंटे की तो आप लोग और स्वीकृति प्रदान करें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही पूरी होने, आज की जो बोलने वाले माननीय सदस्यों की सूची है, वह पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज के बोलने वालों की सूची के पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

...(व्यवधान)...

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बजट 2018-19 की चर्चा पर बोलने का समय दिया ...

श्री उपाध्यक्ष: इसमें एक काम करें जिसकी चर्चा हो गयी उसको छोड़ें, जिसकी नहीं हुई है उस पर करें। आप अगर धन्यवाद देना चाहें वो तो बार-बार दें, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब पर धन्यवाद दे दें और फिर ऐसा कोई विषय हो ...(व्यवधान)...

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): इसके लिए धन्यवाद।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देकर के ...(व्यवधान)... ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बोला उधर से रिपीट किया जाए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट 2018-19 में सबसे पहले कहा कि 'सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय', इसका भावार्थ किया जाए तो सब के हित में, सब के सुख में ही कहा जाएगा। सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात कही। सशक्त, सम्पन्न राजस्थान के लक्ष्य को सुस्थापित किया गया। 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना से तैयार इस बजट में सुशासन और विकास के निरन्तर प्रवाह के साथ आमजन के लिए तत्कालीन राहतों, दीर्घकालीन विकास को लक्षित करते हुए राजस्थान के समग्रामी विकास को शामिल किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री साहिबा का विजन 'सब का साथ सब का विकास' इसमें स्पष्ट झलकता है। विजन 2020 के तहत राजस्थान के विकास के पांच मूल मंत्र जिसके कारण राजस्थान के आम नागरिक के जीवन में सुधार आया है, इसी से राज्य बीमारू श्रेणी के राज्यों से बाहर आकर प्रगतिशील राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहा है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस बजट में सबसे पहले ही बाड़मेर जिले का जिक्र किया गया, यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। एक ऐतिहासिक निर्णय बाड़मेर के इतिहास में ही नहीं राजस्थान के इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया कि 16 जनवरी, 2018 को बाड़मेर रिफाइनरी के कार्य का शुभारम्भ किया गया। इसमें एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा एवं राज्य को 40 हजार की लागत में बचत हुई, बचत करके लाभ पहुंचाया गया।

बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। समाज के हर स्तम्भ को छुआ गया। बच्चों से लगा कर बुजुर्ग, खेल से लगा कर के घर तक की घोषणाएं रखी गयीं। विशेष फोकस युवा, महिला एवं किसानों पर रहा तथा हर विधान सभा क्षेत्र को प्रभावित किये जाने वाला बजट पेश किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर बजट की भांति 2018-19 में भी राजस्थान के विकास को देश के अग्रिम पंक्तियों में खड़े राज्यों के बराबर खड़ा करने हेतु पेश किया गया। सुशासन और विकास के राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, युवा एवं मजदूर के साथ कौशल योग्य क्षमतावान नागरिक तक इस बजट में सुविधा शामिल की गयी।

(श्री हमीरसिंह भायल)

राजस्थान की राजधानी को अन्तरराष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के प्रयासों में रात्रि पर्यटन, लैपर्ड सफारी, रामनिवास बाग़ का मसाला चौक, माधवेन्द्र पैलेस का स्कल्पचर पार्क, द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट आदि योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है जिससे जयपुर विश्व के पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है।

2013 से वित्तीय बजट में विजन 2020 को लक्षित करते हुए पांच प्राथमिकताओं के आधार पर राजस्थान के विकास को लक्षित किया गया। विनिवेश बढ़ावा, बेरोजगारी कम करना, अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा में सुधार करते हुए कौशल विकास करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। युवाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु स्वयं के रोजगार हेतु कई अवसर दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छे काम के साथ अच्छे बनें पर बुरे के साथ बुरे नहीं क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता।

'सारा जहां उसी का है जो मुस्कराना जानता है,
रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है,
हर जगह मन्दिर, मस्जिद, गुरु द्वारे हैं
लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क के बारे में जब-जब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारत वर्ष में पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण बड़े शहरों को जोड़ने वाली सड़क के साथ में पीएमजीएसवाई के नाम से पूरे भारत में तोहफा दिया। हमारे मारवाड़ की रेगिस्तान की धरती बाड़मेर-जैसलमेर हजारों किलोमीटर लम्बाई और चौड़ाई में है, अगर यह पीएमजीएसवाई स्कीम आदरणीय वाजपेयी जी लागू नहीं करते तो आज हमारे धोरों के टीले, एक भी ढाणी तो क्या गांव भी नहीं जुड़ पाता, तो मैं धन्यवाद दूंगा। उसी तर्ज पर रोड़ का काम, सड़क का काम है। आज भी राजस्थान की आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने आगे ब्राडगेज के हिसाब से सारी

(श्री हमीरसिंह भायल)

बड़ी रोड़, छोटी रोड़ की और इस बार भी इस बजट में रोड़ के लिए जो फंड दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य करके राजस्थान के हर गांव और ढाणी को जोड़ने का कार्य किया है।

राजस्थान में परिवहन निगम में भी वृद्ध के लिए फ्री में सफर करने के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिवाना विधान सभा क्षेत्र की मुख्य मांग सिवाना-समदड़ी-कल्याणपुर सड़क स्टेट हाईवे 66 का निर्माण, 7 मीटर चौड़ी अति आवश्यक है, इसके लिए आपके माध्यम से आदरणीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करता हुआ निवेदन करूंगा कि इस बजट में इसको जोड़ कर इसका निर्माण कराया जाए ताकि सांचौर से लगा कर इतना बड़ा भू-भाग है, दो जिलों का मिलान और जोधपुर पहुंचता है, अगर यह हो जाएगा तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी राहत मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन पिछले चार वर्षों में 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र से नवीन सिंचाई क्षमता का विकास किया गया, जिससे आमजन को राहत मिली। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी विभाग द्वारा केन्द्रीय अध्ययन दल भेज कर सर्वे करवाया गया जिसमें 38 जल संरचनाओं की डीपीआर तैयार की गयी एवं लगभग 10 करोड़ लागत के काम प्रगति पर हैं। इसके लिए भी मैं आदरणीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

मेरी आपके माध्यम से मांग रहेगी कि जालौर जिले के बांकली बांध एवं पाली जिले के हेमावास बांध का बरसाती पानी नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु दिया जाता है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीमा तक आता है एवं पाली-जालौर के किसानों को जितना पानी चाहिए, उससे अधिक पानी दिया जाता है, जो बेकार एवं फिजूल पडा रहता है। क्यों न इस नहर को आगे बढ़ा कर मेरे क्षेत्र के अर्थंडी, रातड़ी, छियाली, सेवाली, करमावास, सांवरडा, खण्डप एवं सरवड़ी तक किसानों को पानी देकर फिजूल पानी का उपयोग लिया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मेरा क्षेत्र अरावली पर्वत शृंखला से जुड़ा हुआ है जिससे बरसात के दिनों में कई प्रकार के नदी-नाले चलते हैं,

(श्री हमीरसिंह भायल)

बरसाती पानी बेकार बहता है एवं भूमि का कटाव भी होता है, इसको रोकते हुए विभाग द्वारा केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है, उस पर विचार करके अतिशीघ्र राहत प्रदान करावें।

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत मेरे क्षेत्र में भी जल संरक्षण की कई संरचनाएं खड़ी की गयी हैं।

इससे आमजन और पशु-पक्षियों को बहुत राहत मिली है। जल संसाधन विभाग के सभी कार्य पहाड़ी की तलहटी में टिके हुए है। जबकि पूरी पहाड़ी वन क्षेत्र के अधीन आता है। इसके कारण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, अन्यथा कार्य नहीं होता है। इस ओर राज्य सरकार विशेष ध्यान देकर दोनों विभागों के समन्वय से कार्य करे तो चल रहे कार्यों को और गति मिल सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिए राजस्थान में दीर्घकालीन योजना बीसलपुर से लगाकर के स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने शुरू की। हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने पोकरण-फलसूंड, उम्मेद सागर, बाड़मेर लिफ्ट एवं गुजरात से जो नर्मदा का पानी आता है, उसके लिए 2003 से 2008 तक बहुत कार्य किया। दुर्भाग्यवश 2008-2013 तक की सरकार ने उस पेयजल योजना पर एक भी रुपया नहीं लगाया। वह योजना जहां पड़ी थी, वहीं की वही पड़ी रही। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्रीजी को और हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि अब उसको गति तो मिली है। लेकिन अभी भी धीमी गति है। 2018 तक इसका पानी सारे गांव और ढाणियों तक पहुंचना है। इसमें अभी भी दुविधा है। मंत्रीजी यहां विराज रहे हैं, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ी गति दें ताकि दिसम्बर, 2018 से पहले-पहले हर गांव और ढाणी तक यह पानी पहुंच जाए। इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे यहां ग्रिड भी बने। ऊर्जा क्षेत्र के लिए जहां आवश्यकता है वहां बजट का प्रावधान आदरणीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा किया गया है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि एवं पशुपालन में सीमांत किसानों को 30 सितम्बर, 2017 तक ओवरड्यू होने वाले खातों का ब्याज सहित पूर्ण माफी

(श्री हमीरसिंह भायल)

तथा काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण, 50 हजार तक के कर्ज माफ किये हैं। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया गया है। किसान भाइयों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले इसके लिए समर्थन मूल्य पर कई फसलों की खरीद की घोषणा की गयी है। इसके अलावा जल हौद निर्माण, डिग्गी निर्माण, सौर ऊर्जा पंप लगाने, ग्रीन हाउस बनाने के लिए अनुदान में भी वृद्धि की गयी है।

प्रत्येक जिला स्तर पर नंदी गौशाला, यह राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण घोषणा है। अगर हर जिले में नंदी गौशाला खुल जाएगी तो जो यह नंदी खड़ी फसलों में जाकर घुस जाते थे, उससे किसानों को राहत मिलेगी। गौशाला के लिए 3 माह को बढ़ाकर 6 माह अनुदान जो किया है, इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करुंगा कि स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जब वह मुख्य मंत्री बने तो गांव, गरीब और किसान को समझते हुए पांचवीं से आठवीं स्कूल करके पूरे राजस्थान को तोहफा दिया। इसी की तर्ज पर आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी जब 2003 में मुख्य मंत्री बनी तो उन्होंने आठवीं से दसवीं स्कूल करके गांव और गरीब के बच्चे, बच्ची कैसे पढ़े इसके लिए पूरे राजस्थान को तोहफा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि स्कूलों के लिए कांग्रेस के समय में जब तक लोग थक नहीं लेते थे, तब तक एक स्कूल क्रमोन्नत नहीं होती थी। जब 2013 में राजस्थान की मुख्य मंत्री ने बागडोर संभाली तो एक साथ 5300 सैकण्डरी को सीनियर सैकण्डरी करके गांव, गरीब की बच्चियां कैसे पढ़ें उसके लिए जो तोहफा दिया है, उसके लिए उनको धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक ही नहीं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने 2003 से 2008 में देवासी समाज, जो पशुपालक है, हमेशा वह रेवड़ लेकर के बाहर हरियाणा से लेकर के मध्य प्रदेश तक घूमता है, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने जालौर में हरियाली आवासीय शिक्षा भवन बनाकर के उनके लिए सुविधा की।

मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मंत्री अरुण जी को और आदरणीय मुख्य

(श्री हमीरसिंह भायल)
मंत्रीजी को कि पिछले साल में शिवरात्रि के दिन हमारे जैतसीसर धाम में क्योंकि सबसे ज्यादा रेबारी बाड़मेर और जैसलमेर में देवासी जाति के हैं, वहां जब पधारे तो हमने निवेदन किया कि यह घुमक्कड़ जाति है और इनके लिए शिक्षा की महती आवश्यकता है। उन्होंने उसी समय आवासीय छात्रावास और स्कूल के लिए 13 करोड़ की घोषणा की। यही नहीं, जब डीपीआर बनाकर के नक्शा तैयार हुआ तो उसका बजट 22 करोड़ हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इन 2 जिलों के देवासी समाज के लिए 22 करोड़ की घोषणा ही नहीं की बल्कि आदरणीय मंत्रीजी ने आकर के शिलान्यास भी कर दिया। उसका करीब 30 प्रतिशत कार्य भी प्रगति पर है। सितम्बर या अक्टूबर में उसका उद्‌घाटन हो जाएगा। मुख्य मंत्रीजी उसका उद्‌घाटन करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कल भी शिवरात्रि थी। मैं विधान सभा की वजह से यहां था। वहां आदरणीय बाड़मेर से पधारने वाले माननीय सदस्य की पार्टी के लोग गये और कहा कि हम यहां भाषण देंगे। आप हमारा स्वागत करो। महाराज से लेकर के देवासी समाज के सदस्य विराजे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद तक हम आपके पीछे-पीछे घूमे। लेकिन हमारा जो यह भवन 22 करोड़ का बन रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया है। इसके कारण न हम आपका स्वागत करेंगे और न ही सत्कार करेंगे। इससे ज्यादा बढ़कर क्या बात हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आज की तारीख में बाड़मेर भू भाग की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसी सरकार में आदरणीय गृह मंत्री जब पंचायत राज मंत्री थे, परिसीमन जब हुआ तो पुनर्गठन में सबसे ज्यादा पंचायत समितियां बाड़मेर में बनी। 109 पंचायतें बनीं। अब हमारे यहां 17 पंचायत समितियां हैं। इतने उपखंड हैं। बाड़मेर में रिफाइनरी हो गयी। अरड़की जो सबसे बढ़िया खनिज, धातु मिल रहा है वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। ग्रेनाइट है, लिग्नाइट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को आप हमारी सिफारिश करें कि बालोतरा जिला बनना चाहिए। बालोतरा जिला बनाने के लिए मांग काफी समय से, 1967 से चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मांग की

है और हमारे कई भील जाति के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य हैं। अभी भी हमारे बालोतरा में भील जाति का प्रधान है। इससे गये पीरियड में मेरे सिवाना में भी भील जाति का प्रधान था। टाड़ा, माडा जैसे बांसवाड़ा, देवगढ़ आदि में, ट्राइबल में जैसी सुविधा उनको मिलती है, यह सुविधा जो हमारे यहां भील समाज है, वह भी एस.टी. के ही हैं। लेकिन उनको किसी तरह का सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है। उनको यह लाभ मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार विपक्ष के सदस्यों द्वारा यह बात कही जा रही है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया।

(20.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र ट्राइबल बैल्ट में है, आधा विधान सभा क्षेत्र हमारा प्रतापगढ़ क्षेत्र में आता है, जो ट्राइबल बैल्ट में है लेकिन मैं वहां जब जाता हूं और देखता हूं कि हमारी आदरणीय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से हर पंचायत मुख्यालय पर बारहवीं का स्कूल क्रमोन्नत किया है। उस क्रमोन्नत करने से पहले 15-15, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर बालक और बालिकाओं को या तो प्रतापगढ़ जाना पड़ता था या धरियावद जाते थे या इधर छोटी सादड़ी जाते थे, उन सब बालक बालिकाओं को पंचायत स्तर पर स्कूल की सौगात मिली और यह सौगात मिलने से आज उस क्षेत्र में बालक बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है उसके लिए निश्चित रूप से जितना धन्यवाद आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को दिया जाए उतना कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां देखता हूं कि आज साइकिलें मिली हैं, आप वहां देखेंगे तो एक-एक स्कूल में पचास-पचास साइकिलें मिल

(श्री गोतम कुमार)

जाएंगी। बालिकाएं उन साइकिलों से आ रही हैं, पढ़ने के लिए। हर साल यह बात आती थी, आलोचनाएं होती थी कि स्कूल तो आपने खोल दिये लेकिन आपने आगे की कोई व्यवस्था नहीं की। वहां स्कूल भी खोले, स्कूल खोलने के बाद में अध्यापकों की व्यवस्था भी की और अध्यापकों की व्यवस्था करने के बाद आज जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं, रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहे प्रमोशन करके हों, चाहे कैसे भी हो लेकिन जिस तरह से निजी स्कूलों में लोगों का विश्वास बढ़ रहा था, आज इन दो-तीन सालों में वापस सरकार के द्वारा जो स्कूल खोले गये हैं, नये-नये प्रिंसीपल्स आ रहे हैं, ऊर्जा लगाकर वह स्कूलों में अध्ययन करवा रहे हैं और घर-घर जाकर आग्रह करके बच्चों को लाकर पढ़ाने का काम हमारे स्कूल कर रहे हैं, उसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी समय की हमें लिमिटेशंस हैं, ज्यादा नहीं कहते हुए विद्यालय की बात हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भामाशाह स्वास्थ्य सुविधा की लगातार आलोचना भी हो रही थी और सब कुछ हो रहा था लेकिन जितना अच्छा काम भामाशाह स्वास्थ्य योजना में हुआ है, इतने करीब से हमने देखा है, भामाशाह स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हमने कितने ही मरीजों का आपरेशन करवाया है, निश्चित रूप से इसको देखने पर लगता है कि कैसे उस गरीब आदमी को जो प्रतापगढ़ क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में रहता है वह कभी यह सोच ही नहीं सकता था कि मैं भी कभी बाइपास करवा सकूंगा, मैं भी कभी वॉल्व का आपरेशन करवा सकूंगा। दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये का जब खर्चा आता था तो उन गरीब किसानों की तो बात छोड़ें, आज मैं देखता हूं कि अच्छे-अच्छे लोग भामाशाह स्वास्थ्य योजना का कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास आते हैं कि हमें किसी तरह से इस सुविधा का लाभ मिल जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस योजना से जोड़कर क्योंकि हमारे यहां मूल समस्या गरीब आदमी की है, वह इलाज नहीं करवा पा रहा था और इलाज नहीं करवा पाने की मूल वजह भी गरीबी और बीमारी ही थी। बीमार होने पर वह कर्जदार हो जाता, कर्जदार हो जाने पर जैसे आपरेशन के लिए दो

(श्री गोतम कुमार)

लाख रुपये खर्चा आया, लाख रुपये की व्यवस्था हुई, लाख की वह नहीं कर पाया तो आदमी भी हाथ से चला जाता था और इलाज भी नहीं करवा पाता था। आदमी के हाथ से लाख रुपया खर्च भी हो गया और वह कर्जदार भी हो गया, उसके बाद में आदमी भी चला गया। आदमी के जाने के बाद थोड़ा धूप-ध्यान करने में और कर्जदार होता और वह परिवार वहीं का वहीं रह जाता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार से गरीब आदमी को ध्यान में रखकर कैसे वह आदमी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सके, इसके लिए भामाशाह स्वास्थ्य योजना चालू की और उसका लाभ हम देख रहे हैं। राजस्थान के एक हजार प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हमारे यहां जो हॉस्पिटल है, गीतांजलि-अमेरिकन, उन हॉस्पिटलों में आम आदमी, गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि हम इलाज करवा पाएंगे लेकिन आज उन हॉस्पिटलों में अभी कल ही बात है, कल हमने मित्तल हॉस्पिटल, अजमेर में वाल्व का एक आपरेशन करवाया जिसका लगभग डेढ़-दो लाख रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल वाला बता रहा था। वहां की सुविधा देखकर उसने कहा कि मुझे कहीं यह महसूस नहीं हुआ मैंने फ्री में इलाज करवाया या पैसा देकर करवाया, इतनी अच्छी सुविधा हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, किसानों की जो बात हुई, धाकड़ साहब कर रहे थे, कहां से कहां से लेकिन काश्तकारों के लिए जो इस सरकार ने किया है, ऐसा शायद क्योंकि हम भी किसानी क्षेत्र से ही आते हैं और हम देखते हैं कि किसानों के लिए पूर्व की सरकारों ने कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया। इस बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में, आपदा राहत मंत्रीजी भी सामने विराजे हुए हैं, इन्होंने वहां पर लगभग दो बार फसल खराबा हुआ और दोनों बार फसल खराबे में हमारे विधान सभा क्षेत्र में डेढ़ सौ करोड़ रुपये का मुआवजा दिया और किसानों को आपदा के समय में जो नुकसान हुआ था उसको राहत देने का काम उस समय हुआ था। उसके बाद फिर वापस अभी तीसरी बार, इनके कार्यकाल में किसानों को राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस बार सीमांत कृषकों को, लघु सीमांत कृषकों

(श्री गोतम कुमार)
को भी, कैसे गरीब आदमी, छोटा किसान लाभांवित हो, कैसे वह आगे बढ़ सके, कर्जदार यदि वह हो गया तो वह पीछे की पंक्ति में नहीं रहे, वह भी आगे आ सके उसके लिए जो उन्होंने पचास हजार रुपये की कर्ज माफी का काम किया, उसके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है।

कृषि के साथ-साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन चार सालों में दो लाख कृषि कनेक्शन देने का काम किया और इस साल भी दो लाख नये कृषि कनेक्शन देने का काम किया है। जब बजट भाषण मैडम ने पढ़ा था उसके बाद अगले दिन महाशिवरात्रि थी, अधिकतर पब्लिक स्थानों पर हम गये, जहां-जहां पर भी हम गये, कर्ज माफी और कृषि कनेक्शन जो दिये सरकार ने दो लाख, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। इसलिए मेरा तो यह आग्रह है कि आप भी खुलकर जो अच्छी बात हो उसकी तारीफ करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो ज्यादा नहीं कहता हुआ अपने क्षेत्र में हुए विकास की बात भी करूंगा। बहुत सारी बात हो रही है कि कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ लेकिन मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो काम हुए वह भी आपको गिना सकता हूं कि किस तरह से हमारे वहां पहले की सरकार में पांच साल तक आपकी सरकार रही, तीन-तीन बार बजट में घोषणा हुई कि मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी तक की आपकी सड़क बन जाएगी लेकिन वहां कोई सड़क का नाम न निशान। एक बार घोषणा हुई कि टू लेन से फोर लेन सड़क बनेगी लेकिन न तो फोर लेन सड़क बनी, न कोई बजट में प्रावधान किया गया और न वह सड़क मिली, सिर्फ और सिर्फ हमें घोषणाएं मिलीं। जैसे ही हमारी सरकार बनी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे वहां सीआरएफ से दो-दो सड़कों का, लगातार जिनकी तीस-पैंतीस सालों से डिमांड चल रही थी, मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी सड़क की केवल घोषणा नहीं की, उसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया। आज हम बिना टोल दिये, पिछली बार सरकार में फोर लेन सड़क की बात हुई थी, टोल की बात हुई थी लेकिन बिना टोल के आज हम उस मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी की सड़क पर आराम से घूम सकते हैं। इसी तरह से औड़ा चौराहे से लगाकर बानछी तक की सड़क की बात थी जो लगभग साठ किलोमीटर लम्बी है, वह भी

(श्री गोतम कुमार)

बड़ी जर्जर स्थिति में थी उसके लिए भी 77 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर आज उस सड़क पर भी हम आराम से घूम सकते हैं। लोगों को काफी राहत इससे मिली है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बात कर रहे हैं, मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। हमारे प्रतिपक्ष के कुछ बंधु बात करते हैं आपकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी जब पिछले कार्यकाल में भी मुख्य मंत्री थीं तब हमारे वहां पिंड डैम है, उस पिंड डैम का आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास किया। उसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया और लगभग 17 करोड़ रुपये उसके लिए स्वीकृत किए थे लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आयी उसने पिंड बांध परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसे ही हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी बनीं, सिंचाई मंत्रीजी, रामप्रतापजी ने उस बांध की वापस सुध ली और सुध लेकर के बांध जिसके लिए 17 करोड़ रुपये स्वीकृत थे, मुआवजा राशि भी काफी अपर्याप्त थी किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 70-70 हजार रुपये जमीन की रेट चूंकि बढ़ चुके थे तो जो 70-70 हजार रुपये बीघा के थे, उसको बढ़ाकर लगभग 4-4 लाख रुपये पर बीघा की दर से मुआवजा देकर किसानों को संतुष्ट करके और उस पर 32 करोड़ रुपये का किसानों को मुआवजा देकर, आज उस बांध का 90 प्रतिशत काम हमारे उस बांध का पूरा हो चुका है।

(20.09 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमारे वहां सड़कों का निर्माण हुआ, हमारे वहां पिंड डैम, जो हमारी महत्वपूर्ण मांग थी, उसको भी पूरा करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए छोटी-मोटी हमारे क्षेत्र में कुछ कमियां रह गयी हैं तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से, आदरणीय मंत्री महोदय से कि हमारे वहां एक सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है।

(श्री गोतम कुमार)

सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में 12 महीने हरियाली रहती है, 12 महीने वहां नदियां बहती रहती हैं और उस वन्य जीव अभयारण्य में सारे प्रकार के जीव हैं। चौसिंगा ऐसा प्राणी है वहां पर, वहां उड़नगिलहरी ऐसी गिलहरी है, जो पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलती है। मेरा तो आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय उस ओर भी ध्यान देकर के उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में अगर विकसित करेंगे तो जैसा सवाईमाधोपुर और सरिस्का अभयारण्य है, मेरा ऐसा सोचना है उसमें बहुत सारी औषधियां भी हैं, अगर वह डवलप होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में बोहेड़ा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू विलेज है, वह बड़ी सादड़ी तहसील में है। वहां जो पीएचसी है, वह सीएचसी में कन्वर्ट हो जाए तो वहां जो लगभग 10-15 हजार की आबादी रहती है, उन्हें काफी राहत मिलेगी।

मार्बल के खण्डों के लिए तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी कटौती प्रस्ताव में निश्चित रूप से राहत देने का काम किया। मेरा तो आपसे आग्रह है कि मार्बल के उद्यमी तो बड़े उद्यमी होते हैं, लेकिन हमारे वहां खोड़ित में लाइम स्टोन के पत्थर निकाले जाते हैं और उन खनन व्यवसायों में भी खण्डे इसी प्रकार से निकाले जाते हैं। चूंकि वहां तो छोटी-छोटी खानें हैं, गरीब आदमी हैं, अगर उन खोड़ित के खण्डों को भी इस रियायत में शामिल कर लिया जाए, कल-परसों जब मुख्य मंत्री महोदया रिप्लाई देंगी और इन खोड़ित के खण्डों को भी इसमें जोड़ लेंगीं तो उस क्षेत्र के आस पास में रहने वाले जो गरीब आदमी हैं, जो मकान का सपना देख रहे हैं, उन सबको निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

एक हमारी महत्त्वपूर्ण मांग है एडीजे कोर्ट की। हमारे वहां कैंप कोर्ट चलती है। 15 दिन में दो-दो दिन के लिए कैंप लगता है। बड़ी सादड़ी से जो स्थायी कोर्ट है वो निम्बाहेडा है और बड़ी सादड़ी में जो कोर्ट है, वहां से उसकी दूरी 45 किलोमीटर है। हमारा डूमला उपखण्ड भी बड़ी सादड़ी में एडीजे कोर्ट में कैंप के रूप में है और उस दो दिन के कैंप के अलावा आवश्यक सुनवाई के अलावा उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि वहां कैंप कोर्ट की जगह अगर स्थायी कोर्ट हो जाए और इस

(श्री गोतम कुमार)

रिप्लाई में अगर वह भी जुड़ जाए तो निश्चित रूप से जो डूमला से 70 किलोमीटर दूर हमें निम्बाहेड़ा जाना पड़ता है, उससे हमें राहत मिलेगी और बड़ी सादड़ी के बाशिंदों को बहुत राहत मिलेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट के वाद-विवाद में बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कैलाश जी भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति जी, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट 2018-19 का पेश किया है, वह जानदार और शानदार है। सारे प्रदेश में उसकी वाहवाही हो रही है। हर व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है, यह बजट अभी की जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप बनाया गया है। 'सबका साथ, सबका विकास' लेकर बनाया गया है। 20 दिसंबर, 2013 को पांच प्रायोरिटी सैक्टर्स तय किये थे- निवेश को बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, अर्थव्यवस्था में सुधार, शिक्षा में सुधार और कौशल विकास। सभी में सुधार किये गये। जो सबसे बड़ी बात हुई है बाड़मेर में रिफाइनरी पचपदरा में। डील नेगोशिएट करके 40 हजार करोड़ की बचत की गयी है और फेयर बढ़ाया गया है, 1 लाख लोगों को रोजगार जैसलमेर, बाड़मेर में मूंदड़ा-काण्डला बंदरगाह से जोड़ने वाली रेल लाइन बनने का लाभ होगा। पश्चिमी राजस्थान के लिए ऐसा वरदान बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। रिफाइनरी और पैट्रो केमिकल्स प्रोडक्शन की हमारे प्रिय प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई ने घोषणा की थी। मार्च, 2022 तक रिफाइनरी, पैट्रो केमिकल्स शुरू कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से जो उद्घाटन करता हूं, उसे क्रियान्वित करने में विश्वास रखता हूं, ऐसा आश्वासन पचपदरा में आम सभा में दिया गया था। मैं समझता हूं, जोधपुर के लिए तो सबसे बड़ा वरदान है। जोधपुर सौ किलोमीटर पर सबसे बड़ा राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र है और पैट्रो केमिकल्स का बाय-प्रोडक्ट्स के लिए जो इंडस्ट्री लगेगी, वह जोधपुर में ही लगेगी। जोधपुर का आर्थिक विकास होगा और जोधपुर टूरिस्ट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा स्थान है। खूब देशी और विदेशी आते हैं और अब फ्लाइट्स

(श्री कैलाश भंसाली)
भी खूब होने लग गयी हैं और इसका सीधा लाभ जोधपुर की आम जनता को होगा।

इतनी घोषणाएं इस बजट में की गयी हैं। सभी एक से बढ़कर एक हैं और जिन चीजों की जरूरत है, उन सभी को लिया गया है। विशेषकर, किसानों को जो राहत दी गयी है, सीमांत और लघु को 50 हजार रुपये की माफी, यह कोई कम नहीं है। दो लाख बिजली कनेक्शन देने की बात की गयी है, बहुत ही अच्छी बात हुई है। हमारी भामाशाह योजना से लोग लाभान्वित हुए हैं। 1 लाख 50 हजार को सरकारी व 13 लाख को स्वरोजगार दिया जाएगा। जयपुर, कोटा व उदयपुर में सहकारी बैंकों के 9.47 लाख कार्ड हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', 'राजश्री योजना' में 7.92 लाख बेटियों को 198 करोड़ का लाभ दिया गया है, 5 लाख बालिकाओं को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह बालिकाओं के लिए आजकल बहुत जरूरी है, उनका शोषण बहुत हो रहा है। आज की भी घटना है, टीवी में चल रही है। वह रोकना जरूरी है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सड़कों का जो जाल बिछ गया है, हमारे जोधपुर से बाड़मेर, जोधपुर से नागौर, जोधपुर से फलौदी और इतनी सड़कें बन गयी हैं कि जाने वाले सब आराम से काण्डला और सांचौर पहुंच जाते हैं। यह बहुत ही शानदार बात हुई है और प्रत्येक विधायक को 15 किलोमीटर की सड़क देने की जो घोषणा की है, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई तोहफा विधायकों को नहीं मिल सकता था। आरटीओ पेपरलैस हो जाएगा, फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स बनेंगी।

मैं खास बात कर रहा हूं कि जोधपुर नगर-निगम बहुत खस्ता हालत में है। जेडीए भी खस्ता हालत में है। हैरिटेज लुक देने के लिए राजस्थान सरकार ने जिस तरह से जयपुर को 100 करोड़ रुपये दिये हैं, जोधपुर के लिए 50 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये जेडीए को भी दिए जाएं, ताकि हैरिटेज लुक आ सके और जोधपुर एक टूरिस्ट हब बन सके, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे जोधपुर की बहुत सारी चीजें बाकी हैं। विशेषकर, पीडब्ल्यूडी सड़कें तो बन गयी हैं, परंतु नगर-निगम और जेडीए के पास बजट नहीं होने के कारण सड़कें नहीं बन पा रही हैं। जगह-जगह खड्डे हैं, सीवर लाइन का

(श्री कैलाश भंसाली)

काम अधूरा पडा है। सड़कें खोद दी गयी, वापस नहीं बनाई गयी, विशेषकर मधुबन में, झालामण्ड में और शहर के रखेरा बाजार से लेकर माणक चौक तक सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा है, वह तुरंत प्रभाव से पूरा हो।

मण्डी शुल्क, जब जीएसटी लगा दिया, फिर मण्डी शुल्क को समाप्त करना चाहिए, ऐसा मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है। मण्डी शुल्क समाप्त करें। जीएसटी ले लिया, उसके बाद 'एक टैक्स, एक नेशन' वाली बात को हम तवज्जोह दें।

वृद्धजनों के लिए रोडवेज में फ्री ट्रेवलिंग और उसके सहायक को 50 प्रतिशत की छूट दी है तो यह भी बुजुर्गों का सम्मान किया गया है।

जयपुर में 72 करोड़ की इलेक्ट्रिक बसें लगायी गयी हैं ताकि प्रदूषण नहीं हो तो मैं जोधपुर के लिए मांग करता हूं कि वहां पर भी 30 ऐसी इलेक्ट्रिक बसें प्रारम्भ की जाए।

कमजोर आय वर्ग को स्टाम्प ड्यूटी में राहत दी गयी है। एक हजार अन्नपूर्णा भण्डार उचित मूल्य पर जो नाश्ता और भोजन की व्यवस्था हो रही है, सराहनीय है।

शिक्षा के क्षेत्र में 2872 विद्यालय क्रमोन्नत होंगे। मेरा निवदन है कि पदम चन्द बिलम कंवर विद्यालय में वाणिज्य और बॉटनी विषय को जोड़ा जाए। उस पूरे एरिया में सिर्फ एक विद्यालय है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ाता है तो यह काम जरूरी है। पूरे एरिया में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है जहां ये सब विषय हो। इसलिए उस विद्यालय को क्रमोन्नत में रखा जाए। झालामण्ड एरिया में जो 10वीं तक का विद्यालय है उसको 12वीं तक सभी सब्जैक्ट, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में क्रमोन्नत किया जाए।

आज सुबह ही मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मिला था और मैंने कहा था कि के.के. कॉलोनी में जो पीएचसी है उससे 40 से 50 हजार लोग लाभान्वित हैं। वहां से उसको स्थानांतरित करने के लिए सीएमएचओ अड़ गये हैं तो वहां की महिलाओं ने धरना दिया तो अभी तो उसको स्थगित किया गया है। मेरा निवेदन है कि बासनी गांव बहुत छोटी आबादी का है,

(श्री कैलाश भंसाली)
40-50 हजार की जनता का ध्यान रखते हुए इस पीएचसी को रखा ही जाना चाहिए।

हमारी सड़क और नालियों के लिए 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक भी था क्योंकि जगह-जगह नालियां खुदी पड़ी हैं, बरसात का पानी आता है जिससे सड़कें अवरूद्ध हो जाती है तो यह जरूरी है इसलिए इसको तुरन्त प्रभाव से किया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जब मैं बोलने लगा तो आपने 15 मिनट का कहा है और 15 मिनट अभी हुए नहीं हैं। मैं घड़ी देख रहा हूं। आपके यहां उपखण्ड में भी कुड़ी भक्तासनी में तहसील बनायी गयी है उसके लिए आपको बधाई। भैरोंसिंह जी की आत्मा को अन्त्योदय का जो स्वरोजगार का दिया है उसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई। इसी तरह से सुन्दर सिंह जी भण्डारी को स्मरण किया गया और अन्य पिछड़े आय वर्ग के लोगों के लिए जो सुविधा दी गयी है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि जोधपुर में बड़ी भीड़भाड़ है कि आखरिया चौराहे से लेकर पावटा तक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाए। मुझे विश्वास था और हमारी कोर कमेटी ने भी जब मुख्य मंत्रीजी के साथ जोधपुर में बैठक हुई थी तब भी कहा था कि यह बड़ा आवश्यक है क्योंकि इतनी भीड़ हो गयी है कि लोगों का चलना मुश्किल होता है और आम आदमी को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है तो एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाया जाए। यह मेरी मांग है।

एम्बुलेंस के लिए एक करोड़ रुपये दिये गये हैं उसके लिए धन्यवाद। नन्दी गौशाला योजना बहुत ही स्वागत योग्य है। जोधपुर में हमारे यहां गौशाला है उसको सामाजिक संस्था हरे कृष्णा वाले देख रहे हैं। उससे बहुत लाभ हुआ है। वैसी नन्दी गौशालाएं जोधपुर में करीब 50 हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसलिए सरकार द्वारा पूरा ध्यान देकर उनको मंजूरी के साथ में पैसा दिया जाए ताकि चारे की व्यवस्था हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): गाय और गौ संरक्षण का कार्य बहुत आवश्यक है। जोधपुर की अनेकानेक समस्याएं हैं जिनमें सबसे बड़ी जैसे मैंने अभी पूर्व में कहा कि झालामण्ड एरिया में सीवर लाइन बन गयी है, खड्ड़े खोद दिये गये हैं पर सड़क नहीं बनी है इसलिए सड़क बनाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सीवर लाइन तो बन गयी परन्तु खड्ड़े इतने हैं कि लोग चल नहीं सकते और बारिश में तो हाल बहुत ही बुरा हो जाता है।

इसी तरह से जोधपुर के मण्डोर उद्यान को पीपीपी मोड पर लोग लेने को तैयार हैं। उसका इतना अच्छा खाका सम्भागीय आयुक्त ने बनाया था और उसको तैयार किया था कि उसमें ट्रेन भी चले, 4 करोड़ रुपये में ट्रेन लगती है, अहमदाबाद के कांकरिया में चल रही है वैसा ही मण्डोर उद्यान को किया जाए। यह काम जेडीए को दे दिया जाए ताकि वो इसका विकास करे।

जोधपुर की इन समस्याओं के साथ में मैं एक बार पुन: मुख्य मंत्रीजी का शानदार और जानदार बजट पेश करने के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद कैलाश जी। माननीय सदस्य श्री जयराम जी जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति जी, लास्ट में जो बजट भाषण पर अपना भाषण प्रस्तुत करता है उसको धन्यवाद देने के लिए जो अन्त में व्यक्ति बच जाते हैं वो बहुत जल्दी मेज बजाने लग जाते हैं और ओपनिंग वालों को फुल छूट होती है।

माननीय सभापति जी, 12 फरवरी को इस पवित्र सदन में राजस्थान प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट भाषण लगभग दो घंटे 20 मिनट में बोलकर प्रस्तुत किया। यह राजस्थान का वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक का ब्यौरा है। इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के भू-भाग में सड़क, पानी, बिजली और विकास के साथ-साथ रोजगार के नये आयाम हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को कि जो बजट पुस्तिका है, पेज 1 से 78 तक और पैरा 1 से 269 तक, इस बजट पुस्तिका में ऐसा कोई बिन्दु नहीं होगा जिसमें राजस्थान के विकास के लिए कोई काम छोड़ा हो। सर्वजन हिताय, सर्वजन

(श्री जयराम जाटव)

सुखाय की भावना से ठोस नीतियों के कार्यक्रम तैयार कर अमल किया जाए इस तरह का बजट प्रस्तुत किया। हम यहां कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे दायीं ओर कांग्रेस के माननीय सदस्य असत्य बोलने के लिए अपनी एक अच्छी भूमिका तैयार करके आते हैं। एक ही माननीय सदस्य हैं और वो भी बानसूर से आने वाली हमारे पड़ौस की बहन आयी हैं, बाकी सब छोड़ गये। बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या बार-बार सोचती रहती हैं कि मैं प्रदेश की मुख्य मंत्री को किन शब्दों में धन्यवाद दूं पर ये इसलिए सोच जाती हैं कि धन्यवाद देने के साथ-साथ मुझे जवाब क्या देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश को वर्ष 2008-09 के बीच में जब कांग्रेस के हाथ में छोड़कर गये थे तब मुझे याद है कि 14 अप्रैल, 2007 को राजस्थान के इस बजट में डाक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ के लिए 7 करोड़ का बजट दिया था और उस 7 करोड़ के बजट से जयपुर के पास रामगढ़ में लगभग 75-80 बीघा जमीन में डाक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ का निर्माण हुआ, भवन तैयार हुआ।.....

02 अक्टूबर, 2008 को उसका माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा लोकार्पण हुआ और मैं बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के नाम से केवल डाक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर, आरक्षण की बात कहकर वोट लेना जानते हैं। पांच साल तक कांग्रेस की सरकार ने उस डाक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ में कोई निदेशक नहीं बैठाया, कोई विकास कार्य नहीं हुआ और उसका नाम बदलकर डाक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब काम हो रहा है पीजी के लिए कि पीजी यूनिवर्सिटी के रूप में काम करेंगे। मुझे इस बात की तकलीफ है कि डाक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ का मकसद क्या है? उनके द्वारा बचपन से लगाकर जब तक उन्होंने संविधान का निर्माण किया और जहां वह बाहर भ्रमण करने गये तो उस विद्यापीठ में इस तरह के शोध संस्थाएं वहां होंगी और उसका नाम बदलकर उसको छोड़ दिया। तीन साल में गलत नाम से एक वी.सी. बैठाकर और आज उसके बाद में जब हमारी सरकार आयी। पिछले वर्ष माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 50 लाख रुपया देकर वहां निदेशक के रूप में एक कर्मचारी का चयन किया और वहां लाइब्रेरी में अनुसूचित जाति,

(श्री जयराम जाटव)

जनजाति के छात्र पीजी कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं। वहां जाकर उस लाइब्रेरी में वह पढ़ते हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को कि पहली बार डाक्टर अम्बेडकर का नाम नगरपालिकाओं में, छात्रावास भवन के लिए, डाक्टर अम्बेडकर भवन बने, यह घोषणा की है। मैं केवल इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूं, हम जब चुनाव पीरियड में एससी और एसटी के गांवों में जाते थे तो लोग कहते थे कि कांग्रेस के लोग आये थे और वह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह आपका अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है, इसको समाप्त करने के कगार पर है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जब लगातार केन्द्र में मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, लगातार 10 साल तक केन्द्र में सरकार रही, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो पदोन्नति में आरक्षण का ढिंढोरा पीटते हो, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, क्यों नहीं आप लोगों ने लोक सभा में बिल पास किया और उसको पदोन्नति में आरक्षण के लिए देते। आज मैं निश्चित रूप से यह आरोप आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर लगा रहा हूं। इन लोगों ने आरक्षण के नाम से अनुसूचित जाति, जनजाति का वोट लिया, वह अनुसूचित जाति, जनजाति का वोट अब नहीं मिल सकता। चूंकि 1952 का पहला चुनाव जब लोक सभा का हुआ था, डाक्टर अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ, उस प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के जो प्रथम प्रधान मंत्री थे जवाहर लाल नेहरूजी, उनके ही कर्मचारी को चुनाव लड़ाया गया और वहां चुनाव हराया गया। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति विरोधी पार्टी कांग्रेस है।

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जो पंचायतों में आरक्षण दिया, महिलाओं को दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति को दिया तो वह भी माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी की देन थी, जो राजस्थान में आरक्षण दिया गया। मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को, जब पिछली बार पंचायतों का परिसीमन हुआ, हमारी सरकार बनी तो पंचायतों का परिसीमन हुआ, उसमें योग्यता रखी कि अनुसूचित जाति, जनजाति चाहे महिला, कोई भी सरपंच बनेगा तो आठवीं, मिडल पास से कम नहीं होगा। पंचायत समिति का प्रधान 10वीं का होगा। जिला प्रमुख 10वीं का होगा। मैं

(श्री जयराम जाटव)
धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं, आज भी अनुसूचित जाति की युवा बहिनें, जो पंचायत समिति में प्रधान या जिला प्रमुख बनीं, चाहे कोई भाई बना और वह पढ़े-लिखे लोग आज राजस्थान में उन ग्राम पंचायतों में सरपंच और प्रधान बने हैं। लगातार 10 साल और 15 साल तक कांग्रेस के लोगों ने पंचायत परिसीमन को लटका कर रखा। बड़ी-बड़ी पंचायतों का जब परिसीमन हुआ तो एक पंचायत से तीन-तीन ग्राम पंचायतें बनीं। उसमें एसएफसी, टीएफसी का बजट आया और उस बजट से विकास हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद इसलिए भी नहीं देना चाहता हूं कि हम झूठी वाहवाही कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं। गांव में तब जूतियां घिस जाती थीं जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, हमको आठवीं का स्कूल चाहिए, हमको गांव में सड़कें चाहिए। भला हो इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का जिन्होंने गांव में पीएमजीएसवाई, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़कों का निर्माण करवाया। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने ग्राम पंचायतों में जाकर ग्रामीण गौरव पथ बनवाये। आपने बहिनजी, मालाखेड़ा को देखा। मालाखेड़ा में बहिन कोई पैदल जाती थी, वह कपड़े ऊंचे करके जाती थी। कभी हमने मालाखेड़ा की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे क्षेत्र में एक मालाखेड़ा तहसील है, वहां कभी हमने सूखा नहीं देखा। किसी भी ग्राम पंचायत में कभी हमने सूखा नहीं देखा। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया और नाली सहित करवाया।

मैं शिक्षा की बात कहना चाहता हूं। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं। यह सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है। राजस्थान में यह तोहफा दिया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति के उन छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति की बहिनों के लिए गांवों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल करायी। 70 साल की आजादी के बाद में, मैं पहले की बात कर रहा हूं। बीच में एक ऐसा टाइम आया था कोई अपनी बेटी का रिश्ता करने जाता था तो पूछते थे कि लड़की कितनी पढ़ी है? 12वीं है या ग्रेजुएट है, तो ही रिश्ता लेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को कि हर ग्राम पंचायत में सीनियर

(श्री जयराम जाटव)

सैकण्डरी स्कूल दिया। हमारे चौथा गोत्र बचता था, वह शिक्षा का बचता था। जो वर्ग सैकड़ों-हजारों साल तक शोषित रहा, पीड़ित रहा, उस समाज को शिक्षा की दृष्टि में शिक्षा के द्वार अगर खोले तो प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा जी ने खोले हैं।

मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं भामाशाह कार्ड के माध्यम से। भामाशाह कार्ड क्या है? माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं। मैं इनका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं कि भामाशाह कार्ड का एक बहुत बड़ा विजन प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने गरीब के इलाज के लिए दिया है। उसमें 1,000 कुछ बीमारियों को रखा है। लगभग 1,000 कुछ राजस्थान के प्राइवेट अस्पतालों को जिम्मेदारी दी। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए व्यक्ति जाता है, भामाशाह कार्ड लेकर जाता है तो वह कहता है कि आपका खाद्य सुरक्षा में जुडा हुआ नाम नहीं है या इसका मिलान नहीं खा रहा है या आपकी इसमें कोई न कोई कमी है, इसमें चैकिंग जरूर आप करायें। मंत्रीजी शायद यहां नहीं हैं।

श्री सभापति: मंत्रीजी विराजे हैं।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): बैठे हैं। ये जरूर आप चैक करा लें कि सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पताल जो आपने लिये हैं, उनमें वह जरूर कोई न कोई ग्रामीणों के लिए भामाशाह कार्ड को देखते हुए खाद्य सुरक्षा के नाम से अडंगा लगा देते हैं। इसमें जरूर इसकी चैकिंग करा दें। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, हम अंत में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। किसानों के लिए लगान के लिए किसी ने सोचा क्या? क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? मैं भी किसान हूं। कभी लगान माफ किया तो प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार इस बजट में किया है। यह कांग्रेस के लोग किसान की बात करते हैं। ये फसल बीमा की बात करते हैं। जब पिछली बार हमारे यहां ओलावृष्टि हुई थी, इनके टाइम में तो केवल अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा हुआ तो उनको मुआवजा मिलता था। मैं देश के प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां से चिट्ठी गयी

(श्री जयराम जाटव)

जाकर यह उन्होंने तय कर दिया, पास किया कि आपका 30 परसेंट से ज्यादा अगर खराबा है तो आपको फसल बीमा में लाभ मिलेगा। किसानों के लगान माफ के साथ-साथ, 50,000 रुपये का कर्जा ग्राम सेवा सहकारी समिति से माफ हुआ या कहीं माफ हुआ, जब किसान आन्दोलन कर रहे थे और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, पश्चिमी राजस्थान के किसानों ने आंदोलन किया। किसानों का कर्जा माफ हुआ तो ये कह रहे हैं कि सारा कर्जा माफ कर दो। पांच साल तक ये लोग थे, राजस्थान में सरकार इनकी थी। इन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: धन्यवाद। यह विषय आ चुका है।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के स्वरोजगार, जिन भाइयों ने सन् 1980-81 के बाद में लोन लिया था उनको रोजगार के लिए, उसमें जो माफ किया है दो लाख रुपये तक। मैं भी जान रहा हूं, मैं भी लेट हो रहा हूं। मेरी तबीयत खराब है तो भी मैं रूका हूं माननीय मंत्रीजी। मैं धन्यवाद क्यों नहीं दूंगा। भर्तृहरिजी महाराज ने, यहां अभी इस बजट सत्र में हमारे लिये देवनारायण आवासीय विद्यालय की घोषणा की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं चार-पांच बात और कहूंगा। मैं अपनी डिमांड तो रखूंगा माननीय सभापति महोदय, ऐसे मत करो।

श्री सभापति: डिमांड पर आ जाएं सीधे ही आप।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): सीधे ही डिमांड पर आ रहा हूं। अन्नपूर्णा कलेवा रसोई, ये कह रहे हैं सब्सिडी को चैक करो...

कहीं ज्यादा मोटा घोटाला तो नहीं है, घोटालेबाज आप हो। कभी घोटोले के अलावा कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। हम गांव के लोग, यहां विधान सभा में बड़ा रौळा होता था कि ढाणियों को, गांव के लोगों की ढाणियां में, कब कनेक्शन होगा बिजली का। यह पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ज्योति

(श्री जयराम जाटव)

योजना से गांव की ढाणियों में कनेक्शन मिला, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री ज्योति योजना के माध्यम से कनेक्शन मिले। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और पानी बचाओ, पानी बचा नहीं........

श्री सभापति: आप डिमाण्ड पर आ जाय।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): पहली बार प्रदेश में मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के रूप में एनीकट्स, जोहड़, तालाब बनाये तो उस पानी का जो बहाव है, वह रुक करके समाधान हुआ, बिजली ये दे नहीं पाये, किसी को पढा नहीं पाये, गांव के लोगों को पांचवीं, आठवीं पास, बिना पढ़ाये पास कर दो, बहन शकुन्तला जी जरूर कुछ ध्यान दे रही है। मैं सच्ची बात का आदमी हूं सच्ची बात कहने से चूकता नहीं हूं....

श्री सभापति: अब डिमाण्ड पर आ जाए, समय नहीं....

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सच्ची बात कहें, हमारे माननीय सदस्य, अच्छी बात है, मेरे नजदीक के हैं, लेकिन कहीं कोई कनेक्शन दिया होता तो मैं भी धन्यवाद, ये कह रहे हैं ना धन्यवाद देने में संकोच, संकोच नहीं है, एक काम मेरे यहां का गिना दो, मैं धन्यवाद दे दूंगी। क्या दिया है बिना बात ही, दिया है, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): माननीय सदस्य को जानकारी दे दूं, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी दूं 71 करोड़ रुपया आपके एन.सी.आर. में, नारायणपुर वाला रोड दिया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज तक तो काम चालू नहीं हुआ है....

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): काम चालू होगा, आप जा ही नहीं रही हैं क्षेत्र में। वर्क आर्डर हो गया, काम चल रहा है...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये झूठी घोषणाओं का पुलिन्दा, जो बताया है शंकर जी ने, यह पुलिन्दा कब तक दोहराते रहोगे मंत्री महोदय? आज तक कहां दिया वर्क आर्डर, काम हो गया, हो गया काम, अभी तो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उतने के उतने दो-दो फुट के गहरे खड्ड़े हो रहे हैं, नारायणपुर रोड पर, बानसूर रोड पर पांच साल में एक सड़क तो बना दो।

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य। आप एक मिनट में पूरा करें अपना व्यक्तव्य।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति जी, मैं जरूर बोलूंगा, मैं जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य को, 31 दिसम्बर, 2008 तक के बिजली के कनेक्शन प्रदेश की मुख्य मंत्री जब थी, 2003 से 2008 तक, तब घोषणा कर गयी थी, कांग्रेस ने वो 2008 तक के कनेक्शन, आज तक नहीं दिये। अब 2 लाख किसानों को.....

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, एक भी दीनदयाल उपाध्याय के तहत कनेक्शन, आज तक नहीं हुआ, चार साल हो गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सदस्य, मेरे नाम से बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा ही ना।

श्री सभापति: आप विराजे प्लीज। आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): सभापति जी, मैं जानकारी दे रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं किसानों को 4 घन्टा बिजली, कांग्रेस के राज में आती थी, हमारे राज में आज 6 घन्टे....

श्री सभापति: मेरी अनुमति के बिना जो बोले अंकित नहीं हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में बोले नहीं, तो मैं नाम पुकार रहा हूं। मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं कांग्रेस के झूठे पुलिन्दे को जरूर खोलूंगा, कांग्रेस के राज में, इन लोगों ने न बिजली दी, हमने किसानों को ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद 72 घन्टे में ट्रांसफार्मर बदले, इनके राज में किसान का ट्रांसफार्मर फुंकता था, दो महीने में नहीं मिलता था और इनके जब तक सुविधा शुल्क कर्मचारी के जेब में नहीं जाता था, तब तक काम नहीं होता था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजे। समय से ऊपर हो गया, माननीय सदस्य श्री मनोज जी न्यागली।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मेरी ये डिमाण्ड रह गयी।

श्री सभापति: हां तो, डिमाण्ड पहले कह दें, फटाफट।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहादरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उप तहसीलें लगभग आजादी के कुछ दिनों के बाद में, वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें।

मालाखेड़ा हमारे विधान सभा क्षेत्र का बड़ा कस्बा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिछली बार सिविल न्यायाधीश कोर्ट वहां खुली। लेकिन वहां ए.सी.एम. कार्यालय हो या एस.डी.एम. कार्यालय हो, ये डिमाण्ड मेरी है,

तीसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में, जो विकास कार्य हुए मैं अगर उनको आंकड़ा के आधार पर गिनने लगूं तो दो घन्टे हमको लगेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्री को ये जो बजट है न, केवल इनको तो ऐसा लगा अलवर लोक सभा और अजमेर लोक सभा का चुनाव जीतने के बाद में कि आसमान के तारे हम तोड़कर लाये हैं। इनकी आंखे खुलेगी जब ये 2018 के चुनाव में, विधान सभा में जाएंगे, जब जनता के सामने जाएंगे। सभापति महोयद, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरी ज्यादा लम्बी चौड़ी नहीं, दो डिमाण्ड है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज जी न्यागली।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2018-19 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हम बजट के बारे में अगर कहें तो इस प्रदेश का बजट एक प्रतिबिम्ब है, इसके लिए हम यह नहीं कह सकते कि किसी भी सरकार के द्वारा प्रस्तुत कोई भी बजट प्रदेश के हित में नहीं है, प्रदेश के लिए अहित में है। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बजट में

(श्री मनोज कुमार)
जितनी घोषणाएं की जाए, उन पर अंतिम छोर तक कार्य कैसे किया जा सकता है, उसकी पालना कैसे की जाए, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कर्त्तव्य भी है कि इस प्रतिबिम्ब में, जो भी चीज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत की है, उसमें किस तरीके की कमियां और रह गयी, किस तरीके से इसमें और नया संशोधन किया जा सकता है, यह आईना दिखाने का काम प्रतिपक्ष के रूप में हमारा बनता है, इसलिए हम उस बात पर विचार करेंगे। धन्यवाद का काम आप करते हैं लेकिन हम आपको धरातल की बात बताना चाहेंगे, मूल रूप से जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दो-चार बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ए.डी.जे. कोर्ट दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

दूसरा कर्ज माफी का जो कदम माननीय मुख्य मंत्री ने उठाया, वह धन्यवाद का कार्य है। लेकिन 9 तारीख को मैंने अभिभाषण पर बोलकर बताया था कि सरकार कहीं न कहीं, उसमें बैरिकेड्स डालने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार से कहना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान आप पर आस लगाये बैठा था आपने उस समझौते में कहा था कि प्रत्येक किसान का हम 50 हजार रुपये का कर्जा माफ करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रदेश के प्रत्येक किसान का, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक से हो, चाहे प्राइवेट बैंक से हो, चाहे सहकारी बैंक से हो और ये जो लघु, सीमान्त की बाधा है, इसको हटाकर कर्जा माफ किया जाए। जिससे किसान खुशी के साथ, आपका धन्यवाद, जनता, जिस क्षेत्र में जाओगे, वहां करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हम किसान की बात हर समय करते हैं। आज ये विपक्ष में हैं ये चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि किसान के लिए आपके कुछ नहीं किया पर मुझे लगता है कि पिछले पांच साल में ये थे तो भी इन्होंने किसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं की। कोई बड़ा कर्जा माफी की बात करें तो इन्होंने भी नहीं किया।

(श्री मनोज कुमार)

मैं कहना चाहता हूं किसान की स्थायी आय के लिए हमारी सरकारों को विचार करने की जरूरत है कि किसान अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकता है, किसान की स्थाई आय कैसे बढ़ सकती है, उस पर विचार करें। कर्जा माफी किसान के लिए एक स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने नन्दी गोशाला की घोषणा की, बड़ा सराहनीय कार्य है। लेकिन इसको जिला हैड क्वार्टर पर करना, बड़े क्षेत्र का मामला है, अपने प्रत्युत्तर में तहसील मुख्यालय पर इसकी घोषणा हो। नन्दी गोशाला, जो बन रही है, जिनको आपने नाम दिया, जनता ने उनका नाम जो दे रखा है, मैं बताना चाहता हूं कैलाश जी आपको, जनता ने काला धन जो आप कह रहे हैं न वापिस लेकर आएंगे, जनता ने उसका नाम कालाधन दे रखा है। इसलिए उस काले धन को आप तहसील हैड क्वार्टर पर करेंगे तो जनता आपका और धन्यवाद करेगी।

इसी के साथ ही मैं कहना चाहता हूं किसान को बिजली मुफ्त, 90 पैसे प्रति यूनिट कोई ज्यादा राशि नहीं है, लेकिन अगर सरकार ये बड़ा कदम प्रत्युत्तर में उठा दें किसान को बिजली मुफ्त दी जाए तो किसान के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा।

इसी के साथ ही मैं एक कहना चाहूंगा सिंचाई के बारे में। .....

एक तो हमारी सिद्धमुख वितरिका, सुबह हमारी चर्चा हो गयी थी और माननीय मंत्री महोदय तो आंकड़ों के जाल में हमें घुमाते-घुमाते हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में ले गये। माननीय मंत्री महोदय, सुबह आपने जो जवाब दिया उस बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे पच्चीस किलोमीटर का दायरा है उस पच्चीस किलोमीटर के दायरे में आप पूरी चौकसी करा कर, चोरी रोक कर और खाले-नाले जो शेष बचे हुए हैं उनकी आप पूर्ति करके हमारे किसानों को लाभ देने का काम करें। कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना, तारानगर में दो वर्ष से किसान धरने पर बैठे हैं। आपकी सरकार का कोई भी नुमाइन्दा वहां आज तक वार्ता करने नहीं गया। कम से कम इतना बेशर्म मत बनो कि आप आखिर जनता के हित में वार्ता करने भी नहीं जाओ। हम किस तरीके से

(श्री मनोज कुमार)
आगे बढ़ेंगे। उन किसानों को उठा दो, उनसे वार्ता करके और मांग क्या है, सिंचित एरिया आपकी माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की हुई घोषणा को घटाने का काम भी आपने कर दिया। 138 लाख हैक्टेयर भूमि को कमाण्ड से अनकमाण्ड कर दिया। उसकी डिमाण्ड को लेकर बैठे है इसलिए आप आज सदन में तारानगर के किसानों पर कृपा करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात हो रही थी। मैं धरातल की सच्चाई कहना चाहूंगा। बिजली आप 6 घंटे किसी भी किसान को नहीं दे रहे हो, एक बात। दो नंबर, आप कह रहे हो कि हम दीनदयाल में करेंगे, एमएलए कोटे से 6-6 महीनों से पैसे दे दिये, लेकिन फिर भी मैटेरियल के अभाव में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। इससे ज्यादा और कोई गंभीर बात नहीं हो सकती कि लोगों के पैसे देने के बाद भी आप कनेक्शन नहीं कर पाओ और आप कहते हो कि हम बिजली में अपने आप में सक्षम हो गये, कहीं से खरीदनी नहीं पड़ेगी। फिर भी ये हालात हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। 2004 का एक सर्कूलर है बिजली विभाग का। जो शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जो कृषि भूमि पर कालोनी में बस गये, वहां भू माफिया उनको जमीन बेच कर चले गये, प्लाट की कीमत तो लाख रुपये है और वहां कनेक्शन लेने की कीमत भी पचास हजार रुपये से कम नहीं है। डेढ़ सौ रुपये पर वर्गमीटर उनसे वसूला जाता है डिमाण्ड राशि। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप प्रत्युत्तर में जब भी घोषणा करें तो इस सर्कुलर को खतम करके हमारे उन लोगों को जो बिजली लेना चाहते हैं उनको बिजली कनेक्शन दिया जाए। एक साधारण डिमाण्ड के माध्यम से दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एससी/एसटी के लोगों के लिए बहुत बड़ा, उनके आरक्षण को बचाने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी घोषणाओं के माध्यम से देख रहा हूं जिस तरीके से आप शिक्षा को पीपीपी मॉडल पर दे रहे हो। चिकित्सा को आप पीपीपी मॉडल पर दे रहे हो। ये प्राइवेटाइजेशन आपकी आरक्षण को खतम करने की एक नयी योजना है, क्योंकि वहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से नौकरी लगाएंगे। आरक्षण को बचाने के लिए जनता संघर्ष करेगी इसलिए ये पीपीपी मॉडल आपका दोनों का है,

(श्री मनोज कुमार)

चिकित्सा और शिक्षा का, आरक्षण से जो दलित एससी/एसटी के लोगों को वंचित करना चाहते हैं, आप बंद करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ ही मैं स्वास्थ्य पर चर्चा करना चाहूंगा। सरकार की हठधर्मिता रही। आप अच्छी तरह से जानते हैं माननीय चिकित्सा मंत्री भी बैठे हैं कि आपने सैंकड़ों लोगों को यहां मारने का काम डाक्टरों की हड़ताल के समय में आपकी हठधार्मिता के कारण किया। ऐसा दुबारा इस प्रदेश में कम से कम कलंकित कार्य नहीं हो और भामाशाह योजना की बात भी कहना चाहूंगा कि आपकी पारदर्शिता में अभी कमी है। इसमें ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा से जोड़ने वाला जो सिस्टम है इसकी माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, पूरी मानीटरिंग करें, जिससे जनता को इसका और ज्यादा लाभ मिल सकें। कहना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों को तो आपने इसमें शामिल कर लिया, लेकिन किडनी, कैन्सर, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां, जो खाद्य सुरक्षा में व्यक्ति नहीं है वो भी सक्षम नहीं है इसका पैसा वहन करने के लिए। ऐसी बीमारियों को आप बिना खाद्य सुरक्षा योजना के भी इस भामाशाह योजना में शामिल करें, जिससे उनको लाभ मिल सके। मेडिकल कालेज, हमारे प्रदेश में सात मेडिकल कालेज की आपकी घोषणा हुई लेकिन दो साल आपने निकाल दिये। हमारे प्रदेश के उन नौजवानों को मेडिकल कालेज में एडमिशन से वंचित रखा। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्ष में कम से कम प्रदेश को उसका लाभ मिल जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए, इसकी मानिटरिंग माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, करके जनता को लाभ देने काम करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं परिवहन विभाग के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। लोक परिवहन सेवा जनता के लिए घातक हो गयी। लोक परिवहन सेवा वालों की तानाशाही हो गयी। जगह-जगह झगड़े हो रहे हैं। जगह-जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सवारियों के लिए एकदम गति से बढ़ते हैं। ओवरलोड वाहनों को रोकने का प्रयास करें। एक निवेदन था कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अस्सी साल की उम्र के व्यक्तियों को आपने नि:शुल्क यात्रा के लिए घोषणा की है। मैं इसमें एक छोटी सी

(श्री मनोज कुमार)

बात कहना चाहूंगा, मुझे बजट में तो वह बात नहीं मिली, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस पूरे देश में कहीं भी जाएं वहां पूरी जगह उनको फ्री होना चाहिए। कहीं यह बेरिकेड्स न आ जाए कि सिर्फ राजस्थान में यात्रा के दौरान ही हम फ्री करेंगे। उनको पूरे देश में जहां-जहां भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस जा रही है उनको वहां फ्री किया जाए। इसी के साथ ही दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनकी सीट भी रिजर्व की जाए। इनकी दो-चार सीट रिजर्व इसलिए की जाए कि अस्सी साल का व्यक्ति यात्रा करने आये, रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं हो और बैठने को सीट न मिले तो फिर वह व्यक्ति बहुत परेशानी में रहेगा। इनके लिए इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही बेरोजगारी बहुत ही गंभीर इश्यु है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में यह कहा था संविदा कर्मचारी जितने भी हैं उन सबको हम स्थायी करेंगे। एक भी कर्मचारी को आपने जनता जल योजना कर्मी प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, कृषि मित्र, पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश कर्मचारी, एनआरएचएम कर्मी, नरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपरेटर, शिक्षक, इनमें जितने भी थे, नियमित नहीं किया। इसलिए सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन बेरोजगारों को आप नियमित करने का काम करें। जनता के युवक जो बेरोजगार हो जाएंगे इनको आप नियमित करें। रोजगार देने की बात आपने कही कि एक लाख आठ हजार लोगों को अभी नौकरी देंगे और दिसम्बर का आपने नाम लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस भर्ती की बड़ी पारदर्शिता से विज्ञप्ति निकालना, नहीं तो आप दिसम्बर तक इन एक लाख आठ हजार लोगों को नौकरी नहीं दे पाओगे, यह मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी आदमी को। अगर कहीं न कहीं विज्ञप्तियों में पारदर्शिता और सही तरीके से आपने आकलन नहीं किया तो दिसम्बर तक एक भी आदमी को नौकरी नहीं लगा पाएंगे। इसमें आपने एक घोषणा और कर दी कि आगामी वर्ष में 75 हजार लोगों को हम नौकरी देंगे। आगामी वर्ष कहां है? जब तक तो सरकार दुबारा आएगी? कौन करेगा, कब करेगा, कम से कम इसमें तो ऐसी बात न लिखें। आगामी वर्ष में 75 हजार लोगों को हम और नौकरी देंगे।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात कहना चाहूंगा। 15 किलोमीटर सड़क, अबकी बार आखिरी वर्ष है। हमारे लोगों पर दया कर देना कि कम से कम आपकी चिट्ठी हमारे पास जाए कि आप अपनी 15 किलोमीटर सड़क जो मिसिंग लिंक है उसकी अभिशंसा करो, जिससे हमारी अभिशंसा पर बन जाए तो हमारे क्षेत्र में हम भी यह कहेंगें कि आपने भेदभाव नहीं किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-709 ए पिलानी से राजगढ़ रोड़ का है, जो 2011 से आज पैंडिंग पड़ा है, बहुत जर्जर हालत है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि सरकार जो भी प्रयास कर सकती है, उसके लिए करे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ कृषि विभाग पशुपालन विभाग की बात करूंगा। पशुपालन विभाग में ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण एवं विपणन केन्द्र जयपुर रखने की बात की है। मरु प्रदेश हमारे चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वहां कहीं न कहीं आप ऐसी जगह करो जहां ज्यादा ऊंट पालने का स्थान है। वहां से लोग उसका लाभ ले सकें, तो आपका मिनी प्लांट जो भी लगे, मैं तो यह कहता हूं कि मेरे चूरू जिले में लगे, जिससे हमारे वहां की जनता को लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहूंगा कि 1996 में एक भर्ती निकाली पशुपालन विभाग ने, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक नाम दिया सईस, सईस कर्मचारियों को 1996 में लगाया और आज तक उन सईस कर्मचारियों को आपने नियमित नहीं किया। एक साल के लिए कहा था कि एक साल में हम नियमित करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। किसी की डैथ अगर हो गयी तो अनुकम्पात्मक नियुक्ति में उनके बच्चे रेगुलर लगे हुए हैं, लेकिन जो मूल रूप से नौकरी कर रहे हैं उनको आज तक नियमित नहीं किया, इसलिए उनको नियमित करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती का मामला था। माननीय चिकित्सा मंत्री की अध्यक्षता में माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वास्थ्य विभाग और श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था कि आपकी भर्ती हम एक महीने में पूरी कर देंगे और उसकी विज्ञप्ति पांच महीने हो गये, आज तक

(श्री मनोज कुमार)
जारी नहीं हुई। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, आपका आश्वासन है। आपकी कमेटी के द्वारा घोषणा की गयी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती आपने नहीं निकाली इसलिए इसको निकालने का काम करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं दो मिनट और लूंगा। इसी के साथ पीपीपी मॉडल की बात मैने बतायी। शिक्षा से संबंधित कहना चाहूंगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा इसी बजट में करें और राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, क्योंकि व्याख्याताओं के बिना उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। आईटीआई की आपने घोषणा की, राजकीय आईटीआई मेरे उपखंड कार्यालय में नहीं है इसलिए आईटीआई विद्यालय खोला जाए।

(21.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर विषय और हमारे सामने हैं, आरपीएससी में प्री परीक्षा में आब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो गणित था लेकिन अब मुख्य परीक्षा में भी गणित को जोड़ दिया। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वह आरपीएससी के मुख्य एग्जाम में गणित से पीछे रहते हैं और जो गणित के स्टूडेंट हैं, वह उनको इफैक्ट करते हैं। इसलिए पहले जो सिस्टम था, जिसमें गणित नहीं था, सब्जेक्ट के ही एग्जाम होते थे, मुख्य परीक्षा में सिर्फ सब्जेक्ट के एग्जाम हो और इस गणित विषय को उससे हटाया जाए। इसके लिये अभी एक कमेटी भी गठित कर दी गयी है लेकिन जल्द से जल्द निर्णय करके इन लोगों को लाभ देने का काम करें।

इसी के साथ मैं खाद्य सुरक्षा के विषय के बारे में एक बात जरूर कहूंगा। खाद्य सुरक्षा में पात्रता के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी बजट में घोषणा की है कि कुछ लोगों को हम पात्रता में शामिल कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपका 69 प्रतिशत का बैरिकेड इसमें लगा हुआ है। ज्यों ही पात्रता बढ़ती है, आपकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनको इकाई मानो जो इसमें पात्र हो गये हैं, उन्हीं को शामिल करने का काम करे।

(श्री मनोज कुमार)

उज्ज्वला योजना की आपने खूब प्रशंसा की है। मैं कहना चाहूंगा जो आपकी उज्ज्वला योजना है, उसमें आपने कहा कि हमने फ्री में दिया। लेकिन आप दूसरी तरफ जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो कि सब्सिडी में से पैसे काट रहे हो। उनके पैसे आप सब्सिडी से काटकर पूर्ति कर रहे हो और आपने सलेण्डर की कीमत कम से कम 100 रुपये उज्ज्वला योजना के बाद बढ़ा दिये। आप कह रहे हो ना कि सलेण्डर देकर हमने उज्ज्वला योजना में लाभ दिया है, आप उसकी सब्सिडी काट रहे हो, उस व्यक्ति को भुगतान करना मुश्किल हो गया। इसलिए आप इस सब्सिडी को ना काटकर उन गरीब लोगों को लाभ देने का काम करें।

श्री सभापति: बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक बात और कह दूं। मैं कर के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा एक राष्ट्र, एक कर। इस प्रदेश में चीनी पर 5 परसेंट और देसी घी पर 12 परसेंट टैक्स है जो जीएसटी में शामिल है और उसके बाद भी 1.60 पैसे आज भी मंडी टैक्स लग रहा है। एक राष्ट्र, एक कर के तहत जहां जीएसटी लग गया उसका दुबारा मंडी टैक्स नहीं लगना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसका बड़ा इफैक्ट यह है, हमारे प्रदेश में हरियाणा सीमा जहां से लगती है, लोग हरियाणा के बिल से वहां माल खरीद रहे हैं, जिससे सरकार को करोडों रुपये का नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मुख्य मंत्री महोदय जब भी अपना उत्तर दें, मंडी टैक्स हटाया जाए और एक कर, एक राष्ट्र की बात को रखते हुए देसी घी और चीनी से मंडी टैक्स हटाया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री जगदीश नारायण जी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह लास्ट हैं क्या साहब?

श्री सभापति: मंत्री महोदय, यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे

(श्री जगदीश नारायण)
2018-19 के बजट पर बोलने के लिये परमिशन दी, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, 2018-19 का पवित्र दस्तावेज बजट हमारी माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने सदन में पेश किया है, मैं ह्रदय की गहराइयों से इसका सम्मान करता हूं। इसके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान को विकसित पायदान तक ले जाने का एक सपना देखा है और वह सपना साकार होगा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इस पवित्र दस्तावेज का जब गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, उद्योग, खाद्य, सड़क, परिवहन, रोजगार, पेयजल, सिंचाई आदि क्षेत्रों में बहुत बड़े-बड़े प्लान बनाकर इस प्रदेश को आगे ले जाने का एक प्लान बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, किसी प्रदेश की गरीबी तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक इस तरह का कोई ठोस प्लान नहीं बनाया जाए और प्लान बनाकर उस पर काम किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा सीधा आसन को संबोधित करुंगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करके मेरी बात नहीं रखूंगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरी बात से या मेरे शब्दों से कोई पीड़ा पहुंचे तो कृपया वह पीड़ा के कारणों को ढूंढने की कोशिश करें, वह बीच में शोर शराबा करने की कोशिश न करें। क्योंकि मैं अनुशासन में भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं। मैं न किसी के बीच में शोर शराबा करता हूं और न मेरे वक्तव्य के बीच में किसी का शोर शराबा बर्दाश्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस का नारा रहा है गरीबी मिटाओ। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गरीबी मिटाओ का नारा तो दिया लेकिन नारा देने के बाद उस गरीब को और ज्यादा गरीब करने का काम किया। नारा गरीबी मिटाने का था और काम उलटा उस गरीब को ज्यादा गरीब बनाने का था। माननीय सभापति महोदय, जो गरीब वर्ग था, गरीब तबका था उस गरीब वर्ग को भी भ्रष्टाचार से नहीं बख्शा गया। गरीब वर्ग की जो योजनाएं बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान सरकार से आती थीं, उनमें भी अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम यहां से 100 रुपया भेजते हैं लेकिन वहां तक जाते जाते वह 15 रुपये तक सिमट

(श्री जगदीश नारायण)

जाता है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है उस पार्टी के लिये जिस पार्टी ने वर्षों तक राज किया है और वर्षों तक राज करने के बाद उस गरीब को और गरीब बनाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी इस सोच को कि उन्होंने जमीनी सच्चाई को परखा, जमीनी सच्चाई को ढूंढा और पता लगाया कि आखिर गरीब, गरीब क्यों बनता जा रहा है। उस गरीब की गरीबी को रोकने के लिये, उस गरीब से गरीबी भागे, इसके लिये उन्होंने योजना बनायी और योजना का नाम दिया भामाशाह योजना। माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना बनायी उस वक्त भी कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द चला और आज वह योजना धरातल पर उतर कर आ गयी, लोग जुड़ चुके, लोग लाभ ले रहे हैं, उसके बावजूद आज भी वह योजना उन लोगों को पच नहीं पायी। अभी उप चुनावों में भी अपने प्रचार प्रसार के दौरान उस योजना के बारे में इस तरह से कडी टिप्पणी की कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो इस भामाशाह योजना के टुकड़े-टुकड़े करके डाल देंगे। यह इस प्रदेश के लिये बड़ी शर्म की बात है, कि गरीब के लिये कोई योजना बनती है और उस योजना के टुकड़े-टुकड़े करने के लिये वह लोग तैयार हैं, वह क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। सभापति महोदय, जितनी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का जो पैसा गरीब लाभार्थी तक जाता था, उसमें से बहुत सारा पैसा बीच के लोगों के हाथों में रह जाता था और उससे उलटा हुआ है, जिस योजना का जो पैसा है, वह सरकार से लेकर गरीब तक पहुंचता है। बीच में कोई मांई का लाल उसमें से एक पैसा भी खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, वह सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। इससे बढ़िया राजस्थान प्रदेश की गरीब जनता के लिये क्या हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हम जब फील्ड़ में जाते हैं और बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, तो बड़े बुजुर्गों का जवाब मिलता है कि हमने जीवन में पहली बार ऐसी योजना देखी है, राजस्थान में ऐसी मुख्य मंत्री हमने पहली बार देखी है जिसने गरीब की चिंता की है और गरीब के पैसों को हमारे अकाउंट तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदय, यह है

(श्री जगदीश नारायण)
गरीबी दूर करने का काम, यह है गरीबी हटाने का एक रास्ता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि गरीब के स्वास्थ्य की कांग्रेस के लोगों ने आज तक चिंता नहीं की। नि:शुल्क दवा वितरण योजना बनाकर अपने आपको इतना जबरदस्त प्रदर्शित करने की कोशिश की जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा योजना कांग्रेस ने चलायी, हम उनको धन्यवाद देते हैं लेकिन उस नि:शुल्क दवा योजना के बाद हमारी सरकार ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीस हजार से लेकर तीन लाख रुपये तक उस गरीब के घर में मुफ्त इलाज पहुंचे जिस गरीब को वहां कोई पैसा देने वाला नहीं है।

जिस गरीब के पैसों के अभाव में प्राण चले जाते हैं, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, उस गरीब को सहारा देने का काम किया है। यह उस गरीब के घर से गरीबी भगाने का एक रास्ता है। यह उस गरीब को मजूबत बनाने का एक कदम है इसलिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वाकई उन्होंने गरीब की चिंता की है और गरीब के घर से गरीबी भगाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, संकट काल में और संकट वह संकट, जिस परिवार का कोई कमाऊ मुख्य व्यक्ति कहीं काम धंधा करते काल का ग्रास बन जाए तो उसके बाल बच्चे और परिवार हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते हैं। वह परिवार बर्बाद हो जाता है और वह इतना पिछड़ जाता है कि विकास की धारा में जुड़ ही नहीं पाता। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकारों और कांग्रेस के व्यक्तियों ने आज तक इस बात के लिये कतई चिंता नहीं की। कतई उनके दिमाग में यह सोच पैदा नहीं हुई कि ऐसी स्थिति में, ऐसे संकट काल में उस परिवार को कैसे बचाया जाए? मैं माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और सरकार को कि उन्होंने श्रमिक कार्ड योजना बनाकर श्रम विभाग के द्वारा ऐसे परिवारों को पांच लाख से लेकर नौ लाख रुपये तक संकट काल की स्थिति में उस परिवार को मदद देने का काम किया है। जो आज भी जनता की जुबां है। आज भी जनता उसको सराह रही है और आज भी जनता दुआएं दे रही हैं

(श्री जगदीश नारायण)
और ये दुआओं का ही परिणाम है, जो 163 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक यहां पर आकर बैठे हैं और यह भी बददुआओं का एक परिणाम है कि सत्ता पर साठ वर्षों तक रहने वाली पार्टी 23-24 की संख्या में सिमटकर-सिकुड़कर यहां पर बैठी है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में लिंगानुपात में भारी अंतर आया। बच्चियों का संरक्षण कम हुआ। बच्चियों से लोग नफरत करने लग गये। उस लिंगानुपात के अंतर को देखते-देखते ऐसी स्थिति बन गयी कि बहुत से अच्छे-अच्छे परिवारों के लड़के कुंवारे रहने लग गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस चीज को गंभीरता से लिया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसकी जमीनी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की और जानकर माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 'राजश्री योजना' बनायी, 'राजश्री योजना' के तहत आज बेटी के जन्म से लेकर सीनियर क्लास पास करने तक 50 हजार रुपये उस बेटी के खाते में सरकार के माध्यम से पहुंचाये जा रहे हैं। यह लिंगानुपात कम करने का एक ठोस कदम है। इसके माध्यम से लिंगानुपात कम हो सकता है। इसके माध्यम से बेटी का संरक्षण हो सकता है। इस माध्यम से बेटी को बचाया जा सकता है। मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? बेटी को बचाने के लिये कौनसा कदम उठाया? लिंगानुपात को कम करने के लिये आपने क्या कदम उठाये? जरा बतायें तो सही।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस बिंदु की चर्चा कर रहा हूं, जिसके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी राहत जनता को देने का काम किया है और वह है खाद्य सुरक्षा के तहत राशन सामग्री। खाद्य सुरक्षा के तहत मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वास्तव में गरीब का हक गरीब तक पहुंचे, गरीब का हक गरीब की झोली में पहुंचे, उसके घर में पहुंचे, इस बात की चिंता की। इस चिंता को लेकर राशन सामग्री की जो वितरण व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में पोस मशीन का प्रचलन किया। पोस मशीन की व्यवस्था की। माननीय सभापति महोदय, आज उस पोस मशीन के माध्यम से गरीब का जो हक है, जो राशन का सामान है, वह सामान आज

(श्री जगदीश नारायण)

उस गरीब तक पहुंच रहा है। अगर वह गरीब समय पर लेने भी नहीं पहुंचे तो उसके हक को कोई खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। वह स्टोर में सुरक्षित रहता है। जबकि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के राज में कितने कोटे आया करते थे, यह किसी को पता नहीं था। पांच कोटे उठते थे, दो कोटों का वितरण होता था और तीन कोटे बीच में साफ हो जाते थे। भूल से एक-दो कोटे वहां पर पहुंच भी जाते थे तो राशन डीलर एक-डेढ़ या दो दिन दुकान खोलकर थोड़ा बहुत सामान बांटने का काम करता था और तीसरे दिन बंद करके कह देता था कि राशन सामान खतम हो गया है, अब बंटवारा नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, ऐसी सरकार व ऐसी मुख्य मंत्री जो गरीब की चिंता करे, गरीब के हक को गरीब तक पहुंचाने की व्यवस्था करे और पोस मशीन जैसी व्यवस्था करके भ्रष्टाचार का खात्मा करे, इससे बढ़िया इस राजस्थान के लिये कोई प्लान नहीं हो सकता, कोई कदम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत-बहुत उनका शुक्रगुजार करूंगा।

श्री सभापति: सभी मैम्बर आपको भी धन्यवाद दे रहे हैं। सभी मैम्बरों की भावना मैंने आप तक पहुंचायी है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): वह तो मुझे पता है, लेकिन मैं भी संतोषी हूं कि लास्ट तक इंतजार किया है। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण जनता की व्यवस्थाओं में, ग्रामीण जीवन में सुधार अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने किया है। वर्षों से जिन गांवों और क़स्बों में कीचड़ था, वर्षों से जिन गांवों में चलने-फिरने में दुविधा थी। कांग्रेस के लोगों ने नहीं देखा और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको नजदीकी से देखा। गांव का गौरव बढ़े, गांव को गौरव को मिले, गांव-कस्बे में गौरव पथ बनाकर वहां की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिसका आज लोग गुणगान भी कर रहे हैं और उस सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था अपने आपमें विकास की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। यह ऐसी व्यवस्था है, ऐसी योजना है जो राजस्थान

(श्री जगदीश नारायण)

को विकास के पायदान तक ले जाने वाली है। माननीय सभापति महोदय, पशुपालकों के लिये खुशखबरी, पशुपालक का पशु मर जाता था, वह बेचारा हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता था। कर्ज लेकर पशु लाता था, लेकिन अब क्या करे? ऐसी स्थिति में पशुपालकों को अगर सहारा देने का काम किया है तो माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है कि पशुपालकों के लिये भी भामाशाह पशु स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करके आज उन पशुपालकों की मदद की है। आज पशुपालक इस बात के लिये निश्चिंत हो चुका है कि यदि खुदा न खास्ता मेरा पशु मर भी गया तो मुझे सरकार से पूरा पैसा मिलेगा। मुझे अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, समूचे देश में पेयजल और जल की व्यवस्था के लिये अगर किसी ने सोचा है तो वह भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार और हमारे पूर्व माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है। इन लोगों ने तो इस बारे में भी नहीं सोचा। इन लोगों ने तो इस बारे में कतई कोई चर्चा ही नहीं की। उन्होंने जो नदी जोड़ने की योजना बनाई, दस साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम जरूर किया है। जनता के हित में जो काम था, वह न करके जनता के अहित में कौनसा काम हो सकता है, जनता के लिये नुकसानदायक कौनसा काम हो सकता है, उसको करने का जरूर काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं आपको निवेदन करूंगा कि ऐसी योजना..

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कांग्रेस का और कोई सुनने वाला तो है नहीं। अकेली सुमित्रा जी हैं, नहीं, शंकुतला जी बैठी हुई हैं। शकुंतला जी कहीं न कहीं नोट तो करो। ..(व्यवधान)..

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सचेतक महोदय, वह तो लिखा हुआ ही है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, सचेतक महोदय तो नाम भूल गये।

श्री सभापति: शकुन्तला जी है, सुमित्रा जी नहीं। श्रवण जी और बैठे हैं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सचेतक महोदय, मुझे किसी व्यक्ति विशेष को सुनाना है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सचेतक महोदय, इन्होंने तीन सीटें क्या जीत लीं, पूरा राजस्थान जीतकर बैठे हैं, इसलिये उनको घर पर रहने दो। अपने काम चलने दो, अपने को आगे भी पूरे बहुमत से आना है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इन्होंने आज सबकी क्लास ली है। इसीलिए आज बुलवा रहे हैं। नहीं तो और दिन तो छ्ह बजे ही बस्ता संभाल कर चले जाते थे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से धाप गयी है। अब खतम हो गया है, अब आगे कुछ नहीं करना है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आगे देखना क्या-क्या परचम लहराती है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सचेतक महोदय, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मेरा समय बीतता जा रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें। आप बोलें।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सचेतक महोदय, मेरे पर थोड़ी से मेहरबानी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं चर्चा केवल इस बात की करना चाह रहा हूं कि जनता ने हमको चुनकर भेजा है और जनता हमसे अपेक्षा भी करती है। कोई दो लाख वोटों के क्षेत्र से चुनकर आया है, कोई तीन लाख वोटों के क्षेत्र से चुनकर आया है और इतनी बड़ी जनता का एक सपना भी देखा है। उसकी एक आकांक्षा भी है कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि वहां जाकर हमारे हित के लिये क्या स्टेप उठाता है? क्या मुद्दे उठाता है?

माननीय सभापति महोदय, आज तक सदन में रहकर मैंने जो महसूस किया है, वह मेरा अनुभव है कि कांग्रेस को काम करने का तो कोई तजुर्बा ही नहीं है, कांग्रेस का काम करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। काम करने के लिए तो कोई सोच बनायी नहीं है। कांग्रेस के लोगों का सदन में जैसा आचरण रहा है, जैसा शिष्टाचार रहा है, जैसा मर्यादा के खिलाफ बोलने का एक तरीका रहा है, वह भी यह जाहिर करता है और साढ़े सात करोड़ जनसंख्या को एक संदेश देता है कि वे लोग कैसे हैं? जो अपने आपमें

(श्री जगदीश नारायण)

आचरणों का विकास नहीं कर पाये, जो अपने आप को शिष्टाचार से नहीं बांध सकें, वे क्या विकास कर पाएंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पूरे सदन से यह साढ़े सात करोड़ की जनसंख्या का सदन है, यहां अगर एक मिनट भी खराब होता है, इसका मतलब है साढ़े सात करोड़ की जनसंख्या का सीधा-सीधा नुकसान है। यहां तो वे तर्क-वितर्क होने चाहिए जिनके माध्यम से उस जनता का कोई हित सधे, जनता के लिए कोई नया रास्ता निकले या जनता के विकास में और कोई नया आयाम जुड़े।

माननीय सभापति महोदय, स्वच्छता कार्यक्रम जैसी योजना पूरे हिन्दुस्तान में, फिर हमारे भाई कहते हैं कि 20-25 परसेंट रह गये। यदि 20-25 परसेंट रह भी गये, 75 परसेंट जुड़ तो गये ना 80 परसेंट लोगों को स्वच्छता से जोड़कर उन्होंने इस भारत को, इस देश को स्वच्छ बनाने का काम किया है। 20-25 परसेंट रह भी गये तो और जुड़ जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, भूखों को खाना देना, मैं कहता हूं कितने मुख्य मंत्री राजस्थान में कांग्रेस के रह चुके है? उनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आयी? हमारी माननीय मुख्य मंत्री के दिमाग में क्यों आयी? जिन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वाहन भेजकर के भूखों को खाना खिलाने का काम किया है और आज उस खाने को जो खा रहे हैं, वे समझते हैं कि गरीब की चिंता करने वाला कौन व्यक्ति है। गरीब की चिंता करने वाली मुख्य मंत्री है।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में गिरते भूजल के बारे में अगर किसी ने चिंता की है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से, गांव-गांव में इस तरह के कार्यक्रम करवाना कि गिरते हुए भूजल को रोकना है, उसको सुरक्षित करना है क्योंकि भविष्य में जल को लेकर संकट में आने वाला है। कई लोगों ने भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले समय में अगर कोई वर्ल्ड वार होगा तो वह पानी को लेकर के होगा। समय रहते ऐसी व्यवस्थाओं को करना बहुत जरूरी है और यह हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय को दुगना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सपना देखा है, कदम भी उठाये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझकर आप अपना वक्तव्य दें। मेरी तरफ से मना नहीं है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, हमारी धरती माता के स्वास्थ्य की चिंता आज तक किसी ने नहीं की। इस धरती माता से लोगों ने लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसका भी कोई स्वास्थ्य है, इसके भी स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ सकती है, इसके बारे में कांग्रेस की सरकार ने कतई चिंता नहीं की। ये चिंता करने वाली भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी माननीय मुख्य मंत्री और हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण योजना बनाकर किसानों की आय को दुगुना करने के लिए एक स्टेप उठाया है जो कारगर साबित होगा और उसके माध्यम से किसान की आय भी दुगुनी होगी। यह मुझे पूरा भरोसा है। फसल खराबे की बात करें तो वह भी हमारी सरकार ने नजदीकी से देखा है और किसानों की मदद करने का काम किया है। गांव की महिलाओं के आंसू पोछने का अगर किसी ने काम किया है तो वह भी हमारे प्रधान मंत्रीजी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन देकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है।

माननीय सभापति महोदय, योजनाएं बहुत सारी हैं। आप समय भी मुझे कम दे रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन मैं इतना इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि सत्ता हथिया लेना, सत्ता में आ जाना ही राजस्थान का विकास नहीं है, सत्ता ले लेना ही इस राजस्थान प्रदेश की सेवा नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि काम ऐसा करें, योजनाएं ऐसी बनाएं, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आएं जिससे राजस्थान प्रदेश की जनता का भला हो, जिससे राजस्थान प्रदेश विकास के आयाम तक, पायदान तक पहुंचने की स्थिति में आ जाए। ये तो है सेवा करना, ये तो है राजनीति करना और मात्र कुर्सी हथियाने के लिए या सत्ता में आकर के राज में बैठ जाना, मैं तो समझता अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। हो गया अब।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय एक ही मिनट। इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कितना बड़ा कदम उठाया है स्कूली बच्चों को दूध पिलाना, उनको स्वस्थ रखना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना और उनको स्वस्थ रखकर के राजस्थान को स्वस्थ बनाना। यह अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पहले दूध को चैक करवा लो दूध को। दूध कौनसा है? गाय का है, भैंस का है, कौनसा दूध है?

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया है अगर किसी को तकलीफ है तो तकलीफ के कारणों को ढूंढे, मेरे से वाद-विवाद न करें। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे समय नहीं देना चाह रहे हैं। मैं इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है इस राजस्थान प्रदेश को विकास के पायदान तक ले जाना, राजस्थान की गरीब जनता के हित में काम करना और राजस्थान की जनता के समय की एक-एक मिनट की कद्र करके शिष्टतापूर्वक इस सदन में आचरण करके राजस्थान की जनता को संदेश देना। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मैं अपने बजट पर वक्तव्य के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा और जनता की जो दुआएं उनको मिल रही हैं, उस पर भरोसा जताना चाहूंगा कि वह अगली बार भी इसी रूप में आकर के सरकार बनाएंगी। अगली बार भी ऐसा ही बजट पेश करेगी। लोग जलने वाले जलते रहेंगे। उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 21:27 बजे शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा जिले में क्रेशर प्लान्टों के प्रदूषण पर कार्यवाही

127. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थापित अधिकांश क्रेशर व ग्राइन्डर प्लांटों के चारों ओर वृक्षारोपण व पूर्ण कवर्ड दीवारें नहीं होने के कारण उक्त प्लांट के चारों ओर कृषि भूमियों में डस्ट पाउडर की परत जमने से जमीन बंजर हो रही है? यदि हां, तो आमजन की सेहत व बंजर होती कृषि भूमि के बचाव हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर के संभागीय आयुक्त द्वारा भीलवाड़ा जिले के निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता द्वारा शिकायत करने पर तत्कालीन जिला कलक्टर को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो उक्त निर्देशों के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भीलवाड़ा जिले में ईंट भट्टें, सोप स्टोन ग्राइण्डर प्लांट और गिट्टी क्रेशर प्लांट कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उक्त प्लांट संचालकों के प्लांटों का विभागीय अधिकारियों ने अन्तिम बार कब-कब निरीक्षण किया तथा निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पायी गयी तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पर्यावरण संबंधी नियमों एवं शर्तों की अनदेखी के प्रकरणों में गत 2 वर्षों में भीलवाड़ा जिले में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण विभाग के अधीन राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर स्टोन क्रेशर एवं मिनरल ग्राइडिंग उद्योग की स्थापना हेतु जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ही वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना व संचालन हेतु सम्मति प्रदान की जाती है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी वर्तमान मार्गदर्शिका

(पर्यावरण मंत्री)

दिनांक 15.10.2014 के अनुसार किसी भी स्टोन क्रेशर को स्थापना से पहले राजस्व विभाग से भूमि का रूपान्तरण, औद्योगिक (स्टोन क्रेशर उद्योग) प्रयोजनार्थ करवाया जाना आवश्यक हैं जिसके पश्चात् ही राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा स्थापना एवं संचालन सम्मति प्रदान की जाती है।

प्रदेश में स्थापित क्रेशर व ग्राइडिंग प्लान्टों के चारों ओर सम्मति शर्तो के अनुसार व्रक्षारोपण एवं क्रेशर प्लान्टों में कनवेयर्स के मध्य वायु रोधक दीवारें बनाई जाने की बाध्यता होती है।

कृषि विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार क्रेशर व ग्राइन्डर प्लांटो के आस पास के क्षेत्रों में डस्ट पाउडर खेतों की मिट्टी पर जमा होने से मिट्टी के गुणधर्म एवं उर्वरा शक्ति प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। यदि खड़ी फसलों व फलदार वृक्षों की पत्तियों पर डस्ट पाउडर जमा होता है, तब पौधों की वृद्धि एवं विकास प्रभावित हो सकता है।

(2) भीलवाड़ा जिले के निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) भीलवाड़ा जिले में संचालित ईंट भटटों, सोप स्टोन ग्राइण्डर प्लांट एवं गिटटी क्रेशर प्लांट का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट ब एवं विभागीय अधिकारियों के अन्तिम निरीक्षण, निरीक्षण में पायी गई कमियां एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(4) पर्यावरण संबंधी नियमों एवं शर्तो की अनदेखी के प्रकरणों में विगत दो वर्षो में भीलवाड़ा जिले में स्टोन क्रेशर, ईंट उद्योग एवं मिनरल ग्राइण्डिंग उद्योगों के विरुद्ध राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त शिकायतों एवं की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

वैर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

130. श्री भजन लाल (वैर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में गत चार वर्षों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कब-कब व कहां-कहां पर खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुईं है ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में दो परियोजनाएं क्रमश: वैर एवं बयाना संचालित हैं, जिसमें गत चार वर्षों में बाल विकास परियोजना वैर में 11 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये। परियोजना बयाना में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया। नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिश्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र वैर में एक शिकायत दिनांक 11.08.2016 को श्री मुकेश चन्द शर्मा निवासी नगला मनका बयाना भरतपुर से सैक्टर कलसाड़ा में पोषाहार वितरण व भुगतान में अनियमितता सम्बंधी शिकायत श्रीमती गिरजा, महिला पर्यवेक्षक के विरुद्ध प्राप्त हुई थी जिसकी जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यवाही अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर से करवाई गयी। जांच में उक्त शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कृषि विकास के कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

131. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कृषि विकास हेतु वर्ष 2016-17 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) फव्वारों सहित अन्य अनुदानों एवं विकास हेतु वर्ष 2016-17 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया व उसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि विकास पर बजट घोषणा के अनुसार राशि व्यय नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तों क्यों?

(4) प्रदेश में गत तीन वर्षों में कितने किसानों ने किन-किन कारणों से आत्महत्या की? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार ने उक्त किसानों के परिवार को कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि विकास हेतु वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग हेतु संशोधित बजट प्रावधान राशि रुपये 2513.18 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 2245.63 करोड़ एवं उद्यान विभाग हेतु संशोधित बजट प्रावधान राशि रुपये 363.64 करोड के विरुद्ध राशि रुपये 304.17 करोड़ 31 मार्च, 2017 तक व्यय हुए।

(2) फव्वारा सहित अन्य अनुदानों एवं विकास हेतु वर्ष 2016-17 में कृषि एवं उद्यान विभाग हेतु संशोधित बजट प्रावधान एवं व्यय राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कृषि विकास पर वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग हेतु संशोधित प्रावधान राशि का 89.35 प्रतिशत एवं उद्यानिकी विभाग हेतु संशोधित प्रावधान राशि का 83.65 प्रतिशत व्यय हुआ है।

(4) राज्य में विगत तीन वर्षों में 4 किसानों ने जिला जालौर एवं जिला बूंदी में आत्महत्या की है। किसानों द्वारा की गयी आत्महत्या एवं आत्महत्या का सम्भावित कारण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) राज्य आपदा मोचन निधि में आत्महत्या के प्रकरणों में सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सरकार द्वारा मृतक किसानों के परिवारों को दी गयी सहायता का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के सड़क से वंचित गांव

132. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के कई गांव वर्तमान में सड़क की सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सड़क से वंचित गांवों को विभिन्न योजनाओं में सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाओं के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 23 गांव डामर सड़कों से वंचित हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) इन गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने की कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सड़क से वंचित गांवों को डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं व नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में रायल्टी नाकों का आवंटन

133. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा करौली शहर में लाल रोड नाका, मण्डरायल रोड करौली पर एक्सेस रॉयल्टी/ अधिशुल्क नाका कब एवं किसको किन शर्तों पर आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आबंटी द्वारा नियम और शर्तों की पालना की गयी है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्व क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों?

(श्री रमेश)

(3) क्या यह सही है कि उक्त नाके पर लगे कांटे की जांच कराया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो जांच कब-कब की गयी एवं कब-कब कांटे का सत्यापन किया गया व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार को उक्त आबंटी द्वारा ई-रवन्ना जारी करने हेतु निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) करौली जिले में ताल रोड (मण्डरायल रोड) पर दिनांक 04.07.2017 से अधिक अधिशुल्क वसूली ठेकेदार मैसर्स ओम शिव नीलकण्ठ एसोसियेट, बरवाड़ा हाउस कालोनी, सिविल लाइन, जयपुर को नाका लगाने की अनुमति दी गयी है। नाके की अनुमति राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 44(3), 44(20) व 44(21) के तहत दी जाती है। नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलबध है।

(2) दिनांक 22.12.2017 को खनि. कार्यदेशक द्वारा उक्त नाके की जांच के दौरान ई.आर.सी.सी. ठेकेदार द्वारा जारी की जा रही रॉयल्टी रसीदों में कुछ प्रविष्टियां अपूर्ण पायी गयी थीं तथा माह दिसम्बर के मासिक रिटर्न के अवलोकन में भी उक्त कमी पायी गयी थी जिसके क्रम में दिनांक 24.01.2018 को चेतना पत्र जारी किया गया था। उक्त चेतना पत्र की पालना में ई.आर.सी.सी. ठेकेदार द्वारा उत्तर दिनांक 06.02.2018 को प्रस्तुत करते हुए उक्त त्रुटि को सुधारने एवं भविष्य में न दोहराने बाबत् लिखा गया, जिसकी खनि. कार्यदेशक द्वारा दिनांक 07.02.2018 को जांच की गयी तथा सही पाया गया। अत: राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार ई.आर.सी.सी. ठेकेदार पर रुपया 10,000/- की शास्ति आरोपित की गयी जो ठेकेदार द्वारा जरिये जीआरएन नं. 0021121145 दिनांक 13.02.2018 से जमा करवाई जा चुकी है।

(3) जी हां। नियमानुसार तुलायंत्र की जांच नाप तोल विभाग द्वारा की जाती है एवं नाप तोल विभाग से सत्यापन किया जाना भी आवश्यक है। उक्त कांटे का सत्यापन नाप तोल विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2017 को किया गया है।

(राज्य मंत्री, खान)

(4) विभाग द्वारा अनकन्फर्मड ई-रवन्ना को कन्फर्मड करने हेतु कोई भी दर निर्धारित नहीं की गयी है। न ही इस संबंध में कोई लिखित शिकायत ई.आर.सी.सी. ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त हुई है। किन्तु उक्त के संबंध में श्री रमेश मीणा (माननीय विधायक, सपोटरा) द्वारा ई-रवन्ना बनाने के रुपये वसूले जाने तथा कांटे में गलत तरीके से तौल करने बाबत् मौखिक शिकायत दिनांक 21.12.2017 की गयी थी जिसके क्रम में कार्यालय के खनि कार्यदेशक द्वारा दिनांक 22.12.2017 व 01.02.2018 को मौके पर उक्त तुलायंत्र की जांच की गयी जिसमें तुलायंत्रधारक द्वारा वाहनों से ई-रवन्ना कन्फर्म करने हेतु रुपया 100/- प्रति वाहन (ट्रक) वसूलना पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। जिसके क्रम में दिनांक 02.02.2018 को ठेकेदार को ई-रवन्ना कन्फर्म करने के एवज में लिये जा रहे 100/- रुपये प्रति वाहन को अनियमित मानते हुए संबंधित अतिरिक्त वसूल की गयी राशि तथा उक्त राशि कब से कब तक ली गयी है इस हेतु अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का जवाब प्राप्त होना शेष है जिसके पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही खनि. कार्यदेशक की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2018 के अनुसार उक्त ई.आर.सी.सी. ठेकेदार दिनांक 06.02.2018 से तुलाई पेटे केवल तुलाई फीस 50/- प्रति वाहन के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ में पेयजल योजना के स्वीकृत कार्य

134. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में गत 4 वर्षो में पेयजल के कार्यो हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत राशि से कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना अधूरा है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अधूरे कार्यों को पूरा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, अनूपगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर, 2017 तक) की अवधि में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 101 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि रुपये 3874.38 लाख, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 42 योजनाओं/कार्यों हेतु राशि रुपये 761.08 लाख एवं सांसद मद में 1 कार्य हेतु राशि रुपये 5.00 लाख, इस प्रकार कुल 144 योजना/कार्यों हेतु राशि रुपये 4640.46 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी। योजनावार स्वीकृति विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत 101 योजनाओं/कार्यों में से 51, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 42 योजनाओं/कार्यों में से 25 तथा सांसद मद में स्वीकृत 1 कार्य अब तक पूर्ण किये जा चुके हैं।

विभागीय तथा सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत शेष रहे क्रमश: 50 एवं 17 योजनाएं/कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। योजनावार प्रगति विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार शेष प्रगतिरत योजनाएं/कार्य चरणबद्ध रूप से माह नवम्बर, 2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित हैं। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में वन क्षेत्रों की वृद्धि की कार्ययोजना

135. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वनों के आच्छादित क्षेत्रों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है? यदि हां, तो वर्ष 2014 से 2017 तक किस-किस जिले में कितने-कितने भू-भाग पर वन भूमि की कमी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन क्षेत्रों में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(श्री बाबू सिंह)

(3) क्या प्रदेश में वृक्षों की अवैध कटाई के प्रकरण दर्ज किये गये? यदि हां, तो वर्ष 2014 से 2017 तक दर्ज प्रकरणों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त दर्ज प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उपग्रह आकंड़े का प्रयोग कर प्रत्येक दो वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2015 एवं 2011 में उपग्रह आकंड़ों क्रमश: अक्टूबर, 2013 से फरवरी, 2014 एवं अक्टूबर, 2008 से मार्च 2009 के आधार पर जारी की गयी है। उक्त रिर्पोटों के अनुसार राजस्थान राज्य की जिलेवार वन आच्छादित क्षेत्र की सूचना संलग्न परिशिष्ट ए एवं बी पर है। जिसके अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक छत्र घनत्व (Crown dansity) वाला आच्छादित क्षेत्र में 84 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है।

राजस्थान राज्य में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 एवं 2015 के आधार पर अत्यन्त सघन वन (छत्र घनत्व 70 प्रतिशत से अधिक), सामान्य सघन वन (छत्र घनत्व 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत) एवं खुले वन (छत्र घनत्व 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत) की जिलेवार कमी / बेशी की सूचना संलग्न परिशिष्ट सी पर है।

(2) वन आच्छादित क्षेत्र (Forest cover) में वृद्धि हेतु निम्न विकास योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण एवं वन सरंक्षण के कार्य किये जा रहे हैं-

1. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना
2. नाबार्ड ऋण अंतर्गत वनारोपण
3. जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक कार्यक्रम
4. परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण
5. भाखडानांगल नहर वृक्षारोपण
6. गंग नहर वृक्षारोपण
7. कैम्पा के अन्तर्गत वृक्षारोपण
8. राज्य वन विकास अभिकरण

(पर्यावरण मंत्री)

9. पर्यावरण वानिकी

10. फार्म फोरेस्ट्री

11. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

(3) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2014-15 से 2017-18 में वृक्षों की अवैध कटाई के दर्ज प्रकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट डी अनुसार है।

(4) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानो अन्तर्गत नियमानुसार एवजाना वसूल कर अथवा प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट डी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में फॉर वाटर कन्सेप्ट के कार्य

136. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में सरकार द्वारा फॉर वाटर कन्सेप्ट के कार्य कहां-कहां स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत कार्यों को मानदण्डानुसार नहीं कर भारी अनियमितता की गयी है?

(3) क्या सरकार संवदेक व दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग द्वारा फॉर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत कार्यों को निर्धारित मापदण्डानुसार संपादित किया गया है।

(3) कार्य मापदण्डानुसार संपादित किये जाने से किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के लम्बित आवेदन

137. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(1) क्या प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी व नहीं तो क्या सरकार इसकी समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां तो, कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के उपखण्ड कार्यालयों में वर्तमान में कितने आवेदन निस्तारण के लिए लंबित हैं? उपखण्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में गत चार वर्षों में सरकार के पास नाम जुड़वाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने आवेदन निरस्त किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों का पुन: सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन के निस्तारण हेतु अधिकतम 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 24.10.2017 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के प्राधिकृत कार्यालयों में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने हेतु स्थिति जनवरी, 2018 के अनुसार 116537 आवेदन लम्बित हैं। संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जुड़वाने एवं हटाने हेतु प्राप्त अपीलों के निस्तारण की समयावधि 30 दिवस निर्धारित की गयी है। अपील का निस्तारण एवं न्यायिक प्रक्रिया है तथापि समय-समय पर इस संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किये जाते रहे है। इस संबंध में दिनांक 19.12.2017 को जारी निर्देश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) प्रदेश में जनवरी,2018 तक खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

जुड़वाने के लिए 856239 आवेदन प्राप्त हुए उनमें से 250520 आवेदन निरस्त किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 में सम्मिलित है।

(5) राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों का पुन: सर्वे करवाने की कोई कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र व्यक्तियों के समावेशन एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन हेतु अपीलीय प्रक्रिया लागू है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.11.2015, 02.08.2017 एवं 29.09.2017 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं के रिक्त पद

138. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो रावतसर तहसील की आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पौषाहार वितरण करने पर वर्ष 2016-17 में कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ताओं के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कब तक करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतो में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण करवाया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में रावतसर तहसील के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण पर 1,72,92,192 रुपये का बजट व्यय किया गया।

(2) पीलीबंगा विधान सभा के अन्तर्गत चार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त है।

1. वार्ड नम्बर 1 बी
2. 29 एसटीजी
3. गोलूवाला निवादान सी

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

4. प्रेमपुरा ए

(3) भवन निर्माण हेतु नि:शुल्क भूमि प्राप्त होने पर एवं बजट उपलब्ध करवाए जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति होती है। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 273 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 68 विभागीय भवनों में 175 अन्य विभागों के भवनों/सामुदायिक केन्द्रों में एवं 30 किराये के भवनों में संचालित हैं। इनमें से 08 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगतिरत है। शेष केन्द्रों के भवनों के भवन निर्माण हेतु निशुल्क भूमि प्राप्त होने पर एवं बजट उपलब्ध होने पर निर्माण करवाया जाएगा।

कृषि उपज मण्डियों में फुटकर व्यापारियों को दुकानों का आबंटन

139. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में फुटकर व्यापार के लिए दुकानें आबंटित कर अनुज्ञा पत्र जारी किये गये है? यदि हां, तो चौमूं कृषि उपज मण्डी में कितनी दुकानें आबंटित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे फुटकर व्यापार की दुकानों को 'क' वर्ग का अनुज्ञापत्र जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त अनुज्ञा पत्र जारी करने में महिलाओं को प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति चौमूं के मुख्य मण्डी प्रांगण चौमूं में 14 निर्मित फुटकर दुकानें तथा 4 फुटकर दुकानों के भूखण्ड कुल 18 फुटकर दुकान/भूखण्ड आंबंटित की गई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(कृषि विपणन मंत्री)

(3) जी नहीं। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 एवं नियम 1963 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोडवेज कर्मियों के बकाया परिलाभों का भुगतान

140. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज की जमीनों को बेचा जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा रोडवेज की कौन-कौनसी जमीनों को बेचने का निर्णय लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रोडवेज कर्मियों के महंगाई भत्ते एवं बोनस पर रोक लगाई गयी है? यदि हां, तो कब व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार राजस्थान रोडवेज की जमीनों को बेचने का विचार नहीं रखती है। वर्तमान में सिर्फ एक भूमि, ग्राम हथरोई में स्थित खसरा नम्बंर 151/443 की कुल 19390.55 वर्गमीटर भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से खुली नीलामी प्रक्रिया अपनाकर विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इस हेतु दिसम्बर 2017 में जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से खुली बोली का आयोजन भी किया गया था जिसमें किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग नहीं लिया गया।

(2) बिन्दु संख्या "1" पर दिये गये के अलावा कोई भूमि विक्रय किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जनवरी, 2017 व जुलाई, 2017 में रोकड़ तरलता की स्थिति उपयुक्त न होने के कारण महंगाई भत्ते की दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। निगम की आर्थिक स्थिति ठीक होते ही महंगाई भत्ते व बोनस के भुगतान पर विचार किया जाएगा।

नागौर जिले में डी.एम.एफ.टी. द्वारा स्वीकृत कार्य

141. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 31 मई, 2016 को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर खनन पदार्थों की रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि The District Mineral Foundation Trust (DMFT) में जमा करवाने का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो उक्त आदेशों के पश्चात् नागौर जिले में उक्त ट्रस्ट का गठन कब किया गया एवं अब तक कितनी राशि किस-किस विधानसभा क्षेत्र से उक्त ट्रस्ट में रायल्टी के रूप में जमा हुई तथा उक्त ट्रस्ट की बैठकें कब-कब आयोजित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त ट्रस्ट में जमा राशि को व्यय करने के लिए क्या प्रावधान बनाए गये है एवं प्राथमिकता का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रस्ट के गठन के पश्चात् नागौर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में ट्रस्ट के माध्यम से स्वीकृत राशि व कार्यों का विधानसभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में किस-किस जन प्रतिनिधि की अनुशंसा पर कौन कौनसे कार्य स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2016 को The District Mineral Foundation Trust (DMFT) के नियम बनाये गये, जिसमें अप्रधान खनिज के पट्टाधारियों से रॉयल्टी राशि की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि DMFT फण्ड में जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। नागौर जिले में The District Mineral Foundation Trust (DMFT) का गठन दिनांक 09.06.2016 को किया गया है। अब तक नागौर जिले में विधानसभावार DMFT के तहत जमा राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त ट्रस्ट के अन्तर्गत गठित मैनेजिंग कमेटी की दो बैठकें क्रमश: दिनांक 04.10.2016 एवं 09.02.2017 को आयोजित की गयी तथा

(राज्य मंत्री, खान)

गवर्निंग काउन्सिल की बैठके क्रमश: दिनांक 18.11.2016 व 11.05.2017 को आयोजित की गयी। बैठकों की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त ट्रस्ट की राशि खर्च करने के लिए दो श्रेणियां बनायी गयी हैं। प्रथम श्रेणी में उच्च प्राथमिकता के कार्यो को रखा गया है, जिसमें DMFT के तहत जमा राशि का न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है तथा दूसरी श्रेणी में अन्य प्राथमिकता के कार्यों को रखा गया है, जिसमें जमा राशि का 40 प्रतिशत तक खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। संबंधित नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) नागौर जिले में DMFT ट्रस्ट के गठन के पश्चात् अभी तक कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(4) नागौर जिले में किसी भी जन प्रतिनिधि की अनुशंसा पर कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली में पेयजल की योजनाएं

142. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाऐं, क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलना व नवीन टंकी निर्माण के प्रस्ताव सरकार के के विचाराधीन है? सरकार उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर पूर्ण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की चार हजार की आबादी वाली कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में विभागीय मानदण्डों के अनुसार पीएण्डटी योजना को पाइप्ड योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव बनाये जा सकते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की 1500 की आबादी वाली कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में विभागीय मानदण्डों के अनुसार हैण्डपम्प योजना से

(श्री दलीचन्द डांगी)

पीएण्डटी योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव बनाये जा सकते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने राजस्व गांव ऐसे हैं, जो अभी भी पेयजल योजनाओं से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त गांवों को पेयजल योजनाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों को अब तक पेयजल योजनाओं से नहीं जोड़ा गया है? में क्या सरकार योजना स्वीकृत होने तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, मावली में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3 जल योजनाओं हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइन जोड़ने-बिछाने के कार्य, नवीन उच्च एवं भू-तल जलाशयों का निर्माण एवं भू-तल जलाशयों का सुदृढ़ीकरण कार्य, जल स्रोतों के निर्माण, पम्पिंग मशीनरी इत्यादि कार्य का प्रावधान लिया गया है।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध 2 जल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही तथा शेष 1 योजना हेतु तकनीकी स्वीकृति की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त मावली क्षेत्र की किसी भी पेयजल योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, मावली में कुल सम्मिलित 219 राजस्व ग्रामों में से 4 ग्राम क्रमश: डबोक, देबारी, लकड़वास एवं ईंटाली की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 4000 से अधिक है। ग्राम डबोक एवं ग्राम लकड़वास क्षेत्रीय जल योजनाओं से तथा ग्राम देबारी एवं ईंटाली पाइप्ड जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

उपरोक्तानुसार 4000 से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी ग्राम को पाइप्ड जल योजना में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त चार ग्रामों में उक्त जल योजनाओं से वर्तमान पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, मावली में 58 ग्रामों की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 1500 या इससे अधिक तथा 4000 से कम है। इनमें से 17 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 8 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 21 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा शेष 12 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित उक्त 12 ग्राम विभागीय नीति अनुरूप हैण्डपम्प योजना से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना के मानदण्ड में आते हैं। इन 12 ग्रामों में से 4 ग्रामों के स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण इनमें आर.ओ. संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

विभिन्न जल योजनाओं से लाभान्वित उक्त समस्त 58 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति संबंधी विवरण परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र, मावली की पंचायत समिति मावली, गिर्वा एवं बड़गांव में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 219 ग्रामों में से 31 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 23 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 49 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 116 ग्राम हैण्डपम्प जल योजना से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

मावली क्षेत्र के उक्त समस्त ग्रामों में विभिन्न जल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है तथा कोई राजस्व आबाद ग्राम पेयजल आपूर्ति से वर्तमान में वंचित नहीं है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(5) उपरोक्तानुसार मावली क्षेत्र में विभिन्न जल योजनाओं से जुड़े समस्त 219 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है तथा कोई राजस्व आबाद ग्राम पेयजल आपूर्ति से वर्तमान में वंचित नहीं है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-द में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 143

(स्थगित)

प्रदेश में यमुना का पानी लाने की योजना

144. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश के मध्य यमुना नदी के जल के बंटवारे का समझौता का किस वर्ष में हुआ था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समझौते के तहत चूरू व झुंझुनूं जिलों को कितने बिलीयन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अपर रिवर यमुना बोर्ड ने भी उक्त समझौते को स्वीकृति प्रदान कर दी थी? यदि हां, तो किस वर्ष में?

(4) अपर रिवर यमुना बोर्ड के द्वारा समझौते को मंजूरी दिये जाने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा उक्त पानी को लाने के लिए अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं होने के उपरान्त भी राजस्थान सरकार द्वारा पानी लाने की असमर्थता के मुख्य कारण क्या रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और हिमाचल राज्यों के मध्य यमुना नदी के जल बंटवारा के संदर्भ में वर्ष 1994 में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। एम.ओ.यू. की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इस एम.ओ.यू. के अनुसरण में अपर यमुना रिवर बोर्ड ने दिनांक 21.12.2001 को आयोजित 22वीं बैठक में ताजेवाला हैड पर जुलाई-अक्टूबर की अवधि में राजस्थान को 1917 क्यूसेक (0.577 बीसीएम) यमुना जल निर्धारित किया, इस जल को चूरू एवं झुंझुनूं जिलों में उपयोग हेतु योजना बनायी गयी।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) दिनांक 12.05.1994 को हुए एम.ओ.यू. के अन्तर्गत राज्य को आबंटित यमुना जल को राजस्थान में लाने के लिये किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) यमुना नदी के आवंटित जल को राजस्थान में लाने का कार्य हरियाणा राज्य द्वारा योजना की क्रियान्विति हेतु एम.ओ.यू. पर सहमति प्रदान नहीं किये जाने से, नहीं किया जा पा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में राशन डीलरों का निलम्बन

145. श्री हीरालाल (निवाई): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कितने राशन डीलर के अनुज्ञा पत्र/लाइसेंस निलम्बित अथवा निरस्त हैं? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में निलंबित अथवा निरस्त राशन डीलर का चार्ज वितरण हेतु अन्य डीलर को देने हेतु क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं ?नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निलंबित व निरस्त राशन व केरोसीन डीलरों का चार्ज किन-किन डीलरों को दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के राशन डीलरों को लाभ पहुंचाने हेतु नियम विरुद्ध एक से अधिक राशन व केरोसीन डिपो का चार्ज दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व इसके क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निलंबित/ निरस्त राशन डीलरों का चार्ज देने में नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 13 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण निरस्त है एवं निलम्बित प्राधिकार पत्रों की संख्या शून्य है। कारण सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में विभिन्न कारणों से उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र निलम्बित एवं निरस्त किये जाने से रिक्त हुई उचित मूल्य दुकानों को समीप की अन्य उचित मूल्य दुकानों से अटैच (सम्बद्ध) किया जाता है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में निलम्बित व निरस्त राशन डीलरों के अटैचमेन्ट की सूचना परिशिष्ट-1 में सम्मिलित है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नियम विरुद्ध एक से अधिक राशन दुकानों व केरोसीन डिपों का चार्ज नहीं दिया गया है।

(5) प्रदेश में निलम्बित/निरस्त उचित मूल्य दुकानों को अन्य समीप की दुकान से अटैच करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 23.08.2016 को जारी किये हुए है, जिसकी अवहेलना की शिकायत होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम में नवीन आगंनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना

146. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत तीन परियोजनाएं क्रमश: परियोजना भीम, देवगढ़ एवं राजसमंद शहर संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत परियोजना भीम में 157, देवगढ़ में 110 एवं राजसमंद शहर में 15 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत किये जाते है। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2015-16 में 03 एवं वर्ष 2016-17 में 04 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 03 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि कार्यों हेतु शिक्षित बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना

116. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के शिक्षित बेरोजगार कृषक परिवार के युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्नत किस्म के पशु खरीदने एवं छोटी जोत को विकसित करने के लिए अनुदान देने व बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो अधिकतम ऋण सीमा कितनी होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के शिक्षित बेरोजगार कृषक परिवार के युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्नत किस्म के पशु खरीदने एवं छोटी जोत को विकसित करने के लिए अनुदान देने एवं बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने संबंधी अलग से कोई विशिष्टि योजना वर्तमान में स्वीकृत नही है।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उन्नत किस्म के पशु खरीदने एवं छोटी जोत विकसित करने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना एवं डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।

डेयरी विकास योजनान्तर्गत कम से कम 10 इकाई की योजना (परियोजना आधारित) हेतु 5 वर्ष के लिये 12 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

किसानों की सभी कृषि संबंधी ऋण आवश्यकताओं को सरलीकृत प्रक्रिया के द्वारा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु सहकार किसान कल्याण योजना क्रियान्वित है।

कृषि में अतिरिक्त आय के साधन विकसित करने, पशुपालन व बागवानी को प्रोत्साहन देने, आधुनिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु साख सीमा के रूप में अधिकतम रुपये 2.50 लाख एक वर्ष की अवधि के लिए, साख सीमा का प्रतिवर्ष खाते में लेन देन के आधार पर नवीनीकरण एवं 10 लाख रुपये तक टर्म ऋण के रूप में अधिकतम 9 वर्षों के लिए 11 प्रतिशत ब्याज

(कृषि मंत्री)

दर पर उपलब्ध कराया जाता है। टर्म ऋण को समय पर चुकाने पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय है।

राज्य की प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा भी डेयरी योजना में ऋण दिया जा रहा है जिस पर राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण चुकाने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत अनुदान देय है। इसमें अधिकतम ऋण की सीमा नहीं है।

जायल के पशु चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन

117. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्ष 2013-14 से दिसम्बर, 2017 तक कितने पशु उप केन्द्र खोले गये एवं कितने पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय भवन रहित संचालित हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशु उप केन्द्रों व पशु चिकित्सालयों में कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में वर्ष 2013-14 से दिसम्बर 2017 तक स्वीकृत पशु चिकित्सा उप केन्द्रों एवं क्रमोन्नत की गयी पशु चिकित्सा संस्थाओं का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में कुल 6 पशु चिकित्सालय राजकीय भवन में संचालित नही हैं। जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	पंचायत समिति का नाम
1	गंठीलासर	नागौर
2	गोराऊ	जायल
3	ऊचाईडा	जायल
4	जालनियासर	जायल
5	तंवरा	जायल
6	तरनाऊ	जायल

(पशुपालन मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल की पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट- 2 पर संलग्न है। रिक्त पदों को मानव संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

118. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सामान्य बच्चों के साथ खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कब-कब उक्त प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गयी तथा कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार, वर्षवार आबटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये ग्रीष्म अवकाश में कितने कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया गया तथा इसके लिए कितनी राशि आबंटित कर व्यय की गयी? जिलेवार, वर्षवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ पृथक् से कोई खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित खेल संघों द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती है।

1. राजस्थान स्पोर्ट्स कौसिंल ऑफ दी डीफ

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

2. राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ

3. राज्य पैरा संघ

उक्त संघों द्वारा गत तीन वर्षों में करवाई गई प्रतियोगिताओं में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पैरा, डीफ व डम्ब खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के फलस्वरूप अनुदान नियमों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती रही है।

वर्ष 2015-16 में इन खिलाड़ियों को राशि रुपये 73.88 लाख एवं वर्ष 2016-17 में 104.48 लाख तथा वर्ष 2017-18 में 337.50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है।

(2) उक्त खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट- "क" में उल्लेखित है, तथा खिलाड़ियों को दी गई राशि का विवरण बिन्दु संख्या- 1 में उल्लेखित है।

(3) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् द्वारा ग्रीष्म अवकाश में कौशल विकास शिविरों का आयोजन नहीं करवाया जाता है अपितु खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पदक जीतने के फलस्वरूप अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेंगूं में एम.जे.एस.ए. के तहत स्वीकृत कार्य

119. श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा बेंगू क्षेत्र में वर्ष 2013 के पश्चात् M.J.S.A. में कितने कार्य स्वीकृत हुए व उनमें से कितने पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में एम.जे.एस.ए. फेज I, II एवं III में वन विभाग द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

(वन मंत्री)

क्र.सं.	नाम कार्यालय	योजना	स्वीकृत	पूर्ण कार्य	सूची
1	उप वन संरक्षक चितौड़गढ़	एम.जे.एस.ए.-I (ग्रामीण)	23	23	परिशिष्ट-ए अनुसार
		एम.जे.एस.ए.- II (ग्रामीण)	315	315	परिशिष्ट-बी अनुसार
		एम.जे.एस.ए.-III (ग्रामीण)	417	डी.पी.आर अनुमोदन प्रक्रियारत डी.पी.आर अनुमोदन उपरांत कार्य सम्पादित किये जाकर पूर्ण किये जाएंगें	परिशिष्ट-सी अनुसार
		एम.जे.एस.ए.- II (शहरी)	2	निर्धारित समयावधि पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।	परिशिष्ट-डी अनुसार
2	उप वन संरक्षक परियोजना बेगूं	एम.जे.एस.ए.- II	6	6	परिशिष्ट-ई अनुसार

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

120. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अवलर जिले में वर्तमान में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त (नोन पेचेबल) हैं एवं उनमें से कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कों हेतु कितनी-कितनी

(मास्टर मामन सिंह यादव)

राशि नवीनीकरण के लिए स्वीकृत की जा चुकी है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीनीकरण हेतु कितनी लम्बाई की सड़कों लिये कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में शेष क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 1049.95 किमी. सड़कें क्षतिग्रस्त (नोन पेचेबल) हैं, जिनमें से 971.52 किमी. की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विधानसभावार स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीनीकरण हेतु 109.06 किमी. सड़कों हेतु राशि रु. 2338.90 लाख की स्वीकृत की गई है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त क्षेत्र में शेष रही क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन की क्षतिग्रस्त सड़कें

121. श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव से गांव जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति सही नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के कार्य में अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित गांव से गांव जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन की सड़कों के सभी कार्य निर्धारित मापदण्डानुसार गुणवत्तापूर्वक सम्पादित किये जा रहे हैं। अत: इनकी जांच कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में मांझी की बावड़ी से वन तालाब तक सड़क निर्माण

122. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आमेर स्थित मांझी की बावड़ी से वन तालाब तक सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आमेर स्थित मांझी की बावड़ी से वन तालाब तक का क्षेत्र नगर निगम जयपुर के अधीन है। इस सड़क का क्षेत्राधिकार सिंचाई विभाग व वन क्षेत्र में होने के कारण वर्तमान में सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भोमपुरा-सुल्तानवाला अड्डा सड़क का नवीनीकरण

123. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अनूपगढ़- रायसिंहनगर स्थित भोमपुरा से सुल्तानवाला अड्डा वाया 6 पी.टी.डी. सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त सड़क हेतु रु. 446.23 लाख की स्वीकृति पीएमजीएसवाई फेज-द्वितीय योजना के तहत जारी की जा चुकी है एवं निविदा दिनांक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

01.02.2018 को खोली जा चुकी है। निविदा स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) दिनांक 08.02.2018 को जारी किया जा चुका है। उक्त सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

नगर व डीग पंचायत समितियों के फ्लोराइड से प्रभावित गांव

124. श्रीमती अनीता (नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति नगर एवं डीग के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों को चम्बल धौलपुर, भरतपुर पेयजल परियोजनाओं से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के लिए अनुबंधित फर्म को राशि व कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, नगर एवं डीग के क्रमश: 164 एवं 119, इस प्रकार कुल 283 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र, नगर के 235 ग्राम सम्मिलित) तथा नगर एवं डीग कस्बे में मानक मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतही जल स्रोत चम्बल नदी से दो परियोजनाओं की स्वीकृति एवं इनकी वर्तमान प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर प्रथम चरण की पेयजल परियोजना के पार्ट द्वितीय के प्रथम पैकेज के अन्तर्गत चम्बल नदी से भरतपुर जिले की डीग, नगर, कामां एवं पहाड़ी तहसील के 755 ग्रामों हेतु मुख्य ट्रंक मेन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.08.2012 को राशि रुपये 311.49 करोड़ की जारी की गयी।

इस परियोजना से पंचायत समिति, नगर एवं डीग को कुचावटी में प्रस्तावित स्वच्छ जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है तथा इस हेतु मलाह भरतपुर से कुचावटी स्वच्छ जलाशय एवं नगर स्वच्छ जलाशय तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्य ट्रंक लाईन

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

एवं आधारभूत संरचनाओ के कार्य हेतु मैसर्स आई.वी.आर.सी.एल. को दिनांक 13.09.2012 को राशि रुपये 202.79 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया तथा यह कार्य दिनांक 22.03.2015 तक पूर्ण करना निर्धारित था। परन्तु फर्म द्वारा कार्य अत्यन्त धीमी गति से करने के कारण दिनांक 03.09.2014 को लिये गये निर्णय अनुसार उक्त कार्य दिनांक 22.09.2014 को रिसाइण्ड कर दिया गया।

उक्त कार्य के निष्पादन हेतु पुन: निविदा आमंत्रित की जाकर मैसर्स एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड, गुड़गांव को दिनांक 29.01.2016 को राशि रुपये 262.62 करोड़ का जारी किया जा चुका है। कार्यादेश अनुसार यह परियोजना दिनांक 07.02.2018 तक पूर्ण की जानी निर्धारित थी परन्तु, कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधित फर्म से रुपये 414.00 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में रोक ली गयी है। यह परियोजना अब दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करनी अपेक्षित है।

(ब) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर प्रथम चरण की पेयजल परियोजना कें पार्ट द्वितीय के पैकेज द्वितीय के अंतर्गत कामां-पहाड़ी, डीग-नगर एवं भरतुपर-कुम्हेर-रूपवास सैक्शन के ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को राशि रुपये 720.31 करोड़ की जारी की गयी।

इस परियोजना से पंचायत समिति, नगर एवं डीग के क्रमश: 164 एवं 119, इस प्रकार कुल 283 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र, नगर के 235 ग्राम सम्मिलित) तथा नगर एवं डीग कस्बे को क्लस्टर वितरण प्रणाली से लाभान्वित करने हेतु मैसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड को राशि रुपये 263.00 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 18.09.2013 को जारी किया जाकर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। कार्यादेश अनुसार यह परियोजना दिनांक 27.03.2016 तक पूर्ण की जानी निर्धारित थी परन्तु, कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधित फर्म से रुपये 548.00 लाख

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में रोक ली गयी है। यह परियोजना अब दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करनी अपेक्षित है।

पैकेज प्रथम एवं द्वितीय परियोजनाओं के कार्य उक्तानुसार पूर्ण होने के उपरान्त ही पंचायत समिति, नगर एवं डीग के 283 ग्राम तथा कस्बा नगर एवं डीग को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

पाटोदी (बाड़मेर) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

125. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पाटोदी में सहायक अभियंता कार्यालय नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति मुख्यालय पर सहायक अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, पाटोदी के ग्रामों की विभिन्न पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय, पचपदरा के अधीन है।

(2) पंचायत समिति पाटोदी में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 92 ग्रामों में से 39 ग्राम उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप परियोजना से तथा 26 ग्राम क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, बिठूजा-पाटोदी से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के शेष 27 ग्रामों में विभागीय हैण्डपम्पों/टांकों इत्यादि से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

उम्मेदसागर-धवा-समदड़ी-खण्डप परियोजना से लाभान्वित 39 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति का कार्य निष्पादनकर्ता अनुबंधक फर्म द्वारा परियोजना खण्ड, समदड़ी के अधीन तथा शेष 53 ग्रामों की पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य वर्तमान में सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय, पचपदरा (पाटोदी से लगभग 25 किलोमीटर दूर) द्वारा सुचारू रूप से निष्पादित किये जाने के कारण पंचायत समिति मुख्यालय, पाटोदी में सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता नहीं है।

झुन्झुनूं जिले में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग

126. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भारत सरकार से किसको कितना बजट स्वीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त घोषित कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हो चुका है व कितने का प्रारंभ होना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा झुंझुनूं जिले के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग (11) व (709) की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी है? यदि हां, तो अब सरकार उक्त का कार्य कब प्रारंभ करवाकर पूर्ण कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1 अप्रैल, 2014 से लेकर दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में 13 राष्ट्रीय राजमार्ग 1197 किमी. की घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त घोषित राजमार्गो पर भारत सरकार द्वारा 7 कार्यों की 5870.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त घोषित राजमार्गो पर 7 कार्यो की 1082.72 किमी. की 5870.95 करोड़ रुपये की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी है, जिनमें से 1 कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है, जो शीघ्र प्रारम्भ होने की सम्भावना है एवं 6 कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है, विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी हां। भारत सरकार द्वारा झुन्झुनूं जिले के लिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-11 दिनांक 04.03.2014 व एन.एच.-709 विस्तार दिनांक 22.02.2012 को घोषित किये गये थे, आदेशों की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) जी नहीं। उक्त घोषित राजमार्गों पर भारत सरकार से अब तक नवीनीकरण, चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कुल 6 कार्यों पर 343.12 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, इनमें से अब तक 8.96 करोड़ रुपये व्यय कर 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 2 कार्य प्रगति पर हैं, जिनके वर्ष 2018-19 में पूर्ण होने की सम्भावना है एवं 2 कार्यों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है जिनके वर्ष 2019-20 में पूर्ण होने की सम्भावना है, विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में पेयजल समस्याग्रस्त गांव

127. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2018 तक सरकार द्वारा पेयजल सम्बन्धी क्या-क्या कार्य करवाये गये? योजना व कार्य का नाम तथा ग्राम पंचायतवार व्यय राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में सरकार द्वारा कितने हैंडपम्प एवं नलकूप लगाए गए? ग्रामवार व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा पेयजल समस्याग्रस्त कौन-कौनसे गांव चिन्हित किए गए हैं तथा उनमें पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किए गये? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, जमवारामगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2014 से माह जनवरी, 2018 की अवधि में

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पेयजल संबंधी विकास कार्यों के अंतर्गत 127 नवीन हैण्ड पम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 150.63 लाख, 43 संवर्धन/परिवर्तित/पुनर्गठित जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 843.41 लाख, 24 आर.ओ. संयंत्रों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु रूपये 475.46 लाख, सौर ऊर्जा आधारित 2 बोरवेल्स हेतु रुपये 19.24 लाख एवं सौर ऊर्जा आधारित 1 बोरवेल मय डी-फ्लोरिडेशन इकाई के स्थापना कार्य हेतु रुपये 12.20 लाख, इस प्रकार कुल 197 कार्यों/योजनाओं हेतु राशि रुपये 1500.94 लाख की स्वीकृति जारी की गयी। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध 116 हैण्ड पम्प, 36 पेयजल योजनाएं, 7 आर.ओ. संयंत्र, सौर ऊर्जा आधारित 2 बोरवेल्स एवं सौर ऊर्जा आधारित 1 बोरवेल मय डी- फ्लोरिडेशन इकाई के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

शेष रहे 11 हैण्ड पम्प एवं 17 आर.ओ. संयंत्र एवं 6 संवर्धन जल योजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। शेष 1 योजना के कार्य प्रारम्भ करने हेतु निविदा संबंधी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रगतिरत एवं शेष समस्त कार्य चरणबद्ध रूप से माह मई, 2018 तक पूर्ण करने अपेक्षित हैं।

स्वीकृत योजना/कार्यों के नाम सहित ग्राम पंचायतवार व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र, जमवारामगढ़ में माह जनवरी, 2014 से माह जनवरी, 2018 की अवधि में 127 नवीन हैण्ड पम्पों के निर्माण एवं विभिन्न संवर्धन/परिवर्तित/पुनर्गठित जल योजनाओं के अंतर्गत 42 नवीन थ्री-फेज नलकूपों की जारी स्वीकृति के विरूद्ध 116 हैण्ड पम्प एवं 34 नलकूपों का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण किया गया है। ग्रामवार स्थान सहित वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

128. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं और वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त हेतु चलाई जा रही योजनाओं हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाएं राजस्व ग्राम की कुल आबादी के आधार पर बनाई जाती है? यदि हां, तो क्या नेशनल हेबिटेशन सर्वे 2003 के अनुसार राजस्व ग्रामों की 45-65 प्रतिशत आबादी जो उस राजस्व ग्राम की दूर-दराज ढाणियों/मजरों में निवास करती है, उनको भी योजनान्तर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के द्वारा राजस्व ग्राम की दूर-दराज ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है और वर्तमान में कितनी ढाणियां वंचित हैं? राजस्व ग्रामवार, ढाणियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय नीति अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1500 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों में हैण्ड पम्प योजना, 1500 से अधिक एवं 4000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 4000 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में पाइप्ड जल योजना लागू करने के मानदण्ड निर्धारित हैं।

राज्य के ऐसे ग्राम जिनकी वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जनसंख्या 1500 से अधिक व 4000 तक है, को अन्य जल योजना से पाइप्ड जल योजना में परिवर्तित निम्न शर्तों के अधीन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(अ-1) बनाई गयी योजना की 50 प्रतिशत राशि सांसद/विधायक कोष से अथवा जन सहभागिता के अंतर्गत दिये जाने पर सहमति हो

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(अ-2) योजना का संचालन व संधारण तथा विद्युत बिल का भुगतान जनता जल योजना पैटर्न पर संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाए एवं

(अ-3) प्रस्तावित पाइप्ड जल योजना में स्थानीय भू-जल स्रोत का प्रावधान लिया जाए।

(ब) टी.एस.पी. क्षेत्र के ग्राम जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है।

(स) आपणी योजना के ग्राम जिनकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, परन्तु योजना की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा जन सहयोग द्वारा प्रस्तावित है।

(द) बी.ए.डी.पी. क्षेत्र में ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है एवं जिन्हें बी.ए.डी.पी. योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट के तहत पाइप्ड योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य योजना क्षेत्र एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत कुल रुपये 434543.74 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है। विस्तृत बजट प्रावधान योजना/मदवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल जनसंख्या 51500352 व्यक्ति है। प्रदेश में कुल 121648 हैबिटेशन्स में से 43283 मुख्य हैबिटेशन (ग्राम) एवं 78365 अन्य हैबिटेशन (ढाणियां) हैं। 43283 मुख्य हैबिटेशन्स के विरुद्ध 42991 तथा 78365 अन्य हैबिटेशन्स के विरुद्ध 68362 हैबिटेशन्स को माह दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण/आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल से अब तक लाभान्वित किया गया है।

(3) भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार विधान सभा क्षेत्र, श्रीमाधोपुर की चिन्हित समस्त 774 ढाणियां (अन्य हैबिटेशन्स) पूर्ण/आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

वर्ष 2016 एवं 2017 में उक्त क्षेत्र के मुख्य हैबिटेशन में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किये गये कार्य एवं इनकी वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त दोनों वर्षों में ढाणियों हेतु पेयजल संबंधी किसी भी कार्य की स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छबड़ा के गांवों में नवीन ट्यूबवैलों की स्थापना

129. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं तथा वर्तमान में कितने हैण्डपम्प खराब हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश मे गर्मी के मौसम को देखते हुए हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने व किस आधार पर हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद के हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल से वंचित गावों में पेयजल की क्या व्यवस्था है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले की पंचायत समिति, छबड़ा में कुल स्थापित 1672 हैण्डपम्पों में से 87 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य खराब तथा 76 हैण्डपम्प परित्यक्त (स्थाई रूप से खराब) तथा पंचायत समिति, छीपाबड़ौद में कुल स्थापित 1553 हैण्डपम्पों में से 36 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य खराब तथा 94 हैण्डपम्प परित्यक्त हैं।

उक्त दोनों पंचायत समितियों के ग्रामों में स्थापित हैण्डपम्पों का ग्राम पंचायतवार वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह जनवरी, 2018 तक 4093 नवीन हैण्डपम्प एवं 1690 थ्री- फेज नलकूपों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा आधारित 708 नलकूप, सौर ऊर्जा आधारित 1241 नलकूप मय डी-फ्लोरिडेशन यूनिट तथा 441 आर.ओ. संयंत्र का निर्माण कार्य कराया गया है।

आगामी ग्रीष्म के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनाये रखने हेतु नवीन हैण्डपम्प एवं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

नलकूपों का निर्माण भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार सतत प्रक्रिया के तहत कराया जाएगा।

(3) पंचायत समिति, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमश: कुल 188 एवं 176, इस प्रकार कुल 364 ग्राम सम्मिलित हैं। इनमें से 4 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 34 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा शेष 326 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

उक्त समस्त ग्राम नलकूप एवं हैण्डपम्प आधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों में पर्याप्त संख्या में हैण्डपम्पों से तथा हैण्डपम्प के अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं में नलकूपों के साथ-साथ हैण्डपम्पों/अन्य जल स्रोतों से स्वच्छ पेयजल वर्तमान में उपलब्ध कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ बांध में मेज नदी से पानी लाने की योजना

130. श्रीमती गोलमा देवी (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ए.आइ.डी.पी. योजना के अन्तर्गत मेज नदी एनीकट (चम्बल) से पानी लिफ्ट करके जयपुर जिले के रामगढ़ बांध तक पानी लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ए.आई.डी.पी. योजना के अन्तर्गत मेज नदी एनीकट (चम्बल) से पानी लिफ्ट करके जयपुर जिले के रामगढ़ बांध तक पानी लाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जल संकट के निदान हेतु नदियों को जोड़ने की योजना

131. श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो योजना कब प्रारंभ हुई? इसके तहत कितनी लागत से किन-किन नदियों को जोड़ा जाएगा व इसकी लागत कौन वहन करेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में नदी जोड़ने का कार्य कब प्रारंभ होगा व इससे कितने जिले लाभान्वित होंगे एवं कितनी भूमि सिंचित होगी तथा कितने लोगों को पेयजल मिलेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभिन्न नदियों को जोड़ने से जलीय जीवों और वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना हाथ में लिये जाने की तिथि, लागत, नदियों के नाम एवं लागत वहन किये जाने आदि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) नदियों को जोड़ने का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्धतानुसार प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। विचाराधीन योजनाओं से प्रस्तावित लाभान्वित जिलों, क्षेत्रफल आदि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। नदियों को जोड़ने से संबंधित योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स में जलीय जीवों एवं वनस्पतियों पर इम्पैक्ट अध्ययन के प्रावधान अन्तर्गत सुझावों के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नहरी क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण

132. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहरी जमीन पर कई मुरब्बों में बिना खाले/कच्चे खालों से सिंचाई करनी पड़ती है?

(2) क्या सरकार नहरी क्षेत्र में बिना खाले/कच्चे खालों के मुरब्बों को चिन्हित करके पक्के खालों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस हेतु ओएफडी कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के पीएमकेएसवाई के तहत प्रस्तावित आईएसबीआईजी कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार कर पत्र दिनांक 09.10.2017 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गयी है।

प्रश्न संख्या 133

(स्थगित)

श्रीगंगानगर में उज्जवला योजना के तहत जारी गैस कनेक्शन

134. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना में जनवरी, 2018 तक कुल कितने गैस कनेक्शन जारी किये गये व कितने जारी करना शेष हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष पात्रताधारियों को गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्यौग से प्राप्त सूचना अनुसार

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 2018 तक कुल 7362 (आईओसीएल-1526, एचपीसीएल-2848 एवं बीपीसीएल-2988) गैस कनेक्शन जारी किये गये है। ग्रामवार सूची वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php

https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx

https://ebharatgas.com→mylpg→Ujjwala Beneficiary

विधान सभा क्षेत्रवार कनेक्शन से शेष पात्रताधारियों की सूची तेल कम्पनियों द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2019 तक शेष वंचितों को (एसईसीसी अन्तर्गत) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। उक्त योजनान्तर्गत ऐसे परिवार जिनका नाम पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी SECC (आर्थिक, सामाजिक एवं जातिगत जनगणना) 2011 लिस्ट में है, उस घर की किसी भी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, के नाम से गैस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।

प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डारों से विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का आकलन

135. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डारों की स्थापना की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कुल कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अन्नूपर्णा भण्डारों के माध्यम से किन-किन वस्तुओं का विक्रय किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आमजन को लाभान्वित करने हेतु उक्त अन्नपूर्णा भण्डारों में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का आकलन किस प्रकार किया जाता

(श्री पब्बाराम)

है? क्या उक्त वस्तुए बाजार दर से कम दर पर विक्रय की जाती हैं? यदि हां, तो कुल कितने प्रतिशत कम दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में अन्नपूर्णा भण्डार योजना के तहत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से अन्नपूर्णा भण्डारों का संचालन किया जा रहा है। फलौदी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 36 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से विक्रय की जानेवाली दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) अन्नपूर्णा भण्डारों के माध्यम से मानक ब्राण्डेड कम्पनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है।

उक्त वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य पर 2% से 30% तक की छूट दी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के सरकारी मन्दिरों के पुजारियों का विभागीय कार्यालयों में पदस्थापन

136. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर में कुल कितने सरकारी मंदिर हैं एवं उनकी देखरेख हेतु पुजारियों, सेवागिरों व मैनेजरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के कितने मंदिरों के पुजारी व सेवागीर कब से कहां-कहां किन आदेशों के तहत विभागीय कार्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के अनेक मंदिर न तो समय पर खुल रहे हैं, न ही समय पर उनमें सेवा-पूजा हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश भंसाली)

(4) क्या सरकार सरकारी मंदिरों की व्यवस्थाओं के सुधार हेतु कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 6 मंदिर एवं राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के 8 मंदिर हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। इन मंदिरों की देख-रेख हेतु पुजारियों, सेवागीरों व मैनेजरो के कितने-कितने पद मंदिर अनुसार स्वीकृत है एवं कितने पद वर्तमान मे रिक्त है इसकी सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(2) श्री ताराचंद, पुजारी सहायक आयुक्त कार्यालय, देवस्थान विभाग, जोधपुर में दिनांक 12.12.2012 से कार्यरत है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। सरकारी मंदिरों की व्यवस्थाओं के सुधार हेतु नीति बनायी गयी है जिसका विवरण परिशिष्ट 3 सलंग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले के पंजीकृत मंदिरों को देय सुविधाएं

137. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले के कितने मंदिर विभाग में पंजीकृत हैं? उक्त मंदिरों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर जिले में अपंजीकृत मंदिरों को पंजीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार के 41, आत्मनिर्भर के 7 तथा सुपुर्दगी श्रेणी के 41 मंदिर है। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2017 तक जयपुर जिले में 526 मंदिरों के

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

ट्रस्ट पंजीकृत हैं। राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों की व्यवस्था व सेवा पूजा पर उपलब्ध बजट के अनुसार राजकीय एवं निधि मद से व्यय किया जाता है। सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिरों की व्यवस्था का प्रबंध सुपुर्दगार द्वारा मंदिर से प्राप्त आय के अनुसार किया जाता है।

(2) अपंजीकृत मंदिरों को राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर मंदिरों (ट्रस्ट) को पंजीकृत किया जाता हैं।

कोटा जिले में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने की योजना

138. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत 03 वर्षों में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ किये गए एवं कितने उपकेन्द्रों को क्रमोन्नत किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में कोटा जिले में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां ब्लॉकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 3 वर्षो में 901 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये एवं एक भी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र को मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत नहीं किया गया है। खोले गये नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत किये जाते है। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लम्बित मानदेय

139. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गत 04 वर्षों में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं? क्या उक्त के लिये कार्यकर्ता, सहयोगिनी आदि का चयन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत आशा सहयोगिनी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय बकाया है? यदि हां, तो कब से? सरकार द्वारा उक्त कार्मिकों का मानदेय कब तक दे दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में तीन परियोजनाएं क्रमश: परियोजनाएं सिवाना, सिणधरी एवं नोखड़ा संचालित है।

परियोजना सिवाना में वर्ष 2016-17 में 08 नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं एवं परियोजना सिणधरी में वर्ष 2009-10 में स्वीकृत 06 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन उक्त अवधि में प्रारम्भ किया गया है। परियोजना सिणधरी द्वितीय (मुख्यालय नोखड़ा) में उक्त अवधि में कोई केन्द्र नहीं खोला गया है।

परियोजना सिवाना में 08 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी की चयन की प्रक्रिया जारी है। सिण्धरी में 06 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 06 कार्यकर्ता एवं 02 सहयोगिनियों का चयन किया चुका है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में मानदेय भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

परियोजना का नाम	कार्यकर्ता मानदेय भुगतान की स्थिति	सहयोगिनी मानदेय भुगतान की स्थिति
सिवाना	जनवरी, 2018	जनवरी, 2018
सिणधरी	जनवरी, 2018	जनवरी, 2018
नोखड़ा	दिसम्बर, 2018	जनवरी, 2018

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) जी हां। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6000 रु. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 4500 रु. एवं आशा सहयोगिनी का 2500 रु. मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गयी है।

प्रदेश में सीमेंट ब्लॉक आवंटन की नीति

140. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सीमेंट ब्लॉक आबंटन के क्या नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित हैं? संबंधित नियमों/ आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के पांच में से एक सीमेंट ब्लॉक के लिए ही टैक्नीकल बिड में टैण्डर आये हैं? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर ब्लॉक के लिए कोई टेण्डर ही नहीं आया? यदि हां, तो क्या सरकार सीमेंट ब्लॉक आवंटन की नीति पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सीमेन्ट ब्लॉक का आवंटन एम.एम.डी.आर. (संशोधन) एक्ट, 2015 एवं खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के तहत ई-नीलामी से किया जाता है। सम्बन्धित अधिनियम/नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है

(2) जी नहीं। खनिज लाइम स्टोन के पांच ब्लॉक्स की ई-नीलामी हेतु दिनांक 15.12.2017 को विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 19.01.2018 तक तकनीकी बिड प्राप्त की गयी। इन पांच ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक पर 3, एक ब्लॉक पर 2, दो ब्लॉक पर 1-1 व एक ब्लॉक पर कोई तकनीकी बिड प्राप्त नहीं हुई। किसी भी ब्लॉक पर प्रथम बार में तीन अथवा इससे अधिक तकनीकी बिड प्राप्त होने पर ही दूसरे चरण हेतु टेण्डर खोले जाने एवं इससे कम तकनीकी बिड प्राप्त होने पर नीलामी को बिना टैण्डर खोले ही निरस्त

(राज्य मंत्री, खान)

किये जाने का नियमों में प्रावधान हैं। अत: केवल एक ब्लॉक पर ही तीन निविदाएं प्राप्त होने के कारण ई-ऑक्शन किया गया। शेष ब्लॉक जिनमें तीन से कम अथवा कोई तकनीकी बिड प्राप्त नहीं हुई है उन्हें पुन: नीलामी करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। यह सही है कि जैसलमेर के ब्लॉक पर एक भी तकनीकी बिड प्राप्त नहीं हुई। अत: उक्त ब्लॉक की ई-नीलामी हेतु पुन: विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इन ब्लॉक्स का आवंटन भारत सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर सीमेन्ट ब्लॉक आवंटन की नीति के संबंध में पुनर्विचार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रद्द खानों की पुनः बहाली

141. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खान घोटाले के बाद सरकार द्वारा सभी आवंटित खानों का आवंटन रद्द कर दिया गया था? यदि हां, तो कितनी खानों का?

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से अधिकांश खानों को उच्च न्यायालय द्वारा बहाल कर दिया गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि न्यायालय में तथ्यों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया एवं वकीलों द्वारा भी सही तरीके से पैरवी नहीं किया जाना पाया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि लोकायुक्त जांच एवं एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की जांच में खान घोटाले में आरोपी अधिकारी दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त तथ्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा खान बहाली रोकने हेतु अग्रेत्तर क्या कदम उठाये गये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अवधि दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 तक खनन पट्टों हेतु जारी मंशा पत्रों एवं अन्य प्रकार के अनुज्ञा पत्रों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2015 से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेश के क्रम में कुल 551 मंशा पत्रों एवं 52 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों को निरस्त किया गया।

(2) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 197 प्रकरणों में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.10.2015 एवं आवेदन पत्र के संबंध में जारी अस्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए दो पृथक-पृथक प्रकार के आदेश पारित किये हैं जिनमें से तीन प्रकरणों में खनन पट्टा स्वीकृत करने तथा 194 प्रकरणों में सचिव स्तर के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई जाकर पुन: व्यक्तिगत सुनवाई कर नियमानुसार आदेश पारित करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिये हैं।

(3) जी नहीं। माननीय न्यायालय में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई है।

(4) कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता पाये जाने पर आवंटन निरस्त किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा जांच लोकायुक्त को दी गई। वर्तमान में लोकायुक्त में जांच विचाराधीन है। उक्त तथ्यों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना दिनांक 12.02.2018 के अनुसार लोकायुक्त जांच में अब तक 22 राजपत्रित अधिकारी एवं 5 अराजपत्रित कर्मचारी दोषी पाये गये हैं। उक्त जानकारी न्यायालय निर्णय के पश्चात् प्राप्त हुई है।

(5) 196 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा एक प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है जिसके उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।